राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या: 10

गुरुवार,

16 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर में हथियार लाइसेंस के लम्बित आवेदन

157. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्षों में जिला नागौर में आत्म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितनों में लाइसेंस जारी किये गये व कितने निरस्त हुए तथा कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त को लाइसेंस जारी करने के क्या मानदण्ड रहे एवं क्या आवेदन उक्त मानदण्ड के तहत ही निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जिला नागौर में विगत दो वर्षों में कुल 66 आवेदन आत्म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हेतु प्राप्त हुए हैं।

(2) उक्त प्राप्त 66 आवेदनों में से किसी भी आवेदक को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। 01 आवेदन निरस्त किया गया है। 46 आवेदन पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., तहसीलदार तथा वन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने तथा 19 आवेदन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन होने के कारण विचाराधीन हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(3) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। हथियार लाइसेंस आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 13 व आयुध नियम, 2016 के नियम 12 के तहत जारी किया जाता है। हथियार लाइसेंस जारी करने के मानदण्डों का विवरण परिशष्ट "अ" पर संलग्न है।

हथियार लाइसेंस का आवेदन आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत निरस्त किया गया है। हथियार लाइसेंस के आवेदन निरस्त करने के मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि नागौर जिले में हथियारों की लाइसेंस की पेंडेंसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के जो कारण बताये हैं, क्या तहसीलदार, पुलिस, सी.आई.डी. या अन्य विभागों की जो रिपोर्ट है, उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा है अथवा नहीं है? यदि है, तो फिर रिपोर्ट समय पर नहीं भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही का नियम बना है? आप ऐसे मामलों में रिपोर्ट नहीं भेजने वाले आफिसरों की जिम्मेदारी कब तक तय करोगे, उसकी समय सीमा क्या है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखिये, तहसीलदार से, पुलिस अधीक्षक से और वन विभाग से तथा सी.आई.डी. से, इनसे जिलाधीश को प्राप्त करने की समय सीमा तो 30 दिन है और 30 दिन के बाद में यह जो पेश कर देते हैं, तो उसके बाद में जिला कलेक्टर या तो निरस्त करता है या आवेदन लेता है।

दूसरी बात, आपने पूछा कि इसके निरस्त करने के मापदण्ड क्या हैं? निरस्त करने के मापदण्ड यह हैं कि किसी कारण से अगर वह आदमी अयोग्य समझा जाता है या विकृत चित्त का है या 21 साल से कम उम्र का है और आवेदक के विरुद्ध, पर शांति कायम करने का या सदाचार के लिए उसको पाबंद कर रखा है, आवेदक किसी अपराध में दोष सिद्ध कर दिया गया हो और फायर आर्म्स रखने के लिए मना कर दिया गया हो, अगर उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है और मजिस्ट्रेट द्वारा लोक सेवक या स्वयं की सुरक्षा के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने के इंकार करना आवश्यक समझा जाता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर भेजा, उसमें जो आपका एक्ट है, उसमें बिन्दु संख्या 13 की अनुज्ञप्तियों के पैरा 2 (क) में लिखा है कि जहां निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है। वहां यदि अनुज्ञापक अधिकारी ठीक समझे तो विहित समय के अवसान के पश्चात् उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किये बिना ऐसा आदेश कर सकेगा। जब दो-दो साल हो गये और मंत्रीजी, वे पेंडिंग पड़े हैं, एक को भी आपने लाइसेंस नहीं दिया है, तो क्या आप इसके लिए कोई अलग से आदेश जारी करने की मंशा रखते हैं? या तो उनको लाइसेंस दें या फिर उनका खारिज करके उनको समय पर कोई दूसरा काम लगाइये, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिला कलेक्टर के पास जब भी अभिशंसा आ जाती है, तो उसके बाद निर्णय करना उसका अधिकार है। वह चाहे तो उसको निरस्त भी कर सकता है और चाहे तो लाइसेंस भी जारी कर सकता है, लेकिन यह उसके अधिकार पर सब कुछ निर्धारित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न

158. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करने के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा का आधार क्या रखा जाता है व उक्त की समीक्षा कब की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न आदेश दिनांक 31.04.2015 में वर्णित मानदण्डानुसार स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा किये जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) आदेश दिनांक 30.04.2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदो की स्वीकृति के मानदण्ड जारी किये गये हैं, जिसके आधार पर ही समीक्षा

(शिक्षा मंत्री)

किये जाने का प्रावधान है। प्रथमत: उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षण सत्र 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गयी थी।

(3) जी हां। माध्यमिक शिक्षा में 30.09.2022 के नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विषयवार एवं पदवार बैक एण्ड पर गणना कर विश्लेषण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे-छोटे तीन प्रश्न हैं। पहला, पूर्व में 30.04.2015 के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया, जिसके कारण शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई क्या आज भी स्कूलों में उसी पैटर्न के अनुसार स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं, तो कितने स्कूलों में अगैन्स्ट द पोस्ट अन्य विषयों के या अन्य ग्रेड के लगे हुए हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो स्कूल वर्तमान सरकार ने क्रमोन्नत किये, क्या वहां इसी पैटर्न के अनुसार ही स्टाफ नियुक्त हुआ है? क्या वहां जनरल विषयों के पद भी सृजित किये हैं? आप कहें तो तीसरा भी बता दूं?

श्री अध्यक्ष: Hon. Member, please be confined to the ‘question’.

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): स्टाफ पैटर्न पर ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने पहला प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष: आपने पैटर्न के बारे में पूछा है। आप डिटेल में जायेंगे तो कहां होगा?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं, स्टाफ पैटर्न का क्या लगा हुआ है, यह तो पूछ सकता हूं न?

श्री अध्यक्ष: मैं भी सुन रहा हूं आपकी बात। आप पूछें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: सुन लिया। माननीय मंत्रीजी पहले प्रश्न का जवाब दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 30.04.2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार की जाती है और 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गयी और इसी को आधार मानकर आगे 2017-18 में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
इसका स्टाफिंग पैटर्न तय करना था, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि उस समय आपने उसको नहीं किया। हमने दो बार वर्ष 2019 में और वर्ष 2021 में स्टाफिंग पैटर्न प्रारम्भिक शिक्षा में किया। इसके अन्तर्गत 2019 में प्रारम्भिक शिक्षा में 124 वरिष्ठ अध्यापक नामांकन के आधार पर अध्यापक L2- 1,927 पद, L1 अध्यापक 5,736 पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II 2,232 पद, कुल 10,019 पद अतिरिक्त सृजित किये। 2021 में आधार 2019 को रखा और इसमें जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 10 से अधिक थी, तृतीय भाषा का एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया। ऐसे 1,002 पद स्वीकृत किये गये।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामला है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया 30.09.2022 के नामांकन के आधार पर प्रक्रियाधीन है और इस बीच में हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में अब तक 1,395 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय, 4,443 माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 1,194 उच्च प्राथमिक से सीधे ही सीनियर उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये। इन क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों में मानदण्डानुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं और वर्तमान में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका जो प्रश्न है, उसी का उत्तर दें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा प्रश्न यह है, क्या आज भी स्कूलों में उसी पैटर्न के अनुसार स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं, तो कितने स्कूलों में अगैन्स्ट द पोस्ट अन्य विषयों के, ग्रेड के लगे हुए हैं? मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगैन्स्ट द पोस्ट लगने का इन्होंने कोई प्रश्न पूछा नहीं। मैंने स्कूल वर्षवार बता दिये कि कहां-कहां कितने पद स्वीकृत किये। 61,984 पद हमने क्रियेट किये हैं, जो स्कूल क्रमोन्नत किये हैं उनमें और 30.09.2022 से नामांकन के आधार पर हमारी प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। जो भी स्टाफ की नामांकन के आधार पर जरूरत होगी, वहां पर स्टाफ प्रोवाइड करायेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा प्रश्न यह है कि क्या आज भी इसी स्टाफ पैटर्न के अनुसार स्कूलों में स्टाफ लगा हुआ है या नहीं? इतना पूछ रहा हूं। अगर नहीं, तो कितनों में नहीं लगा हुआ है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैंने आपसे जैसा जिक्र किया कि जो स्टाफिंग पैटर्न तय हो चुका है, उसके अनुसार जैसे-जैसे नये स्कूल क्रमोन्नत होते हैं, आप जानते हैं आठवीं से नवीं बनेगी, नवीं से दसवीं आयेगी, फिर ग्यारहवीं बारहवीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे बोलोगे, I will not allow it. आप डिसीप्लिन रखोगे तो मैं भी डिसीप्लिन रखूंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नामांकन और कालांश के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न तय किया गया है, हमने 30.09.2022 से नामांकन के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में काफी पद भरे गये हैं। करीब-करीब 90 हजार से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। हम बराबर स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर टीचर्स का पदस्थापन कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं यह पूछ ही नहीं रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अलग ढंग से लेकर आयें। माननीय सदस्य, आप अलग ढंग से लेकर आयें। आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं, अलग ढंग से लायें, मैं आपको अलाउ करूंगा।

अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

प्रतापगढ़ नगर परिषद् में कच्ची बस्तियों के पट्टों के लम्बित आवेदन

159. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगर परिषद् प्रतापगढ़ में कच्ची बस्ती, बगवास, तिलकनगर में कच्चे मकानों में कई वर्षों से जीवन यापन करने वाले आवासियों ने पट्टे के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो प्रशासन शहरों के संग अभियान में उक्त की पत्रावलियों का निस्तारण क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को उक्त अभियान में कोई विशेष छूट देकर पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगर परिषद् प्रतापगढ़ में स्थित बगवास सर्वेशुदा कच्ची बस्ती है, जबकि तिलक नगर कृषि/ आबादी भूमि पर स्थित कालोनी है।

बगवास कच्ची बस्ती में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टे हेतु कच्ची बस्ती के कुल 571 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

भूमि (किस्म)	प्राप्त आवेदन	प्रक्रियाधीन	निरस्त	जारी पट्टे
आबादी	89	0	41	48
चरागाह	185	185	0	0
रीको भूमि	297	297	0	0

आबादी भूमि पर निजी खातेदारी, नाला, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि एवं एक से अधिक आवेदन होने से 41 आवेदन निरस्त किये गये है। राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तित होने एवं रीको से एनओसी प्राप्त होने पर पट्टे जारी किये जा सकेंगे।

तिलक नगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टे हेतु कृषि भूमि रूपान्तरण के पट्टे हेतु कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19 प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं एवं शेष दो प्रकरण आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण लम्बित हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत उक्त को कच्ची बस्ती एवं कृषि भूमि में पट्टा जारी किये जाने हेतु छूट प्रदान की गयी है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी की पूरी मेहरबानी मेरे पर है, चरागाह भूमि में 185 और रीको के 297 आवेदन जो प्रक्रियाधीन हैं, माननीय मंत्री महोदय, इनके कब तक पट्टे मिल जायेंगे?

दूसरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर जमीन आबंटित हो गयी, लेकिन वहां मौके पर लोग बैठे हुए हैं, वहां सड़क भी नहीं है। इनके पट्टों की कार्यवाही भी करवाने की कृपा करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राजस्व रिकार्ड में जो भूमि चरागाह के लिए दर्ज है, उसकी जब तक किस्म का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वहां पर पट्टे नहीं मिलेंगे।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): हो गये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिए आपके आवेदन लम्बित हैं।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): वह हो गयी। जमीन नगर परिषद् को समर्पित कर दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर नहीं सुनना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कर दी, जो मुझे तो मालूम नहीं है। आपको मालूम हो तो अब क्या करें उसका?

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अब तो कृपा करके करें।

श्री अध्यक्ष: बहुत मेहरबानी है। बैठो आप। मेहरबानी कह दिया उन्होंने, बैठो बस।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मेहरबानी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

ब्यावर में वन भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

160. श्री अविनाश (जैतारण) (श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) के स्थान पर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कई ऐसे गांव हैं जो वन भूमि पर बसे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव तथा कब से बसे हुए हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रावधान के तहत?

(3) क्या सरकार वर्षों से उक्त भूमि पर बसे हुए गांवों को राहत देते हुए उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री मुरारी लाल (कृषि विपणन, राज्य मंत्री): (वन मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो खण्ड-1 का उत्तर दिया है, जी नहीं। यह बिलकुल गलत उत्तर है। सरविना जो गांव है, वह उसी वन क्षेत्र में 100 वर्षों से बसा हुआ है। सरूपा, खोरनाल गांव भी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत प्रश्न पर आपको पूरा अधिकार है, उसको लाने का।

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर देता हूं कि यह जो उत्तर गलत मिला है, इसमें सरविना, सरूपा, खोरनाल, राफा, दूधलेसर ऐसे गांव हैं जो 50, 100 वर्षों से बसे हुए हैं। उसकी किस्म वन क्षेत्र है। क्या सरकार गलत उत्तर देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खण्ड-2 में उत्तर दिया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है। क्या सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत, उसमें क्या ऐसा क्लॉज है कि जिसमें वन क्षेत्र की जमीन के बराबर जो गांव बसे हुए हैं, उनको आल्टरनेट के तौर पर दूसरी जमीन क्षतिपूर्ति के माध्यम से करके जो गांव बसे हुए हैं, वहां उनका आवासीय परिवर्तन कर सकती है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, हमारा जो विभाग का उत्तर है, वह बिलकुल ठीक है। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में वन मंडल, अजमेर के अंतर्गत रेंज ब्यावर के अधीन आने वाली वन भूमि पर कोई गांव बसा हुआ नहीं है, किन्तु काफी वर्षों से नगर परिषद् ब्यावर के वार्ड संख्या 57 में इंद्रा कालोनी, मसूदा रोड पर वन विभाग की भूमि पर बसी हुई है। इसके अलावा कोई गांव हमारी जानकारी में, विभाग की जानकारी में नहीं है।

दूसरा, आपने पूछा है कि इसमें क्या संशोधन करने का विचार रखते हैं? मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि गाइड लाइन में क्लियरकट यह बताया हुआ है आवासीय के लिए, मैं पढ़कर सुना देता हूं, "the Central Government will not entertain any proposal for diversion of forest and for construction of residential or dwelling houses". मतलब आवासीय के लिए क्लियर-कट लिखा हुआ है कि न तो क्षतिपूर्ति से कर सकते हैं और न वैसे कर सकते हैं। अन्य जो योजनाएं हैं, उनके लिए जरूर कर सकते हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं तो यह कह रहा हूं कि जिन्होंने गलत उत्तर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे पूछेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। एक तो मैंने आपको अलाउ किया है। गलत बात है। आपको अधिकार है, गलत है तो लेकर आओ न, क्या तकलीफ है?

अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

आबियाना ब्याज पर छूट देने की कार्ययोजना

161. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक सरकार द्वारा किसानों को आबियाना ब्याज पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसान हित में उक्त में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) वर्ष 2019 के बाद दिसम्बर, 2022 तक सरकार द्वारा आबियाना ब्याज पर छूट नहीं दी गयी है।

(2) वर्तमान में आबियाना ब्याज पर छूट दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आईजीएनपी में सरकार सिंचाई आबियाना ले रही है। दूसरी तरफ खड़ी फसल के दौरान बड़ी नहर बंदी ले ली जाती है। 70-70 दिन की नहर बंदी ली जाती है। किसान के खेत में लगभग 90 दिन बाद पानी आता है।

जो किसान अपने ट्यूबवैल्स से बीजान करते हैं, अपने खर्चे से बीजान करते हैं, उनसे आप आबियाना भी वसूल कर रहे हो और ब्याज भी वसूल कर रहे हो। यह आबियाना और ब्याज में छूट होनी चाहिए। आप छूट करने का विचार रखते हो या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मना कर दिया न।

अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

भीलवाड़ा में अल्पकालीन फसली ऋण

162. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालीन फसली ऋण में ढाई लाख किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है व उन्हें दो साल से ऋण भी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भीलवाड़ा में विगत पांच वर्षों में कितने किसानों को फसली ऋण दिया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं।

(2) भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा विगत 5 वर्षों में निम्नानुसार कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**ऋण वितरण से लाभान्वित कृषकों की संख्या**
1	2017-18	1,02,807
2	2018-19	77,911
3	2019-20	1,00,042
4	2020-21	1,21,221
5	2021-22	1,27,618

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने खण्ड-1 में जवाब दिया है कि, जी नहीं। मेरा प्रश्न, सिर्फ भीलवाड़ा जिले में अल्पकालीन फसली ऋण में 19,799 किसानों को डिफाल्टर घोषित किया है। उनमें से 18,273 को ऋण दिया गया। शेष किसानों को ऋण कब तक दिया जायेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरकार डेढ़ लाख के बजाय अल्पकालीन ऋण किसानों को देने एवं पोर्टल को लगातार खोलने का विचार रखती है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 2019-20 में जो डिफाल्टर किसान थे, ऐसे किसानों को ऋण नहीं दिया गया था। आज की तारीख में 11.08.2020 से आदेश कर दिये हैं, जिन किसानों ने अपना ऋण मय ब्याज जमा करा दिया, जो डिफाल्टर थे, सभी किसानों को राजस्थान में ऋण दिया गया है, कोई किसान बाकी नहीं है। डेढ़ लाख से ऊपर ऋण देने का दूसरा प्रश्न पूछा है, डेढ़ लाख से ज्यादा देने का प्रावधान ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रताप लाल भील।

उदयपुर में फसल खराबे का मुआवजा

163. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में वर्ष 2022 में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस तहसील में? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि फसल खराबे का सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। वर्ष 2022 में जिला उदयपुर में अतिवृष्टि से हुई बाढ़ से तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा में फसल खराबा हुआ है।

(2) खरीफ फसल संवत् 2079 (वर्ष 2022) की गिरदावरी करवाई जा चुकी है। वर्ष 2022 में तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा में 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा वाले प्रभावित पात्र कृषकों को एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान देय है, जिसके लिए दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, उदयपुर जिले में आपने सलूम्बर और झल्लारा में फसल खराबा बताया है, जिले की बाकी तहसीलों की क्या स्थिति है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सलूम्बर और झल्लारा में फसल खराबा हुआ है तो कितने किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? संख्या बताएं। इस पर कितनी राशि व्यय होगी? एसडीआरएफ में क्या-क्या नोर्म्स हैं?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल संवत् 2079 में उदयपुर जिले की तहसील सलूम्बर एवं तहसील झल्लारा में फसल खराबा 33 परसेंट से अधिक प्रभावित काश्तकारों की संख्या 52 हजार 631 है। उक्त तहसीलों में प्रभावित काश्तकारों के डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु तहसीलदारों को पाबंद कर दिया गया है। पोर्टल इनका खोल दिया गया है और उदयपुर में ये दो ही तहसील हैं। जहां तक नियम की बात है, सिंचित क्षेत्र में 17 हजार रुपये और असिंचित में 8 हजार 500 रुपये का फसल का खराबा नियम के तहत जो डीआरएमएस का नोर्म्स है, इसका जो भी सिस्टम है, उसके तहत असिंचित को 8 हजार 500

(श्री गोविंद राम)

रुपये और सिंचित को 17 हजार रुपये देते हैं, इस अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि इस बारे में दिशा-निर्देश कब जारी हुए? कितने दिन में इनको मुआवजा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। संख्या बताएं।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 164

श्रीमती इन्दिरा देवी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्रजी मेघवाल।

भीलवाड़ा में स्टार्ट अप फण्ड से देय राशि

165. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्टार्टअप हब के प्रोत्साहन हेतु राजीव फण्ड की स्थापना की गई है? यदि हां, तो उक्त फण्ड में जिला भीलवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिसम्बर, 2022 तक कितनी राशि का अनुमान लगाया गया है? पंजीबद्ध प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्टार्ट अप फण्ड से उक्त जिले में होनहार बालकों को उत्साहवर्धन हेतु कितनी-कितनी राशि कौन-कौनसे स्टार्ट अप के लिए दी गई है? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) (राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्थान पर): (1) जी हां। प्रदेश में स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु राजीव फण्ड की स्थापना की गई है। यह एक समेकित (consolidated) फण्ड है, जिसके द्वारा प्रदेश के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है।

जिला भीलवाड़ा से आईस्टार्ट पोर्टल पर अब तक 21 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 स्टार्टअप्स द्वारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। इन 2 स्टार्टअप्स को राशि रुपये 6 लाख 20 हजार की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है:-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

वित्तीय वर्ष 2021-22

1- स्टार्टअप का नाम- Prepyoung Ventures Pvt. Ltd., Bhilwara

- वित्तीय सहायता का प्रकार: विपणन सहायता (Marketing Assistance)
- अनुमोदित राशि: रुपये 5,00,000/-
- वितरण (Disbursement) दिनांक: 21.08.2021.

वित्तीय वर्ष 2022-23

1- स्टार्टअप का नाम- Xpawnential Power Pvt. Ltd., Bhilwara

- वित्तीय सहायता का प्रकार: निर्वहन भत्ता (Sustenance Allowance)
- अनुमोदित राशि: रुपये 1,20,000/-
- वितरण दिनांक: 25.05.2022.

-वितरित राशि: रुपये 80,000/- (दिसम्बर एवं जनवरी की किस्त रुपये 20,000/- प्रक्रियाधीन है)

(2) जिला भीलवाड़ा से आईस्टार्ट पोर्टल पर 21 पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 2 स्टार्टअप्स द्वारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। इन 2 स्टार्टअप्स को कुल राशि रुपये 6 लाख 20 हजार की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है:-

1- स्टार्टअप का नाम- Prepyoung Ventures Pvt. Ltd., Bhilwara

- वित्तीय सहायता का प्रकार: विपणन सहायता (Marketing Assistance)
- अनुमोदित राशि: रुपये 5,00,000/-
- वितरण (Disbursement) दिनांक: 21.08.2021.

2- स्टार्टअप का नाम- Xpawnential Power Pvt. Ltd., Bhilwara

- वित्तीय सहायता का प्रकार: निर्वहन भत्ता (Sustenance Allowance)
- अनुमोदित राशि: रुपये 1,20,000/-
- वितरण दिनांक: 25.05.2022.

-वितरित राशि: रुपये 80,000/- (दिसम्बर एवं जनवरी की किस्त रुपये 20,000/- प्रक्रियाधीन है)

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न करने का एक ही उद्देश्य था, यह एक योजना है वो बहुत ही धीरे चल रही है, इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो। मैं आपसे अगर यह पूछूं, राजस्थान में 2022-23 में इस फंड में कितना पैसा स्वीकृत था और कितना खर्च हुआ? इसमें भीलवाड़ा को कितना अलाट हुआ और कितना खर्च हुआ? कम खर्च होने के कारण आप बता दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है इसलिए मैं आपसे पूछता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव फण्ड में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 291 लाख रुपये खर्च किये। 2021-22 में 26 करोड़ 18 लाख 36 हजार रुपये व्यय किये और 171 व्यक्ति लाभांवित हुए। 2022-23 में 156 व्यक्ति लाभांवित हुए और इसमें 580.10 लाख यानी 5 करोड़ 80 लाख 10 हजार रुपये व्यय हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक भीलवाड़ा का सवाल है 21 व्यक्तियों ने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन किया और 2 ही व्यक्तियों ने अप्लाई किया, जिनको मैंने आपको बता दिया है कि एक को 5 लाख और दूसरे को 1 लाख 20 हजार रुपये मिले हैं। जो-जो अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): अलाट कितना हुआ, बताएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जो भी इसमें स्टार्टअप वाला अप्लाई करेगा, इसका एक प्रोसीजर है, पहले वो आईस्टार्ट पोर्टल में अप्लाई करेगा, 2 ही लोगों ने अप्लाई किया 21 में से, फिर उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसकी रेटिंग होगी, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, फिर उसके बाद में कमेटी अपनी मीटिंग के बाद उसकी फंडिंग करेगी। दो ही व्यक्तियों ने अप्लाई किया है, दस, बीस, पचास, जो भी अप्लाई करेंगे और एलीजिबल होंगे उन सबको इसका लाभ मिलेगा।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): अभी 21 पेंडिंग क्यों पड़े हैं? भीलवाड़ा में जिनने अप्लाई किया उनमें से 2 को दिया है। 21 प्रार्थना पत्र अभी भी पेंडिंग हैं, इसका कारण बता सकते हैं क्या? अप्लाई किया है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अप्लाई नहीं किया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उससे आगे नहीं बढ़े हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो उनको मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर में पंजीकृत बेरोजगार

166. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं? शिक्षित बेरोजगारों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कितने आवेदनकर्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तथा कितने वंचित हैं? महिला व पुरुष बेरोजगारों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) विभागीय पोर्टल के अनुसार उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, बीकानेर में दिनांक 12.02.2023 को 34972 (स्नातक एवं उच्च योग्यताधारी) शिक्षित बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। जिला बीकानेर में शिक्षित बेरोजगारों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	शिक्षित बेरोजगारों की संख्या
1	बीकानेर (पूर्व व पश्चिम)	12,080
2	खाजूवाला	3,372
3	कोलायत	2,998
4	लूणकरणसर	5,413
5	नोखा	5,892
6	श्रीडूंगरगढ़	5,217
	कुल	**34,972**

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 737 आवेदनकर्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, जिनमें 224 महिला एवं 513 पुरुष लाभार्थी हैं तथा 158 पात्र आवेदन जांच उपरान्त योजनान्तर्गत एक समय में दो लाख आशार्थियों को लाभांवित की सीमा निर्धारित होने के कारण लम्बित है, जिनमें 54 महिला एवं 104 पुरुष आशार्थी हैं। जांच हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार आरएसएलडीसी ट्रेनिंग सेंटर, जो वर्तमान में सिर्फ जिला मुख्यालयों पर हैं, उनको ब्लाक मुख्यालयों पर खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तों क्यों?

(श्री सुमित गोदारा)

दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता के रूप में चार से साढ़े चार हजार रुपये की राशि चार घंटे कार्य के लिए इंटर्नशिप के रूप में दी जा रही है, माननीय प्रधान मंत्रीजी की कृषि योजनाओं के कारण गांवों में मजदूर भी हजार रुपये में मिल रहे हैं तो क्या सरकार मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? ऐसे बेरोजगार जिन्होंने इंटर्नशिप की है, उनको सरकारी नौकरियों में पांच से दस प्रतिशत आरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सवाल माननीय सदस्य ने पूछे, पहला कि आरएसएलडीसी के ब्लाक स्तर पर कब तक सेंटर्स खुल जाएंगे। आरएसएलडीसी की एक प्रक्रिया है, हमारी योजनाएं तय हैं, उनमें ट्रेनिंग पार्टनर अप्लाई करते हैं कि हमको इस-इस जिले में, इस-इस ब्लाक में सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं। हम उनकी ईओआई जारी करके उन्हें सैंटर्स की परमिशन दे देते हैं। इस महीने वापस अगले 01 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए ईओआई जल्द ही जारी होने वाली है। उसमें किसी भी ब्लाक के लिए जो भी अप्लाई करेगा, उन सबको हर ब्लाक के ऊपर, जहां भी अप्लाई होगा, वहां हम सैंटर्स चालू करेंगे। पहला जवाब।

दूसरा, आपने कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, उस इंटर्नशिप के बाद क्या सरकारी नौकरियों में भी उन्हें कोई प्रायोरिटी मिलेगी? अभी तक ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि वह तो सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें वे अपीयर करें और उनके लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़त की बात की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

वल्लभनगर में नवीन जी एस एस की स्थापना

167. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु नये

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

जीएसएस एवं 33 केवी लाइन स्वीकृत करने पर विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में ऐसे क्षेत्रों में, जहां जीएसएस एवं 33 केवी लाइन कनेक्शन की कमी के कारण अन्य स्टेशनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में नवीन जीएसएस व 33 केवी लाइन कनेक्शन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश के विद्युत निगमों में विद्युत भार को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार नये 132/33 केवी जीएसएस, 33/11 केवी सब-स्टेशन एवं 33 केवी लाइन स्वीकृत किये जाते हैं। पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी नये जीएसएस सब-स्टेशन एवं 33 केवी लाइन स्वीकृत करने हेतु अन्य क्षेत्रों की तरह समान प्रावधान है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में स्थापित 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, 33/11 केवी सब-स्टेशन एवं 33 केवी लाइन की क्षमता विद्युत भार के अनुरूप है एवं उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। भविष्य में विद्युत भार को देखते हुए, उक्त विधान सभा क्षेत्र में नया 33/11 केवी सब-स्टेशन बांसड़ा मय 33 केवी लाइन स्वीकृत किया गया है। उक्त सब-स्टेशन का कार्य आरडीएसएस स्कीम के तहत किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नया 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सुधार हेतु प्रस्तावित क्रम संख्या 2 में 33/11 केवी सब-स्टेशन बांसड़ा स्वीकृत किया गया है, इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? साथ ही, मैं यह जानना चाहती हूं कि गत दो माह में कितने किसान भाइयों का बिल शून्य हुआ और कितनों को योजना का लाभ मिला?

श्री अध्यक्ष: दो पार्ट्स मत कीजिये, एक ही पार्ट।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत आरडीएसएस योजना (फेज प्रथम) के अन्तर्गत 33/11 केवी सब-स्टेशन बांसड़ा के निर्माण हेतु वर्तमान में

(श्री भंवर सिंह भाटी)

कार्यादेश प्रक्रियाधीन हैं, जिसका निर्माण कार्य लगभग 30 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुल 13,235 सामान्य ग्रामीण कृषि उपभोक्ता हैं, जिनमें से जनवरी, 2023 तक 12,759 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से लाभान्वित किया गया है, जो कुल उपभोक्ताओं का 96.40 प्रतिशत है। कुल लाभान्वित कृषि उपभोक्ताओं में से 12,245, यानी 95.97 प्रतिशत कृषि उपभोक्ताओं का शून्य राशि का विद्युत बिल जारी किया गया तथा अनुदानित राशि 9.7 करोड़ रुपये है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोराराम कुमावत।

तख्तगढ़ (सुमेरपुर) के कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण की कार्ययोजना

168. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कस्बा तख्तगढ़ में कन्या महाविद्यालय कब स्वीकृत हुआ व उक्त में वर्तमान में कौन्कौनसे विषयों का अध्ययन कराया जाता है तथा वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कितने व कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कस्बा तख्तगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय वर्ष 2021 में स्वीकृत किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, इतिहास व समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में 246 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) राजकीय कन्या महाविद्यालय, तख्तगढ़ में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व भरे हुए पदों का विवरण क्रमश परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथा समय रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) जी हां। राजकीय कन्या महाविद्यालय, तख्तगढ़ के भवन निर्माण हेतु आदेश दिनांक 05.03.2022 द्वारा भूमि आबंटित की जाकर आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा राशि रुपये 4.50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। आदेशों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-4 व परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है, तख्तगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत हुआ, उसमें एक विषय कला संकाय खुला है, आज भी बच्चियां दूर-दराज के कालेजों में जा रही हैं, क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने का विचार रखती है?

मेरा दूसरा प्रश्न है, वहां कन्या महाविद्यालय में 10 शैक्षणिक और 11 अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं। कन्या महाविद्यालय खुले 20 महीने हो गये, लेकिन मंत्री जी ने उत्तर दिया है, "नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथा समय रिक्त पदों को भरा जायेगा।" कब ये चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे और कब ये पद भरे जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: आप नये विषय क्यों खुलवा रहे हैं?

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): वह भी करना पड़ेगा न, साहब।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां 10 शैक्षणिक और 11 अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं। जो नोडल महाविद्यालय बाली में चल रहे हैं, 6 पद वहां पर अभी भरे हुए हैं, जिसमें इंग्लिश में हमारे पास कुल 4 छात्राएं हैं। जो आपने दूसरे सब्जेक्ट्स मांगे हैं, गुण और अवगुण को देखते हुए, छात्रों की संख्या देखते हुए उन पर विचार करके खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं, वहां पर पूरा का पूरा स्टाफ है। जहां हमने कालेज खोल दिये, वहां अभी स्टाफ नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

विभाग को इस बारे में रिव्यू करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में यदि पोस्ट खाली हो तो वहां पर रिटायर्ड आदमी मिल जायेगा, लेकिन गांवों में जो नये कालेज खोले हैं, वहां कम से कम आपके स्थायी लेक्चरर्स का ट्रांसफर करके एजुकेशन को रेगुलर करें ताकि बच्चों की एजुकेशन ठीक हो सके।

कालेज वहां खुलने से मां-बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चों को यहीं पढ़ाएं। ऐसे में यदि वहां फैकल्टी नहीं मिलती है तो उसमें बच्चों का नुकसान होता है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग एक बार बैठकर, आपकी जितनी भी स्थायी मैनपावर अवेलेबल है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करें और जो नये कालेज खुले हैं, वहां कम से कम स्थायी अध्यापक हों और विद्या सम्बल जो भी लगाना है, वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लगाएं। इससे दोनों ही व्यवस्थाएं ठीक ढंग से हो सकेंगी। इस बारे में जरूर चिन्ता करें और व्यवस्था करें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी उप-खण्ड मुख्यालय पर मिनी सचिवालय की स्थापना

169. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उप-खण्ड मुख्यालय थानागाजी पर मिनी सचिवालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(2) क्या उक्त उप-खण्ड पर मिनी सचिवालय हेतु भूमि का चिह्नीकरण कर रिकार्ड में मिनी सचिवालय दर्ज हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सचिवालय के भवन निर्माण हेतु बजट में वित्तीय प्रावधान करने का विचार रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): (1) वर्तमान में मुख्यालय थानागाजी में मिनी सचिवालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

(2) उप-अधीक्षक पुलिस/उप-खण्ड मुख्यालय थानागाजी पर मिनी सचिवालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने के कारण भवन निर्माण हेतु बजट में वित्तीय प्रावधान नहीं है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने मिनी सचिवालय की तर्ज पर सभी विभागों के कार्यालयों के लिए जमीन तो अलाट कर दी, पर इनके कार्यालय कब तक खुलेंगे और कब तक रिकार्ड पर चढ़ेंगे?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है, थानागाजी में जितने भी कार्यालय चल रहे हैं, वे स्टेट टाइम की बिल्डिंग्स में हैं। कल को कोई हादसा हो जायेगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन जमीनों पर भवन बनवाएं ताकि कोई हादसा होने से बचे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तो वर्तमान में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। आगे जब भी कोई वित्तीय प्रावधान होगा तो विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

जयपुर में धरोहर संग्रहालय हेतु बजट का आबंटन

170. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जयपुर में विश्वस्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाने की बजट में घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा कब की गयी तथा उक्त के लिए कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त संग्रहालय के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है व न ही अब तक उक्त संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है? सरकार उक्त हेतु अब कब तक बजट का आबंटन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। पुरानी विधान सभा भवन, जयपुर में विश्वस्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाये जाने की घोषणा वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में की गयी थी। विश्वस्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा राशि रुपये 96.90 करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ ही प्रथम चरण के कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राशि रुपये 34.22 करोड़ की सहमति प्रदान की गयी है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राशि रुपये 34.22 करोड़ की सहमति के पेटे सर्वप्रथम राशि रुपये 14.23 करोड़ की पर्यटन विकास कोष से स्वीकृति जारी की गयी है। दिनांक 25.11.2022 से प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि 2019-20 की बजट घोषणा विश्वस्तरीय धरोहर संग्रहालय का कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ? कारण सहित बतायें क्योंकि चार साल हो गये हैं और अभी तक शुरू नहीं हुआ। बजट की भी अभी सहमति हुई है पर खर्चा एक भी नहीं हुआ है। आप यह दर्शा रहे हैं कि बजट की सहमति हुई।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो आप।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं यह पूछ रहा हूं कि काम शुरू क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, काम शुरू हो चुका है। प्रथम चरण का काम जून, 2023 से पहले-पहले पूरा हो जाएगा और द्वितीय चरण की भी डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। द्वितीय चरण का कार्य अप्रैल, 2023 से शुरू कर मई, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट अभी का नहीं है। वर्ष 2008-09 के बजट में अन्तरराष्ट्रीय संग्रहालय की घोषणा की गई थी, तब आपकी सरकार थी। आपने 30.01.2008 को मैसर्स लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, कनाडा को डीपीआर तैयार किये जाने हेतु नियुक्त किया। 06.06.2011 को 45 करोड़ रुपये, जिसमें राज्य की 70 प्रतिशत और केन्द्र की 30 प्रतिशत राशि की स्वीकृति जारी की गयी। आबंटित बजट 15 करोड़ रुपये, दिनांक 02.11.2011 को प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ, राशि 17.54 करोड़ के कार्यादेश आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण को आपने दिये, व्यय हुए 9 करोड़ 62 लाख 55 हजार और 1 करोड़ 17 लाख का भुगतान सलाहकार मैसर्स लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, कनाडा को किया गया। माह जनवरी, 2014 में उच्च स्तर से मौखिक निर्देशों की पालना में कार्य बन्द कर दिया गया, तो यह बहुत पुराना काम है। हम तो जून तक प्रथम चरण पूरा कर देंगे और द्वितीय चरण अप्रैल, 2023 से शुरू करके 2024 की मई तक पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधि आयोग का गठन

171. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कानून की समीक्षा हेतु राज्य विधि आयोग के गठन की नीतिगत घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा कर उक्त को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध या सरकार से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात कर रहे हैं, यह गलत बात है। समाराम जी, अपनी जगह पर बैठो। अपने-अपने स्थान पर बैठो।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अभिशंसा के अनुरूप एक समिति का गठन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य में विधि आयोग के गठन की उपादेयता नहीं है।

(2) जी हां। विभिन्न विभागों से संबंधित अधिनियमों का परीक्षण किया जाकर अधिनियमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, तत्सम्बन्धित विधेयक शीघ्र विधान सभा के समक्ष विचारार्थ लाया जायेगा।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्टेट लिटिगेशन पालिसी-2018 बनाई गई है, जिसमें मुकदमों को कम करने के लिए प्रावधान किये गये हैं, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मेगा लोक अदालत/लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण भी करवाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जानना चाहूंगा कि जन घोषणा पत्र आपका नीति पत्र है और उसकी घोषणा को दरकिनार करके कैबिनेट सब कमेटी की रिकमंडेशन पर जो समिति गठित करने की बात आपने कही, उस समिति के गठन करने का निर्णय कब लिया? समिति का गठन कब हुआ और समिति के गठन में कौन्-कौन सदस्य बनाये गये?

खण्ड-2 में आपने कहा कि प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के सम्बन्ध में उन्हें समाप्त करने के लिए तत्समय विधेयक लाने की भी बात आपने कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितने कानूनों का परीक्षण आपने कर लिया और उनके कितने रिप्लेसमेंट बिल लाने का फैसला कर लिया तथा इसी सत्र में आप क्या कोई रिप्लेसमेंट बिल लेकर आयेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने पूछा है कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने जो अभिशंसा की, देखिये, 05.09.2020 को मंत्रिमण्डलीय समिति की 7वीं बैठक में यह फैसला हुआ कि किसी सेवानिवृत्त वित्त सचिव को इसका अध्यक्ष बना दिया जाये और उनसे इनकी समीक्षा करवायी जाये। कानूनों की समीक्षा करना और पेचीदगियां किस प्रकार से दूर हो सकती हैं, उसके सुझाव देना, यह समिति का काम था, लेकिन उसके बाद में विचार बदल गया। फिर प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह अभिशंसा कर दी कि सेवानिवृत्त के बजाय विशिष्ट शासन सचिव, ड्राफ्टिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाये और वह इस सारे मामले को देखे। जो प्रशासनिक सुधार विभाग से कमेटी बनी, उसमें विशिष्ट शासन सचिव, विधि इसके अध्यक्ष होंगे; उप सचिव, विधि (संहिताकरण) विभाग, इसके सदस्य होंगे और सेवानिवृत्त उप सचिव स्तर का एक अधिकारी उसमें होगा। इस प्रकार तीन आदमियों की यह कमेटी बनी। जो आपने कहा कि यह फैसला कब हुआ तो 21.12.2020 को यह फैसला हुआ और फैसले के तहत इस समिति का गठन हो गया।

अब आपने पूछा कि समिति ने क्या किया, तो समिति ने अपनी बैठकें लगातार की हैं। लगातार बैठकें करके कुल 650 विद्यमान कानून हैं, उनमें से 296 कानूनों की पहचान कर ली गयी और पहचान कर यह फैसला किया गया कि इनको स्टेट्यूट बुक से हटाकर रिपील किये जा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक विभागों के द्वारा कुल मिलाकर 133 कानूनों को ही निरसित करने का अनुमोदन किया गया है तो 133 का बिल बाकायदा इसी विधान सभा सत्र में लाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने आपसे खण्ड-2 में ये जो अप्रासंगिक कानून हैं, उन्हें समाप्त करने का पूछा और आपने कहा कि हमने इसमें निर्णय लिया है। इसमें आपने कहा कि आपकी जो पालिसी है, उस पालिसी के अनुसार लिटिगेशन के लिए पालिसी बनी हुई है और उसमें आपने कितनों का परीक्षण कर लिया? राजस्थान में अप्रासंगिक कानून आज कितने विद्यमान हैं? खण्ड-2 में आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपने परीक्षण किया है। आप अपने खण्ड-2 का उत्तर पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष: बता दिया है कि 296 में 133 कानून।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह तो खण्ड-1 में आ गया। मेरा दूसरा अप्रासंगिक कानूनों के बारे में है कि उक्त को समाप्त करने का विचार रखती है तो आपने कहा कि, जी हां, तो कितनों का विचार रखते हो आप? अप्रासंगिक कानून कितने हैं।

श्री अध्यक्ष: 133 बता दिया न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं पहले बता चुका हूं और फिर आपको बता देता हूं। आप विराज जाओ। समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श और सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों से बैठकें करने के पश्चात् यह सिफारिश की कि राज्य में वर्तमान में जो 650 कानून, अधिनियम विद्यमान हैं उनमें से 296 कानूनों की पहचान कर ली गयी है जिनको रिपील किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने पूछा कि कितने कानूनों को ला रहे हो, तो 133 कानूनों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिनको रिपील करने के लिए यहां पर बिल लाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी, आज तैयारी अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न। आज तैयारी अच्छी नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

तालछापर वन्य अभयारण्य से हिरणों का स्थानान्तरण

172. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तालछापर वन्य अभयारण्य से हिरणों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के लिए कोई भूमि चिह्नित की गई है? यदि हां, तो कहां व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मनोज कुमार)

(3) क्या उक्त भूमि के आबंटन में आवासीय, औद्योगिक एवं खनन स्थलों से होने वाली परेशानियों व गतिविधियों से प्रभावित होने की स्थिति को ध्यान में रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मुरारी लाल (कृषि विपणन, राज्य मंत्री) (वन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। तालछापर अभयारण्य, चूरू से कृष्णमृगों की बढ़ती संख्या के कारण इनको स्थानान्तरण हेतु लीलकी बीड़, जिला चूरू, बीड़ झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं, जसवन्तगढ़, जिला नागौर का चिह्नीकरण किया गया है।

(2) स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) इन चिह्नित स्थानों में किसी भी स्थान में ईको सेंसेटिव जोन नही बनाया जायेगा। अत: इन स्थानों के आस-पास आवासीय, औद्योगिक एवं खनन जैसी गतिविधियों पर पृथक् से कोई प्रतिबंध नही रहेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि ईको सेंसेटिव जोन नहीं बनाया जायेगा तो स्वत: ही 10 किलोमीटर का जो परिधि एरिया है, वह इससे इफेक्ट होगा। उसमें कोई खनन कार्य व कोई सड़क नहीं बन पायेगी और जीता-जागता उदाहरण है कि सुजानगढ़ से छापर के बीच में जो सड़क है, वह स्टेट टाइम की बनी हुई, महाराजा गंगासिंहजी के टाइम की बनी हुई है, जब बीकानेर जयपुर का रास्ता होता था। उसको विभाग ने दो साल पहले मिट्टी डालकर बन्द कर दिया। वहां खाई खोद दी जिससे कोई आ-जा नहीं सकता है। सरकार ने पिछले बजट में एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। एक नई सड़क जो गांव से निकलती है, उसको डवलप करने के लिए, उसका भी जब टेंडर लगा तो वन विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पर स्टे करवा दिया। उसको भी नहीं बनने दे रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है?

दूसरा, इन्होंने जो क्षेत्र चुना है, वहां हालत यह है कि दो तहसीलों का सुजानगढ़ और लाडनूं का पानी भरा रहता है। उस पानी की क्या व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): प्रश्न यह है कि इन्होंने कहा कि हिरणों की संख्या बढ़ गई है तो पिछले दशक में कितनी बढ़ी है? वह संख्या बतायें? दूसरा, अगर आपने वहां हिरण शिफ्ट कर दिये तो उनके वहां खाने की क्या व्यवस्था होगी? वे जीयेंगे कैसे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इर्रेलेवेंट जा रहे हैं। मेरे समझ में आ गया। माननीय मंत्री जी, आप रेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दे दें। इनका कहने का मतलब है कि आलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, जो पुरानी रोड थी, वह भी फोरेस्ट विभाग ने बन्द कर दी है। अब जो नया क्षेत्र बना रहे हैं, उस क्षेत्र में ईको जोन का सरकार का कान्सेप्ट है। उसमें 10 किलोमीटर में कोई खनन कार्य नहीं हो सकेगा तो इनका कंसर्न यह कि आप इसको कैसे रोकेंगे?

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): एक और है, इन्होंने जो जसवन्तगढ़ का एरिया चुना है, वहां पानी भरता है, पानी सूख जाता है तो वहां एक तिनका भी घास नहीं है। वहां हिरण क्या खायेगा? और तीसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। प्लीज बैठें। आप पहले सुन लें, फिर आप बोल लेना।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, वह सड़क वन क्षेत्र से गुजर रही थी और हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश से उसको बन्द किया गया था।

दूसरा, जो आप बता रहे हैं, जहां ईको सेंसेटिव जोन होते हैं, वहीं पर अन्य गतिविधियों पर रोक लगती है। यहां पर किसी प्रकार का कोई ईको सेंसेटिव जोन नहीं है, इसलिए अन्य गतिविधियों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके कहने का मतलब यह है कि जो नया प्रपोज कर रहे हो। वहां ये कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, वहां पानी भरने के कारण खनन में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। इसलिए हमने उसको प्रपोज किया है।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जो जगह अलग चिन्हित की गई है, बाकायदा सर्वे करके, वह पहले से फोरेस्ट एरिया में थी और जो शिफ्ट कर रहे हैं, वह भी हाई कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं। वहां पर ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं है। उसके लिए बाकायदा सर्वे करके देख लिया गया है कि वहां पर हिरणों को कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें। आप मंत्री जी से मिल लें। अपनी बात मंत्री जी से मिलकर बता दें।

अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा के बांधों की मरम्मत

173. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के बांधों, एनिकटों की मरम्मत व नहरों का पक्का निर्माण कराने की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो किन-किन बांधों, नहरों व एनिकटों की? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत किरावल सागर एवं मलिकपुर बांधों एवं इनकी नहरों की मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। 5 बांध एवं नहरों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। वर्तमान में एनिकट मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि सन् 2018 में बजट घोषणा के अन्दर मेरे नमोक्या एनिकट और डूंगरिया एनिकट की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकल गई थी और उनका वर्क आर्डर जारी होना था बाकी, सरकार बदलने के बाद उनके वर्क आर्डर नहीं देकर आज 5 साल हो गये, अभी तक उनका कोई दुबारा टेंडर नहीं लगाया, दुबारा सैंक्शन नहीं निकली है तो उनकी सैंक्शन निकालने का आपका विचार है या नहीं है?

दूसरा, सन् 2002 के अन्दर जितने भी तालाब, जिनकी क्षमता 300 हैक्टेयर से कम थी, उनको ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर कर दिया गया है। आज 20 साल हो गये हैं। उनकी स्थिति यह है कि वे बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न पंचायती राज का है। यह इर्रिगेशन का प्रश्न नहीं है। यह पंचायत का प्रश्न है, क्यों पूछ रहे हैं? माननीय मंत्री जी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिन एनिकट के बारे में जानकारी दी गई है, मैं विभाग से इसकी पूरी जानकारी लूंगा और जानकारी लेकर यदि बजट में इसको स्वीकृत किया गया था तो आगे क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह, 174 स्थगित प्रश्न है।

करवाड़ा (रानीवाड़ा) की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के फसल बीमा से वंचित किसान

174. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., करवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर की लापरवाही से सदस्य ऋणी किसानों का रबी 2022-23 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का बीमा कम्पनी को निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो कितने ऋणी किसानों का बीमा प्रीमियम का बीमा कंपनी को भुगतान नहीं किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋणी किसानों को फसल बीमा से वंचित रखने के लिए कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें।

विधायकों के पत्रों पर की गई कार्यवाही की सूचना

175. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधायकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित को विभाग द्वारा भिजवायी जाती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी विभागों को उक्त के द्वारा विकास कार्य के लिए लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) माननीय विधायकगण से प्राप्त पत्रों की पावती भिजवाने एवं उन पर की गई कार्यवाही से संबंधित माननीय विधायक को अवगत कराने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 12.05.2022 को परिपत्र जारी किया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(परिपत्र पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 के जवाब में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 12.05.2022 को परिपत्र जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो 12.05.2022 को आदेश जारी किया है, इसके कालम नम्बर 3 में जो दिया गया है, उसकी पालना हो रही है क्या? विधायकों के पत्र विकास कार्यों के लिए दिये जाते हैं, उनका जवाब ही नहीं दिया जाता है। सरकार उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही कर रही है? शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन के कार्यक्रमों में विधायकों का नाम अनिवार्य है, परन्तु कई विभागों में इसकी पालना नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेरे पास इसकी सूची है। मंत्रीजी से निवेदन है कि इस पर क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? मेरा यही निवेदन है।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15.03.2022 को आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी हुई। उसके बाद दिनांक 12.05.2022 को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया। जो माननीय सदस्य को हमने उत्तर में उपलब्ध करवा दिया है। इस सम्बन्ध में 2021 में 20 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 17 माननीय सदस्यों की शिकायतों का निस्तारण हो गया है। 2022 में 13 का निस्तारण हो गया है और 8 बाकी हैं, जो शेष हैं, वे प्रक्रियाधीन हैं। जो शिकायतें आई हैं, हमने 17 व 8 का निस्तारण कर दिया है। माननीय सदस्य की कोई शिकायत नहीं है।

इसमें हमने नियम भी बनाया है। हर जिले में नोडल अधिकारी है। शिलालेख के जो भी नियम जारी किये हैं, एम.एल.ए. लैड का होगा तो उसमें एम.एल.ए. का नाम अंकित होगा। जहां एम.पी. लैड होगा, वहां एम.पी. का नाम होगा। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं, उनमें एम.पी. और सम्बन्धित विधायक एवं सम्बन्धित वहां के मंत्री को सूचना देकर काम करेंगे। नोडल अधिकारी सम्बन्धित विभाग का होगा।

इसके अन्दर कोई भी अधिकारी बदमाशी या लापरवाही करता है तो लास्ट में यह नियम है कि इनको माननीय सदस्य को 30 दिन में जवाब देना है और केन्द्रीय मंत्री या सांसद को 15 दिन में जवाब देना है। हमने लास्ट में जो नियम बनाया है, अगर मान लें उसमें कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो यह निर्देश दिये गये हैं कि जो निर्देशों की अवहेलना करेगा, राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण एवं नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा तथा दोषी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक

(श्री गोविंद राम)

कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। माननीय सदस्य यदि शिकायत करेंगे और इनकी कहीं भी अवहेलना हुई है, उसके खिलाफ यदि ये शिकायत करेंगे तो जांच करायेंगे। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ नियम 1971 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सन्तुष्ट हैं? माननीय मंत्री जी, मैं बताता हूं। आप प्रश्न समझ लें। क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 का निस्तारण हो गया है। 22 में से 8 का निस्तारण हो गया है। इस सम्बन्ध में, मैं जानकारी करूंगा और आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपने अच्छा कहा, लेकिन मेरे पास बराबर शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों के लिए एक बार आप दुबारा प्रशासनिक अधिकारियों को जो आपने सर्कुलर बनाया है, उसकी पालना करने के लिए निर्देश दें।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): आपका आदेश मानते हुए सख्त कार्यवाही करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 176

श्री राम निवास गावड़िया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल। माननीय सदस्य, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। आप प्रश्न पूछ लें।

श्रीडूंगरगढ़ में खेल स्टेडियम की स्थापना

177. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने खेल मैदान प्रस्तावित किये गये व कितने तैयार व कितने अपूर्ण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल)

(2) क्या सरकार खेल मैदान से वंचित पंचायत मुख्यालयों पर उक्त को शीघ्र तैयार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी नहीं। सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least one Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत पूर्ण एवं अपूर्ण खेल मैदानों की संख्या निम्नानुसार हैः-

स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
29	15	14

(2) ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least one Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

(3) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/ जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जाती है, जिसे वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रावधानानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। यह नाम ही दिया गया है। मेरे डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत खेल मैदान 29 बताये गये हैं, पूर्ण 15 बताये गये हैं और अपूर्ण 14 बताये गये हैं। मुझे ये बता दें कि ये 29 स्वीकृत किन-किन पंचायतों से हैं? इतना ही मेरा पूछना है। पिछला छोड़ देता हूं, समय पूरा हो रहा है। अभी इस बजट में एक करोड़ मैचिंग ग्रांट राशि की गई है तो उसमें सरकार एक करोड़ मैचिंग राशि स्टेडियम पर, क्या जनप्रतिनिधि या सीएसआर फण्ड देने पर ही खर्च करेगी या नहीं करेगी? यही बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मैंने प्रश्न का मौका दिया है और आप समय निकाल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

(समय: 12.00 बजे)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): ...तो उसमें क्या सरकार एक करोड़ मैचिंग राशि क्या जनप्रतिनिधि या सीएसआर फंड देने पर ही खर्च करेगी स्टेडियम पर या नहीं करेगी? यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विधान सभा क्षेत्र में या तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर दो तरीके से खेल स्टेडियम ज्यादातर सैंक्शन होते हैं। पहला, बजट घोषणा के माध्यम से दूसरा, विभाग के पास में एक बहुत शानदार योजना है मेजर ध्यानचन्द योजना और ऐसी योजना की डिमाण्ड पर दो वर्ष पूर्व विधान सभा में कट मोशन पर चर्चा हुई थी तो विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा थी कि सभी ब्लाक पर यदि स्टेडियम सम्भव नहीं है तो ऐसी कोई योजना बनायें जिसमें कुछ हम दें, कुछ सरकार दे, उसी के तहत विधायक कोष, मैम्बर पार्लियामेंट कोष, कोई सीएसआर, कोई लोकल बॉडी पंचायती राज की, कोई नगरपालिका, आप वहां सबसे मिला कर जितना कोष ले आयेंगे उसके बराबर तक एक करोड़ तक हाइयेस्ट यह कैटेगरी कर दी गई है, पहले पच्चीस लाख था। एक करोड़ तक खेल विभाग की तरफ से उसमें मिला कर...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कुर्सी इधर है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जी, साहब। तो एक करोड़ तक जो भी ये राशि उपलब्ध करायेंगे उसकी सैंक्शन इनको मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में सांवतसर से लिखमीसर इयारा कैम्प के मध्य सड़क का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सहकारी समितियों के चुनावों में प्रशासन की मिलीभगत से की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की उप तहसील हरनावदाशाहजी को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना-सिणधरी पेयजल योजना से पचपदरा क्षेत्र में जल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ओजियाणा, इरास व उंखलिया के राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका रावतसर में बरसाती जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त रिहायशी व व्यावसायिक भवनों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर नगर निगम द्वारा पट्टों के वितरण में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में गम्भीर पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले में सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने एवं आरओबी निर्माण में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांवों में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड के अन्तर्गत गांवों में विगत गर्मी के पेयजल परिवहन का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री अर्जुन लाल जीनगर, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समतुल्य परिलाभ देने के सम्बन्ध में।

(14) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(15) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में यूआईटी द्वारा बिना बजट पास कराये मनमाने ढंग से व्यय करने के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा संधारण की निर्धारित प्रक्रिया में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से परिवहन अधिकारियों द्वारा बेणेश्वर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में ऑनलाइन भूमि-नामान्तरण प्रक्रिया (म्यूटेशन) बाधित होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(19) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण पर लगी रोक को खुलवाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के निवासियों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल, श्री अविनाश, श्री नारायण बेनीवाल, श्री अर्जुन लाल जीनगर, श्री विट्ठल शंकर अवस्थी एवं श्री मदन दिलावर को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित गैर सरकारी बी.एड. कालेजों (सीटीई संस्थाओं) में कार्यरत कार्मिकों का शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ट्रोमा सेन्टर में नवीन पद सृजित कर पदस्थापित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जे. पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी की उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से नगर परिषद् पाली के कथित ठेकेदार द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग में कार्यरत ठेका श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर के राजकीय स्वामित्व के समस्त हेरिटेज भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा हेतु प्रदेश में अलग से सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में औद्योगिक इकाइयों का संचालन कर क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से किशनगढ़ अरांई मालपुरा हाईवे सड़क का किशनगढ़-अरांई से अजमेर सीमा तक ही पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत देवला को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती कृष्णा पूनियॉं, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में फसल बीमा कम्पनियों द्वारा अतिवृष्टि से हुए नुकसान का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत लूणकरणसर की भूमि को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु किये गये आबंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों की मांगों पर विचार कर उन्हें अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, 295 आज सब पढ़े हुए माने जायेंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि 3.00 बजे नेता, प्रतिपक्ष की तरफ से अपना भाषण होगा और 4.00 बजे मुख्य मंत्री जी भाषण देंगे। 5.00 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होगी। सभी माननीय सदस्य बाहर जो हमारा गेट है वहां पर फोटो के लिए आमंत्रित हैं, उसके बाद सभी माननीय सदस्य 7.15 बजे दुबारा इस सदन में एकत्रित होंगे जहां हमारे नव मनोनीत राज्यपाल माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया के सम्मान में हम अपना फंक्शन करेंगे और उसके बाद डिनर होगा। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज जो समय की कांस्ट्रेंट है उसमें अपनी बात को कहें।

श्रीमती अनिता भदेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अजमेर नगर निगम द्वारा पट्टों के वितरण में अनियमितताएं

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मुझे अजमेर नगर निगम में पट्टों को लेकर के जो घपला हुआ है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का समय दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश में दस लाख पट्टे बांटने की घोषणा की थी लेकिन अजमेर नगर निगम ने उसके अनुपात में पच्चीस प्रतिशत पट्टे भी नहीं बांटे और अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जायेगा कि अजमेर नगर निगम से खाली पट्टे चोरी करके फर्जी पट्टे, नगर निगम से खाली पट्टे चोरी किये गये, नगर निगम की सील चोरी की गयी और सील चोरी करके, खाली पट्टे चोरी करके फर्जी पट्टे बनाये गये और ताज्जुब की बात है कि वो फर्जी पट्टे पंजीयन और रजिस्ट्रेशन विभाग से पंजीकृत भी हो गये और ऐसे तीन पट्टे नगर निगम के ध्यान में आये। पता नहीं और ऐसे कितने पट्टे होंगे जो फर्जी तरीके से बनाये होंगे और जिनकी रजिस्ट्रेशन विभाग में रजिस्ट्री भी करवा दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि नगर निगम के प्रशासनिक विभाग में पहला जो है अनु कुमावत के नाम से सावन स्कूल के पास कोटड़ा में 70.55 वर्ग गज जमीन का पट्टा जारी किया। दूसरा, गिरधारी के नाम से माहेश्वरी स्कूल के पास कोटड़ा में माहेश्वरी स्कूल के पास की जमीन बहुत कीमती जमीन है और उस पर 160 वर्ग गज का पट्टा जारी हुआ है। ऐसा ही तीसरा सुमन गहलोत के नाम से बैरवा बस्ती कोटड़ा में 227.10 वर्ग गज क्षेत्रफल का पट्टा जारी हुआ है। ये तीनों पट्टे नगर निगम से खाली पट्टे चुरा करके जारी किये गये। इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा के चौसाला के खसरा नम्बर 502 की वर्किंग जमाबन्दी के नया खसरा 554 और 586 के खसरा जो भी हैं जो नगर निगम को अप्रैल, 2022 को ट्रांसफर हुए एडीए के माध्यम से। यह पूरी की पूरी जमीन पूरी तरह से रिक्त है, खाली है लेकिन इस खाली जमीन पर 69 ए धारा के तहत पट्टे जारी कर दिये फर्जी तरीके से उस पर कब्जा बता करके जबकि उस पर कोई काबिज नहीं है। करोड़ों रुपये की यह जमीन है। 2200 वर्ग गज की जमीन पर पांच से सात पट्टे जारी किये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय

(श्रीमती अनिता भदेल)

का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो फर्जीवाड़ा नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया है, कम से कम ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को सज़ा मिले और जिन्होंने ये पट्टे चोरी करने का काम किया, खाली पट्टे चोरी करने का काम किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि आइन्दा किसी अधिकारी/कर्मचारी की हिम्मत नहीं हो इस तरह से खाली पट्टे चुरा करके और जारी करने की। इतना निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

जैतारण में गम्भीर पेयजल समस्या

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या के बारे में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में जो घोषणा की, उसके पैरा नम्बर 106 से 112 में पेयजल के बारे में हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं के बारे में घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के घोड़ावड, दयालपुरा, पातूस, झुझुंडा सिणला, कोट-किराणा, कालाकोट, ऐसे गांव हैं जहां पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। घोड़ावड ऐसा गांव है जहां 3-4 हजार की आबादी है और पिछले 25 वर्षों से वहां किसी प्रकार की पाइपलाइन से पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहां मजबूरी में ग्रामवासी एक महीने में 3-4 टैंकर पानी के डलवाते हैं। एक टैंकर का पैसा कम से कम 700-800 रुपये आता है, तो एक महीने में आप कल्पना करें कि तीन से साढ़े तीन हजार रुपये अगर टैंकर पर खर्च करेंगे तो कैसे होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके समाधान के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि पड़ोस में बलाड़ा गांव है, वहां पानी की सुविधा है, उसके पड़ोस में बांझाकुड़ी है, वहां सुविधा है। अगर उनको वहां पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ दिया जाये तो घोड़ावड़ जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, वहां पानी की व्यवस्था हो जायेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस गंभीर विषय पर तुरंत एक्शन लेकर घोड़ावड़ ग्राम पंचायत और दयालपुरा जैसे गांवों में पानी की सुचारु व्यवस्था करावें ताकि गर्मी के मौसम में जो परेशानी होगी, उससे निजात मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग व आरओबी निर्माण में विलम्ब

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नागौर जिले में सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने व नागौर शहर में आरओबी निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा नहीं होने से जिलेवासियों को हो रही दुविधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आकर्षित करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ी खबर है कि ठेकेदार को 15 महीने में करना था काम पूरा, 68 महीने बाद भी 35 प्रतिशत अधूरा। आरओबी की सुविधा के नाम पर शहर साढ़े पांच साल से झेल रहा दर्द। माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी भी यहां बैठे हैं। मैं मांग करूंगा कि सीआरआईएफ का बड़ा पैसा हमारी विधान सभा को जो पिछली बार मिला, उसमें मूंडवा से मेड़ता रोड, चातरा मांजरा से पांचला सिद्धा 34 किलोमीटर और मुदियाड़ से जोरावपुरा 19 किलोमीटर लम्बाई की जो सड़क बनी है, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को आप ब्लैक लिस्ट करें और शहर में जो सड़कें बनीं, माननीय मुख्य मंत्री जी जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और 'दिशा' जैसी महत्वपूर्ण कमेटी ने भी यह सिफारिश भेजी है कि चीफ इंजीनियर लेवल के व्यक्ति से इसकी जांच करा कर इसमें दोषी ठेकेदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि इस संवेदनशील मामले को दिखा कर जनता को न्याय दिलावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में बिगड़ती कानून-व्यवस्था

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र तथा निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के भोपालसागर पंचायत समिति के ग्राम निलोद में नारायण लाल जाट को 6 फरवरी, 2023 को मार कर जंगल में डाल दिया और मृतक के हाथ पीछे बांध कर उसको पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और न हत्यारों का पता लगा है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

दूसरी घटना, एक राजनीतिक घटना की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी में लगातार एक साल से राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना, 22 जनवरी, 2022 को सरपंच करणपुराकलां, मृतक केरीग मीणा, मृतक की बोडी विद्यालय में मिली और मोटरसाइकिल एक किलोमीटर दूर। सरपंच को घसीट कर मारा। नंबर 2, 19 मार्च, 2022 को भूरालाल मीणा ढाबड़ा, दोष, सरपंच का चुनाव लड़ना, उसको कार से घसीट कर मारना। हत्या नंबर 3, 6 अप्रैल, 2022 को विकास प्रजापत, निवासी केसून्दा, दोष, बीजेपी का झंडा उसके घर पर लगाना और सहकारिता मंत्री जी का भतीजा अरविंद आंजना ने उसको थप्पड़ों से, लट्ठ से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। अभी अरविंद आंजना जेल में बंद है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आरोप लगाएं तो प्रूफ दें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। अरविंद आंजना अभी जेल में बंद है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव में आप काम की बात बोलें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): चौथी घटना, 2 फरवरी, 2023 को विकास उर्फ बंटी आंजना केसुंदा को निम्बाहेडा की जेल के सामने गोलियों से भून कर मारा। मैं एसपी, चित्तौड़, राजेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इस मामले का खुलासा किया, अख़बार में भी आया, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। अजय पाल और उसके साथियों ने मिलकर हत्या की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक तरफ तो पुलिस को धन्यवाद दे रहे हो, दूसरी तरफ लॉ एण्ड आर्डर बिगाड़ रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? प्लीज, वाइंडअप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप वाइंडअप करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट में। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि अरविंद आंजना...

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow. आपने स्थगन प्रस्ताव ... (व्यवधान) दोनों बात नहीं कर सकते। न, न, प्लीज, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो पुलिस अच्छा काम कर रही है। क्या बातें कर रहे हो?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ...(व्यवधान) मंत्री के भतीजे ने 15 लाख की सुपारी दे दी ...

श्री अध्यक्ष: No. Please, I will not allow it. Not allowed! रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज, माननीय सदस्य, गलत बात, गलत परम्परा नहीं। बैठें प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा। श्री मदन दिलावर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, हो गया, आप बैठें। प्लीज बैठें, अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। सुन नहीं रहे हैं आप? बैठें आप। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: आप सुन नहीं रहे हैं क्या? I will name him. Mr. Rathore, I have given the latitude. I will not allow it. I said, आपको बोलना कानून व्यवस्था पर है और आप किस पर आ गये? आप कानून व्यवस्था की बात करें, आप पर्सनल आ जाते हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव अलाउ ही नहीं करूंगा।

माननीय मदन दिलावर।

रामगंज मंडी के निवासियों को मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मंडी तहसील की कुंभकोट और लक्ष्मीपुरा पंचायत के लगभग आठ हजार निवासी वहां निवास करते हैं। वहां की एक माइनिंग कंपनी एएसआई है, जो वहां पिछले 40-50 सालों से रह रहे हैं, उनको वह बिजली का कनेक्शन नहीं लेने देती है, पानी का हैंडपम्प नहीं खोदने देती है, पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाने देती है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाने देती है, आंगनबाड़ी नहीं बनाने देती है, शौचालय नहीं बनाने देती है। कंपनी वालों ने एक शौचालय नदी के ऊपर बनाया है, उसमें अभी तक दर्जनों लोग गिर कर मर गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। इस बात को लेकर लगभग 10 लोगों ने सुकेत थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। सुकेत थाने ने उसमें एफ.आर. लगा दी। मैं समझता हूं कि एफआर. लगाना बहुत ही निंदनीय है। वहां अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती हो रही है, परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इनके बयान भी नहीं लिए गये, एक दो के बयान लिए तो वह दर्ज नहीं किये गये।

(श्री मदन दिलावर)

यह एट्रोसिटी का मामला बनता है लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। सुधीर बाबू, पवन सोनी, दीपक बाबू, वासू बाबू, एसी गुप्ता और गोविंद गुप्ता के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। अनुसूचित जाति के लोगों पर इतना अत्याचार और अन्याय होने के बाद एफआर लगा देना कहीं न कहीं हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लिखते क्या हैं, बोलते क्या हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्योंकि यह कंपनी के लोग बहुत पैसे वाले हैं। यह मेरे पास भी आये थे कि आप हमारी शिकायत करते हो, आपको क्या चाहिये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो लिखा हुआ है, उसी पर तो आप बोलेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमको वहां पर पानी मिले, बिजली मिले, आम आदमी को जो सुविधाएं होती हैं, वह सब मिले। यह कहते हैं स्टे है। आप अनुमति दें तो मैं टेबल कर सकता हूं कि उस पर किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं है, न वहां माइनिंग के लिए कोई लीज आबंटित है, फिर भी इस प्रकार से किया जा रहा है। आप अनुमति दें तो मैं यह टेबल कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: जरूर रखें, कोई मना नहीं। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा यूआईटी में वित्तीय मनमानी

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भीलवाड़ा शहर में यूआईटी है, उस यूआईटी का बजट पिछले दो सालों से पारित नहीं करवाया गया है। यूआईटी के हालात यह हैं कि वहां मनमर्जी का व्यवहार होता है। यूआईटी शहर से सारी कमाई करती है और पेरीफेरी के नाम पर दूसरी जगह पैसा लगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में शहर उपेक्षित हो रहा है। यूआईटी में मनमानी तरीके से मुआवजे बांटे जाते हैं, कोई कानून यूआईटी पर लागू नहीं हो रहा है। नगर परिषद् द्वारा यूआईटी में कितना पैसा बकाया है, हम मांगते हैं लेकिन बार-बार मांगने के बाद भी यूआईटी पैसा नहीं देती और सारा बजट पेरीफेरी के नाम भीलवाड़ा शहर से बाहर लगाया जाता है। इसके कारण से पूरे शहर की व्यवस्था खराब हो रही है।

मेरा आपसे निवेदन है कि यूआईटी व्यवस्थात्मक रूप से बजट पारित करे। दो साल से बजट पारित नहीं हुआ है। रोज अखबारों में आता है कि

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा बिना बजट पारित किये ही कार्य करवाये जा रहे हैं और मनमाने तरीके से करवाये जा रहे हैं। इसलिए इस पर रोक लगाकर शहर में व्यवस्थित रूप से विकास में पैसा खर्च कराया जाये। यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखने वाले पत्र आदि। नियम समिति, श्री संयम लोढ़ा।

समिति प्रतिवेदन

नियम समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 1)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, 2022-23 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री रमेश चन्द मीना।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.4(4)संशो/नियम/विधि/पंरा/2022/101 दिनांक 08.02.2022 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: प.4(4)संशो/नियम/विधि/पंरा/2022/267 दिनांक 15.03.2022 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है; एवं

3. अधिसूचना संख्या: प.4(4)संशो/नियम/विधि/पंरा/2022/777 दिनांक 16.06.2022 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष (2022-23) (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगें (वर्ष 2022-23) (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

मुख बन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष (2022-23) का पारण

मांग संख्या 02 - मंत्री परिषद्

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 - मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,27,95,000/- (पांच करोड़ सत्ताईस लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 03 - सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,06,96,58,000/- (छब्बीस अरब छह करोड़ छियानवे लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 04 - जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की संख्या 4 - जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,22,92,000/- (पन्द्रह करोड़ बाईस लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(**स्वीकृत**)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार करनी है तो हां तो बोलना पड़ेगा।

मांग संख्या 05 - प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,40,59,09,000/- (दो अरब चालीस करोड़ उनसठ लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 06 - न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,91,04,20,000/- (एक अरब इक्यानवे करोड़ चार लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 07 - निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 - निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,92,49,000/- (पन्द्रह करोड़ बानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 09 - वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 - वन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,78,29,000/- (उन्नीस करोड़ अठहत्तर लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,55,13,33,000/- (तीन अरब पचपन करोड़ तेरह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,57,99,000/- (सोलह करोड़ सत्तावन लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 - अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 - अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,90,79,38,000/- (एक अरब नब्बे करोड़ उनासी लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 - पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 - पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,12,03,64,000/- (तेरह अरब बारह करोड़ तीन लाख चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 16 - पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 - पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,14,66,82,000/- (चार अरब चौदह करोड़ छियासठ लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 - कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 - कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,18,95,000/- (पैंतीस करोड़ अठारह लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,36,10,000/- (तिहत्तर करोड़ छत्तीस लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,12,84,000/- (उनसठ करोड़ बारह लाख चौरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 20 - आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 - आवास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,03,000/- (दो करोड़ पचपन लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,23,73,59,000/- (पांच अरब तेईस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000/- (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,94,44,16,000/- (तेईस अरब चौरानवे करोड़ चवालीस लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 25 - कोषागार एवं लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 - कोषागार एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,00,04,37,000/- (छह अरब चार लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86,40,86,000/- (छियासी करोड़ चालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,82,83,19,000/- (एक अरब बयासी करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,45,53,90,000/- (बाईस अरब पैंतालीस करोड़ तिरेपन लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,000/- (उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,95,64,54,000/- (दो अरब पचानवे करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,70,18,54,000/- (बारह अरब सत्तर करोड अठारह लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,38,38,000/- (तीन अरब अड़तीस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,84,57,000/- (तीन करोड़ चौरासी लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,82,41,000/- (बारह करोड़ बयासी लाख इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,93,31,000/- (एक अरब नौ करोड़ तिरानवे लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,25,02,000/- (चौंतीस करोड़ पच्चीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42 - उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 - उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,87,87,82,000/- (एक अरब सतासी करोड़ सतासी लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 - खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 - खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 46 - सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 - सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये वाले जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 95,40,55,000/- (पचानवे करोड़ चालीस लाख पचपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48 - विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 - विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,84,07,000/- (तीन अरब दो करोड़ चौरासी लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा व समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,000/- (तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,000/- (छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल पुर:स्थापित करेंगे।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा पदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल के माध्यम से कंसोलिडेट फंड से 48 हजार 332 करोड़ 27 लाख 3 हजार रुपये की और अतिरिक्त राशि लेने की आज्ञा के लिए ये प्रस्ताव आया है।

मैं सदन का ध्यान 2022-23 के जिस बजट के आधार पर ये एप्रोप्रिएशन बिल आया है, उसमें जो राजस्व घाटा था, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह है बजट भाषण 2022-23, पेज 119, आपका राजस्व घाटा है 23 हजार 448 करोड़ रुपया। अगर ये राशि जिस राशि की अतिरिक्त रूप से मंत्री महोदय, आज आप सदन से आज्ञा ले रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी, आप जानते हैं, it is a past practice that we never discuss in the House. We just pass it. जब आप बजट के बाद आएंगे, उसमें चर्चा करें। इसमें कुछ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, आज्ञा आपकी चलेगी।

श्री अध्यक्ष: आप और मैं दोनों बराबर के साथी हैं। Let us not break the tradition. पुरानी ट्रेडिशंस को मानना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप विराजिए। मैं पांच ही मिनट में बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: वह रिकार्ड में, why should you want a wrong precedent?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आप ही की बात कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर श्रीमान इसी सीट पर विराजे थे। इसी तरह विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ था। श्रीमान ने इसी तरह एतराज किया था, जिस तरह मैंने किया है और उसके बाद उस पर डिस्कस हुआ था। अगर सदन आज्ञा नहीं देगा, आसन आज्ञा नहीं देगा, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, परंतु, अध्यक्ष महोदय, 48 हजार 332 करोड़ पैसा और ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई परम्परा जो है उसको तोड़ कर, कोट करके और परम्परा तोड़ना जारी रखना है अपने को। मैं समझता हूं कि जो चीजें हैं, उसको समझना चाहिए। जो आप कोट कर रहे हैं, उसकी मुझे जानकारी है। मैं इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि यह सदन की परम्परा रही है कि हम एप्रोप्रिएशन की स्टेज पर नहीं करते। जब मुख बन्द

(श्री अध्यक्ष)

होता है, बिना बहस के पास किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस पर चर्चा नहीं करें और बिल को पास करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, चर्चा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक निवेदन करूं आधा मिनट के लिए?

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow you to have a wrong precedent. माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तीन शब्दों के अलावा चौथा शब्द बोलूं तो बैठा देना। अध्यक्ष महोदय, आगे से जब भी ये कार्यवाही निकले तो इसके नीचे भी मुख बन्द का प्रयोग लिख देते तो शायद इतने कागज-पानड़े लाने की जरूरत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, वी वांट डिविजन, वी वांट डिविजन। (व्यवधान) राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जो पक्ष में हो वह हां कहें, जो विपक्ष में हो वह ना कहें।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद।

माननीय सदस्य, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि 3 बजे माननीय विपक्ष के सदस्य बोलेंगे, हमें उनको समय देना है। 3 बजे के पहले पक्ष व विपक्ष के साथी समयानुसार अपनी बात कहें।

श्री रोहित बौहरा।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहां से रखना शुरू करता हूं कि जब तक केन्द्र सरकार के बजट पर बात नहीं होगी, तब तक राज्य के बजट पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सम्बोधन करना उचित नहीं समझता हूं। अभी हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पास किया, उसमें अमृत काल का जिक्र किया। अमृत काल चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास होने की बात की। आप सबको पता है कि यह मित्र काल चल रहा है। मित्र काल में सिर्फ एक आदमी का विकास हुआ। 2008 में जिसकी नेटवर्थ 48 हजार करोड़ थी, उसकी नेटवर्थ लास्ट ईयर 15 लाख 20 हजार करोड़, सिर्फ एक फैमिली

(श्री रोहित बौहरा)

की, एक अधिकारी, एक परिवार की सिर्फ यह नेटवर्थ हुई तो यह मित्र काल है, यह अमृत काल नहीं है। अगर मित्र काल चल रहा होता है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह बजट पर डिस्कशन नहीं है... (व्यवधान) कौनसा मित्र काल आ गया बजट में? (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप अपनी बात कर रहे थे... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनसे भी पूछ लो... (व्यवधान) जरा अपने चेहरे पर देखो जरा।

श्री अध्यक्ष: दोनों को बुला दें वैल में? हमारा काम भी खतम हो जाएगा। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, आप स्वयं जानते हैं कि जीएसटी आने के बाद किसी भी स्टेट में फाइनेंस डिवोल्व होते हैं सेंटर से। वे तो अभी अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं? माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, स्पीकर महोदय। पिछले दो सालों में जब से कोरोना आया है तब से जो फिगर केन्द्र सरकार ने लोक सभा में दिये हैं, 1.12 लाख मतलब 1 लाख 12 हजार 'wage earners' ने सुसाइड किया है। ऐसा अमृत काल जो यह केन्द्र सरकार चला रही है। भगवान ही बचाए कि 1 लाख 12 लाख लोगों का अमृत काल में किस तरह से उन्होंने भला किया है।

(समय: 12.44 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

आप हंगर इन्डेक्स की बात कर रहे हैं। हंगर इन्डेक्स की बात करें तो हमारा स्थान 109 देशों में 101 स्थान पर था। हंगर इन्डेक्स इस बार हमें 107वें स्थान पर लेकर आ गया। क्या इसी अमृत काल की बात हम करना चाह रहे हैं? किस तरीके से यह बजट दिया जा रहा है? किस तरीके से गरीब आदमी जो और गरीब होता जा रहा है, ऐसा अमृत काल चल रहा है। अदनान सामी ने एक गाना गाया था, हम सबको लिफ्ट करा दे, गाड़ी, बंगला, कार दिला दे। मैं तो यह कहता हूं, अमृत काल में यदि ऐसा होता तो हम आज मित्र काल की बात ही नहीं करते। अमृत काल की हम भी आपके साथ यह बात करना चाहते थे, बट आप यह करना ही नहीं चाहते हो। आप तो सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाना चाहते हो। यह मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, पूरा देश बोल रहा है।

(श्री रोहित बौहरा)

आज यदि हम केन्द्रीय बजट की बात करें, 45 लाख करोड़ रुपये का उनका एक्सपेंडीचर है, जिस पर ग्रोथ 7.5 परसेंट की आई है। यदि हम इंफ्लेशन को अकाउण्ट में लें तो लास्ट ईयर का बजट और इस साल के बजट में इंफ्लेशन के बाद कोई डिफरेंस नहीं आया है। इस-इस तरह से राजस्थान सरकार का यदि हम बजट लेते हैं तो हम 2.97 लाख करोड़ का खर्चा करते हैं, which has increased by 7.1 per cent. 7.1 परसेंट की बात करते हैं तो यह भी इंफ्लेशन हम लगाएंगे तो करीब-करीब पिछले साल हमने जो खर्च किया था, वह ही हम इस साल खर्च करेंगे।

इसी तरह रिसीट का है। इस साल रिसीट में केन्द्र सरकार को 17.16 लाख करोड़ मिलेंगे। उन्होंने यह बताया कि हमारे को 11.17 परसेंट इन्क्रीज होगा, over the revised estimate. इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया, उसके अन्दर 2.34 करोड़ का इन्क्रीज आया और वह भी करीब-करीब 8.4 परसेंट का, तो कोई डिफरेंस नहीं है?

अब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें। रेवेन्यू डेफिसिट केन्द्र सरकार का 2.9 परसेंट आफ जीडीपी है। राज्य सरकार ने बजट दिया, उसका रेवेन्यू डेफिसिट 1.6 परसेंट आफ जीडीपी है। यह आप सबको विदित है कि रेवेन्यू डेफिसिट किसका कम है, केन्द्र सरकार का या राज्य सरकार का?

इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट की बात करें। हमने फिस्कल डेफिसिट अपने पेपर में भले ही 4 परसेंट दिखाया हो, बट वह 4 परसेंट नहीं है। एफआरबीएम एक्ट के तहत 3 परसेंट प्लस पावर रिफार्म में 0.5 परसेंट हमें मिलेगा। हमने 4 परसेंट दिखा रखा है। हमने वह कम्पोनेंट इसके अन्दर अपना ले रखा है, जो जीएसटी में पैसा केन्द्र सरकार ने लोन के रूप में लिया है और वह सेस के थ्रू दे रहे हैं, वह हमारे को लोन के रूप में दिया है, but over the years वह ग्रांट में बदल जाएगा।

चूरू से आने वाले हमारे विधायक महोदय हैं, वह जो गड़बड़ का जाल करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझाते हैं। आपने कई बार देख लिया तो, हुजूर यह 3.5 परसेंट ही है। आप अपने आप अपने फिगर्स को कृपया करके करेक्ट कर लें। इतना ही कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड ठीक है? (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बिलकुल, रिकार्ड ठीक है। यह रिकार्ड ठीक है, क्योंकि आपकी केन्द्र सरकार ने... (व्यवधान)

श्री सभापति: इधर, इधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा नाम लेंगे तो मैं भी स्पष्टीकरण दूंगा। (व्यवधान) एफआरबीएम एक्ट आपने दिया है 2023-24 का, पेज 19 पर देख लो, क्या है... (व्यवधान) इसको भी करेक्ट करते। I may be wrong, I wanted to be wrong.

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह किताबें भी ठीक करा दो। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): You are always wrong.

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप पढ़ते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। (व्यवधान) आप पढ़ते कुछ हैं और बताते कुछ हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर सम्बोधित करें, उधर नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, सॉरी।

श्री सभापति: No. It is not allowed.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, सनसनी फैलाने के लिए... (व्यवधान) यह मेरी तरफ घौंचा कर रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज कंटीन्यू।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज कंट्री का फिस्कल डेफिसिट 5.9 परसेंट है। क्या इन लोगों ने एफआरबीएम का फोलो किया? अपने लिए कुछ फोलो नहीं करते। केन्द्र सरकार अपने लिए कुछ फोलो नहीं करती। वह सब फोलो किसको कराना है, राज्य सरकारों को कराना है। वह भी उन राज्य सरकारों को कराना है, जहां उनकी सरकार नहीं है। यानी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ हुई है, इनकी ग्रोथ 6.5 परसेंट की आ गई। 7 परसेंट की बात कर रहे थे, अभी के फिगर्स आये हैं 6.5 परसेंट से ऊपर की ग्रोथ नहीं रहेगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ 11.06 परसेंट की रहेगी, जो कि करीब-करीब डबल है। अब आप हाथ जोड़ो या कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

मैं पर-कैपिटा इनकम की बात करना चाहता हूं। राजस्थान में जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है पर-कैपिटा इनकम हमारी हर साल, एवरेज की बात कर रहा हूं, हर साल एवरेज में 10 परसेंट बढ़ी है। आज हमारी पर-

(श्री रोहित बौहरा)

कैपिटा इनकम 01 लाख 56 हजार 149 रुपये की है और वह लास्ट ईयर जब हमारी हालत खराब थी, इन लोगों ने हमारा पैसा रोककर रखा था, हमारे को जी.एस.टी. का पैसा नहीं दिया था, तब भी हमारी ग्रोथ 14.85 परसेंट रही और उससे पिछले साल हमारी ग्रोथ 18 परसेंट रही in our per capita income.

जब इनकी सरकार थी तो हम स्टैंड करते थे 21 पर, जब यह कहते थे न कि बीमारू प्रदेश कर दिया तो इन्होंने बीमारू प्रदेश कर दिया। हमारी रैंकिंग 21वें स्थान पर थी और आज हमारी रैंकिंग जब हमारी गहलोत सरकार चल रही है, गहलोत साहब ने जो फाइनेंस की स्पीच दी, चार साल से फाइनेंस सम्भाला, तो आज हमारी रैंकिंग देश में 9वें स्थान पर आ गयी। अब 21वें स्थान से 9वें स्थान पर आ गयी।

साहब, अब आप 9 साल की बात करें। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। उससे पहले कि जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है सेंटर की और स्टेट की, सेंटर की outstanding liabilities over GSDP is today, 57 per cent. यानी, 57 परसेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है केन्द्र सरकार की और हमारी कितनी है, हमारी है 36.8 परसेंट।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य उस दिन क्या कह रहे थे कि हमारी जो लायबिलिटी है केन्द्र सरकार से उसको कम्पेरीजन नहीं कराएंगे। कम्पेरीजन करते तो इनको यह पता लगता कि हमारी जो लायबिलिटी है वह 36.8 परसेंट है और केन्द्र सरकार की 56.7 परसेंट है जो मैंने राउंड आफ करके 57 परसेंट कर दी।

आज आप इंटरेस्ट पेमेंट की बात करो तो what is the interest payment? केन्द्र सरकार इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रही है? एक रुपये कमाती है, उसमें से 41 पैसे का उनका इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है और हमारा कितना पेमेंट हो रहा है? हमारे को वे यह बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने फाइनेंसेज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पेमेंट हो रहा है एक रुपये में से 8.34 पैसे और उधर 41 परसेंट हो रहा है।

आज हम क्या बताने की कोशिश करते हैं? किस तरह से आप गुमराह करते हैं पूरे सदन को, मैं वह आपको बताना चाह रहा हूं। इस तरह से गुमराह मत करिये सदन को, साहब।

(श्री रोहित बौहरा)

कैपिटल आउट-ले की बात करी। इन्होंने यह कहा कि हमने कैपिटल आउट-ले जो साढ़े सात लाख करोड़ रुपये जो इन्होंने पिछले साल कैपेक्स करा, साढ़े सात लाख करोड़ रुपये में से भी यह सिर्फ सवा सात लाख करोड़ रुपये ही खर्च कर पायेंगे इस साल और इन्होंने कैपेक्स बढ़ा दिया 33 परसेंट यानी, दस लाख करोड़ रुपये। किस तरह से यह खर्च करेंगे दस लाख करोड़ रुपये? यह तो आप बतायें। जब आपसे साढ़े सात लाख करोड़ रुपये ही खर्च नहीं हुए तो आप किस तरह से उसको दस लाख करोड़ रुपये खर्च करा कर लेकर जाओगे? यह अभी तक किसी के पास जवाब नहीं है।

नौ साल में यह पहली बार हुआ है कि जब हमारी मनमोहन सरकार गयी थी तो वह आपको लोन छोड़कर गयी थी 55 लाख करोड़ रुपये का और आज मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख है कि हमारा आज 31 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन 01 लाख 55 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा। 100 लाख करोड़ रुपये का लोन इन नौ सालों में केन्द्र सरकार ने लिया है, बिना सोचे समझे लिया है कि किस तरह से इसका री-पेमेंट होगा। 140 करोड़ जनता में... (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह बजट पर बोल रहे हैं?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 140 करोड़ जनता में यदि हम 155 लाख करोड़ का लोन लेंगे तो हमारा 01 लाख 10 हजार का पर-आदमी का हमें लोन चुकाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: Please, don't disturb him.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, आज हम बात करते हैं नरेगा की। नरेगा में इन्होंने क्या प्रोमिस करा कि हम हर आदमी को सौ दिन का रोजगार देंगे। पूरे कंट्री में एवरेज क्या आया? 27 दिन का रोजगार भी आप पूरे देश में नहीं दे पाये। अपन क्या बात कर रहे हैं? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यह समझ में ही नहीं आ रहा। सिर्फ 27 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया और इस बार मनरेगा का बजट आपने 33 परसेंट और घटा दिया तो मतलब, 27 दिन भी इस बार रोजगार नहीं मिलेगा इस साल आपको। सर, 33 परसेंट और आपने बजट घटा दिया।

आपने बात की कि हम किसान को, पी.एम. फार्मर्स किसान योजना में हम फार्मर्स को हर साल छह हजार रुपया देंगे। हर साल देंगे। इनका यह टार्गेट बना हुआ है कि 14 करोड़ किसानों को हम पैसा बांटेंगे। आज दिन तक जब से

(श्री रोहित बौहरा)

यह योजना शुरू हुई है, हम साढ़े दस करोड़ किसानों से ऊपर नहीं बढ़ पाये। That means, जो हमारा टार्गेट था, हम तीस परसेंट टार्गेट आज भी उन किसानों को नहीं दे पाये जिनको यह पैसे की जरूरत है और यह केन्द्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर पायी।

इसी तरह से एग्रीकल्चर में इस साल आपने सात हजार करोड़ रुपये का बजट डाउन कर दिया over the revised estimates और इसी तरह से रूरल डवलपमेंट का आपने कर दिया साढ़े बारह, तेरह परसेंट और इसी तरह से आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी साढ़े बाईस परसेंट इस साल घटा दी, तो आप कहना क्या चाह रहे हो? न एग्रीकल्चर में आप बजट दे रहे हो किसान को, न पी.एम. किसान योजना, जिसमें आप छह हजार रुपये किसान को देते हैं, उसमें भी आपने बजट कम दिया। आपने बजट कम कर दिया फर्टिलाइजर सब्सिडी में, आपने बजट कम कर दिया फूड एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, आपने दोनों को, पी.डी.एस. को और जो किसान को पी.एम. योजना के तहत फ्री में बांटते थे, उसमें आपने 90 हजार करोड़ रुपया इस साल कम करा है। 90 हजार करोड़ रुपया इस बार आपने कम करा है, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। जब आप किसी को भी, मेरे ख्याल से इस बार आप फ्री अनाज नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने 90 हजार करोड़ रुपया डाउन कर दिया।

हम क्या करना चाह रहे हैं? किसान को फसल बीमा योजना, जहां पर इनका बजट था 14,500 करोड़ रुपये का, यह खर्च ही नहीं कर पाये। किसानों का बीमा ही नहीं कर पाये। इन्होंने टोटल रुपया उसमें खर्चा करा 11,500 करोड़ रुपये। क्यों नहीं आप खर्च कर पाये, किसने रोका था आपको खर्च करने से? क्यों नहीं आपने करा? फिर यहां आकर मिथ्या भाषण करते हैं कि किसान को पैसा नहीं मिल रहा फसल बीमा योजना का, आपने पूरा पैसा खर्च नहीं करा।

इसी तरह से इन्होंने पैसा खर्च नहीं करा जल शक्ति योजना का। आपने जल शक्ति योजना का वापस बजट बढ़ा दिया। पिछले साल ही आपका जो बजट था, उसमें से सात हजार करोड़ रुपया आपने खर्च कम करा है। यह तो बताओ कि क्यों कम खर्च करा आपने सात हजार करोड़ रुपया? आप क्या लोगों को पानी पिलाना नहीं चाहते? आपकी मंशा खतम हो गयी लोगों को पानी पिलाने की, नल देने की? आपकी क्या इच्छा है? आप सात हजार करोड़ रुपया नहीं दे पाये और आप बड़े फख्र से यह बोलते हैं कि यह सेंटर की स्कीम है। सेंटर ने क्या दिया?

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): केन्द्र जो स्टेट गवर्नमेंट को बजट दे रहा है, उसको तो पूरा खर्च करो, केन्द्र ने दिया जिसको तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सरकार, बैठो। बैठो।

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सुनो, सुनने का माद्दा रखो।

श्री सभापति: यह बीच में टोकाटाकी नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पहले यह 90 परसेंट देते थे, अब हम पचास परसेंट अपने शेयर में से दे रहे हैं, कोई आप भीख नहीं दे रहे हो हमारे को... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलेंगे तब इनको भी मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): भीख नहीं दे रहे हो। हमारा पैसा है, स्टेट का पैसा है। हम खर्च करते हैं। जी.एस.टी. देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। जो कांस्टीट्यूशन से हमको डिवोल्व होता है, आप नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर ही सम्बोधित करिये। बैठिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपकी मंशा नहीं थी हमारे को देने की। आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यह बात कर रहा था कि कोविड के अन्दर इन्होंने एक एम.एस.एम.ई. क्रेडिट लिंक योजना शुरू करी कि हम एम.एस.एम.ई. सैक्टर को पैसा देंगे। एम.एस.एम.ई. सैक्टर जो भारत का ऐसा सैक्टर है जिससे सबसे ज्यादा एम्प्लायमेंट जनरेशन कोई करता है, तो स्माल स्केल और एम.एस.एम.ई. सैक्टर करता है। आपका बजट था 15 हजार करोड़ रुपया और आपने खर्च कितना करा? 10,500 करोड़ रुपया मतलब, which means 33 per cent of the budget was not spent. आपने एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्री को पैसा ही नहीं दिया क्योंकि अल्टीमेट आपकी ऐम क्या है? आप व्यापारियों के खिलाफ हो। आप नहीं चाहते कि व्यापारी उठे इसीलिए आपने यह नोटबंदी की और इसीलिए आपने कोविड में उनकी कोई मदद नहीं की। आपने जो भी पैसा दिया, एक पैसे की आपने उनको मदद नहीं की, जो भी पैसा दिया उसका आपने इंटरेस्ट वसूल किया साढ़े सात परसेंट से।

साहब, एक अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम निकली। केन्द्रीय बजट में यह कहा गया कि हम वुमन को वुमन एम्पावरमेंट के लिए साढ़े सात परसेंट का इंटरेस्ट देंगे। भाई साहब, यह तो देखो कि बैंक ही साढ़े सात परसेंट दे रही

(श्री रोहित बौहरा)

है तो आप देकर कौनसी बड़ी बात कर रहे हो? आज की डेट में कोई भी प्राइवेट बैंक हो, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, आज की डेट में इंटरेस्ट रेट क्या है? आज की डेट में इंटरेस्ट ही more than 7.75 per cent है। आप लोग क्या बात कर रहे हो? जो बात करनी है वह बिलकुल डिफरेंट तरीके से बात करते हैं।

(समयः 13.00 बजे)

अभी एक और रिपोर्ट आयी, साहब। वह रिपोर्ट क्या थी? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट लास्ट ईयर आयी, जोकि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। उन्होंने अपनी रिसर्च की और उनकी रिसर्च विंग ने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने रिपोर्ट यह दी कि 5.6 करोड़ लोग पावर्टी लाइन के नीचे आ गये। केन्द्र सरकार ऊपर तो बढ़ा नहीं पायी, उनको नीचे और धकेल दिया। पावर्टी लाइन से नीचे धकेल दिया। 5.6 लोग पावर्टी लाइन से नीचे और चले गये। एक आक्सफैम की रिपोर्ट और आयी, जो कि बहुत ही शानदार है। About one per cent of the Indians during the BJP rule, one per cent of the country की जो पापुलेशन है, they hold 40 per cent of the wealth of this country. 01 प्रतिशत लोग 40 प्रतिशत वैल्थ होल्ड कर रहे हैं इस कंट्री की, जबकि जी.एस.टी. में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3 प्रतिशत है। वन प्रतिशत लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ तीन प्रतिशत है।

इसी तरह से जो हमारे बॉटम फिफ्टी परसेंट लोग है, उनका जी.एस.टी. में कंट्रीब्यूशन करीब-करीब 64 परसेंट है। जो गरीब हैं, वह तो जी.एस.टी. में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो अमीर हैं, वह सिर्फ 3 परसेंट जी.एस.टी. में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज यह देखिये कि बिलिनियर्स तीन साल के अंदर, इस कंट्री में 121 लाख बिलिनियर्स पैदा हो गये, जबकि गरीबी के नीचे की बात तो मैंने आपको बता ही दी।

अब जितने अर्थशास्त्री हैं, सब तीन बात कर रहे हैं, that there are three Engines of growth for this country. तीन इंजन आफ ग्रोथ क्या-क्या हैं? एक तो एक्सपोर्ट बढ़े, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़े और तीसरा कैपेक्स, Capex they have taken care off! जनवरी महीने के अंदर एक्सपोर्ट, आज ही की रिपोर्ट है 6.6 परसेंट से आपका एक्सपोर्ट इस साल वापस डाउन हो गया और जो ट्रेड डेफिसिट था, all time high trade deficit, 17.75 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इस महीने हो गया। अभी आपके दो महीने और बाकी हैं।

(श्री रोहित बौहरा)

एक बात और हुई। ग्लासगो के अंदर हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने एक अनाउंसमेंट किया। वह अनाउंसमेंट क्या किया? हम 500 गीगावॉट बिजली बनायेंगे और वह भी सोलर एनर्जी में हम इन्वेस्ट करेंगे। इसके तुरंत बाद एक अनाउंसमेंट आता है अडाणी ग्रुप से, कि हम ग्रीन एनर्जी में अपना पैसा लगायेंगे। क्या यह कोइंसीडेंस था या यह और कुछ था? इसका जवाब यदि आप दे सको तो आप लोग दे देना। मैं इस बात के जवाब का इंतजार आपसे करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अब सबसे बड़ी बात आयी कि हमारा स्टेट का जो बजट आया है, मुख्य मंत्रीजी ने जो यहां बजट दिया है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें। (व्यवधान) नहीं, जब आप लोग बोलते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। so, let him speak. यह गलत है। बोलिये आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): In education department, जो एजुकेशन पर है, इस साल हम लोग खर्च कर रहे हैं 57,953 करोड़ रुपया, सिर्फ एजुकेशन पर। यह हमारे बजट का 19.5 परसेंट है। हम राज्य की अपनी जनता को एजुकेट करेंगे, तभी जाकर हम एम्प्लायमेंट जनरेट करेंगे। जब हमारे लड़के दूसरे प्रदेशों में जायेंगे, नई नौकरियां ढूंढेंगे, नया एम्प्लायमेंट होगा तो नये स्टार्ट-अप्स करेंगे। इसी बार इसीलिये बजट के अंदर पहली बार हुआ है कि जो स्टार्ट-अप्स हैं, उनके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने 25 लाख रुपये से बढ़ाकर सीड मनी 01 करोड़ रुपये तक कर दी। केन्द्र सरकार ने क्या किया, स्टार्ट-अप को मारने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या किया? केन्द्र सरकार ने एंजेल टैक्स लगा दिया। आप समझते हैं एंजेल टैक्स क्या होता है?

श्री सभापति: आप इधर बताओ।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं उनसे पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, इधर बताइये आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एंजेल टैक्स वह होता है, जब आप लम्प-सम एक सेल करते हो अपने शेयर का किसी भी फोरेन इन्वेस्टर को, इंडियन इन्वेस्टर्स को तो लगा ही था टैक्स, पहली बार हुआ है। स्टार्ट-अप को खतम

(श्री रोहित बौहरा)

करने के लिए केन्द्र सरकार ने एंजेल टैक्स लगा दिया। जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है, अब वह भी टैक्सेबल हो जायेगा। स्टार्ट-अप्स सब इसके लिए खड़े हो गये हैं, सरकार के खिलाफ हैं कि फोरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आयेगा हमारे पास, क्या करें। एंजेल टैक्स लगा दिया। स्टार्ट-अप्स को आप खतम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बजट में, नया बजट आता है तो कभी आता है स्टार्ट-अप इंडिया, कभी आता है मेड-अप इंडिया, कभी आता है एग्रीकल्चर में हम फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे। हर साल हम एक नया शगूफा फेंक देते हैं। बाद में इन सब शगूफों को भूल जाते हैं और एक नया शगूफा फेंक देते हैं।

लास्ट ईयर कहा था कि डिफेंस यूनिवर्सिटी खोलेंगे। डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक भी ईंट नहीं लगी आज तक। यह जो बोलते हैं न केन्द्र सरकार की क्यों, जी.एस.टी. के बाद स्टेट्स की सोवेरनिटी खतम हो गयी है। हम केन्द्र पर डिपेंड हो गये हैं, क्योंकि पैसा केन्द्र से आता है, केन्द्र के खातों में ही जमा होता है। इसलिए केन्द्र की बात करनी पड़ती है, नहीं तो मैं केन्द्र की बात एक दिन भी नहीं करता।

हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर में इस बार हमारा बजट and we have grown by 10 per cent. हर जगह नई सी एच सी, कहीं पी एच सी, कहीं सब-सेंटर, हमारे मंत्रीजी ने पूरे सिस्टम को एक ऐसा कर दिया, आपके सी एच सी, पी एच सी में कहीं डाक्टर्स की कमी नहीं होने देंगे। अभी 1786 डाक्टरों की नई भर्ती हुई है, उन डाक्टर्स की पोस्टिंग हो रही है। हर जगह अब आपको डाक्टर मिलेंगे। सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरफ है। जो सिस्टम पांच साल से कम्प्लीटली इन्होंने दवाइयां बन्द कर दी थीं, ये नई स्कीम भामाशाह बनाई, जिसमें लोगों ने इतना करप्शन किया कि वह स्कीम अपने आप ही फेल हो गयी।

अब यह चिरंजीवी स्कीम को इसीलिये तो नहीं पचा पाते। चिरंजीवी स्कीम में पहली बार हुआ कि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक आप चिरंजीवी स्कीम में इलाज करा सकते हो। किसी की डैथ हो जाये तो 5 लाख से आप 10 लाख रुपये तक डैथ कैजुअलिटी पर आपको बीमा मिल जायेगा। एक गरीब आदमी, जिसको पहले राज्य सरकार एक-एक लाख और दो-दो लाख रुपये देती थी, अब इन केस आफ एक्सीडेंट उसको 10 लाख रुपये का बीमा

(श्री रोहित बौहरा)

मिलेगा। इससे उनके बच्चों का जो भविष्य है, वह काफी ठीक रहेगा, क्योंकि उसको न सिर्फ यह बीमा मिलता है, विधवा पेंशन मिलती है, पालनहार योजना में उसको पैसा भी मिलता है और इंदिरा रसोई से वह 16 रुपये में खाना खा सकते हैं। ऐसी सोशल सैक्टर्स की स्कीम निकली है, 16 रुपये में आदमी खाना भी खा लेगा। मतलब 500 रुपये में वह दोनों टाइम खाना खा लेगा।

आपने शहरी नरेगा शुरू कर दी। आपने नरेगा शुरू कर दी कि जहां 100 दिन का रोजगार मिलेगा, वहां आपको 25 दिन रोजगार और मिलेगा और शहरी नरेगा में भी आपको 100 दिन के अलावा 25 दिन और देंगे। आपको किसने रोका था चार-पांच साल पहले, आप यह शुरू करते? आपको किसी ने रोका था क्या? कोई नई चीज मुख्य मंत्रीजी लेकर आये, बुराई के अलावा इनको कुछ नहीं है। कोई सराहना करने का इनका काम नहीं है। पहली बार हुआ है जब हमारे बड़े-बूढ़ों को सम्मान मिला है। उनकी आज पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये हो गयी। यह सम्मान बड़े-बूढ़ों का है। गांवों में हम देखते हैं कि लड़के बड़े-बूढ़ों को देखते तक नहीं थे, उनकी केयर भी नहीं करते थे। अब वह हजार रुपये में अपना घर-खर्च आराम से चला सकता है, क्योंकि जमीन उसी के नाम रहती है।

सोशल सेक्टर पर इतना काम हुआ है, वह अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है, और किसी ने नहीं किया है। हमारे सोशल सेक्टर्स में हर साल हमारी पेंशन स्कीमों पर 15 परसेंट हमारे को पैसा बढ़कर मिलेगा।

अब आप बात करो एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हमारा बजट इस बार करीब-करीब 4.4 परसेंट से बढ़ाया। इसी तरह से वाटर सप्लाई में पहली बार करीब-करीब 43 परसेंट बजट बढ़ गया, 9,773 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, क्योंकि हमें मैचिंग ग्रांट देनी पड़ेगी न। केन्द्र सरकार ने तो ऐसा काम किया है, यह चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा जो गला है, राज्य सरकार का गला किस तरह से दबाया जाये।

पहले कह रहे हैं कि आप अपना पैसा डालो केन्द्र आधारित योजनाओं में, फिर हम अपना पैसा डालेंगे। उसके बाद काम करेंगे। सेस से आप साढ़े 4 लाख करोड़ डीजल और पेट्रोल का पी जाते हो। हमारे को उसमें से हमारा शेयर नहीं देते हो। सब पैसा आप खा जाते हो। हमारे को पैसा काहे पर मिलता है? डिवोल्यूशन किस पर होता है? डिवोल्यूशन सिर्फ पापुलेशन और ज्योग्राफिकल

(श्री रोहित बौहरा)

लिमिट्स के अकोर्डिंग हमें पैसा मिलता है। पैसा कितना-सा मिलता है? वह सब आप खा जाते हो। फिर भी आप यह चाहते हो कि जो केन्द्र आधारित स्कीम हो, उस पर पैसा राज्य सरकार पहले डाले, फिर हम डालेंगे। कम से कम यह सब तो आप नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, आज एक आर्टिकल आया। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल आया। पत्रिका ने आज ही आर्टिकल दिया है। जो बीजेपी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है, आज वह क्या कहती है कि हम ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं। क्यों, लाहोटी जी, आज आपने अख़बार पढ़ा था? आप एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। लौटकर बुद्धू घर को आये। आ गये, सोचा कि वोट नहीं मिलेंगे। वोट नहीं मिलेंगे इसलिए लौटकर बुद्धू घर को आ गये। कहा कि बीच का रास्ता निकाल दो। हम अपने कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन देंगे।

कंट्री के एक ही आदमी के शेयरों में धड़ाम हुआ। 190 बिलियन से उसकी प्रोपर्टी 55 बिलियन डालर एक दिन में घट गयी। एक दिन में घट गयी। मतलब, उसकी वन थर्ड वैल्यू का इरोजन एक दिन में हो गया।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप लौटकर के वापस क्यों आ रहे हो, यदि आपको नहीं करना था तो। आप लौटकर के तो इसीलिए वापस आ रहे हो न कि आपको फिक्स्ड रिटर्न, जिस आदमी ने 30-31 साल सरकारी नौकरी में दिये, आपको उसे फिक्स्ड रिटर्न देना पड़ेगा।

इसी तरह से जो आज यह स्कीम निकाली मुख्य मंत्रीजी ने, 76 लाख लोगों को आप सिलेंडर फ्री दे रहे हो। आज सिलेंडर्स की हालत यह है कि जो 2 सिलेंडर इन्होंने फ्री में दिये, इन्होंने कोहनी पर तो गुड़ लगा दिया और फिर कहा कि इसको चाटते रहो। चाटेगा कहां से? जो औरतें पहले चूल्हा जलाकर आंसू बहाती थीं, अब वह एक-एक सिलेंडर लेकर आंसू बहाती हैं कि किस तरह से 1100 रुपये का हम सिलेंडर ले सकें। इसी आंसू पोंछने की स्कीम हमारे मुख्य मंत्री ने लागू की। 76 लाख लोगों को 500 रुपये में हम सिलेंडर फ्री देंगे।

इसी तरह से एक करोड़ लोगों को फूड पैकेट्स फ्री दिये जा रहे हैं। फूड पैकेट्स में आप चीनी दे रहे हो, दाल दे रहे हो, नमक दे रहे हो, मसाले दे रहे हो और एडिबल ऑयल दे रहे हो। मतलब, उसका घर खर्च is almost

(श्री रोहित बौहरा)

taken care of, जो 4 आदमियों का घर खर्च है वह सरकार अपने जिम्मे ले रही है। यह सोशल सेक्टर में क्यों कर रहे हैं? इनको यह चीज समझ में नहीं आयेगी क्योंकि इनको गरीबों का दर्द नहीं है। गरीबों का दर्द वह समझता है जो खुद गरीबी में से निकला हो और उसको पता हो कि गरीबों का दर्द क्या होता है। यह गरीबों का दर्द हम समझते हैं।

आज जो गरीबों के लिए हम कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आज हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेट होगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। यह नहीं चाहते कि देश बढ़े। यह तो देश को गरीब रखना चाहते हैं जिससे यह दिखायें कि हम आपके लिए यह-यह कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप 3 मिनट में कन्क्लूड कर लें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं तो जल्दी से कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति: 3 मिनट में कर लें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी। हमने 2 हजार यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को फ्री दे दी, तो करीब-करीब यह समझिये कि हर किसान का बिल अब जीरो होना शुरू हो जायेगा। 100 यूनिट से करीब-करीब हर गरीब व्यक्ति का जीरो यूनिट का बिल होना शुरू हो जायेगा। इतनी सारी योजनाएं हैं।

आज 5 करोड़ रुपया हमने यूथ के डवलपमेंट में खर्च किया। उसमें से क्या कर रहे हैं? उसको स्किल कर रहे हैं। उसकी पर्सनलिटी डवलपमेंट कर रहे हैं। उसको स्कालरशिप दे रहे हैं। यूथ को हम मार्जिन मनी दे रहे हैं, to put up the industry. यह फर्स्ट टाइम हुआ है। किसी ने किया है? सीड मनी दे रहे हैं। 5 लाख रुपये तक सीड मनी दी जायेगी जिससे कि वह अपना धंधा एस्टेब्लिश करे।

इन्होंने मुद्रा लोन चालू किया। 85 per cent of the Mudra loan is given to whom? 50 हजार रुपये की ही मुद्रा स्कीम है। 80 परसेंट लोग सिर्फ 50 हजार रुपये का लोन लेते हैं। 5 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 10 परसेंट लेते हैं। 5 परसेंट लोग सिर्फ 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं। उनके पास देने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिये उनको मुद्रा लोन से बाहर रखा जाता है।

(श्री रोहित बौहरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से इस बजट में सिर्फ 3-4 गुजारिश करना चाहता हूं। एक तो पूरे राजस्थान में लवकुश कल्याण बोर्ड की स्थापना हो। अवंती बाई कल्याण बोर्ड की स्थापना हो। निषाद समाज के कल्याण बोर्ड की स्थापना हो। देवी अहिल्या बाई बोर्ड की स्थापना हो। एक स्वर्णकार समाज की स्थापना हो। अलग-अलग बोर्ड जैसे बैठे रहेंगे, जैसे आपने दिया है, 500 करोड़ रुपये एस सी के लिए दिया है, 500 करोड़ रुपया एस टी के लिए दिया है। 100 करोड़ रुपया हमारे वाल्मीकि समाज को दिया है। उनके उत्थान के लिए दिया है। यदि यह बोर्ड बनेंगे तो यह भी अल्टीमेटली डिफरेंट जातियों के उत्थान के लिए बनेंगे कि किस तरह से इनका लिविंग स्टैंडर्ड पूरा किया जाये। वह तब होगा जब हम गरीबों की मदद कर सकेंगे।

हमें केन्द्र सरकार जैसे सिर्फ 2 आदमियों की सरकार नहीं बनना है। हमें 140 करोड़ जनता की आवाज बनना है। हमें सिर्फ 2 आदमियों की आवाज नहीं बनना है। हमें इन सबकी आवाज बनना है।

जो एक सबसे बड़ा काम किया है चिरंजीवी संबल योजना, यदि कोई श्रमिक बीमार हो जाता है और वह चिरंजीवी के अंदर एडमिट हो जाता है, उसको डायरेक्ट डीबीटी से 200 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। जितनी उसकी मजदूरी खोयी है, उसको 7 दिन डीबीटी से पैसा मिलेगा, जिससे उसके घर का रोज के लालन-पालन का पूरा इंतजाम हो सके। उसको सफर नहीं करना पड़े क्योंकि वह रोज मजदूरी कर रहा है, रोज खा रहा है। यह उन्होंने किया है।

जो गिग वर्कर्स की 200 करोड़ रुपये की, गिग वर्कर्स वह हैं जिनको सिर्फ इंसेंटिव बेस सैलेरी मिलती है। उनको इंसेंटिव के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। जितनी डिलीवरी करेंगे सिर्फ उनको उतना ही पैसा मिलेगा।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सिर्फ एक सैकण्ड और लूंगा। गिग वर्कर्स को 200 करोड़ डवलपमेंट का जो दिया है, वह पूरे भारत में एक ऐसा एग्जाम्पल सैट किया है, जो कि केन्द्र सरकार को भी अगली बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग इफेक्ट होंगे। यदि सरकार नहीं करेगी तो यह बीजेपी सरकार अगली बार वापस नहीं आयेगी। इनको इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें जो मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं और 15 हजार हमारी इंदिरा रसोई बढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं।

(श्री रोहित बौहरा)

एक सेल्फ हैल्प ग्रुप्स पर हम बहुत काम कर रहे हैं। 8 लाख फैमिलियों को हम सेल्फ हैल्प ग्रुप्स से जोड़ रहे हैं स्पेशल रूप से वुमैन। वुमैन एंटरप्रिन्योर की हम बात कर रहे हैं। वुमैन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। उनको 8 परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी राज्य सरकार देगी। यह ऐसा है जिसमें हमने वुमैन अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका बहुत्बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अशोक लाहोटी।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि समय आप लोगों का निर्धारित है। हाउस का शिड्यूल और असेम्बली का निर्धारित है। जैसे अब 10-10 मिनट हैं या 5 मिनट हैं, जब 2 मिनट टाइम बचेगा तो मैं निवेदन कर दूंगा कि आप अपना समअप करिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरा समय ज्यादा है।

श्री सभापति: आपका 10 मिनट है। थैंक यू।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): किसका? 10 मिनट नहीं है, सर, 30 मिनट है।

श्री सभापति: बोलिये प्लीज। आपका 10 मिनट है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, 30 मिनट है, आप चैक कर लें। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जिस बजट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय बुद्धिमान मित्र ने अभी इतनी सारी बातें कीं। मैं तो केवल एक ही बात कह रहा हूं कि पड़ोसी की भैंस क्या कर रही है, उसको छोड़ो, आपकी भैंस कितना दूध दे रही है, वो तो बोलते एक शब्द इतनी देर में।

श्री सभापति: आपका समय आपके सचेतक महोदय ने 30 मिनट किया है, 30 से 31 नहीं होगा, आप 30 तक बोलिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय जो अभी

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय महामहिम भी बन गये हैं, उन्होंने कई बार इस सदन में कहा और इन दिनों में भी यह बात कही कि बजट बनाने का तरीका ही जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बजट की जो तीन-चार किताबें देते हैं, बजट एट ए ग्लांस, आप देखो तो उसमें संख्या लिखी हुई है लाखों में, एफआरबीएम एक्ट उठाओ तो उसमें संख्या लिखी हुई है करोड़ों में और आप सुबह जो बिल लेकर आये हो उसमें संख्या लिखी हुई है हजारों में। 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये के बजट की संख्या हजारों में लिखकर देना, केवल इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस सिस्टम में यहां बैठे हुए माननीय सदस्य जो 200 लोग हैं, न तो उस बजट को देख सकें, न उस बजट को पढ़ सकें, न समझ सकें, इसलिए बजट बनाने का तरीका, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ यही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा क्यों सबसे पहले आउटकम बजट नहीं आता, सरकार ने पिछले साल क्या घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं पर कितना काम हुआ, उन घोषणाओं में कितना खर्चा हुआ, वह आउटकम बजट पहले क्यों नहीं लाया जाता? क्यों वो अंग्रेजों के जमाने की परिपाटी उस बजट की हजारों तरह की मदें बनाकर बजट को उलझाया जाता है ताकि उस बजट को कोई न पढ़ सके, न कोई समझ सके और न बात कर सके।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट को देखने के साथ ही मैं आपका ध्यान 2013 के बजट की तरफ दिलाना चाहूंगा। 2013 में जब बजट आया था तो राजस्थान में इसी तरह का एक वातावरण बना, इसी तरह का एक माहौल बना और इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की, इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने आज तक 15 बजट पढ़े हैं। 15 बजट में इन्होंने 1281 पन्ने पढे, 3618 बिन्दु इन्होंने पढ़े, हजारों इन्होंने घोषणाएं कीं। मैं इनके पहले बजट की घोषणाएं याद दिलाता हूं जो इन्होंने 1999 के बजट में की कि राजस्थान के पानी को फ्लोराइड मुक्त करेंगे। इस सदन में बैठे हुए 200 लोग ईमानदारी से बता दें कि क्या राजस्थान में पानी फ्लोराइड मुक्त हो गया? यह सदन की घोषणा थी। इस जयपुर शहर को भिखारी मुक्त करेंगे। क्या भिखारी मुक्त हो गया? यह इस सदन में घोषणा थी। माननीय सभापति महोदय, 2013 की मैं थोड़ी-सी याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में घोषणा की थी, मुख्यमंत्री शहरी व ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज मुक्त ऋण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क योजना, राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना। माननीय

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इस योजना में तो आप बड़ा आश्चर्यजनक फिगर देखोगे। इसको देखकर आपको लगेगा कि यह घोषणा थी कि क्या थी? इस योजना में इन्होंने 55 हजार विद्यार्थियों को साढ़े तीन लाख लैपटाप बांटने की बात कही। विद्यार्थी 55 हजार और साढ़े तीन लाख लैपटाप बांटेंगे। इसी बजट में घोषणा की थी पुरुषों को 1 रुपये में 1 कम्बल, 1 करोड़ महिलाओं को 2 साड़ी, 1 रुपये में गेहूं, सिक्थ पे कमीशन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का बजट डबल करके 1 लाख 96 हजार करोड़ किया, 7 हजार 900 किलोमीटर राजमार्ग, 2 हजार 737 गांवों को सड़कों से जोड़ा, 1 हजार 700 किलोमीटर बीओटी रोड दी, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30-40 किलोमीटर रोड दी, 28 आरओबी, 1 लाख 86 हजार 460 हैक्टेयर जमीन सिंचित करने का वादा, 50 लाख परिवारों को दो-दो सीएफएल, प्रशासन शहरों के संग में 2 लाख पट्टे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय इस बजट को देखकर वो बजट इसलिए धराशायी हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो अहंकार में इतना बोल रहे हैं, इनका परिणाम यह हुआ कि 2013 के बजट के बाद ये एक मिनी बस के 21 रह गए, मात्र 21. राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है, आप जनता को बेवकूफ समझकर यहां जो घोषणाएं करते हो, जनता बडी समझदार है। माननीय सभापति महोदय, आप उस समय के बजट को देखो, उस समय इनका बजट था 94 हजार करोड़ और उसमें खर्चा करने का बजट था 18 हजार करोड़, आज से तो बेहतर स्थिति थी। इसलिए मैं इनको याद दिला रहा हूं कि समझने वाले समझ जाएंगे कि इस बजट के मायने क्या हैं? उस समय इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 19.6 प्रतिशत था और उसके बावजूद ये मिनी बस में आ गये, तो उस बजट का जो हाल हुआ, इस बार राजस्थान में तो वो भी नहीं है, इस बार राजस्थान में क्या होगा?

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट क्रियान्वयन में और बजट घोषणा में बड़ा फर्क है। एक में जान तो दूसरा बेजान है। राजाखेड़ा से आने वाले मित्र, 2013 में आपने इस किताब में अंतिम पेज पर लिखा था, आपके मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में पढ़ा था, 'विचार मजबूत और निर्मल होंगे तो नतीजे भी हमेशा मजबूत और निर्मल आएंगे।' नतीजा क्या आया? 21, मात्र 21, वर्ष 2013 में 21 आये तो आपका विचार मजबूत था कि नहीं था?

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस बजट में इस देश में एक नया शब्द ईजाद हुआ, डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा और वह शब्द था, 'रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी बांटना', यह डिक्शनरी में आया। आज तक मीडिया लिख रहा है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने आर्टिकल लिखा कि रेवड़ी कल्चर के बजट के क्या हाल हैं? ये रेवड़ी कल्चर बजट 2013 में यह शब्द नया डिक्शनरी में जुड़ा और आज वो ही 2023 में बजट आया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बार जो बजट आया है तो थोड़ा-सा ध्यान मैं इन चार सालों पर दिलाना चाहूंगा। यह पांचवें साल का बजट है, पांचवें साल के बजट में आपने चार साल में क्या घोषणा कीं, एक बार उस पर मनन कर लो। इसी सदन में घोषणा हुई थी कि दस लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ेंगे। जब आपको फ्री अनाज मोदीजी दे रहे हैं तो आप जोड़ने में क्यों डर रहे हो? आज तक जुड़ गये? इसी सदन में घोषणा हुई थी कि प्रत्येक गांव और वार्ड में जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। सदन में जवाब में आया कि अभी तक केवल 12 जनता क्लीनिक खोले हैं। इसी सदन में कहा कि पंचायत समिति पर नन्दी शाला खोली जाएगी, आज तक नहीं खुली। इसी सदन में कहा 11 हजार 266 विकास पथ खोले जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, इस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस विकास पथ का हाल क्या है? इस विकास पथ की जो घोषणा हुई थी, गौरव पथ तो हमने बनाये थे, इन्होने विकास पथ कहा। इस विकास पथ का इनका, पीडब्ल्यूडी का 2022-23 का मैनिफेस्टो दिया है, इसमें इन्होंने लिखा है, 2022-23 में दिसम्बर तक मात्र 183 विकास पथ बने हैं। ये इनके पीडब्ल्यूडी का पेज नम्बर 28 पर 6.4.63, इस टेबल में साफ लिखा हुआ है कि दिसम्बर तक केवल 183, केवल 183 गौरव पथ आपने बनाये हैं, 11 हजार 266 की घोषणा की थी।

माननीय सभापति महोदय, इसी में आपने 5 हजार नये डेयरी बूथ देने की बात की थी। कल आपने कहा कि अभी तक 9 दिये हैं। 1 हजार करोड़ से 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की बात की। मैं कहना चाहूंगा, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बजट धोखा है, वो धोखा इसलिए है कि इसका आउटकम बजट आता तो पता चलता कि आपने 1 हजार करोड़ रुपये का जो प्रोविजन किया था वो, प्रोविजन कहां गया। इस बजट में एक लाइन नहीं लिखी हुई है कि ये जो आपने प्रोविजन किया था तो इस प्रोविजन

(श्री अशोक लाहोटी)

का क्या किया? इस प्रोविजन को वापस जमा करते यदि खर्च नहीं हुआ तो, वो जमा नहीं हुआ है, माननीय सभापति महोदय, वो किसी जेब में गया या गया नहीं। था ही नहीं, असत्य घोषणा थी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो बजट है इसको आप देखो। इन चार सालों में आपने जो बजट दिये हैं, उनका हाल क्या है, उन चार सालों के आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। चार साल में हमारे पास 3 एक्चुअल बजट आ गये और एक आरई आ गया, चारों सालों का बजट आप देखो। इस सरकार ने चारों साल के बजट में 11 लाख 22 हजार 405 करोड़ रुपये का कुल बजट साइज, कुल घोषणाएं हुई हैं बजट की, ये बजट अभी तक आया है राजस्थान का, इस साल का छोड़ दो। इन बजट में से सरकार जो बड़ी बातें कर रही है वो क्यों नहीं पूरी हो रही है, वो मैं बता रहा हूं कि 8 लाख 12 हजार 680 करोड़ रुपये, 72.37 परसेंट कुल बजट का इन्होंने केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जिसमें आपकी पेंशन जाती है, सैलरी जाती है, ब्याज जाता है। राजस्थान की सरकार 72.37 परसेंट तो केवल सैलरी दे रही है, ब्याज दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 2013 में आपका 19 परसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो अभी तक चार सालों का एवरेज मात्र 82 हजार 374, यानी मात्र 7.3 प्रतिशत रह गया है। केवल 7.3 प्रतिशत, यही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने घोषणा की है, खर्च कितना हुआ, वो आपको आगे वाली मदों में बताऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे राजाखेड़ा से आने वाले मित्र केन्द्र सरकार की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। आपकी स्टेट की कुल इनकम इस 11 लाख करोड़ रुपये के बजट में केवल 2 करोड़ 87 लाख 52 रुपये है, जो आपकी पूरे बजट साइज का 2.5 प्रतिशत है। यह स्टेट की आन इनकम है, आप इसको जोड़ लेना, आप बुद्धिमान हैं, सीए हैं, आप इसको जोड़ लेना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका थोड़ा-सा ध्यान दिलाऊंगा कि केन्द्र ने क्या किया। यहां खड़े होकर बड़ी-बड़ी बातें करना, केन्द्र ने क्या किया, केन्द्र ने क्या किया, केन्द्र ने क्या किया, कुछ नहीं किया। केन्द्र ने क्या दिया, वो बता रहा हूं। 4 साल में एक्चुअल और आरई में आपने लिखा है इन किताबों में, बजट एट ए ग्लांस और बजट स्टडी में, 1 लाख 83 हजार 160 करोड़ रुपये तो आपको सेंट्रल शेयर मिला है। सेंट्रल ग्रांट मिली है 1 लाख 34 हजार 166 करोड़ रुपये, यानी आपकी इनकम 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये और केन्द्र से

(श्री अशोक लाहोटी)

आपको 30 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं। आपकी इनकम केवल 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये और केन्द्र से आपको 30 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं, यानी 3 लाख 17 हजार 326 करोड़ रुपये, ये केन्द्र से आपको चार साल में मिले हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी-बड़ी बात करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, जिनका इस साल का बजट 3 लाख 90 हजार करोड़ का है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने 2 लाख 55 हजार करोड़ तो खुद ने लिखा है, यानी 66 परसेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर 38 हजार करोड़ रुपये लिखा है, यानी 9.7 परसेंट। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं। गलत बात। जब आप बोलते हैं तो सभी सुनते हैं। आप इन्हें सुनें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मित्र, यह रामगंज नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस 2023-24 के बजट में यहां पर मुख्य मंत्रीजी ने पहली ही घोषणा यह की थी कि 80 प्रतिशत से अधिक जन घोषणाओं को चार वर्ष में हमने पूरा किया। नम्बर भी पढ़ा, 1279 तो पाइंट पढ़े, 2722 आपने घोषणाएं कीं पांच वर्ष में, 525 पेज आपने पढ़े। सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका की यह एक रिपोर्ट छपी। हमारे उप-नेता, प्रतिपक्ष ने भी कहा था, इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 2019-20 का जो बजट था, उसकी 25 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हुई हैं। अभी तक आपकी कुल घोषणाओं का 49 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ। आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो कहीं धरातल पर दिख ही नहीं रहीं।

करीब 2/3 घोषणाएं अधूरी हैं। 2722 घोषणाओं में से 49 प्रतिशत पर तो काम ही पूरा नहीं हुआ। जिनमें काम पूरा हुआ है उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप देखें, क्या स्थिति है। क्या बाकी चीजों की स्थिति है। जयपुर मेट्रो कहां गयी, सैटेलाइट हास्पिटल कहां गये, जयपुर में चार बस टर्मिनल्स बनने थे, वे कहां गये? आज तक दो वर्षों की बजट घोषणाओं में हमारे यहां सांगानेर में जो 5 करोड़, 10 करोड़ रुपये की सालाना की बजट घोषणा थी, सड़कें बननी थीं, उनके टेंडर तक नहीं हुए। सभापति महोदय, सैकड़ों कालेज की घोषणा हुई। कल मंत्री जी कह रहे थे कि धर्मशालाओं में खोल देंगे। यह हाल है राजस्थान की शिक्षा का। यह हाल है युवाओं का।

(श्री अशोक लाहोटी)

आप क्या युवा बजट की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूलों के बारे में क्या-क्या नहीं आया। न शिक्षक हैं, न क्लास रूम्स हैं, न दरी है, न बस्ता है, न पैन है, न पेंसिल है। महात्मा गांधी जी को भी शर्म आ रही होगी कि ये मेरे नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान के इस बजट में आप देखें कि 2021-22 का एक्चुअल बजट आया। जब घोषणा की थी तो 2 लाख 50 हजार करोड़ का बजट था। यह बढ़कर 2 लाख 90 हजार करोड़ हो गया। यह किसमें बढ़ा? क्या विकास में बढ़ा है? नहीं, यह बजट साइज इसलिए बढ़ा, जो आज इन्होंने अभी 48 हजार करोड़ की और सहमति इस सदन से मुखबन्द करवाकर ली, जो पिछले साल के बजट में, यह इनका घाटा बढ़ा।

इन्होंने जो एक्स्ट्रा बोरोइंग की है, इन्होंने लिखा है, हम 61 हजार करोड़ बोरोइंग करेंगे। इन्होंने कितनी की, 1 लाख 1 हजार 363 करोड़, यानी 40 हजार करोड़ की बोरोइंग एक्स्ट्रा की 2021-22 में। सभापति महोदय, 2022-23 के आरई में इन्होंने माना कि हमारा जो बजट था, वह 3 लाख 46 हजार करोड़ का था और अब वह बढ़कर हो गया 3 लाख 82 हजार करोड़ का। यह बढ़ोतरी कैसे हो गयी? फिर इन्होंने जो लिया, 28 हजार करोड़ की बोरोइंग अब तक एक्स्ट्रा कर चुके हैं। ये आरई का फिगर बता रहे हैं। अभी जब एक्चुअल आयेगा तब मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यह फिगर 68 हजार करोड़ रुपये से ऊपर जायेगा।

सभापति महोदय, 40 हजार करोड़ रुपये ज्यादा लेकर, एफआरबीएम एक्ट तो पहले ही है, इस बार ये कहां से पूरा करेंगे? ये घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? एफआरबीएम एक्ट की लिमिट ये पहले ही क्रास कर चुके हैं। इनके पास ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं हैं। नया उधार जब मिलेगा नहीं तो राजस्थान की जनता, आप समझ सकते हैं, सभापति महोदय, आप भी सोच में पड़ गये होंगे कि क्या होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस बजट में ज्यादा तो नहीं, पर लगभग मैंने 157 बिन्दु पढ़े। मैं यहां पर मद पढ़ सकता हूं कि किसमें 7500 करोड़ था, किसमें 3 हजार करोड़ था, किसमें 1500 करोड़ था, किसमें 7 हजार करोड़ था, किसमें 20 हजार करोड़ था। ऐसा जब मैंने कुल जोड़ा तो, सभापति महोदय, मेरे नीचे से धरती खिसक गयी, आपका तो पता नहीं क्या, कोई समझेगा कि नहीं।

कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने मात्र 38 हजार करोड़ का रखा है। केवल 157 बिन्दुओं का जो मेरा जोड़ है, गोशालाओं/नन्दीशालाओं पर 1100 करोड़

(श्री अशोक लाहोटी)

रुपये, आपकी कोविड और स्टाम्प ड्यूटी पर 1750 करोड़ रुपये रिलैक्सेशन, यह 157 बिन्दुओं का जोड़ 1 लाख 49 हजार करोड़ आ रहा है। 1 लाख 49 हजार करोड़ की घोषणाएं कीं आपने इस सदन में। ईआरसीपी पर कर दी, जल जीवन मिशन में 11 हजार करोड़ की कर दी। आपने जो घोषणाएं की हैं, उसमें आपने सेंटर का शेयर भी मान लिया, ग्रांट भी मान ली, 1 लाख 49 हजार करोड़ के कामों की घोषणा कर दी और बजट है मात्र 38 हजार करोड़ का। मुख्य मंत्रीजी यह भी बताते कि इन्हें 2028 तक पूरी करूंगा। इन्होंने ठीक कहा था कि मैं 2028 की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पांच साल में पूरी करने की बात कर रहे हैं, ये एक साल में पूरी नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस सरकार की रिसीट्स क्या हैं? जब आपकी जेब में पैसे होंगे तभी तो आप काम पूरे करेंगे। जेब में नहीं है अठन्नी और आप खर्च करना चाह रहे हैं रुपया। उधार लेकर घी पीना चाहते हैं तो घी भी तो तब पीएंगे, जब मिलेगा। घी से बदहजमी तो होगी, लेकिन जब वह मिलेगा तब ही तो पीएंगे।

सभापति महोदय, स्वयं का राजस्व देखें। बीई में इन्होंने माना, 2021-22 में 90 हजार 49 करोड़ रुपये। जब एक्चुअल में आये तो इनके पास आये 74 हजार करोड़ रुपये। यानी मूल जितना मांगा था, उससे इनका 18 प्रतिशत कम रहा। सभापति महोदय, इसी प्रकार इन्होंने आरई में पिछले साल 2022-23 में यह माना कि हम राजस्व 98 हजार करोड़ रुपये लेकर आएंगे, आया मात्र 92 हजार करोड़ रुपये। फिर 6 परसेंट कम। यानी आपका ट्रेंड कम होता आ रहा है। यह आरई लिखा है आपने, एक्चुअल में तो बहुत कम हुआ है। मैं कह रहा हूं दिसम्बर तक अभी तक आप लाये हैं। अभी तक आपने इस बार 2023-24 में मान लिया, 23 प्रतिशत बढ़ाकर 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये हम राजस्व लाएंगे और उसके आधार पर आपने बजट बना दिया। सभापति महोदय, आप मन में कुछ भी सोचकर घोषणा यहां कर दें और आंकड़ों को जोड़-तोड़कर बजट बना लें, इससे आप राजस्थान की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको पहले भी 2013 में आईना दिखाया और 2023 में फिर दिखाएगी।

सभापति महोदय, सैंट्रल शेयर की जो ये बात कर रहे थे अभी, उसमें इन्होंने 2021-22 में 40 हजार करोड़ माना था, इन्हें 54 हजार करोड़ मिला, 35 प्रतिशत ज्यादा। इन्होंने 2022-23 में 49 हजार करोड़ माना, इन्हें 57 हजार करोड़ मिला, 16 प्रतिशत ज्यादा अभी तक इन्हें मिल चुका है। इस बार इन्होंने खुद ने माना है, पिछली बार से भी 12 हजार 341 करोड़ रुपये हमें

(श्री अशोक लाहोटी)

ज्यादा मिलेंगे, यानी 61 हजार 552 करोड़ रुपये मिलेंगे सेंटर के। आप एक शब्द धन्यवाद तो देते मोदी जी को। केवल और केवल आप मोदी जी दें, मोदी जी दें, मोदी जी दें, यह करते रहते हैं। मोदी जी दे रहे हैं, पर उसका धन्यवाद भी नहीं देंगे। थोड़ी बहुत तो शर्म करें। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जरूर धन्यवाद देंगे।

सभापति महोदय, सैंट्रल ग्रांट। 2022-23 की आरई में देखें। इन्होंने टोटल नेट माना कि हम 2 लाख 16 हजार करोड़ लाएंगे। लाये कितने दिसम्बर तक? 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये। यानी आप 83 हजार करोड़ रुपये इन तीन महीनों में ले आएंगे? आप तो आरई दे रहे हैं, दिसम्बर तक का फिगर मैं आपको दे रहा हूं। सभापति महोदय, राजस्थान को बेवकूफ बनाने का इन्होंने जो बजट में काम किया है, इसे राजस्थान की जनता समझती है। आज जीएसटी देखें, 27 प्रतिशत कम, 9 प्रतिशत कम और आप मान रहे हैं कि आप 36 प्रतिशत ज्यादा ले आएंगे, इस बार 48 हजार करोड़ ले आएंगे। कैसे ले आएंगे?

सभापति महोदय, सेल्स टैक्स, जो बड़ा हैड है, आपने 2021-22 में 22 हजार करोड़ माना, आप 2800 करोड़ कम लाये, दस परसेंट कम लाये। 2022-23 में आपने 25 हजार करोड़ माने और आप 23 हजार करोड़ ही ला पाये। फिर आप 6 परसेंट कम लाये। इस बार आप कह रहे हैं, हम 16 परसेंट ज्यादा ले आएंगे। केवल कपोल कल्पित आंकड़े लिखकर बजट बनाना ताकि हम केवल घोषणा कर सकें।

सभापति महोदय, एक्साइज। आप लगातार एक्साइज में, कल सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक्साइज चोरी का बता रहे थे, लम्बी-चौड़ी यहां बहस हुई, इन सब चोरियों के बावजूद भी आप यह देखें कि आपको 13 हजार 250 करोड़ लाना था, 11 हजार करोड़ लाये, 11 प्रतिशत कम। पिछले साल भी 3 परसेंट कम। इस बार आप कह रहे हैं कि हम 17 प्रतिशत बढ़ाकर 17 हजार करोड़ रुपये ले आएंगे।

सभापति महोदय, स्टाम्प ड्यूटी में छूट के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम दस प्रतिशत ज्यादा लाएंगे। या तो वह छूट असत्य है या आप ज्यादा लाएंगे नहीं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में देखें, आप इतनी छूट दे रहे हैं और फिर यह भी कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़कर आयेगा 8 परसेंट। सभापति महोदय, इनके आंकड़े कुछ कह रहे हैं और घोषणाएं कुछ कह रही हैं। या तो ये

(श्री अशोक लाहोटी)

आंकड़े असत्य हैं या ये घोषणाएं असत्य हैं। तय आपको करना है कि क्या असत्य है? यदि आंकड़े सच हैं तो घोषणाएं किसी भी हालत में पूरी नहीं होंगी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें। यही हमारा मूल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बिना बाकी सब चीजें बेकार हैं। आपने रेवेन्यू में कितना दिया, आपने तनख्वाह कितनी दी, ब्याज कितना दिया, उसमें आप कितना ही बढ़ा लें, कितना हैल्थ में बजट बढ़ाया, बजट नहीं बढ़ा, आपका ब्याज बढ़ा है, आपकी तनख्वाह बढ़ी है। आप देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका। 2021-22 में आपने माना था कि हम राजस्थान की जनता के विकास के लिए सड़क, नल, बिजली, पानी, इन पर 26 हजार करोड़ खर्च करेंगे। आपने किया कितना? मात्र 24 हजार करोड़ रुपये। 2022-23 में तो आश्चर्यजनक रूप से आपने कहा कि हम 34 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आपने खुद ही घोषणा कर दी कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम 29 हजार करोड़ ही करेंगे, यानी आपने 16 परसेंट कम कर दिया। एक्चुअल में आप दिसम्बर तक का देखो तो आपने मात्र खर्च ही 38 प्रतिशत 13,802 करोड़ रुपये किये हैं।

सभापति महोदय, यदि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का यह हाल है तो मैं समझता हूं कि शायद राजस्थान की जनता कांग्रेस के बारे में ठीक सोचती है कि ये तो केवल घोषणाएं हैं और थोथी घोषणाएं हैं क्योंकि जब आपने खर्च ही नहीं किया, अभी तक पूरे साल में मात्र 38 प्रतिशत खर्चा किया है और इस साल आप कह रहे हो कि हम 38 हजार करोड़ खर्च कर देंगे। जब पिछले साल दिसम्बर तक आपने खर्च ही 13 हजार करोड़ किये हैं तो इस साल 6 महीने में 38 हजार करोड़ कर दोगे?

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह 31 प्रतिशत ज्यादा केवल आपने लिखा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है। आपका पहले भी 10 हजार करोड़ बढ़ा, फिर बीई में 20 हजार करोड़ बढ़ा यानी आपका ब्याज बढ़ रहा है, आपकी पेंशन बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है और आप खर्चा नहीं बढ़ा रहे हो। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर रहे हो, विकास का पैसा नहीं बढ़ा रहे हो और आप केवल और केवल अपनी मजबूरी का पैसा बढ़ा रहे हो।

मैं कह रहा हूं कि अभी ओपीएस की बात हुई आपने घोषणा की 40 हजार करोड़ रुपये की और घोषणा किये हुए डेढ़ साल हो गये। किसने हाथ

(श्री अशोक लाहोटी)

पकड़ा? किसने आपको रोका? आप पैसा दो। आपके पास जेब में चवन्नी नहीं है और आप घोषणा कर रहे हो कि हम 40 हजार करोड़ की छूट देंगे। आप दो न, हम आपका समर्थन करेंगे, दो आप। पैसा भी नहीं देंगे और घोषणा भी करेंगे और फिर कहेंगे कि, मोदी जी, आप पैसा दे दो, तो मोदी जी पैसा तब देंगे जब डबल इंजन की सरकार होगी और तब इस राजस्थान में हम भी घोषणा करेंगे। इसकी चिंता मत करो, छह महीने और रुक जाओ।

सभापति महोदय, हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर पर हमारे मित्र अभी बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे। आपने क्या किया? आपने पिछली बार के बजट में 2111 रखा और इस बार आपने बजट 20 हजार करोड़ से कम कर दिया। आप कह रहे हैं, बीई में आपने बढ़ाया है, लेकिन आरई में आपने कम किया है, आरई में कम करने के बाद आप कह रहे हैं कि आपने बजट बढ़ा दिया। कौन-सा बढ़ा दिया आपने? 2 हजार करोड़ का आपने आरई में बजट कम किया है पिछले वर्ष में और इस साल आपको तो लिखना ही था, तो आप कितना ही लिख दो। आप 40 हजार करोड़ लिख दो, कौन मना कर रहा है? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे देखें आप। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, 2021-22 में 1667 करोड़ मात्र, आपको केवल इतना ही खर्च करना था और उसमें से आपने खर्च किया, कोविड भी नहीं था, मात्र 627 करोड़ रुपये, 37 परसेंट। पिछले साल आपको 1881 करोड़ खर्च करना था, वह भी पूरा नहीं किया।

इस बार आपने केवल और केवल बजट ही कम करके 15 परसेंट, एजुकेशन में इतनी स्कूल्स खोलेंगे, इतना यह बनाएंगे, इतने कमरे बनाएंगे, माननीय कल्ला साहब, आपको इंगित करके बता रहा हूं कि 1900 करोड़ ही रखा है आपका बजट मात्र। कहां कमरे बने, कम हो गये कमरे। जो बने हुए हैं उनकी रिपेयरिंग का, रंगाई-पुताई का भी पैसा पूरा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल असत्य घोषणाएं करने से नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। उसका बजट आप देखें। अभी आप कह रहे थे कि हमने इतना बजट रख दिया। आपने 2021-22 में 6314 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करना था। आप तनख्वाह, ब्याज छोड़ दें। आपने खर्च कितना किया, केवल 4900 करोड़ रुपये। आपकी मूल रकम से 22 प्रतिशत कम। आप खर्च ही नहीं कर पाये केन्द्र के पैसा देने के बावजूद भी।

सभापति महोदय, पिछले साल आपने खुद इसी बजट में घोषणा की

(श्री अशोक लाहोटी)

है, पिछले साल तो आश्चर्य ही हो गया 6723 करोड़ खर्च करने थे। पानी के ये न तो काम कर पाये, न कुछ और कर पाये। खर्च कितना किया? मात्र 2564 करोड़ रुपये आरई में लिखे हैं इन्होंने। मैं एक्चुअल पर नहीं जा रहा, 62 प्रतिशत कम। आपने आरई में खुद ने लिखा है। इस साल आप कह रहे हैं, हम 5200 करोड़ रुपये खर्च कर देंगे। सभापति महोदय, असत्य के भी कोई सींग-पूंछ होते होंगे, कोई पांव होते होंगे। बिना सींग-पूंछ-पांव, इतना बड़ा असत्य। आपने कुल घोषणा कितनी कर दी? मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपके बजट के पेज नं. 77 और 78 में पाइंट नं. 106 से 111 में आपने घोषणा कितनी कर दी? सभापति महोदय, सबसे बड़ा आश्चर्य, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करने का रख रहे हैं 5284 करोड़ रुपये। चलिये, मैं एक मिनट के लिए मान लूं कि आप 5200 करोड़ पूरे खर्च कर देंगे, लेकिन आपने घोषणा कितनी की है?

मैं पाइंट संख्या बता रहा हूं- 106, 107, 108, 109, 110, 111, इन्हें अभी आप जोड़ लें। इनकी संख्या है 15 हजार 548 करोड़ रुपये। यानी आप बजट ही 5 हजार करोड़ का रख रहे हैं और सदन में घोषणा 15 हजार करोड़ की कर रहे हैं। ये 10 हजार करोड़ क्या आपके काकाजी देंगे? ये 10 हजार करोड़ आप लाये कहां से? आपने अकाउंट में कैसे लिख दिया?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): दो-तीन दिन में पैसा खर्च हो जाता है क्या?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तो इसमें लिखें न पंचवर्षीय योजना है। बजट एक साल का दे रहे हैं। लिखें पंचवर्षीय योजना है 2028 तक की।

सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार आपने ईआरसीपी में लिख दिया 13 हजार करोड़ रुपये, और आप देखें घोषणा क्या की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, ईआरसीपी 2051 तक पूरी होगी। मैंने पंचवर्षीय योजना सुनी थी, एनुअल बजट सुना है, देखा है, पढ़ रहा हूं, लेकिन 28 वर्षीय योजना, 2023 में घोषणा कर रहे हैं, 2051 में पूरी होगी। 28 वर्षीय योजना मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। सभापति महोदय न तो मैंने पढ़ा और न ही सुना। सभापति महोदय, आप यह देखें, 2051 की घोषणा इस सदन में कर रहे हैं।

श्री सभापति: अब आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मेरा समय है अभी। इन्होंने 48 मिनट बोला है। इनका भी 30 मिनट ही था आप देख लें। ऐसा

(श्री अशोक लाहोटी)

नहीं होता। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं बजट के इधर उधर जाऊं तो आप बैठा देना। सभापति महोदय, वेलफेयर आफ एससी, एसटी एण्ड ओबीसी....

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बहुत बड़ी-बड़ी बात की, 500 करोड़ की घोषणा कर दी, 200 करोड़, 100 करोड़, घोषणा ही तो की है आपने, आप आईना तो एक बार देख लो। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यदि बैठे हैं तो आप सब लोग सुनें। 2021-22 में डवलपमेंट के लिए केवल और केवल सरकार ने 2 लाख 90 हजार करोड़ में केवल 255 करोड़ रुपये ही रखे थे और उसमें से खर्च कितना किया? 187 करोड़ रुपये, 26 प्रतिशत कम। इस बार तो आपने और भी कम कर दिया। इस बार तो आपने बजट ही 3101 करोड़ कर दिया। आपने पिछले बजट से बजट कम करके 3101 करोड़ कर दिया यानी आपके 3 लाख 90 हजार करोड़ का एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मात्र एक प्रतिशत बजट भी नहीं है, 0.79 प्रतिशत बजट है और उसमें भी ब्याज, तनख्वाह, पेंशन सब है।

सभापति महोदय, इस प्रकार सरकार लेबर वेलफेयर की बात करती है तो उसमें आपको आंकड़े देखकर शर्म आ जाएगी। लेबर वेलफेयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में यह मद लगातार जीरो है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एक रुपया रख दें, कम से कम मजदूरों के सम्मान में 10 करोड़ ही लिख देते, 5 करोड़ लिख देते पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जीरो है। यह लेबर वेलफेयर कर रहे हैं आप राजस्थान के मजदूरों के साथ और बड़ी-बड़ी बात कर रहे हो कि हमारी पार्टी मजदूरों की पार्टी है। यह मजदूरों की आपकी पार्टी है? जीरो पैसा आपके बजट में लिखा है। केवल और केवल आपने 1702 करोड़ रुपये रेवेन्यू ब्याज और पेंशन का लिखा है।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दो-तीन मदें और हैं, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप मेरे अगले स्पीकर का टाइम ले लेना।

श्री सभापति: श्री अनिल कुमार शर्मा। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन की बहुत बड़ीबड़ी बात की गई।

श्री सभापति: एक मिनट में कर लीजिये आप। करिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन की बात की, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया है केवल चार करोड़ रुपये 2021-22 में और 2022-23 में केवल 40 करोड़ रुपये, इस साल केवल 97 करोड़ रुपये। यह आपका हाल है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और भी कई मदें हैं लेकिन उनको छोड़ो आप। रोड और ब्रिज का आपको एक मिनट में बता दूं कि रोड और ब्रिज की बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुईं। सभापति महोदय, टोटल बजट रखा 10 हजार 556 करोड़ रुपये और इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर था 5400 करोड़ रुपये, रोड बनाने का खर्चा। मैं पाइंट संख्या बता रहा हूं, पेज 53, 70, 71, 72 में पाइंट 93 से 97 में आप देखो कि बजट 5400 करोड़ का है और घोषणा इस सदन में 14 हजार 471 करोड़ की है। वाह, क्या बात है! घोषणाएं 14 हजार करोड़ की हैं और 6 महीने में पूरा कराओगे।

श्री सभापति: श्री अनिल कुमार शर्मा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एफआरबीएम एक्ट की बात हुई ये घोषणाएं इसलिए पूरी नहीं हो सकतीं कि आपका एफआरबीएम एक्ट आपको कर्जा लेने की परमिशन नहीं देता, सभापति महोदय।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। थैंक यू। आप बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, दो मिनट में।

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: आपका रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) बैठिये-बैठिये।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत आयव्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुतबहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस बजट में सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी सौगात दी है।

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री एवं जन नायक माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कंक्लूड करने दें, दो मिनट दे दें। एक मिनट विराजिए।

श्री सभापति: आपके टाइम में से कम होगा। माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, आपके समय में से कम करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, हो जायेगा। एक मिनट विराजिए।

श्री सभापति: आप जो कहना चाहते थे, वह सारा हो गया है। आप बोलिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): गत चार साल में प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है। जन सेवा को समर्पित इस बजट में हमारी लोकप्रिय सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, बुनियादी विकास, राज्य कर्मचारी कल्याण, ऊर्जा एवं उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को बहुत-बहुत बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। विकास का यह क्रम निरन्तर जारी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकास के सभी पैमानों पर अव्वल रहेगा।

राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिन्ता हमारी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह निरन्तर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि महंगाई के इस जमाने में आम आदमी को बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च की चिन्ता से मुक्त कर दे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त दवा एवं जांच की सुविधा भी प्रदान की है। इसी क्रम में, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप द्वारा सरदारशहर कस्बे में मेरे पूज्य पिताजी एवं दिवंगत विधायक पंडित भंवरलालजी शर्मा के नाम से राजकीय उप जिला चिकित्सालय बनाया गया है। इस अस्पताल का भवन 50 साल से भी पुराना है और जर्जर हो चुका है। साथ ही, कस्बे के बाजार से होते हुए कोई इमरजेंसी की स्थिति में चाहे एक्सीडेंट हो या अन्य कोई आपातकाल हो तो आवागमन में बहुत असुविधा होती है और हास्पिटल की जगह भी बहुत छोटी है। इसलिए मैं

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमने उप जिला अस्पताल के लिए जगह भी चिन्हित कर ली है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि उप जिला चिकित्सालय के लिए शीघ्रातिशीघ्र बजट आबंटित करे।

साथ ही, मैं सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जैतासर, मालसर, खेजड़ा एवं भादासर दिखनादा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करने के सन्दर्भ में, मैं मांग करना चाहूंगा ग्राम गोलसर, भानीपुरा और नये उप स्वास्थ्य केन्द्र आसासर, मांगासर, कुसुमदेसर, राजासर चौड़िया, पातलीसर पुरोहितान, पनपालिया, उदासर चारणान, खुण्डिया और बणियासर।

माननीय सभापति महोदय, उप जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर स्वीकृत करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान करायें। इस ट्रोमा सेंटर के भवन के लिए भामाशाह के सहयोग से भवन भी तैयार करवा लिया जायेगा।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में भी नये कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इसी क्रम में मेरा यह निवेदन है कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र एक तरफ बिजली के क्षेत्र में पूरा चूरू जिला और एक तरफ सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र, लोड की दृष्टि से अधिकतर लोड सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में है। आज ही मैंने एसई से आंकड़ा मंगवाया है, 7128 नये कृषि कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।

अभी सरदारशहर का उप चुनाव था, तब माननीय मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी पधारे थे। उनके सामने वस्तुस्थिति है। किसानों द्वारा आये दिन धरने प्रदर्शन किये जा रहे हैं और ये कनेक्शन होने के बाद आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति गम्भीर होने की सम्भावना कम है। इसलिए, मैं सरकार से मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि ग्राम पातलीसर के 132 केवी जीएसएस को 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें। साथ ही ग्राम दल्लुसर एवं घड़सीसर में 132 केवी के नये जीएसएस की स्वीकृति भी प्रदान करायें।

साथ ही हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन है कि सरदारशहर तहसील के लगभग 58 गांवों के रकबों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के सिंचाई के पानी से वंचित कर रखा था,

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

अब इन गांवों के रकबों को पुन: जोड़ने की मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को संजीवनी मिल सके। इसके लिए क्षेत्र के किसान आपके बहुत आभारी रहेंगे।

हमारी लोकप्रिय सरकार ने सड़कों के विकास में भी नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं, जिनमें नवीन सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, राज्य राजमार्गों का विकास, ग्रामीण सड़कों का विकास, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, पक्की सड़क निर्माण इत्यादि शामिल हैं। इसी क्रम में, मैं सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रणसीसर से राजासर पंवारान तक, मालासर से मेलूसर पुरोहितान तक, गोलसर से मेगा हाईवे वाया नांगला जोहड़ तक, गिड़गिचिया से हरियासर घड़सोतान तक, दुलरासर से कल्याणपुरा तक, राजासर बीकान से चारणवासी तक, अमरसर से बैजासर तक, अजीतसर से सारसर तक, उदासर चारणान से मेहरासर चाचेरा तक, कंवलासर से कीकासर तक, आसलसर से देराजसर तक, अमरसर से पाटमदेसर तक, हालासर से मालसर तक, ढाणी राणासर से देवासर तक पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की मांग करता हूं।

इसी क्रम में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न राजकीय सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में समस्त रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाये। कारण यह है कि पद रिक्त रहने से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पिछले बजट में सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भानीपुरा में नई तहसील बनाई गई है। मैं इसमें नवीन कृषि मण्डी स्वीकृत किये जाने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): साथ ही सरदारशहर में नवीन उप परिवहन कार्यालय की बजट में घोषणा की गई है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सरदारशहर कस्बे की वर्तमान में आबादी लगभग सवा से डेढ़ लाख के बीच है और सदर थाने की मैं मांग करता हूं।

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

माननीय सभापति जी, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रसिद्ध भामाशाह मूलचन्दजी मालू के पुत्र विकास मालू द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल, अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त पुलिस थाना भवन बनाया जा रहा है। यह सिर्फ चूरू जिले या राजस्थान में ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश में इस तरह का पुलिस थाना नहीं होगा।

निश्चित रूप से, महीने, दो महीने में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उद्घाटन करवायेंगे। इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि सरदारशहर में सदर थाना खोला जाए।

साथ ही, सरदारशहर में नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि सरदारशहर से कम आबादी की नगरपालिकाओं को भी आपने नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया है। इसलिए मेरी मांग है कि सरदारशहर की आबादी को देखते हुए नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार।

श्री सभापति: थैंक यू। मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित सचेतक महोदय ने जो भी समय निश्चित किया है, वह आसन के सामने रखा हुआ है। पांच मिनट भी है, दस मिनट भी है, ज्यादातर का पांच मिनट है। पांच मिनट होने की स्थिति में, एक मिनट पहले मैं बोल दूंगा कि आप अपना कंक्लूड कर लीजिए। समय के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। थैंक यू। श्री हरेन्द्र निनामा जी।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल ही नहीं बल्कि पूरा उदयपुर सम्भाग आदिवासी इलाका है, जो घोषणाएं की गई हैं, वर्तमान में भी की गई हैं, पूर्व में भी की गई हैं, लेकिन धरातल स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है।

मेरे साथी बन्धु लाहोटीजी ने अभी जो आंकड़े बताये हैं, राजस्थान के हर विभाग के आंकड़े बताये हैं। मैं लाहोटीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इसलिए मैं उन आंकड़ों की तरफ नहीं जाता हूं। लाहोटीजी ने पूरे बजट का जिक्र इस सदन के माध्यम से कर दिया है।

(श्री हरेन्द्र निनामा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा घाटोल विधान सभा क्षेत्र आदिवासी इलाका है, मैंने उपखण्ड स्तर पर एक सरकारी महाविद्यालय खोलने की बात बार-बार कही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको दरकिनार करते हुए घाटोल में महाविद्यालय खोलेने का नाम तक नहीं लिया। इसलिए मैं उनका जोरदार विरोध भी कर रहा हूं।

मेरे साथियों द्वारा यह बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि गाय माता के नाम से वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी करते हैं। हम तो करते आये हैं, हमारा संगठन आगे भी करता रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं मांग करता हूं कि हमारे बांसवाड़ा जिले में माही डैम उदयपुर सम्भाग का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, नहरों की हालत खस्ता है। पूर्व में हमारी सरकार थी उस समय एलएमसी और आरएमसी दोनों कैनालों का पेवर पद्धति के माध्यम से, उन दोनों ही माइनरों की मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो छोटी माइनरें पड़ी हुई हैं उनमें इस बजट के अन्दर कहीं प्रावधान नहीं किया है।

बांसवाड़ा जिले में आदिवासी जो माही के विस्थापित लोग हैं वो कुवानियां गांव में चालीस साल से पड़े हुए हैं उनके लिए कोई जमीन अलाट नहीं की गयी। कडाना के लोग विस्थापित पड़े हुए हैं उनके लिए जमीन अलाट नहीं की गयी। मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार से एक विशेष अभियान चालू करके आदिवासी इलाके के अन्दर जमीनों का आबंटन करने का प्रावधान इस बजट में करने का मेरा आग्रह है।

मेरा एक और निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, उदयपुर सम्भाग में आदिवासी अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने की मांग के लिए लम्बे समय से विभिन्न संगठनों के माध्यम से ज्ञापन हमको भी मिल रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी मिल रहे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाये, लेकिन इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया। यह भी मेरा आपसे निवेदन है।

मेरा निवेदन है कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में घाटोल, गंदोड़ा, खमेरा, नरवाली, घंटाली, प्रतिपुरा, पीपलखूंट में डाक्टर, नर्स के पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, साथ ही मेरा निवेदन है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें। In one minute only, Please.

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): साहब, मैं तो एक मिनट ही बोला हूं अभी। नॉन कमाण्ड क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र में लिफ्ट परियोजना के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, एनिकटों के माध्यम से किसानों को पानी देने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, बिजली विभाग के बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान के किसानों को बिजली बीस घंटे देने की मांग करता हूं। आज किसान परेशान हैं। रात को बिजली दी जा रही है। किसानों की हत्याएं हो रही हैं। किसानों के जानवर काट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिजली विभाग में की गई यह कार्मिक ठेका प्रथा खतम करके नये सिरे से सरकारी नौकरी उनको दी जाये और पूर्णतया बिजली विभाग के कार्मिकों को पूरी व्यवस्था दी जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि परिवहन विभाग, बांसवाड़ा में 2013 के बाद में आज तक कोई बजट का प्रावधान नहीं होने की वजह से वहां बसों के संचालन में काफी दिक्कत हो रही है। यात्रियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बसें खरीदी नहीं जा रही हैं। इसलिये मेरी मांग है कि वहां पर बजट का प्रावधान किया जाये।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही, सभी माननीय सदस्यों को अभिवादन करती हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब को सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म को ध्येय मान कर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट पेश करने पर बधाई देना चाहती हूं।

प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लाने और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के हर तबके चाहे वृद्ध, युवा, किसान, अमीर, महिला, गरीब, सभी वर्गों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां इतनी सुव्यवस्थित चिकित्सा योजनाएं धरातल पर संचालित हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार कर दिखाया है।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में गरीब को गणेश मान कर एक करोड़ परिवारों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिये जाने की भी घोषणा की है, जिसके लिए मैं सभी पात्र परिवारों की ओर से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

बजट 2023-24 में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गई है, जैसे बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर दिया जायेगा। घरेलू कनेक्शनों पर सौ यूनिट प्रति माह नि:शुल्क बिजली दी जायेगी। युवाओं को चार साल में 1 लाख 42 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 81 हजार से अधिक प्रक्रियाधीन हैं।

निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया जायेगा। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा एक से बारह तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि दस लाख से बढ़ा कर पच्चीस लाख रुपये तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि पांच लाख रुपये से बढ़ा कर दस लाख रुपये कर दी गई है और आगामी वर्ष में लगभग तीस हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी की जायेगी।

समस्त विधान सभा क्षेत्रों में दस करोड़ रुपये की लागत से नोन-पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में किसान भाई प्रति माह दो हजार यूनिट तक बिजली का नि:शुल्क उपयोग कर सकेंगे। लम्पी में पशुधन हानि पर प्रति पशु चालीस हजार रुपये और कोरोना के समय अनाथ हुए बच्चों को 18 साल पूर्ण होने पर सरकारी नौकरियां भी दी जायेंगी।

वर्षों से चली आ रही ठेका प्रथा को समाप्त किया जायेंगा। सभी भर्ती परीक्षा में आवेदन नि:शुल्क, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। महिलाओं को रोडवेज बस के किराये के लिए पचास प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है और निगम/बोर्ड/कॉरपोरेशन और अन्य कर्मचारियों को ओल्ड पेन्शन स्कीम के साथ ही और अन्य योजनाओं और जन-कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं भी की गई हैं।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

यही बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं, 'जो कल्याण के कारक थे, वे बोल सुहाने बोल दिये, इस बजट ने जनता के हित सब दरवाजे खोल दिये। आभार आपका राजस्थान को मान और सम्मान दिया, हर गरीब और मध्यम वर्ग की कठिनाई पर ध्यान दिया। सबका मन है हर्षित और हर गली-गली मुस्कुरायी है, इस प्रदेश के लोगों के चेहरों पर खुशियां छायी हैं।'

मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में सबसे ज्यादा युवाओं और शिक्षा को महत्व दिया है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, आपके भविष्य का मैं ध्यान रखूंगा। पहली बार किसी सरकार के कार्यकाल में इतने कालेज और स्कूल खुले हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है। बजट में विशेषतया युवाओं के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं जिससे युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल क्षमता विकास एवं व्यक्तित्व संवर्द्धन हेतु सहायता प्राप्त होगी।

राजस्थान में पहली बार युवा नीति प्रस्तावित कर पांच सौ करोड़ रुपये से युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन भी किया गया है। युवाओं को अपना स्टार्टअप स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहन करने एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने उदयपुर और विशेषकर वल्लभनगर विधान सभा के आम जनों के हितार्थ जो सौगातें दी हैं, इस अवसर पर मैं उन्हें मेरी तरफ से और वल्लभनगर विधान सभा परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

उदयपुर जिले के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्रमुखतया युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर के साइंस पार्क सेन्टर का विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज सम्पदा आदि का नवीन गैलेरीज और प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जायेगा।

साथ ही, आरएनटी मेडिकल कालेज में मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की गई है और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स और अन्य घोषणाएं भी शामिल हैं।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो गजेन्द्र सिंह जी शक्तावत साहब के सपनों को पूरा करते हुए आपने हमारी सभी मांगें पूरी कर दी हैं। मैं सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर परिवार की तरफ से आपका अभिनन्दन करती हूं।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विशेष तौर पर धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने वल्लभनगर में राजकीय महाविद्यालय, भटेवर में आईटीआई कालेज, कानोड में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास, भीण्डर से बलीचा वाया आकोला की 22 किलोमीटर की सड़क, कानोड़ से लसाड़िया 13 किलोमीटर की सड़क और ईडाना से फिला सड़क चौड़ाईकरण 6 किलोमीटर, भटेवर व वाना में पशु केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया है। साथ ही, चैनपुरिया सुखाड़िया, ब्राह्मणों का रोबा, आम्बा तलाई गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से भी जोड़ा जायेगा।

इतनी घोषणाओं के बाद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा राज्य में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है बल्कि आगामी वर्ष हेतु 1,750 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की जा रही है। केन्द्र सरकार से पर्याप्त मदद नहीं मिलने के बावजूद भी हम जन कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि ही कर रहे हैं।

किसी ने सही कहा है 'इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है।' विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में तीन राजकीय कालेज खुलने से युवाओं व क्षेत्रवासियों में अति उत्साह का माहौल है। अब वल्लभनगर के छात्र-छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के दौरे के दौरान कुछ छात्र-छात्राएं मुझसे मिलीं और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देने के लिए कहा क्योंकि 12वीं के पश्चात् माता-पिता का यह रहता था कि बच्चियों की पढ़ाई अब आगे नहीं हो सकती, उन्हें बाहर नहीं भेजा जा सकता, तो उनकी शादी का विचार किया जाता था और उनकी शिक्षा रुक जाती थी। आज वही बालिकाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रही हैं कि अब वह आगे उच्च शिक्षा के लिए विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगी। साथ ही विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में दो आईटीआई भी हो गये हैं। इससे बच्चे तकनीकी तौर से दक्ष होकर रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर अभूतपूर्व नवाचार और नये आयाम को स्थापित किया है, ताकि कोई भी गरीब परिवार का बच्चा अंग्रेजी शिक्षा से वंचित नहीं रह सके।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के प्रतिभावान क्रीड़ा पदक विजेताओं को भी आउट आफ टर्न नियुक्ति प्रदान कर अभूतपूर्व कार्य किया गया है। इससे न सिर्फ खेलों के प्रति रुझान बढ़ा अपितु खिलाड़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुछ घोषणाएं की जानी अभी भी अति-आवश्यक हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर का परिक्षेत्र काफी बड़ा है, इसलिए इसे जिला बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कस्बा वल्लभनगर को नगरपालिका, जगत एवं मीठानीम में नवीन पुलिस चौकी, उप स्वास्थ्य केन्द्र नवाणिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगत को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत। साथ ही भीण्डर में अतिरिक्त जिला न्यायालय, भीण्डर में नर्सिंग कालेज और गणोली से वल्लभनगर, 6 किलोमीटर सड़क का रिन्युअल तथा कुराबड़ में उप-खण्ड कार्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है, जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये। पंचायत भवन वल्लभनगर और तहसील भवन कानोड़ के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति अभी भी बकाया है, इसे शीघ्र जारी किया जाये। साथ ही फसल खराबा होने पर किसान भाइयों को अतिशीघ्र मुआवजा देकर राहत प्रदान की जाये।

सभापति महोदय, हम सब विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के परिवारजन आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल को कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व का भली भांति निर्वहन किया, जिससे राज्य में हर्ष का माहौल है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गोपी चन्द जी मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मुझे बजट वर्ष 2023-24 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुतबहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले के आमजन के लिए इस बजट में कुछ विशेष नहीं दिया गया है। पूर्व के चार साल की बजट घोषणाओं के कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ घोषणा की जाती है, चुनावी वर्ष है, घोषणा कागजों में ही रहेंगी।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

सभापति महोदय, मैं किसानों की बात करता हूं, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र और प्रदेश में रैबारी और देवासी समाज के लोग ऊंट-ऊंटनी पालन का काम करते हैं। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया हुआ है। पूर्ववर्ती वसुन्धरा जी की सरकार द्वारा उनके आर्थिक संबल के लिए ऊंट-ऊंटनी पालन में अनुदान राशि दी जाती थी। इस सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की योजना को बंद कर दिया गया है। यह किसानों के साथ धोखा किया गया है।

(समय: 14.14 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मेरी मांग है कि रैबारी और देवासी समाज गरीब परिवार हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ऊंट-ऊंटनी पालन के लिए पुन: आर्थिक अनुदान चालू किया जाये।

यह मेरे जहाजपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या है कि खेत में काम करते हुए दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है, उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल नहीं किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि इसमें किसान का क्या दोष है? हम सब किसान हितैषी होने की बात करते हैं। किसान को चिरंजीवी योजना में लाभ दिलाने की मैं मांग करता हूं।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा की बात करता हूं। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में सी एच सी जहाजपुर को सरकार ने आदर्श सी एच सी घोषित किया है। वहां 22 पदों में से 18 पद रिक्त हैं। आप बात करते हो कि हमारी जन हितैषी सरकार है। मंत्री महोदय बैठे हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में पी एच सी और सी एच सी में डाक्टर के रिक्त पद भरे जाएं। हमारी पूर्ववर्ती वसुन्धरा जी की सरकार द्वारा पारोली सी एच सी का चार साल से भवन कम्प्लीट है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से उस भवन को उसमें स्थापित नहीं किया जा रहा है और भवन को चालू नहीं किया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से उसको उस भवन में शिफ्ट कराया जाये, ताकि हमारे लोगों को लाभ मिल सके।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में सी एच सी जहाजपुर बड़ा अस्पताल है और वह जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरा निवेदन है 148 डी नेशनल हाई-वे बीच से निकला हुआ है। वहां दुर्घटना होती रहती है, वहां आने-जाने में बहुत समस्या रहती है। जहाजपुर में ब्लड बैंक की स्थापना करने

(श्री गोपी चन्द मीणा)

की मैं मांग करता हूं। मैं ट्रोमा सेंटर खोलने की मांग करता हूं और जहाजपुर सी एच सी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की मांग करता हूं। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुहारीकलां शक्करगढ़, शोयपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। एनएच 52 के पास एक बड़ा गांव है, जिसमें सब-सेंटर है, सब-सेंटर ग्राम टिक्कड को, ग्राम अंबरगढ़, गंदेर, कुराडिया, बरोदा, धोड़, लुहारी, लसाड़िया, बड़ला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में उप खण्ड स्तर पर इंडोर एवं आउटडोर खेल स्टेडियम खोलने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उप खण्ड स्तर पर कालेज खोला जायेगा। मैं कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार बात कर रही है कि जनजाति के हित में हम काम कर रहे हैं। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में जनजाति बहुल के ऐसे बड़ेबड़े गांव हैं, ग्राम बांकरा, लुहारीकलां, इटुंडा, सरसिया में जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। एकलव्य मॉडल स्कूल जो भारत सरकार के द्वारा खोला जाता है, जहाजपुर में आबादी के अनुसार एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की भी मांग करता हूं। ग्राम पंचायत गुढ्‌ढा और पीपलून में भूमि भी आरक्षित कर दी गई है। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री सभापति: श्रीमती निर्मला सहरिया। विराजिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर एक्सईएन...

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट वर्ष 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट बहुत ही सराहनीय है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनजाति छात्रावास खोलने की मांग करती हूं। बीलखेडा, डांग और महुदरा में जीएस खोलने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। शाहबाद एवं नाहरगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए जो राशि दी, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी एच सी खोलने के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष उन मांगों को रखना चाहती हूं। मैं शाहबाद में ट्रोमा सेंटर खोलने की मांग करती हूं। केलवाड़ा में उप चिकित्सालय की घोषणा करें। नाहरगढ़ में बेड की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाये। मेरी अगली मांग एनिकट की है। एनिकटों की मरम्मत के लिए बजट दिया जाये। समरानिया, धंसूरी, पंचमहादेव, मिसाइल, पीपल्दा, इन एनिकटों की मरम्मत के लिए बजट दिया जाये। सोडाना, रेवारपुरा, पीपल्दा, छिनोद, रामपुरिया, बालाखेड़ा को बढ़ावा दिया जाये। बाढ़ बचाओ हेतु सुरक्षा, सुरक्षा दीवार, बम्बौरी रोड, बड़ौदिया के सामने पुल का निर्माण करवाया जाये। कैलवाड़ा को नगरपालिका बनाने की घोषणा की जाये। नाहरगढ़ को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत किया जाये। शाहबाद मुख्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रावास एवं शाहबाद क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की जाये। मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि शाहबाद को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की जाये। नाहरगढ़ में कन्या महाविद्यालय और शाहबाद में कन्या महाविद्यालय खोला जाये क्योंकि सहरिया परिवार एवं जाति की जो लड़कियां हैं, उनको 10वीं एवं 12वीं तक की पढ़ाई कराकर उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि नाहरगढ़ और शाहबाद में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में राड़ी बांध निर्माण के कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करें। मुख्यालय शाहबाद में पुराने बस स्टैण्ड से रियासतकालीन रास्ते का निर्माण एवं शाहबाद में कुण्डा खोह में नीचे की सीढ़ियों का निर्माण कराया जाये।

साथ ही, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने यह बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि गरीबों को देखते हुए, पहले सहरिया परिवारों को ही राशन में घी, तेल, दाल दी जाती थी, अब सभी वर्गों जिनको राशन दिया जायेगा, उनको भी शक्कर, दाल, तेल, नमक आदि की सामग्री दी जायेगी।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में लाइट के लिए कहा है। सामने वाले बार-बार लाइट के लिए कह रहे हैं। मैं जिस इलाके से आती हूं, किशनगंज-शाहबाद है, वहां पर जो लोग बिल तक जमा नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैं मेरे क्षेत्र की ओर से उनको बहुत तहेदिल से धन्यवाद देना चाहती हूं।

शिक्षा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है, बच्चों के लिए फीस जमा कराना मां-बाप के लिए भारी पड़ता था, मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा को देखते हुए बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है, उसके लिए भी मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहेदिल से धन्यवाद। जय हिन्द।

(माननीय सदस्य श्रीमती निर्मला सहरिया के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मुख्य मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। First of all, I want to say that there was so much hype on this year's budget, and which was expected because it was an election year's budget. But, it was through to expectation a different budget, but unfortunately, it created a history for the wrong reasons. And for that I think, all of the Rajasthan was shocked, ashamed and embarrassed. आगे मुझे पूरा समय नहीं देंगे, इसलिए मैं मेरे क्षेत्र की बातों पर सीधे आ जाती हूं। आपने पेज 78 पर अमृत योजना के तहत पेयजल की बात रखी है। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि कोटा में पेयजल की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोटा में निगम नोर्थ में 175 करोड़ एवं दक्षिण में 220 करोड़ की लागत से डीपीआर बनायेंगे। बजट में पाइपलाइन, पम्प हाउस वगैरह के निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत किये गये हैं। मेरी मांग है कि लाडपुरा में एक फिल्टर प्लांट की पेयजल के लिए जरूरत है। जब आप रिप्लाई करें तो प्लीज इस मांग को भी पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोटा जो कि चम्बल के किनारे है

(श्रीमती कल्पना देवी)

और वहां भी हमारे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में हर साल पानी की त्राहि-त्राहि मचती है और भयंकर किल्लत है। भले ही मैं सोगरिया की बात करूं, कोटणी-गोरधनपुरा की बात करूं, रामचन्द्रपुरा की करूं या नयी आवासीय कालोनियों की बात करूं या मल्टी स्टोरीज की बात करूं, हर जगह पर पानी की समस्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में आपने जो अमृत योजना-2 के लिए घोषणा की है, उसमें आप लाडपुरा का भी विशेष ध्यान रखेंगे।

पानी के सम्बन्ध में ही अगर मैं सिंचाई की बात करूं तो मेरा जो मंडाना क्षेत्र है, जो कि डार्क जोन में आता है, इस क्षेत्र की जो वर्षों पुरानी मांग है, नहरी तंत्र विकसित करने की जो मांग है, उसको आपने बिलकुल नजरंदाज किया है। यहां पर जो कृषि कार्य करने वाले लोग हैं, उनके पास चम्बल के अलावा कोई और पानी का स्रोत नहीं है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि आप इनकी मांग का भी ध्यान रखें। इसके लिए कोई नहरी तंत्र की योजना बनायें। जैसे हमारी सरकार ने एक डीपीआर तैयार की थी, परन्तु आपने चार साल से इनको बिलकुल नजरंदाज किया है। मैं मांग रखती हूं कि इस डार्क जोन के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था की जाये।

मैं आगे चलूं, तो आपने पेज 53 पर पैरा 93 पर सड़क और पुलिया की बात रखी है। क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल निर्माण के लिए। हमारे क्षेत्र में बाढ़ में दो साल पहले से कई पुलियां टूट गयी हैं, उनके लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे गांव हैं जो कि बारिश के टाइम पर टापू बन जाते हैं और चिकित्सा सुविधा के लिए भी वे ग्रामवासी हास्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं। कई ऐसे केस हैं जिनमें महिलाएं भी डिलीवरी के लिए हास्पिटल नहीं पहुंच पायीं तो they have lost their children. मेरी यह मांग है कि एक प्रमुख सड़क है, समय कम है, इसलिए मैं सब सड़कों की मांग नहीं रख रही हूं, रायपुरा से कैथून सड़क के लिए, नोटाना की पुलिया की मरम्मत के लिए। सारनपुर पुलिया, जहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा मैंने देखा है। परिवार जन जब अपने परिवार के सदस्य का शव श्मशान घाट ले जा रहे थे, वह पुलिया टूटने की वजह से वह शव ही पानी में गिर गया था। यह बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इसलिए मैं मांग रखती हूं कि नोटाना की पुलिया के साथ, सारनपुर की पुलिया एवं मवासा की दो पुलिया की स्वीकृति आप इस बजट में दें।

इसी के आगे अगर चिकित्सा की बात करूं, पेज 23 के आगे आपने

(श्रीमती कल्पना देवी)

चिकित्सा पर काफी ध्यान दिया है। मैंने जब ताथेड़ में ट्रोमा हास्पिटल के लिए मांग रखी थी तो मुझे बताया गया था कि आपके कई मापदंड पूरे नहीं होते। परन्तु मैंने जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की मांग बोरखेड़ा में रखी है, वह सब मापदंड को पूरा करता है। सिर्फ लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे जिले के हित के लिए यह मांग रखी है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस मांग को भी ध्यान में रखें।

चिरंजीवी की आपने जो बात की है, वह बहुत अच्छी बात है कि आप इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, परन्तु हास्पिटलों का बकाया जो कि करोड़ों में है, वह नहीं चुका पाये। आप उसको आगे कैसे चुकायेंगे? आप हमें ये बात भी बतायें। चिकित्सा की बात ही कर रही हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सी एच सी कैथून में एक सोनोग्राफी मशीन मैंने मेरे विधायक कोष से दी थी, परन्तु प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से वह मशीन बाढ़ के पानी में डूब गयी और वह खराब हो गयी। 18 लाख की मशीन थी, अब वह कह रहे हैं कि उनके पास ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उपकरण की मरम्मत करने के लिए और ठीक करने के लिए भी आप इस बजट में कोई प्रावधान रखें ताकि ऐसे महंगे उपकरण व पैसों का वेस्टेज नहीं हो।

आपने 83 एवं 84 पेज Greening and Rewilding Mission की बात की है। मैं इसमें कहना चाहती हूं कि आपके जो वनकर्मी हैं वे धरने पर बैठे हैं तो आप Greening and Rewilding क्या करेंगे? उनकी सुरक्षा के लिए जब कोई वनकर्मी ही नहीं है। ऐसे ही वेटलैंड की बात करते हैं आप पेज 84 पर और उम्मेदगंज में जो पक्षी विहार के लिए आप अलग से पैसा दे रहे हैं, परंतु साथ ही बिलकुल वहां पर ही आप एक कचरे का पाइंट बना रहे हैं, ट्रेंचिंग ग्राउण्ड बना रहे हैं। वह वेटलैंड कैसे सुरक्षित रहेगा? बगल में राइट विंग कैनाल चल रही है, जो कम से कम 1 लाख 32 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। वह पानी खराब होगा। जो बाहर से पक्षी आते हैं, कहां से आएंगे? इस पक्षी विहार का भी ध्यान रखना है।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना। विराजिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): साहब, बस एक मिनट। शिक्षा की

(श्रीमती कल्पना देवी)

बात करूं तो पेज नंबर 11 पर आपने महाविद्यालय की बात की थी। मैं मांग करती हूं कि लाडपुरा में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। कम से कम एक कन्या विद्यालय या महाविद्यालय दिया जाए।

अंत में डी एम एफ टी की बात रख रही हूं, जो आपने पेज 36 में कहा है, यह कंक्लूडिंग पाइंट है, कि जून में मीटिंग के दौरान यह तय किया गया था कि इस डी एम एफ टी का पैसा कैसे खर्च किया जायेगा और इसकी स्वीकृति दी गयी थी, परंतु आज तक एक भी रुपया उस डी एम एफ टी का खर्च नहीं हो पाया है। ऐसी मांगें थी जहां एस टी की बच्चियों के छात्रावास के लिए हमने पैसे स्वीकृत किये थे, एमबीएस हास्पिटल के लिए, एमआरआई मशीन के लिए पैसे स्वीकृत किये थे। आज तक उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है।

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज। सहयोग कीजिए। श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा वर्ष 2023-24 में की गयी घोषणाओं के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बजट में राजस्थान के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो हर समय गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, महिला और एससी/एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का उत्थान व कल्याण की सोच रखता है।

सभापति महोदय, कोविड की महामारी के समय जो शानदार प्रबंधन मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किया, उसकी प्रशंसा न केवल पूरे देश में बल्कि पूरे संसार में की गयी। उनके मन में जो पीड़ा थी कि मेरे प्रदेश में कोई भूखा न सोये, उसको भी उन्होंने पूरा किया। इस बजट की यहां पर ही नहीं पूरे देश-विदेश में चर्चा है। ऐसा बजट न तो अब तक किसी ने दिया और न अब कोई देगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस वित्तीय वर्ष के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पी एच ई डी का एक्स ई एन कार्यालय, नायला के पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना और नीमला श्रीनगर में 33 केवी

(श्री गोपाल लाल मीना)

का जी एस एस, जमवारामगढ़ में उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम और 48 हैक्टेयर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क और नकचीघाटी से नायला तक की 23 करोड़ की लागत से सड़क स्वीकृत की है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने बजट में किसानों के लिए दो हजार यूनिट तक, घरेलू कनेक्शन की 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक की नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाई है। हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि जो 50 यूनिट था उससे बढ़ाकर 100 यूनिट किया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हमारे किसान भाई हैं, उनका पूर्ण रूप से बिल माफ किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी चिरंजीवी योजना है, इस योजना में बहुत बड़ा काम किया है, 10 लाख से सीधा 25 लाख रुपये तक की उन्होंने नि:शुल्क इलाज की घोषणा की है, साथ ही जो 5 लाख रुपये का बीमा था, उसको बढाकर 10 लाख रुपये तक किया है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ऐसी कोई योजना नहीं है। समस्त प्रदेश की जनता की तरफ से मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार का काम किया है और आगे करने जा रहे हैं, प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया है।

युवाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, सभी बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ये पहली बार किया गया है। पहले ओल्ड पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दिया गया था, अब बोर्ड व निगमों को भी दे रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, कांट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। 2 लाख संविदाकर्मियों को इसका फायदा होगा। साथ ही संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के आर्थिक लाभ की भी घोषणा की है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों की घोषणा करना एक बहुत बड़ी बात है। कैलादेवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटूश्याम, गोगामेडी, बेणेश्वरधाम, पांडूपोल-अलवर, बुड्ढा जोहड़ गुरूद्वारा-श्रीगंगानगर एवं फाल्गुन (मुकाम)-बीकानेर के लक्खी मेलों में जाने वाली रोडवेज बसों में 50 परसेंट की

(श्री गोपाल लाल मीना)

छूट दी है। साथ ही किसानों के खेत पर मकान बनाने के लिए आवश्यक लोन एवं 5 फीसदी का ब्याज अनुदान व सरकारी बैंकों को 3 हजार की ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा इस बजट में हुई है।

जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ एवं पटवारी को टैबलेट देने की घोषणा की है, जिससे उनको काम करने का सम्पूर्ण समय मिलेगा।

एक बहुत बड़ी घोषणा की है, लम्पी से मारी गयी गायों का मुआवजा भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने देने की घोषणा की है। 40 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले एक करोड़ परिवारों को नि:शुल्क राशन के साथ फूड पैकेट, एक किलो दाल, चीनी, नमक, तेल एवं मसाले एवं पीएम उज्ज्वल एवं पीएम बीपीएल योजना के अंतर्गत आने वाले 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर मिलेगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि राज्य सरकार के पास मुद्रास्फीति कंट्रोल करने की कोई ऐसी योजना नहीं है, लेकिन राज्य के मुख्य मंत्री ने ये जो महंगाई से राहत का काम किया है, बहुत बड़ी बात है।

सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के तहत बुजुर्गों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये, पहले 500 से 750 रुपये हुई थी तथा इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत इंक्रीमेंट दिया जायेगा, जिससे परिवारों को, बुजुर्गों को संबल मिलेगा।

बीमार श्रमिकों को 7 दिन तक रोज 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो श्रमिक है, वह बीमार हो जाता है तो उसको 200 रुपये डेली देने का काम किया जाएगा। इस बजट में युवाओं के हित के लिए ऐतिहासिक फैसले लेते हुए सभी ब्लाक मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले वाचनालय डिजिटल लायब्रेरी की घोषणा की गयी है। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व अध्ययन की सुविधा मिलेगी। युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन तथा जिला मुख्यालयों पर 100-100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ होस्टल बनाए जाएंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): सरकार 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। सभी भर्ती परीक्षाओं के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के बाद कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे सभी वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

(श्री गोपाल लाल मीना)

पेपर लीक की घटनाएं भी हुई हैं। उसके लिए विपक्ष ने काफी कुछ कहा है, लेकिन हमारी सरकार द्वारा एस.ओ.जी. के अधीन एस टी एफ का गठन किया गया है, जिससे इसमें रोकथाम की जाएगी।

वर्तमान सरकार में, कार्यालयों में 1 लाख 42 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख 81 हजार से अधिक प्रक्रियाधीन हैं। आगामी वर्ष रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिक भर्तियां भी की जाएंगी। स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत 30 हजार सफाईकर्मियों को भर्तियां दी जाएंगी, इससे जो बेरोजगार बच्चे डोल रहे हैं, उनको फायदा होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व बजट में प्रदेश के सभी सैकण्डरी विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं। 2 हजार अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोले गये हैं जिससे हर ग्रामीण क्षेत्र में, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले गये हैं, इन विद्यालयों से पूरे प्रदेश में, आने वाली पीढ़ी सीख पाएगी, देश-विदेश में बोल पाएगी। यह शिक्षा में एक बहुत बड़ी नई नीति है। बच्चों के लिए एक उजाला है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जाएंगी।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, आपने बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): एक मिनट, मैं डिमांड बोल दूं। वैसे तो मेरे क्षेत्र में काफी कुछ दिया है, पर फिर भी...

श्री सभापति: आप टेबल कर दीजिए। आप टेबल कर दीजिए, क्योंकि समय की कमी है। टेबल कर दीजिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): ठीक है, मैं टेबल कर देता हूं। कुछ बोल देता हूं।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट 2023-24 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2023-24 का बजट पढ़ने की बजाय 2022-23 का बजट पढ़ना शुरू किया, अहसास होने पर इन्होंने इसको मानवीय भूल करार दिया। सभापति महोदय, यह कोई मानवीय भूल नहीं, यह एक घोर लापरवाही थी। बजट भाषण सुनाने के लिए पूरे प्रदेश में 15,000 एलईडी लगाकर सरकार ने अपनी किरकिरी करवाई।

मुख्य मंत्री जी ने 2023-24 का बजट युवाओं को सम्बल देने वाला बजट बताया। इसके लिए उन्होंने युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक साथ 5 लाख नौकरियां निकालकर युवाओं को रोजगार देने का काम करें एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओ को प्रतिमाह 5000 रुपये बेरोजगार भत्ता देकर युवाओं को सम्बल देने का काम करें।

मैं मेरी विधान सभा की बात करूं। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विद्यालयों में पूरा स्टाफ नहीं है, कक्षा-कक्षों का अभाव है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे खुले में दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, विद्यालयों में चपरासी नहीं हैं। पिछले लम्बे समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। विद्यालय में जब चपरासी ही नहीं होंगे तो घंटी कौन बजायेगा, सफाई कौन करेगा, विद्यालय कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा? मैं मांग करता हूं कि विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, स्टाफ की समुचित व्यवस्था करवाई जाए।

सभापति महोदय, मैं पिछले चार वर्षों से रायसिंहनगर में ट्रोमा सेन्टर खोलने की मांग कर रहा हूं, मगर आज तक पूरी नहीं हुई है। अस्पतालों में डाक्टर नहीं है, पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाइयां नहीं है। मैं मांग करता हूं कि मेरे रायसिंहनगर विधान सभा में एक ट्रोमा सेन्टर खोला जाए। तीनों सी एच सी में रिक्त पदों की नियुक्ति की जाए।

सभापति महोदय, महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी, महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएं। सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की थी, वह भी पूरी नहीं हुई, इसे भी पूरा किया जाए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि रायसिंहनगर व श्रीविजयनगर नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज की व्यवस्था कराई

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में जमा करें, प्लेसमेन्ट एजेन्सियों का बिचौलियापन खतम करें। प्रदेश में सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए, इन्हें स्थायी किया जाए। चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, इनसे अपने मूल कार्य के अलावा, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग में, विभिन्न प्रकार के कार्य करवाये जाते हैं। तहसीलदारों द्वारा इनसे सीमांत किसानों के सर्वे तक का काम करवाया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक स्थायी कर्मचारी से भी ज्यादा वर्क करता है और मानदेय मात्र 8400 रुपये मिलते हैं। मैं सरकार से इनको परमानेंट करने की मांग करता हूं तथा इनका मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि किसान भाइयों को उचित क्वालिटी के बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाये जाएं। डीएपी-यूरिया खाद समय पर उपलब्ध करवाये जाएं। सिंचाई के लिए सर्दियों में दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जाए। किसानों को कृषि डिग्गियों पर अनुदान लाटरी सिस्टम से न देकर वरीयता क्रम से उपलब्ध करवाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में आबंटित कृषि भूमि की खातेदारी को लेकर दोहरे नियमों व अधिकारियों की लालफ़ीताशाही के चलते रायसिंहनगर तहसील क्षेत्र के सैकड़ों किसान कृषि भूमि की तमाम किस्तें जमा करवाने के बावजूद खातेदारी हक से वंचित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के 24 पटवार मण्डलों में भूमि के पुख्ता आबंटन संबंधी एक हजार प्रकरण लम्बित हैं, जिससे किसान ऋण, अनुदान, मुआवजा और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लम्बित आबंटित कृषि भूमि की खातेदारी का निस्तारण अतिशीघ्र करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें, जिससे किसानों को मिलने वाले समस्त लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकें। पिछले दस वर्षों से कृषि भूमि के पुख्ता आबंटन समिति की बैठक नहीं हुई है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि श्रीगंगानगर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर 6 माह के लिए डीजल-पेट्रोल का रेट पड़ोसी राज्य पंजाब-हरियाणा के बराबर किया जाए। डीजल-पेट्रोल का रेट राजस्थान में सबसे ज्यादा है। सरकार इस बार वैट कम करके रेटों में कमी करे। राजस्थान में डीजल पर वैट 19.40 प्रतिशत है, पंजाब में डीजल पर वैट मात्र 10 प्रतिशत है। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट 31.04 प्रतिशत है, पंजाब मे पेट्रोल पर वैट 14 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के पृष्ठ संख्या 12 के पैरा नम्बर 17 पर, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की घोषणा की गई है। मेरी मांग है कि उक्त योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि संयंत्रों के निर्माण हेतु एक यूनिट की स्थापना की जाए, जिससे किसानों को कृषि संयंत्र उचित दामों पर मिल सके एवं अनुदान राशि भी मिल सके एवं साथ ही रोजगार के अवसर भी होंगे।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय आईटीआई कालेज खोलने की घोषणा की जाए।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, आधा मिनट। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की जाए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए।

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज। प्लीज, सहयोग करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जिस तरह से इस बार बजट पेश किया है, ऐसा ही बजट आज से दस वर्ष पूर्व 2013 में इन्होंने पेश किया था। तब कई घोषणाएं

(श्री कन्हैया लाल)

आखिरी के बजट में की थीं, जिसके अन्दर साड़ी, कम्बल, 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 80 कालेज। उनका रिजल्ट यह हुआ कि उनकी कोई क्रियान्विति नहीं कर पाए और यह 20 जीतकर आए। वह सारे की सारे 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमने खोले। सारी पी एच सी हमने खोली। इस बजट के अन्दर भी वही दशा होने वाली है। इन्होंने 2019-20 से ही नंदी गोशाला खोलने की घोषणा की, विकास पथ की घोषणा की, कर्जा माफी की घोषणा की, बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। श्रमिक कार्ड 2017 से पेंडिग है, कई लोग दुःखी हैं, उनको नहीं कर पा रहे हैं। आज रोड की स्थिति यह हो रही है कि पेचवर्क भी नहीं कर पा रहे। मेरे यहां मादोलाई से तीन-चार रोड हैं जिनकी स्थिति यह है कि वहां 2-2 फीट गड्ढे हैं।

स्कूल-कालेज खोलने का काम करते हैं, यह घोषणा का काम करते हैं, जैसे इन्होंने 2013 में किया। 2019-20 के बजट से कालेज खोलते जा रहे हैं लेकिन उनमें न तो स्टाफ लगा पा रहे हैं, न भर्ती कर पा रहे हैं, न भवन बना रहे हैं।

मेरे डिग्गी कल्याण जी के विकास के अन्दर, हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपये सैंक्शन किये थे, 30 करोड़ का तो काम हो चुका था, बाकी 30 करोड़ यह दबाकर बैठे हैं। कहते हैं कि हम मन्दिरों का विकास कराएंगे, धार्मिक स्थलों को विकसित करेंगे, पर्यटन का दर्जा देंगे, परन्तु कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।

इसी तरह से आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात करते हैं कि दो साल में भर्ती करेंगे, तो मैं यह कहता हूं कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती तुरंत निकालें और अर्जेंट भर्ती करें जिससे उन्हें अच्छा लगे और इसके अन्दर भी जो रिजर्वेशन किया है उसके अन्दर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दें क्योंकि वास्तव में दूसरे लोगों को अपन भर्ती कर लेते हैं और बाद के अन्दर वे कोई भी सफाई का काम नहीं करते हैं और कहीं बाबू या कोई दूसरे काम में बैठे रहते हैं, तो यह उनका हक नहीं मारें।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से इस बजट के अन्दर 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात की है। कल रात को भी लोगों के फोन आये कि हमारे बिजली जा रही है। रोजाना पांच-पांच, सात-सात घंटे बिजली जा रही है, तो लोग तो ये कहते हैं कि अब 100 यूनिट का हमसे डबल लो

(श्री कन्हैया लाल)

क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। डबल दरें बढ़ाने के बाद में छह महीने में अगर आप 100 यूनिट भी माफ कर देंगे तो उससे लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मेरे मालपुरा क्षेत्र को जैसे टोंक जिले के अन्दर केवल तीन ही विधान सभा क्षेत्र हैं, मालपुरा नहीं है, किसी भी बजट के अन्दर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे लोगों को फायदा हो। अभी बजट से पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हर विधायक से, 200 के 200 विधान सभा क्षेत्र में हम तीन-तीन काम पूछेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया। यह पांचवां बजट हो रहा है, एक भी कोई घोषणा ऐसी नहीं की गयी जिससे मालपुरा क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा हो सके।

आज साढ़े चार साल हो गये हैं। पटवारी वे के वे ही हैं, एक-एक पटवारी चार-चार पदों का काम कर रहे हैं। ग्राम सेवक भी वे के वे ही हैं, सिर्फ यह घोषणा करते हैं कि भर्तियां करेंगे, एक लाख भर्ती करेंगे, दो लाख भर्ती करेंगे, बाकी ऐसे के ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं।

इसी तरीके से महात्मा गांधी मॉडल स्कूल्स खोल दीं। आज मैं मेरी एक स्कूल की बात करता हूं कि टोरड़ी के अन्दर 95 बच्चे हैं और 27 टीचर्स डेपुटेशन के उसमें भर दिये गये हैं और जिस स्कूल में 1100 बच्चे हैं, उसके अन्दर केवल 12 टीचर्स हैं, तो केवल उनको डेपुटेशन करने के लिए एक रास्ता खोल दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर, तो उनको भरने का काम करें।

इसके साथ-साथ, समय की कमी है, फिर आप समाप्त करने के लिए कहेंगे। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की अब आखिरी में ही मांग पूरी कर दें।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मेरी मुख्य मांग है कि बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के सभी बांधों में डालना, टोडारायसिंह से देवली आगमन हेतु बीसलपुर डैम के पास बनास नदी पर पुलिया का निर्माण करवाना। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा में ट्रोमा हास्पिटल के लिए मैं रेगुलर पिछले पांच बजटों में मांग करता जा रहा हूं। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा और टोडारायसिंह में ब्लड

(श्री कन्हैया लाल)

बैंक की स्थापना। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडारायसिंह और मालपुरा में जनाना हास्पिटल खोलना, कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिग्गी क्योंकि यहां लगभग चार सौ-पांच सौ बीघा कृषि भूमि राजस्थान गवर्नमेंट की है। अगर यहां पर खोला जाये तो सारी फैसेलिटी है, केवल आपको इसका सृजन ही करना है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, कृषि महाविद्यालय खोलना। उपखण्ड टोडारायसिंह, मालपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय का संचालन करना, हर उपखण्ड पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, तो किसी एक उपखण्ड में तो मेरे भी खोला जाये।

इसी तरह से मालपुरा में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना, मालपुरा और टोडारायसिंह, दोनों उपखण्डों में मिनी स्टेडियम, इसका जो भी पैसा विधायक कोटे से या हमारी नगरपालिका का जो भी हिस्सा आता है, यह खोला जाये।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): टोडारायसिंह में पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय, टोडारायसिंह में ए.डी.जे. कार्यालय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मालपुरा में आर.ए.सी. और पुलिस के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): भाई साहब, पांच मिनट तो होने दो।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): ग्राम पंचायत लाम्बा में पुलिस चौकी को खोलना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): उसी तरह से लाम्बा हरिसिंह में उप तहसील खोलना, लाम्बा हरिसिंह पचेवर में स्वतंत्र ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके अगले वक्ता का फिर समय कम हो जायेगा, मुझे पता नहीं है। प्लीज, आप विराजिये। प्लीज, सहयोग करें, विराजिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मैं टेबल कर देता हूं मेरी मांग को?

श्री सभापति: विराजिये। इतनी देर पहले ही कर देते। आकाश-पाताल बांध रहे हो और जो मतलब की बात है वह बोल नहीं रहे हो। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

(माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल (मालपुरा) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, बजट वर्ष 2023-24 पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि युवाओं के लिए बजट है, युवाओं के नाम बजट है लेकिन मैं आपके ध्यान में यह दिलाना चाहूंगा कि पिछले चार-पांच वर्षों से जिन बीस से अधिक भर्तियों के लिए युवा प्रदेश में मांग कर रहे हैं, ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, धरना पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं परंतु उन पर कुछ भी बजट में नहीं कहा गया है।

पंचायती राज की जे.ईएन. की भर्ती, सी.एच.ए. की भर्ती, ए.एन.एम., जी.एन.एम. की भर्ती, सूचना सहायक की भर्ती, प्रोग्रामर की भर्ती, कम्प्यूटर अनुदेशक की भर्ती, विद्युत इंजीनियर की भर्ती, माध्यमिक शिक्षा के पदों पर भर्ती, जल संसाधन विभाग में भर्ती, स्टेनोग्राफर, टैक्निकल हैल्पर, चिकित्सा अधिकारी, वेटरिनरी के अधिकारियों की भर्ती, ये सब भर्तियां रुकी हुई पड़ी हैं, तो बजट में इनके लिए एक भी घोषणा नहीं है और ऐसा लगता है कि युवाओं ने मांगा मण और दिया कण, ऐसी स्थिति बजट में है।

यह बहुत प्रचारित किया गया कि पहली बार कृषि बजट पेश कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं।, यह बहुत प्रचारित किया गया कि देश में राजस्थान ने ही यह नवाचार किया है लेकिन उसमें भी आप स्थिति देखिये कि 2021-22 में टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर में 5.4 प्रतिशत था, 2022-23 में बी.ई. में आप 5 प्रतिशत टोटल एक्सपेंडिचर लेकर आये हो और आर.ई. में आते-आते 4.2 प्रतिशत हो गयी और अब एक्चुअल आयेगा तो क्या पता क्या स्थिति होगी? वर्ष 2023-24 की बी.ई. में 4.3 प्रतिशत लेकर आये हो, खूब हमने ढोल पीटा, तालियां बजायीं लेकिन एवरेज आल स्टेट की स्थिति देखें तो 5.8 प्रतिशत और कहां हम 4.3 प्रतिशत पर हैं, तो कहीं पर भी तुलना नहीं हो रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आंकड़ों पर पूरा फोकस करते हुए सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरा आईना सरकार को बताने का प्रयास किया है और जब वे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी बात कह रहे थे तो कंक्लूड करते हुए कहा कि

(श्री बिहारीलाल)

यह स्थिति आपके सामने है। आधारभूत ढांचा, विकास का जो काम होता है, रोड और ब्रिज में होता है, उनमें हमारी क्या स्थिति है? वर्ष 2021-22 में 3.1 प्रतिशत टोटल एक्सपेंडिचर था, 2022-23 में बी.ई. में 3.4 प्रतिशत और आर.ई. में स्थिति देखिये, जो आईना बताने वाली बात है कि आर.ई. में 2.6 प्रतिशत पर आ गये। 2023-24 में बी.ई. 3.6 प्रतिशत, आल एवरेज स्टेट्स के मुकाबले में हम बात करें देश के दूसरे स्टेट्स से, तो वह भी 4.5 प्रतिशत से सब में ज्यादा है, यह स्थिति हमारी इसी आधारभूत संरचना में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि पिछली बजट घोषणाओं में नोखा में नहरी पेयजल परियोजना का काम चल रहा है लेकिन बहुत-सी ढाणियों को सर्वे से वंचित कर दिया गया है, उनको शामिल किया जाये और काम की रफ्तार भी बहुत धीमी है। तय समय में इस स्थिति में कभी भी पूरी नहीं हो पायेगी, तो इसकी गति भी बढ़ाई जाये, कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाये। जैसलसर धुपालिया में टंकी और ओवरहेड के स्थान का चयन जो पंचायत से बिना पूछे, ग्रामवासियों की बिना राय लिए जबरदस्ती पक्षपातपूर्ण मनमाने तरीके से किया गया, उसको भी बदला जाये।

स्टेट हाईवे 20-बी, बजट घोषणा में तीन वर्ष पहले हुई थी, जैसरासर-बीकानेर की 70 किलोमीटर की रोड, जिस पर पांच विधायकों का क्षेत्र लगता है, उसका भी अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। नोखा के मुंसिफ कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट की बिल्डिंग्स की जगह भी अभी तक तय नहीं हो पायी है। जगह चिह्नित हो और उसमें बिल्डिंग भी बने। उप तहसील पांचू, जसरासर के भवन भी अभी नहीं बन पाये हैं और सुचारु रूप से व्यवस्था भी शुरू नहीं हो पायी है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह उम्मीद है कि आज बजट रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्रीजी मदन प्रजापतजी को जूते-चप्पल पहनाने का काम करेंगे, उनका जिला बनायेंगे, बालोतरा-फलौदी को जिला बनायेंगे, तो नोखा की भी एक लम्बे समय से मांग चल रही है जिला बनाने की, तो उस पर भी जरूर संज्ञान लेंगे।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे गजसुखदेसर से धुपालिया वाया झड़ेली काकड़ा, बाड़ काकड़ा, यह रोड है, नोखा पंचायत समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। प्लीज, आवाज नहीं। आप अपने-अपने स्थान पर पधारें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है, खारा से कुम्भासर, वाया सेंगाल धोरा पांचू, यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है। पांचू पंचायत समिति मुख्यालय को दोनों तरफ से एक-एक दर्जन गांवों से पंचायतों से जोड़ती है और सेंगाल तो बहुत ही धार्मिक महत्व का स्थान है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और रास्ता इतना खराब है, डब्ल्यू.बी.एम. रोड अभी इतनी कमजोर स्थिति में है और ट्रैफिक की बहुत भारी समस्या हो जायेगी, इस पर भी ध्यान दिया जाये।

जांगलू से ढिंगसरी वाया बनघरनाड़ी साथरी खेजड़ली पाटा और नोखा से सुरपुरा, जेगला से सुरपुरा वाया रासीसर, यह महत्वपूर्ण रोड है, सरकार से हमारी मांग है कि जनहित में की जाये।

पांचू जो आबादी का, अभी बजट में यह घोषणा की कि दस हजार से अधिक आबादी जिन ग्रामीण क्षेत्रों की है उनमें हम सीवरेज का काम देंगे, तो पांचू तो बीकानेर जिले का सबसे बड़ा गांव है, तो उसमें 25 करोड़ रुपये का सीवरेज सिस्टम डवलप किया जाये।

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): चिकित्सा में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये प्लीज।

श्री बिहारीलाल (नोखा): भामरसर, जैसलसर, धरनोक को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये और कक्कू में पुलिस चौकी की स्थापना की जाये पांचू थाने के अंतर्गत, यह हमारी मांग है।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): ऊर्जा के मामले में बंदाला, देसरसर...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: विराजिये। श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने सरकार के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

(श्री हरीश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद में एक बार तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरूजी लंदन गये थे, उस वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री चर्चिल ने नेहरूजी से पूछा कि आपने हमारी जेल में कितना समय बिताया? नेहरूजी ने जवाब दिया कि मैंने दस वर्ष से अधिक आपकी जेल में समय बिताया। चर्चिल ने उनसे पूछा कि आपने दस वर्ष से अधिक हम लोगों की जेल में समय बिताया तो क्या आप हम लोगों से नफरत करते हो तो जवाब में जवाहरलाल नेहरूजी ने यह दिया कि मैं और हमारे सहयोगियों ने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिन्होंने हमको न ही तो डरना सिखाया और न ही नफरत करनी सिखाई। जब आप सरकार में थे, उस वक्त न ही तो हम डरे और आज न ही हम लोग आपसे नफरत करते हैं।

आज जो देश में हालात बने हुए हैं, यही संदेश लेकर हमारे नेता राहुल गांधीजी कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के अन्दर गये। देश में जो माहौल बना हुआ है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

(समय: 15.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आज महत्वपूर्ण दिन है। नेता प्रतिपक्ष भी बोलेंगे, माननीय नेता पक्ष भी बोलेंगे। बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। प्लीज सहयोग करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, यह इनकी मजबूरी है कि देश के अन्दर काम की बात नहीं हो, मुद्दे की बात नहीं हो। इस तरह का कृत्य करके कहीं न कहीं डायवर्ट करें। यह इनकी मजबूरी है कि जहां इनको रहना है, वहां से ट्रेनिंग भी इनको यही सिखाई गई है। इसी के माध्यम से यह रहेंगे।

राजस्थान सरकार ने 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पक्का? (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यहां पक्का और कच्चा नहीं है, राजेन्द्र राठौड़ जी। यह धन्यवाद किसलिए देना चाह रहा हूं, राजेन्द्र राठौड़ जी, जो अन्याय आप लोगों ने किया, राजस्थान के साथ किया, राजस्थान इलाके के लिए किया। वह अन्याय जो केन्द्र सरकार, नरेन्द्र मोदी जी से पहले 90 प्रतिशत पेयजल योजना के अन्दर केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि होती थी,

(श्री हरीश चौधरी)

राजस्थान सरकार व अन्य सरकारों की 10 प्रतिशत होती थी। सभापति महोदय, इनके सरकार में आते ही, वह 90:10 का रेशो था, उन्होंने वह 45:45 किया। यह हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। 45:45 के बाद 10 प्रतिशत तक जो पैसा था, वह किससे लेना, उपभोक्ता से लेना। उसमें कुछ संशोधन हुआ। संशोधन होकर 47.5-47.5 प्रतिशत, उपभोक्ताओं को सिर्फ 5 प्रतिशत।

सभापति महोदय, इनको नहीं पता कि उपभोक्ता को कितनी तकलीफ होती है। आज रेगिस्तानी इलाका, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में गांव, ढाणियों में रहने वाले लोगों को दो-दो, ढाई-ढाई हजार रुपये देने पड़ रहे हैं। एयर कंडीशन में बैठे हैं, नीतियां बना रहे हैं उनको नहीं पता है। आज राजस्थान की सरकार ने 5 प्रतिशत अंश उन लोगों को देने का प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वह भार राजस्थान की सरकार ने खुद लिया और राहत पहुंचाई। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह धन्यवाद जायज है या नहीं है, यह आप अच्छी तरह से जानते हो।

सिलेंडर 50-100 रुपये की वृद्धि दर के अन्दर होती थी। आप भूल गये हो। अगर भूल गये हो तो वह वीडियो वापस अपनी लाइब्रेरी से निकाल लो। सिलेंडर रखना, सिलेंडर के साथ क्या-क्या कृत्य करना। आज उस सिलेंडर की दरों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर, आम उपभोक्ता पर कितना बोझ है। उस बोझ की कमी राजस्थान की सरकार ने 500 रुपये की राहत दी। उसके लिए तहे दिल से मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन बड़े लोगों को पता नहीं है। इनके तो सिलेंडर अपने आप ही आते हैं। इसलिए इन लोगों को तकलीफ पता नहीं है। सामान्य उपभोक्ता को पता है कि कितना बोझ है, कितना भार है।

सभापति महोदय, 100 यूनिट बिजली फ्री हुई, मैं उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज 8-8, 10-10 टन के एयर कंडीशन अपन लोगों के लगे हुए हैं, अपने को क्या पता 100 यूनिट बिजली का क्या मूल्य है। उस गरीब का 100 यूनिट बिजली माफ होना, बहुत बड़ी बात है। आज किसान पर बहुत बातें होती हैं, बहुत नारे लगाये जाते हैं। किसान की आमदनी दुगुनी, किसान के लिए रंगराजन कमेटी, किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी। जब आप सरकार में फैसला करने के लिए बैठे हो, तो उस वक्त जब किसान शहादतें दे रहा था, 700 से अधिक शहादतें, उसके बावजूद भी किसान के लिए कोई भी योजना, कोई भी फैसला, इन लोगों ने

(श्री हरीश चौधरी)

नहीं किया। राजस्थान सरकार ने 2 हजार यूनिट तक की बिजली माफ की, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हम लोगों का परिवार, बीमारी से नहीं घबराता था, बीमारी में ख़र्चे से हम लोग घबराते थे। बीमारी आ गई, इस बीमारी के ऊपर जो खर्चा होगा, वह खर्चा हम कहां से करेंगे। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से वह डर, खौफ, वह भार हम लोगों पर से हटाया। यह सबसे ऐतिहासिक काम हुआ। चिरंजीवी योजना में 10 लाख से 25 लाख रुपये का प्रावधान किया है, मैं राजस्थान के तमाम नागरिकों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया। इन बड़े लोगों को पता नहीं है। इन लोगों की आप इनकम टैक्स रिटर्न देखोगे तो करोड़ों रुपये बीमा के हैं। राजस्थान के आम लोग, मजदूर, किसान, सामान्य परिवार से हैं, उसके लिए 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये मिलेंगे, तो इसकी राहत कितनी मिलेगी, वह आम लोगों को पता है, इसलिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर, देश के अन्दर निरन्तर आपदा आई। सबसे पहले आपदा टिड्डी के माध्यम से आई। टिड्डी के माध्यम से आपदा आई। बाड़मेर, जैसलमेर के किसानों ने, राजस्थान की सरकार ने, टिड्डी का आक्रमण हुआ, उसे रोका। बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। तत्कालीन जिला कलेक्टर जैसलमेर ने खुद जमीनी स्तर पर जाकर रोका। मैं आज उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उस समय केन्द्र सरकार के यू एन के प्रावधान बने हुए थे, उस प्रावधान में सिर्फ स्प्रे का ही प्रावधान था। उस प्रावधान में जो दवाइयां पाउडर फॉम में थीं, उसके उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था। बाड़मेर, जैसलमेर के किसान ने अपनी खुद की जेब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपये व्यय करके, वह पाउडर खरीद कर, जो प्रावधान केन्द्र सरकार की तरफ और यूनाइटेड नेशन की तरफ से, डब्ल्यूएफए की तरफ था, उसके विपरीत जाकर एक्सपेरिमेंट किया। उन किसानों ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सफल हुए। सभापति महोदय, जब किसान इस तरह का प्रयोग करता है तो क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि हम उसे मदद करें? आज भी जैसलमेर में उस सोसाइटी में 70 से 80 लाख रुपये हैं। पाउडर फॉम में खरीद हुई, उसमें पड़े हैं। मेरा आपकी तरफ से नम्र निवेदन है हम किसानों को प्रोत्साहित करें।

(श्री हरीश चौधरी)

उन दवाइयों का भुगतान भी हम लोग करें। सरकार करेगी तो किसान हतोत्साहित नहीं होंगे। किसानों के परिवार सक्षम हो चुके हैं। आपस में पैसा इकट्ठा करके भी दे देंगे। सरकार करेगी तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा और प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापति महोदय, टिड्डी के बाद कोरोना आया। कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन हुआ। सब लोगों ने सहयोग किया। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कोरोना में अगर सबसे बेहतरीन फैसला कोई हुआ, उस समय स्वास्थ्य विभाग में 5 तरह की दवाइयों का किट। किट लेकर डोर टू डोर जो सर्वे हुआ है, उसमें शामिल हुए तमाम सरकारी कर्मचारी को आज साधुवाद देना चाहता हूं। कोरोना के प्रबंधन में सबसे सशक्त माध्यम था वह विकेन्द्रीकरण था। बड़े बड़े अस्पतालों में कोरोना का प्रबंधन उतना अच्छी तरह से नहीं हो सका, जितना कोरोना के सेंटर्स बनाये थे उन कोरोना सेंटर्स में छोटी-छोटी जगह वह चीज हुई। कोरोना प्रबंधन के लिए भी मैं राजस्थान की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उसके बाद तीसरी आपदा लम्पी आई। बहुत नारे लगाते हैं, जय गोमाता, बहुत पूजन करते हैं। गाय की पूजन, गाय के लिए नारे लेकिन जब लम्पी बीमारी आई, हम लोगों की प्राथमिकता लम्पी के माध्यम से, जो हमारे बीच गोवंश था उसको बचाने की थी या नहीं थी? आज अगर हम आईना देखें, हमें सबको इस बात को स्वीकार करना आना चाहिए, दलगत हम लोगों की विचारधारा से ऊपर कि हम लोग सामूहिक तौर पर लम्पी के अन्दर फेल हुए हमारी गो-माता को बचाने के लिए। बहुत बड़े स्तर पर, किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जो पशु आहार हम अपनी खुद की गायों को देते हैं, उस पशु आहार की सेल बढ़ी है या घटी है? घटी है तो कितनी घटी है? हमारा समाज का आईना अपने आप बता देगा, उस पशु आहार के अन्दर कितनी कटौती हुई। वह किसके कारण हुई हमारी दुधारू गाय थी, दुधारू गाय की मौत हुई, उसके कारण यह हुआ।

सभापति महोदय, हम सबको सामूहिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि गाय पूजन से पलेगी या गाय पालन से पलेगी? यह फैसला हम लोगों को लेना पड़ेगा। मैं सदन के माध्यम से, राजस्थान के पूरे लोगों को कहना चाहता हूं। गाय के ऊपर हम लोगों ने बहुत सियासत कर ली। गाय के ऊपर हम लोगों ने

(श्री हरीश चौधरी)

बहुत विवाद किये। हम लोगों ने गोपालन छोडकर, गो पूजन शुरू कर दिया। लम्पी में गो-वंश की मौत हुई, उसका मुआवजा 40 हजार रुपये राजस्थान सरकार दे रही है, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। राजेन्द्र राठौड जी, यह सब तहे दिल से दे रहा हूं। यह नहीं कि मजबूरन दे रहा हूं। यहां बैठा हूं, वह भी तहे दिल से ही बैठा हूं। ऊपर जाऊंगा, मिट्टी में मिलूंगा, उस वक्त भी यहीं बैठा रहूंगा, इसके अलावा कभी भी जेहन में सोचूंगा भी नहीं। इधर से उधर नहीं होऊंगा। जिस विचारधारा में पैदा हुआ हूं, उसी विचारधारा के अन्दर खतम होऊंगा। रिकार्ड के अन्दर यह बात साझा करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इन बड़े लोगों को पता नहीं है कि ढाणियों में बसने वाले राजस्व गांव, ढ़ाणियों के अन्दर 500 की आबादी तक, हम लोगों के यहां रोड कनेक्टिविटी का फैसला हुआ था। 2011 तक के 500 की जगह 250 का जो फैसला किया गया, मैं तमाम ढाणियों में रहने वाले लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जाटव साहब, आपको और राजस्थान सरकार को। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? माननीय सदस्य, गंभीरता बरतें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है, 2011 के बाद में जो नवसृजित राजस्व गांव हैं, उनके अंदर 500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ा जायेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों के यहां प्रावधान यह नहीं है, रेगिस्तानी इलाका और ट्राइबल इलाके के अंदर, तो 250 की व्यवस्था, यह फैसला PWD डिपार्टमेंट हम लोगों को देकर ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए आप राहत पहुंचायें। 250 नहीं दे सकते तो 350 दे दो। अगले वर्ष वापस 250 कर लेना, यह आपसे मेरी तहे दिल से गुजारिश है।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर कितने ही लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, जिनके घरों के अंदर बिजली नहीं है। क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं बनता? हम लोगों की सबसे पहले प्राथमिकता उन परिवारों की होनी चाहिये, जिन ढाणियों के घरों के अंदर बिजली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के जिले बाड़मेर के अंदर आज भी 41

(श्री हरीश चौधरी)

हजार ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार मिलकर जिस तरह से हमने कोरोना के समय प्राथमिकता से, स्वास्थ्य के अंदर प्राथमिकता रखी तो हमारा दायित्व बनता है कि उन तमाम परिवार, जो बिजली से वंचित हैं, उन परिवारों के घरों में, उनकी ढाणियों में, उनके खेतों के अंदर बिजली पहुंचाकर उनको उजाला दें, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, यह OPS का फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की। आज बड़े लोगों को पेंशन की आवश्यकता नहीं है, पर जो सामान्य सरकारी कर्मचारी हैं, मैं एक सरकारी कर्मचारी के परिवार से आ रहा हूं। हमारे यहां पेंशन के माध्यम से हमको कितनी सुरक्षा मिलती है, वह हम लोग जानते हैं। मैं आज यहां तक पहुंचा हूं उसके अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो इस पेंशन से सुरक्षा का योगदान है। यह हक और अधिकार आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिये। यह OPS के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजस्थान की सरकार ने फैसला किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम आपस के अंदर चर्चा कर रहे थे, हमारी सबसे बड़ी मांग बालोतरा को जिला बनाने की थी। हमारे सबसे होशियार एम.एल.ए. मेवाराम जी जैन साहब को मानते हैं। मैंने उनसे चर्चा की कि मेवाराम जी, आप बताओ किस अटकल से, किस माध्यम से हम इस जिले की मांग को पूरी करें? नेता बनकर मदन प्रजापत जी ने कर लिया, लाडला बनकर मदन प्रजापत जी ने कर लिया, जूते उतारकर मदन प्रजापत जी ने कर लिया, सुदामा बनकर मदन प्रजापत जी ने कर लिया, पर मैं आपके माध्यम से तहे दिल से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी आधार पर बालोतरा को जिला बनाना गलत नहीं हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर बालोतरा को जिला बनाया जाये और बाड़मेर को संभाग बनाया जाये, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यहां सुना, कई विद्वान साथियों ने यह बात कही कि कर्जा बहुत ले लिया। कई विद्वान साथियों ने यह बात कही कि राजस्थान श्रीलंका बन गया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आंकड़े आप देखो। राजस्थान सरकार के आंकड़े अगर हम लोग देखेंगे, अगर देखना चाहें तो

(श्री हरीश चौधरी)

देख सकते हैं और नहीं देखना चाहें, माननीय सभापति महोदय, जोर-जबरदस्ती तो इन लोगों के साथ में नहीं कर सकते। जोर-जबरदस्ती इसलिए नहीं कर सकते कि आज पूरा देश कराह रहा है। किन मुद्दों पर कराह रहा है? बेरोजगारी पर, गरीबी पर, असमानता पर और केन्द्रीय बजट के अंदर एक अक्षर भी इन तीनों के संदर्भ में पूरे बजट के अंदर कहीं भी नहीं लिखा गया, कहीं भी नहीं बोला गया। एक अक्षर भी नहीं बोला गया, फिर इन लोगों को किसके लिए सरकार चलानी? इन लोगों को बड़े लोगों के लिए सरकार चलानी है। राजेन्द्र जी ने बोला। अडाणी जी के लिए मैं कल जम्मू में प्रेस कांफ्रेंस कर रहा हूं, वह लिंक मैं भेज दूंगा अडाणी जी के लिए, महेश जोशी जी हमारे सचेतक महोदय हैं, आप जितनी मेरे पर कृपा नहीं है, मुझे तो सिर्फ 20 मिनट मिले हैं, वरना अडाणी जी की बात भी मैं पूरी की पूरी करता। पर यह आंकड़े क्या कहते हैं? यह आंकड़े यह कहते हैं कि 2019-20 के अंदर राजस्थान सरकार ने जो उनका कर्ज था GSDP का, 35.32 प्रतिशत था और केन्द्र सरकार का 50.9 प्रतिशत। वही के वही हालात 2020-21 के अंदर थे, राजस्थान सरकार के 40.27 और केन्द्र सरकार का था 61 प्रतिशत। वही का वही 2022-23 का था, हम लोगों का 36.56 और केन्द्र सरकार का था 55.89 प्रतिशत। यह हकीकत है, उसके बावजूद भी सिर्फ बोलने के लिए बोलना और विरोध करने के लिए विरोध करना, माननीय सभापति महोदय, यह समझ से परे है।

माननीय सभापति महोदय, सदन की गरिमा देखिये, एक अकेला सब पर भारी। लोकतंत्र के अंदर यह भाषा और ऐसा कृत्य, अगर मैं यह बात कहूं तो यह लोकतंत्र के अंदर शोभा देता है? आज राजस्थान की जनता के सामने मैं अगर यह बात रखता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी सदन के अंदर ऐसे अहंकार से बोलता है, लोकतंत्र के अंदर यह बात कभी भी उचित नहीं मानी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, यह बात बोली गयी, एक अकेला सब पर भारी। माननीय सभापति महोदय, किस पर भारी? उन गरीबों पर भारी? यह आंकड़ा देखो इस हिन्दुस्तान का। 2014 के अंदर स्वास्थ्य के अंदर हैल्थ इंडेक्स के अंदर 2014 के अंदर 85वें स्थान था हम लोगों का और एक अकेला सब पर भारी उन गरीबों के लिए, और आज 146वें स्थान पर हैं। आप इन सभी बातों को नोट कर लेना। यह की यह चीज हंगर इंडेक्स में, भुखमरी के अंदर 2014 के अंदर 55वें स्थान पर था और आज 2022 के अंदर 107वें स्थान पर हैं। यही स्थिति ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है। हम लोगों को यह आजादी कैसे

(श्री हरीश चौधरी)

मिली, वह हम लोगों को पता है। बड़े लोगों को यह नहीं पता है। हमारे पूर्वजों के पास अधिकार नहीं रहते थे। हमारे पूर्वजों के पास भाषा का अधिकार नहीं, हमारे पूर्वजों के पास रहने का अधिकार नहीं, हमारे पूर्वजों के पास जूतियां पहनकर बड़ी जगहों से निकलने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों को अधिकार मिला है और वह अधिकार भारत के नागरिकों से छीना जा रहा है। वह दर्द आज भारत के नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं। यही हालत हैप्पीनेस इंडेक्स में, एनवायर्नमेंट में, जेंडर इक्वेलिटी में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, यही ह्यूमन डवलपमेंट में, प्रेस फ्रीडम में, पेंशन इंडेक्स के अंदर है।

माननीय सभापति महोदय, यह बड़े अहंकार से बात कर रहे थे कि केन्द्र सरकार पैसा दे रही है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार या राजस्थान की सरकार कोई पैसा ऐसे ही नहीं देती, यह हम लोगों से टैक्स के माध्यम से पैसा लिया जाता है। सरकारों के पास अधिकार रहता है। राजस्थान के लोग टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के अनुपात में राजस्थान को कितना पैसा मिलता है, यह आंकलन अगर आप करोगे तो आपका यह अंहकार निकल जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन में गंभीरता बरतें। माननीय सदस्य, गंभीरता बरतें। आप नये-नये आये हैं, कुछ सीख लीजिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, हमें बजट के अंदर केन्द्र सरकार ने जो स्टेट का एलोकेशन था, वह 3,43,039 करोड़ था। पिछले साल मिला कितना, हमको मिला 2,70,936 करोड़ मिला। यह 64 हजार करोड़ गये कहां? अब देश और दुनिया समझ चुकी है। अच्छी तरह जान गयी कि 64 हजार करोड़, जो हमारे राज्यों के लिए थे, वह हमारे राज्यों से लेकर अपने मित्रों को दिये गये। वह ताकत किसको दी गयी? उन मित्रों को दी गयी और जब से सवाल उठाये जा रहे हैं, आज मैंने अख़बार में पढ़ा, बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति यह कह रहे थे कि आरोप लगाओ, पर आरोप लगाने का आधार होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, राहुल गांधीजी ने पार्लियामेंट के अंदर जो बात कही, आज संख्या बल के माध्यम से वह बात वहां से हटा दी गयी है पर यह जो सवाल खड़े किये हैं, वह दुनिया के अंदर कोई भी उन सवालों को मिटा नहीं सकता। आज यह ताकत उन लोगों से छीन ली।

(श्री हरीश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय-

'यूं ही मरकर खो जाना मंजूर नहीं,
थक-हारकर सो जाना मंजूर नहीं,
न सोचो, न डरकर पीछे हो जाऊंगा,
बिना लड़े कुछ होना-जाना संभव नहीं।'

माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकारें BBC और OBC के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? यह बीबीसी के पीछे तो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि जो अभिव्यक्ति का अधिकार स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से है, वह चंद ही मीडिया हाउसेज हैं जिनके ऊपर केन्द्र सरकार का कब्जा नहीं है। बीबीसी को भी दबाया जा रहा है।

ओबीसी के साथ में जो चीज हो रही है, मेरे मित्र मंत्री लोग कह रहे हैं कि सरकार के सामने कोई न कोई विवाद खड़ा करने के लिए मांग की जा रही है। यह सवाल किया जा रहा है। यह विवाद करने के लिए हंगामा नहीं कर रहे हैं। यह हमारा हक और अधिकार है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। यह और बात कर रहे हैं कि 4 साल तक कहां गये?

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने मंडल आयोग के माध्यम से ओबीसी को 27 प्रतिशत राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था की। न्यायपालिका ने कैप लगाया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा वह आरक्षण नहीं दे सकते। ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोगों के यहां प्रस्ताव आया। सर्वसम्मति से हम सब लोगों ने किया। बिना किसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर किया। बहुत तालियां बजायीं, हाथ भी थक गये होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत तालियां बजायीं। न्यायपालिका ने भी यह फैसला किया कि जो 50 प्रतिशत का कैप है, वह अब मान्य नहीं है।

सभापति महोदय, यह जो 27 प्रतिशत का प्रावधान सरकार की तरफ से है।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या हमारा हक, अधिकार और मांग नाजायज है? अगर कोई भी यह बात हमें समझा दे कि यह हक और मांग नाजायज है तो मैं आप लोगों के माध्यम से माफी मांग लूंगा।

(श्री हरीश चौधरी)

सभापति महोदय, जो ओबीसी में विसंगतियां थीं, आज 21 प्रतिशत आरक्षण के सामने उतने पदों पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या यह उन लोगों के साथ में अन्याय नहीं है? सिर्फ विवाद करने के लिए हम लोग यह बातें थोड़े ही कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरी पिछले दिनों भूतपूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से चर्चा हुई। उनका मानना था कि इस देश के सामने सबसे गंभीर अगर कोई चुनौती है तो गलत आंकड़े और आंकड़े नहीं होना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के अंदर गांवों और शहरों के बीच में बढ़ी खाई को लेकर है। अगर किसी को सही आंकड़ा मिलता है तो इससे किसको तकलीफ है? किसके साथ अन्याय हो रहा है?

आज हम लोगों के समाज के अंदर, देश के अंदर जातिगत व्यवस्था है। इस जातिगत व्यवस्था के अंदर अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कहां होगी? हम या तो सर्वसम्मति से इस बात को तय कर लें कि राजस्थान में किसी भी जाति के आधार पर कालम नहीं होगा, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, तो जरूर जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है किन्तु जातिगत जनगणना से हमको हकीकत पता चलेगी कि जो भी योजना हम लोग बना रहे हैं, जो भी फैसला हम लोग कर रहे हैं, अगर केन्द्र सरकार नहीं करे तो मेरा निवेदन है इस सदन को कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, राजस्थान के अंदर भी यह जातिगत जनगणना होनी चाहिए।

बाकी जगह तो हम गठबंधन कर लेते हैं। बड़े-बड़े लोगों के लिए हम गठबंधन कर लेते हैं। प्रधान मंत्री जी अडाणी जी से गठबंधन कर लेते हैं। इस सदन के अंदर भी मैंने एक और गठबंधन देखा।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): बहुत तालियां बजीं, ओम शांति, यह भी सदन के अंदर देखा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए नागौर का गठबंधन भी हमने देखा लेकिन यह गठबंधन इन गरीबों के लिए करो, यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। अगर यह गठबंधन हम गरीब के लिए करेंगे, गठबंधन हम राजस्थान के लिए करेंगे, तब जाकर राजस्थान आगे बढ़ेगा।

(श्री हरीश चौधरी)

सभापति महोदय, ऐसी कई व्यवस्थाएं हुई, कई फैसले हुए। मैं बाड़मेर, जैसलमेर से आता हूं। 5 साल में इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जो पानी किसानों को मिला है, उससे पहले 5 साल तक नहीं मिला है। कहीं भी जाकर, कोई भी चले जाओ, बोर्डर पर ऊंट पर बैठकर भी घूम रहे हैं तो वहां भी हमारे यह ऊंट उन आई जी एन पी वाले किसानों के बीच में ही हैं। 5 साल तक बहुत अच्छा पानी मिला है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): इस तरह का फैसला और इस तरह की व्यवस्था हुई। यह व्यवस्था क्यों हुई क्योंकि वहां के जन प्रतिनिधि चाहे शाले मोहम्मद हों, चाहे रूपाराम जी हों, हेमाराम जी हों, इन तमाम लोगों ने 4 साल तक प्रयास किया कि आई जी एन पी से जैसलमेर में पानी का प्रबंध हो। इस तरह के फैसले राजस्थान की सरकार निरंतर करती आयी।

सभापति महोदय, अंत में, आज राजस्थान की सबसे बड़ी अगर कोई प्राथमिकता है तो वह शिक्षा, रोजगार और संविदा की व्यवस्था खतम करने की है। इस शिक्षा के माध्यम से हम लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ा अन्याय अगर कोई होता है, आर्थिक विषमता से अन्याय नहीं होता है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें, प्लीज।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड करता हूं। आर्थिक विषमता से अन्याय नहीं होता है, सामाजिक व्यवस्था से अन्याय नहीं होता है। यह ज्ञान और शिक्षा के अंदर जो असमानता है उससे बड़ा अन्याय दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज राजस्थान में 10 हजार लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनमें से 9 हजार लोगों ने इसी राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कालेजों से अध्ययन किया है लेकिन उन 10 हजार में से क्या 10 प्रतिशत के भी बच्चे इन विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्ययन कर रहे हैं? सभापति महोदय, उत्तर मिलेगा, नहीं। इन विश्वविद्यालयों को हमने खतम कर दिया है। इन विश्वविद्यालयों की कोख से मैं निकला हूं। आज इस जयनारायण विश्वविद्यालय की क्या हालत बनी हुई है? विश्वविद्यालय हमने बना दिया, लेकिन विश्वविद्यालय की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां रिसर्च एवं डवलपमेंट हो। किसी विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डवलपमेंट हो रहा है?

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज। विराजें अब आप।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): नहीं हो रहा है। एकेडमिक एक्टिविटी हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रह गये हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोग जो सामान्य परिवार से आ रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा का अवसर दे दो।

सभापति महोदय, अंत में, जो अन्याय हम संविदा के माध्यम से कर रहे हैं, उसके लिए सामूहिक रूप से बैठकर हम कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें, वह पीड़ा उन संविदा कर्मचारियों के साथ में नहीं हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): पेपर के संदर्भ में और रोजगार के संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूं। योग्य आदमी को आप बैठाओ।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): योग्य आदमी को अगर आप बैठाओगे तो अपने आप सब चीजें ठीक हो जायेंगी। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम।

श्री सभापति: श्री सतीश जी पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। इस बजट की बहस में नेता, प्रतिपक्ष के नाते सदन की गरिमा आदरणीय गुलाब चन्द कटारिया जी बढ़ाते थे, जिनका इस सदन में और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा लंबा अनुभव रहा। मैं मानता हूं कि यह हम सबका और सदन का सौभाग्य है, राजस्थान की राजनीति में काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि वह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजेंगे। मैं कटारिया साहब को सदन की ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।

आज इसी भूमिका में हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ जी को होना था, लेकिन वह मुझसे पहले बोल चुके थे। मैं उम्र में, अनुभव में और मेरी अग्रणी बैंचेज में उस लिहाज से सबसे छोटा हूं। मेरी स्थिति उस परीक्षार्थी की तरह है कि मैं परीक्षा दे रहा हूं और ऊपर शिक्षक मेरी कापी को जांच रहा होगा। आदरणीय कटारिया साहब की विरासत की जगह मैं हो सकता है अपनी भूमिका के साथ कितना न्याय कर पाऊंगा?

सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि जीवन जहां उत्सव है, वहां राजस्थान है। यहां की संस्कृति, यहां का इतिहास, यहां की परंपराओं ने देश में राजस्थान को अनूठा बनाया है। पूरे देश भर में ही नहीं,

(श्री सतीश पूनियां)

दुनिया में हर तीसरा पर्यटक जब हिन्दुस्तान में कदम रखता है तो राजस्थान जरूर आता है। कदाचित यहां की शांति, यहां की सुरक्षा, यहां का सद्भाव, यहां का लोक संगीत, लोक संस्कृति, उन चीजों को देखने के लिए दुनिया के तमाम देशों के लोग आते हैं।

राजस्थान के बारे में यही कहा जाता है कि राजस्थान where life is celebration. जीवन जहां उत्सव है, वहां राजस्थान है। बजट की पेचीदगियां, बारीकियां और बाकी जो प्रावधान थे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं केवल संकेत रूप में उसकी चर्चा करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 12 फरवरी, 2011 को भारत सरकार के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे रहे थे। भाषण देते-देते पता लगा कि उन श्रीमान् ने पुर्तगाल का भाषण पढ़ दिया। दुनिया के इतने बड़े मंच पर उन माननीय विदेश मंत्री जी को यह अहसास नहीं हुआ कि यह भाषण भारत का नहीं था, पुर्तगाल का था, जो वह 3 मिनट तक पढ़ते रहे। अब यदि इसे मानवीय भूल कहा जाये, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह क्षम्य नहीं होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज होता है, जिसकी एक मर्यादा होती है लेकिन मैं देख रहा था, विचित्र तरीके से राजस्थान की सरकार का यह बजट कुछ अनूठा था। मुझे बताया गया कि जगह-जगह देखा, बचत, राहत और बढ़त। सवा करोड़ रुपये उन विज्ञापनों में खर्च किये गये। यह भी जानकारी मिली खोजते-खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, आप यदि बजट की शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की गोपनीयता भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरह से बजट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। चलिए, वह हो गया लेकिन जो घटनाक्रम यहां हुआ, मैं किसी की मानहानि नहीं करना चाहता लेकिन कम से कम इस सदन में और इस सरकार में जो देश में कभी नहीं हुआ वो क्यों हुआ उसकी पृष्ठभूमि में आज जाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और दंश है, वो पेपर लीक का है। पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का यह बजट, 32 हजार करोड़ रुपये का घाटा, 65 हजार करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा लेकिन पूरे कर्ज का उल्लेख करेंगे, 5 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का घाटा, यह ऐसा लगता है कि चार्वाक ने जो कहा, वो आप पर लागू होता है। 'यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत।' आज राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी लाइबिलिटी 90 हजार रुपये होगी, उसका कर्जा 90 हजार रुपये होगा। इसलिए यह बजट जिसके बारे में पहले बहुत प्रचारित की गई चीजें, एक जन घोषणा पत्र था जिसकी क्रियान्विति की रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद मॉडल स्टेट का विज्ञापन था, उसके बाद अलग-अलग स्कीम्स के इस तरीके के फोल्डर्स बांटे गये। 2018 के चुनाव की घोषणाएं, चुनाव घोषणा पत्र, 5 अभिभाषण और 5 बजट, यदि मैं इसको यह कहूं कि यह बचत, राहत और बढ़त नहीं है। यह चपत है राजस्थान की जनता को, यह खपत है राजकोष की और यह डूबत है राजस्थान की, जो हालात आज पैदा कर दिए गए, दावे बड़े-बड़े किये गये। मैं उल्लेख करूंगा इस बात का लेकिन मैं मेरे मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही थी। पहले बोलने वाले मेरे मित्र ने कहा, पर मुझे लगता है कि अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो मेरे सामने वाला पक्ष है। पिछले चार वर्षों में इन्होंने हैप्पीनेस का नजारा देखा ही नहीं होगा क्योंकि जो सरकार 2018 की बुनियाद पर इस रूप में खड़ी हो कि राजभवन में मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद दूसरे मुख्य मंत्री के नारे लगे। 52 दिन कोई सरकार बाड़े में बंद रहे। मंत्रिमंडल पर झगड़ा हो, मंत्रिमंडल के कमरों पर झगड़ा हो और उसके चलते-चलते जिस तरीके का नजारा हुआ, यहां सदन में बहुत सारी चीजें रिकार्ड पर हैं। चिट्ठी-पत्रियां होती रहीं, बयानबाजी होती रही और अंततः उसकी परिणति इस्तीफों के रूप में हुई।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की, देश की शांति का कारक होता है, राजनीतिक स्थिरता। इस राजस्थान को पिछले चार वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में डालने का दोषी कोई है तो यह राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, जब ये चर्चा कर रहे थे यहां, मुझे अफसोस होता है, लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति है, आपको विरोध करने की अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं आपके चक्षु खोलना चाहूंगा मित्रों, आपने यहां

(श्री सतीश पूनियां)

भारत की सरकार की बुराइयां तो खूब कीं लेकिन कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए कि आजादी से लेकर आज तक का यह पहला कारण है, जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश होते थे, उस ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत आज पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इस देश में बुनियादी विकास की चर्चा होती थी, आप कल्पना कीजिए, बात छोटी लगती होगी, मैं भी गांव से आता हूं, आप में से बहुत-से लोग गांव से आते होंगे, लेकिन उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब किसी की गांव की बहन-बेटी और मां, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। आप विकास की बात करते हो, 55 वर्षों तक आपकी सरकार रही है लेकिन इस देश में उस मातृ शक्ति को सम्मान देने का काम इस देश की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ शौचालय बने और उन माताओं-बहनों को सम्मान मिला। देश में 107 करोड़ बैंक खाते हैं। यदि ऐसा पहले होता तो 47 करोड़ बैंक के खाते अब क्यों खुलते? एक प्रधान मंत्री थे देश में जो कहते थे एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं, 85 पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज उन 47 करोड़ में दिव्यांग का, महिला का, विधवा का, नरेगा के मजदूर का, विद्यार्थी के हक का पैसा उसके खाते में जमा हो जाता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश पड़ा है।

(समय: 15.34 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 वर्षों में 2014 से आज तक के इस कालखण्ड में भारत के प्रति व्यक्ति की आय 1 लाख 97 हजार रुपये हुई है। यह पहली बार हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दु:ख में सब याद करते हैं। हम दु:ख में या तो भगवान को याद करते हैं या राज को याद करते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस तरह का दृश्य नहीं देखा कि जब कोविड जैसी महामारी का संकट था और भारत के प्रधान मंत्री की पहल पर देश के वैज्ञानिकों ने 9 महीने के भीतर देश की दो-दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई और देश के लोगों को 230 करोड़ वैक्सीन लगी। मैं राजस्थान के उन लोगों का भी अभिनन्दन करूंगा कि राजस्थान के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगी और उनको सुरक्षा मिली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपनी

(श्री सतीश पूनियां)

योजनाओं में जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं, यह एक ऐसा दृश्य था जब स्पेनिश फ्लू से 100 वर्ष पहले लोग काल-कवलित हो गए थे। हमारे प्रधान मंत्रीजी की दूरदृष्टि देखिए कि 80 करोड़ लोगों को लगातार अन्न देने का काम किया ताकि कोई भूख से मरे नहीं, ताकि कोई भूखा सोये नहीं। राजस्थान के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम में से बहुत-से लोग इस बात के साक्षी होंगे कि गैस कनेक्शन शहर में कैसे मिलता था। मैं जब खुद जयपुर शहर में आया था तो मुझे सांसद महोदय के कितने चक्कर काटने पड़े थे। आज दस करोड़ बहनों को धुएं से मुक्ति मिली और राजस्थान की 63 लाख मातृ शक्ति को उज्ज्वला के कनेक्शन उनके घर तक पहुंचाए गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान माननीय प्रधान मंत्रीजी का इस बात के लिए अभिनन्दन करता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाजपेयी जी ने शुरू की, आज राजस्थान के किसान को 20 हजार 404 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देकर उसको सम्बल देने का काम किया है। मैं इससे आगे आता हूं, देश ही नहीं दुनिया की ऐसी अनूठी योजना थी, राजस्थान के 77 लाख किसानों के खातों में दुनिया की सबसे बड़ी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और हिन्दुस्तान के 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपये सीधा जमा हुआ है, जिसने राजस्थान के और हिन्दुस्तान के किसानों का जीवन बदला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के 16 लाख नौजवानों को जिसमें 62 प्रतिशत युवा महिलाएं हैं, उनको मुद्रा योजना का लाभ मिला। इनकी 16 लाख संख्या है। जिनके सिर पर छत नहीं होती थी, हम योजनाओं के बारे में केवल सुनते थे कि फलां आवास योजना है, न खिड़की होती थी, न दरवाजा होता था, न छत होती थी, मजाक उड़ाया जाता था। क्या इस किस्म की भी कोई आवास योजना है? आप आंख खोलकर देखिए, तीन करोड़ लोगों को छत मिली है, अच्छा सुसज्जित मकान मिला है। राजस्थान के 17 लाख लोगों को यह सुविधा हासिल हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात चल रही थी। मैं देख रहा था, दीनदयाल कुटीर ज्योति योजना के कनेक्शन को, 50 लाख गांव और ढाणियों तक राजस्थान के लोगों को कनेक्शन देने का काम किया है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे बजट की बारीकियों पर अगर आप जाएंगे, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने जो कहा कि 5 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का कर्जा और उस कर्जे की परम्परा में इस समय आरबीआई कहती है कि राजस्थान सबसे ज्यादा फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट है। 2019 में फिस्कल डैफिसिट थी 32 हजार, 2020 में हुई 33 हजार, 2021 में हुई 47 हजार, 2022 में हुई 58 हजार और अब यह 65 हजार करोड़ से भी ऊपर जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, जो ब्रांडिंग की गयी और जिस बात का मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं, जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति रिपोर्ट है, सरकार ने बड़ा खर्चा करके छापी है। एक पंच लाइन है मॉडल स्टेट की भी।

यहां जो उल्लेख हुआ, बात कर रहे थे कोविड के कालखण्ड में भीलवाड़ा मॉडल की, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के भाषण में भी उसका उद्धरण हुआ और बाकी लोगों ने भी तारीफ की, लेकिन राजस्थान इस बात के लिए भी बदनाम हुआ कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कहीं बर्बाद हुई तो राजस्थान में हुई। वैंटीलेटर्स बर्बाद हुए तो राजस्थान में हुए। और तो और, प्राइवेट हास्पिटल को किराये पर दे दिये गये। यह मैं नहीं कह रहा, यह पब्लिक डॉमेन में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के चार साल के कालखण्ड में पांच अभिभाषण हुए, पांच बजट के भाषण हुए और सरकार के चार साल से भी ऊपर हो गये। 2722 घोषणाएं की गयीं, जिनमें से केवल 49 प्रतिशत पूरी हुई हैं। 1029 बजट घोषणाएं हैं, जिनमें से 350 पूरी हुई हैं और 800 शेष हैं।

किसी प्रदेश की समृद्धि का कारक उसकी कानून-व्यवस्था होती है। राजस्थान में लोग पर्यटन, रिहायश, व्यापार और नौकरी के लिए आते थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में लगभग 9 लाख मुकदमे हैं। एन सी आर बी का आंकड़ा है, जिसमें 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं दिखा था। यदि यहां की सुख, शान्ति और समृद्धि पर ग्रहण लगेगा तो न निवेश होगा, न शान्ति आयेगी और न सद्भाव होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के पूरे कालखण्ड पर जो सबसे बड़ा कलंक है, वह है तुष्टीकरण का, गैंगवार का, बलात्कार का। आपने कह दिया, बलात्कार के 47 प्रतिशत मामले फेक हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे एस एम एस हास्पिटल के बाहर

(श्री सतीश पूनियां)

एम्बुलेंस में कोई भीख मांगती अबला की अस्मत लूट ली जाती है, उसके साथ गैंगरेप होता है। क्या आप उसे फेक बताएंगे? आपने वह दृश्य सीकर में भी देखा होगा। 16 साल की बेटी अपनी गोद में अपने मृत बाप का शरीर लेकर रो रही थी, बिलख रही थी। इस गैंगवार का जिम्मेवार कौन है? इस गैंगवार को पनपाने का दोषी कौन है?

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिसिंग पर ग्रहण लगा, मनोबल गिरा, राजनीतिक संरक्षण में माफिया पनपा और राजस्थान की पुलिसिंग पर बजट में प्रावधान किया, लेकिन केवल पुलिस के संसाधनों के लिए, पुलिस का बजट केवल 3 प्रतिशत है। कैसे कानून-व्यवस्था ठीक होगी? कितनी बार, कितने नजारे, कितने उल्लेख हुए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चर्चाएं यहां हुईं, दूसरा बड़ा कारक है हमारे यहां का किसान। जन घोषणा पत्र में भी, उसके बाद आपके अन्तरराष्ट्रीय नेता के अनेक भाषणों में भी, दस दिन में पूरा कर्जा माफ कर देंगे। माधुरी दीक्षित की तेजाब फिल्म के गाने की तरह गिनती गिना रहे हैं- एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। 1500 से भी ज्यादा दिन हो गये, यदि इसमें सच्चाई होती तो राजस्थान के 18 हजार किसानों की जमीनें नीलाम कैसे होतीं? अब आप कानून बना रहे हैं। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कीं। आपने वह भी देखा होगा कि रायसिंहनगर के ठाकरी गांव के सोहन लाल कडेला ने लाइव वीडियो जारी किया और आत्महत्या करते वक्त कहा कि मैं कर्जे के कारण तंग होकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत का कोई दोषी है तो वह है राजस्थान का मुख्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक डॉमेन में है। केवल यह सोहन लाल कडेला नहीं, सुरजाराम के साथ ऐसा हुआ, राधेश्याम के साथ ऐसा हुआ, राजस्थान के किसानों की इन आत्महत्याओं का कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा कारक है यहां का बेरोजगार, नौजवान और युवा। अभी मेरे से पहले बोलने वाले साथी गिना रहे थे। मैं देख रहा था, इनके भाषण के दौरान, हिन्दुस्तान की बेरोजगारी दर है 7 प्रतिशत और राजस्थान की बेरोजगारी दर है 28.3 प्रतिशत। कम और ज्यादा क्या होता है, आप आकलन करें। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि राजस्थान में पिछले चार बरसों में 10 हजार नौजवानों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें 2400 विद्यार्थी हैं। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। 18-18 परीक्षाएं। बात कर रहे थे

(श्री सतीश पूनियां)

गरीब की, किसान की। उसका बेटा तैयारी करने के लिए शहर में आता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, उसके मां-बाप पेट काटकर उसे कोचिंग सेंटर भेजते हैं, ताकि नौकरी के सपने दिखें और उन्हें पूरा कर सके, लेकिन जब वह परीक्षा केन्द्र पर जाता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया।

राजस्थान में पेपर लीक से बड़ा कोई अपराध नहीं। उस अपराध के लिए आप भले ही आज एंटी चीटिंग एसओजी की घोषणा करते हैं, एटीएस की घोषणा करते हैं, लेकिन क्या फास्ट ट्रैक में किसी तरह की त्वरित कार्रवाई करके किसी दोषी को सज़ा मिलने का काम हुआ? लीपा-पोती की, एक दिन बुलडोजर चलाया, वह भी मकान मालिक पर चला दिया, किरायेदार फरार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विसंगति के कारण राजस्थान का नौजवान, चाहे संविदाकर्मी हो, चाहे सीएचए हो, जितने लोग हैं, जितनी परीक्षाएं दीं, और मैं गिनाऊंगा तो एक लम्बी फेहरिस्त है, लेकिन राजस्थान का नौजवान आज हैरान है, परेशान है, हल्कान है। उसकी दोषी यह सरकार है। कोई रोडमैप नहीं है।

यदि आप स्वरोजगार की बात करें तो राजस्थान के स्टार्टअप्स की रैंकिंग देश के मुकाबले नीचे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बनी तब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना था कि हम जीरो टोलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन जो एसीबी के आंकड़े हैं वे कहते हैं, एवरेज 600 अधिकारी और कर्मचारी हर साल ट्रैप किये जाते हैं। कई लोग आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन मैंने एक आंकड़ा देखा कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में करप्शन होता है, हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी/कर्मचारी पकड़ा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गयी जब एक सार्वजनिक समारोह में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में यह पूछा गया कि क्या तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं? अपेक्षा तो यह थी कि 'न' की आवाज आयेगी, पर उधर से आवाज आती है, "हां, लिए जाते हैं।" फिर भी तसल्ली नहीं होती और दुबारा पूछते हैं कि क्या पैसे लिए जाते हैं? तब भी आवाज आती है कि हां, लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, तबादलों के इस उद्योग ने राजस्थान की राजनीति को कलंकित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस डाक्यूमेंट की, मॉडल स्टेट राजस्थान की, जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति, इनका उल्लेख कर रहा था आपके समक्ष।

इन्दिरा रसोई योजना। भरतपुर में देखा होगा आप लोगों ने, कौन खा रहा था? कितनी अनियमितता थी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका आंकड़ा निकालकर देख लीजियेगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल,

(श्री सतीश पूनियां)

हालांकि मैं इससे नाइत्तिफ़ाक़ी नहीं रखता कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। महात्मा गांधी जी पक्षधर नहीं थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलें खोल तो दीं, लेकिन फैकल्टी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल, इसके भी आप आंकड़े देखियेगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये कुछ मैंने सलेक्ट किये हैं उसमें, आपने इसमें कुछ कम्पन्सेशन देने का तो कारण कर दिया, लेकिन आपके डाक्यूमेंट में, आपकी नीति और नीयत में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सिलिकोसिस को रोकने के लिए क्या करेंगे।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्य मंत्री चले गये। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी। उसके बाद में देश की सरकार आयुष्मान भारत योजना लायी। उसका 600 रुपया भारत सरकार देती है, एक हजार रुपया आप देते हो लेकिन फोटो अपनी है क्योंकि पीआर एजेंसी ने सलाह ऐसी दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट की उन बारीकियों पर आऊंगा जो राजस्थान की नई पीढ़ी से, राजस्थान की तरुणाई से ताल्लुक रखती हैं। राजस्थान की जो ड्राप-आउट है उसको कम करने के लिए आपने स्कूल वापसी के लिए पहले प्रावधान किया था 300 करोड़ रुपये और अभी हुआ है 229 करोड़ रुपये। कम क्यों किया, इसका कोई पता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 जिलों के 2.29 लाख, 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और जो शिक्षा पर खर्च है वह 6 प्रतिशत है, लेकिन प्रदेश के 32 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है, 70 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल तो बिना बिजली के ही हैं और 9 प्रतिशत में न पीने का पानी है, न शौचालय हैं।

उच्च शिक्षा की स्थिति यह है कि आपने पहले 40 खोले, फिर 48 खोले और उसके बाद 31 कालेज खोले। मैं अभी माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, हमारे किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा कि भवन नहीं है, तो मंत्री जी बड़ी सहजता से कह रहे हैं, भले हैं, मित्र हैं मेरे। बोले कोई धर्मशाला देख लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खोलना तो आसान है। दिक्कत यही तो है और मैं मुख्य मंत्री जी को बड़े अदब के साथ घोषणा वीर जी इसीलिए कहता हूं कि घोषणा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं पर लागू करने का कोई रोड मैप नहीं है। इन बातों की चर्चा मैं चार साल बाद कर रहा हूं जब चुनाव में जा रहे हैं। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तब ये घोषणाएं हो रही हैं। आपकी नीति और नीयत ठीक होती तो आप 2018 में करते और 2019 में भवन बनाकर तैयार कर देते तो मान जाते कि आपके पास हुनर है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में भवन नहीं, फैकल्टी नहीं है। एक जगह कालेज में बच्चे दरी पर बैठे थे और एक कालेज में तो बड़ा अजीब दृश्य था कि न फैकल्टी थी, न प्रिंसिपल था और एक लैब असिस्टेंट उस कालेज का इन्चार्ज है, थोड़ा उसको ढुंढवाइयेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लगता है उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2022 में 6795 करोड़ रुपये का पेयजल के लिए प्रावधान किया, 2023 में 5352 करोड़ कर दिये। ये पैसे कम होने से सीधे-सीधे 50 लाख लोग प्रभावित होंगे।

जल जीवन मिशन, देश के प्रधान मंत्री प्रतिबद्ध हैं कि हर घर तक जल जाए और राजस्थान के एक करोड़ लोगों तक जाना है। आपकी देश में 30वीं रैंकिंग है और अभी तक केवल 32 लाख घरों तक आपने यह काम किया है। भारत की सरकार पैसा दे रही है और आपने कहा कि हमारे बस की नहीं है इसलिए योजना का समय बढ़ाया जाए। 2024 तक आपको ये एक करोड़ कनेक्शन देने थे पर आपकी रफ्तार कहती है कि 60 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। यह कमी किसकी है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल और युवाओं के लिए खूब सारी बात हुई। मैंने अभी संयोग से देखा कि बाड़मेर के शिव के कानासर गांव की एक बेटी क्रिकेट खेल रही थी और 36 डिग्री स्ट्रोक्स लगा रही थी। रेत में घरेलू बैट से खेलते हुए मैंने देखा, उसका वीडियो शेयर किया, उससे बात की और मेरे पास तत्काल जो देने का था तथा मैंने क्रिकेट किट पहुंचाया। उसकी एक बहन आलरेडी खेलती है। बाड़मेर के शिव के कानासर जैसे गांव में इस तरीके से खेल की प्रतिभाएं यदि पनपती हैं तो मैंने उससे फोन पर पूछा कि तुम्हें यहां खेलने के लिए क्या चाहिए, तो उसने कहा कि हमारे यहां खेल का मैदान नहीं है, पर आपकी घोषणा तो 2018 में हो चुकी थी कि आप हर पंचायत पर खेल का मैदान खोलेंगे, कोचेज की भर्ती करेंगे। जिस तरीके से पुराने खिलाड़ी जलील होते हैं, मैडलिस्ट जलील होते हैं कि उनका भत्ता समय पर नहीं मिलता, उनका बकाया समय पर नहीं मिलता, उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं है। आप दूसरे प्रदेशों से सीख लीजिये, पंजाब और हरियाणा से सीख लीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में एक चुनौती है पोषण की और वह महिलाओं में और खासतौर पर बच्चों में। भारत की सरकार ने एक

(श्री सतीश पूनियां)

इनिशिएटिव लिया है कि उनका पोषण ठीक हो। राजस्थान की सरकार भी आंगनबाड़ियों में पोषाहार की व्यवस्था करती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर जब सवाल खड़ा हुआ तो माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि हम यह पोषाहार खाकर फिर आगे भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना खाया जाता है इस पोषाहार में क्योंकि ये घोटाले भी सरकार के नाम लिखे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। इन्हीं की किताब है आर्थिक समीक्षा, जो राजस्थान की सरकार प्रकाशित करती है, अच्छे-अच्छे फोटो लगे हुए हैं। अभी कृषि पराशर का एक चौथा श्लोक माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पढ़ा था पर वह तीसरा भूल गये जिसमें किसान को अन्नदाता बताया, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि सरकार ने याचक बना दिया। जो बजट के प्रावधान 2021 और 2022 के थे वे यदि आप देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि उसका एग्जिक्यूशन आप इतने कम समय में कैसे करेंगे। 10,990 करोड़ रुपये का कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 2021 में प्रावधान किया और 2022 में 3,645 करोड़ का। ग्रामीण विकास के लिए 17,486 और 12,012 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए 52 हजार और जीरो, कोई प्रावधान नहीं। सिंचाई और बाढ़ के लिए 3750 करोड़ रुपये और 1,765 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिए 24 हजार करोड़ रुपये और 15,905 करोड़ रुपये, उद्योग और खनिज के लिए 1,389 और 1,143 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर एक लम्बी फेहरिस्त है लेकिन यहां फैंकी लम्बी-लम्बी जा रही थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सतत विकास लक्ष्य को लेकर एसडीजी का एक इंडेक्स प्रकाशित होता है जिसमें भारत के और राजस्थान तथा अनेक राज्यों के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। इसमें उन्होंने अलग-अलग कैटेगरीज बना रखी हैं कि एस्पायरेंट कौन है, अचीवर कौन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में 2020-21 में जो हमारा गोल है वह 60 है। हम लोगों के बीच में शुद्ध जल और स्वच्छता का है वह 54 है यानी बिलो 60 है। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास में 57 है, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना में 45 है। असमानताओं में कमी लाना, जो इनके भाषण में उल्लेख होता है कि हम डिस्पेरिटी को खतम करेंगे, उसमें हम लोग 45 हैं। जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेटिक चैंजेज पर खूब बड़ी बहस होती है और उसमें राजस्थान भी अछूता नहीं है और 49 है। भूमि पर जीवन, हैबिटेशन के लिए 43 है। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं में

(श्री सतीश पूनियां)

73 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि क्रमिक रूप से इसका उल्लेख करेंगे तो हमारी रैंकिंग ग्रेजुअली कम होती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो यहां जिक्र हुआ कि हमने इस बजट के तमाम आंकड़ों में भारत सरकार के मापदण्डों और एफ आर बी एम एक्ट का उल्लंघन तो किया ही है, लेकिन अक्सर एक चर्चा होती है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के भाषण में भी उसका उल्लेख हुआ था, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लगातार बढ़ा और मैं इसका अभी का उल्लेख करूं तो केन्द्र सरकार से करों का हस्तान्तरण राज्य सरकार के अनुमान से अधिक रहा है और संशोधित अनुमानों में, 2022-23 में यह वृद्धि 8019 करोड़ रुपये की देखी गयी है। बात केन्द्र सरकार की नहीं है, प्रदेश की है कि वहां का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और यह तो आपको ही तय करना है कि आप इसको किस तरीके से ठीक करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया, जिक्र किया उसमें एलोकेशन भी मैटर करता है। आपने कृषि विभाग के लिए एलोकेट किये 4127 करोड़ रुपये 2022-23 में और 2023-24 में 3306 करोड़ किये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 350-325, सहकारिता के लिए जो बहुत बड़ा सेक्टर है, जो देश और प्रदेश की आर्थिक नींव को गति देता है वह 2256 करोड़ रुपये-1483 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आवास में 7146-1000, विद्युत के लिए 25260-25191, जिलों की सड़कों के लिए 510-150, स्कूल वापसी में 300-229, मैं उसका उल्लेख कर पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इतना ही करूंगा कि जो दुष्यंत कुमार ने कभी कहा-

"कहां तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए,
कहां तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए,
कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए,
मुझे लगता है कि इसके दोषी कोई हैं तो,
अब तो इस हाथ को बदल दो यारो,
ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे हैं,
ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे हैं।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी, एक मिनट। श्री महेन्द्र जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये राठौड़ साहब नाराज कैसे हैं? ये बोल रहे थे, पक्के जनसंघी हैं, लेकिन राठौड़ साहब उदास क्यों हैं?

श्री अध्यक्ष: आप बाद में पूछ लेना। इसके बारे में आप भी ज्यादा जानते हो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मेरे ख्याल से। मैंने उनका भाषण सुना, क्योंकि माननीय कटारिया साहब नेता, प्रतिपक्ष थे, वे आसाम के माननीय राज्यपाल बन गये हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी शुभकामनाएं भी हैं। आसाम में वहां पर राजस्थान के हमारे हरिदेव जोशी जी, श्री शिवचरण माथुर जी और गुलाब चन्द कटारिया जी राज्यपाल बने हैं। आप वहां जाकर कामयाब हों, मेरी ये शुभकानाएं आपके साथ में हैं। आपके वहां विराजने से राजस्थान का मान-सम्मान बढ़े, हम सबका यह सपना रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें कही हैं। जब पस्कैपिटा इनकम बढ़ती है तब एक अहसास होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा

(श्री अशोक गहलोत)

क्योंकि हमारा तमाम तरह का वित्तीय प्रबन्धन इतना शानदार रहा है, उसके कारण ही हम लोग हर पैरामीटर में कामयाब रहे हैं और यह स्थिति बनी है कि हम सोशल सिक्योरिटी को मुख्य ध्येय बनाकर चल सकें वरना सम्भव नहीं था कि हम बड़ी-बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और किसानों के लिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम, युवाओं के लिए, पेंशनधारियों के लिए, जिस प्रकार का बजट दिया गया है, उसकी चर्चा राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अन्दर हो रही है। बल्कि, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा यह जो बजट का डाक्यूमेंट है, मैं स्वयं हर मुख्य मंत्री को भेज रहा हूं, वह अलग बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि आगे जहां-जहां चुनाव होंगे, वहां-वहां पर सभी राजनैतिक पार्टियां हमारे बजट के डाक्यूमेंट को आधार बनाकर अपना मेनिफेस्टो बनायेंगी।

आपका दिल जानता है, ऊपर से कुछ भी कहो, वह अलग बात है, बहुत शानदार, समग्र विकास वाला बजट पेश किया गया है। मैंने पर-कैपिटा इनकम की बात इसलिए कही, राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 56 हजार 149 रुपये रही, जो कि गत वर्ष से 14.85 प्रतिशत अधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10 प्रतिशत और इस वर्ष 14.85 प्रतिशत रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले चार वर्षों में 10.01 प्रतिशत की औसत वृद्धि देखी गई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 7.89 प्रतिशत ही रही है। गत तीन वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय वाले पिछड़े राज्यों से निकलकर के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। सांख्यिकीय कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2022 में जारी विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी के अनुसार, विभिन्न राज्यों में गत 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में हो रही वृद्धि दर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सदन के माननीय सदस्यों के सुनने लायक है। पिछली सरकार के वक्त में 2016-17 में 21वें पर, 2017-18 में 30वें पर, 2018-19 में 19वें पर रहा था। राज्य सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान 2019-20

(श्री अशोक गहलोत)

में 12वें, 2020-21 में 10वें और 2021-22 में 9वें स्थान पर रहा है। यह प्रकट करता है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये समावेशी बजट कुशल आर्थिक प्रबन्धन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बढ़ते दायरे के कारण राजस्थानवासियों की प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है कि राज्य का जो बजट पेश किया गया, उस वक्त हमारी थीम क्या थी। उसी रूप में भारत सरकार की जो मंशा है, वह भी सबके सामने है, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा के अन्दर भी और अभी दौसा के अन्दर जिस प्रकार के भाव प्रकट किये, वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं, क्योंकि आप राज्य सरकारों के बारे में जो कमेंट कर रहे हो, यह फेडरल डेमोक्रेसी के अन्दर उचित नहीं है।

केन्द्र सरकार को हमेशा आगे आकर राज्यों की इमदाद करनी चाहिए। यहां उलटी गंगा बह रही है। माननीय कटारिया साहब तो बोल नहीं रहे हैं वरना ये तो ऐसी पैरवी करते कि केन्द्र सरकार तो आपको इमदाद करती है, फिर भी आप उनको दोष देते हो। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, यह तो आंकड़े बोलते हैं। मैं क्या करूं?

आप तो आंकड़े देखिये, भारत सरकार ने हर क्षेत्र में खर्चे के अन्दर अधिक कटौती की है। वैसे तो बहुत लम्बी लिस्ट है लेकिन मैं आपको पांच बताना चाहूंगा, पर्यावरण वानिकी में 40 परसेंट, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में... माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दौसा के अन्दर रैली में कहा कि राज्य में बोर्डर पर 50 साल में सड़कें इसलिए नहीं बनीं, ऐसा ही भाव था उनका कि जिससे कहीं दुश्मन देश के लोग इधर सड़कों पर न आ जाएं। अब आप बताइये, ये कोई कमेंट था? आज वे जब ऐसी बात कह रहे हैं, उनको चिन्ता होनी चाहिए थी, बल्कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्दर 71.70 परसेंट की कटौती कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 17.54 परसेंट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 30.47 परसेंट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 32.90 परसेंट, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 30 परसेंट की कटौती की और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 71.19 परसेंट की और नरेगा में जो कटौती की है, वह सबको मालूम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार रवैया अपना रही है, कमियां कर रही है, यह क्या दर्शाता है?

(श्री अशोक गहलोत)

क्योंकि कटौती करना, मैंने पिछली बार सदन को बताया था और खर्च नहीं करना एक ही बात है। हमें दोष देते हो कि आप खर्च ही नहीं करते हो, आपको पैसा भेजते हैं। अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई कि कहां-कहां पर इतना पैसा उनका खर्च नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से मनरेगा में 32.88 परसेंट की कटौती की, मिड-डे-मील में 10 परसेंट लगभग, यूरिया सब्सिडी में 14 परसेंट, अनुसंधान के अन्दर 13%, आईसीडीएस में 38%, एनएफएसए में 17%, इलैट्रोनिक्स और आईटी हार्डवेयर में 41%, अटल पेन्शन योजना में 28% कटौती, पवन ऊर्जा में 14% और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 7%। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो कटौतियां तो की ही हैं, अभी जो नया इनकम टैक्स का स्लेब दिया तो सबको भ्रमित कर दिया। जो लोग अपेक्षा करते थे उसके आधार पर तो नहीं मिला, बल्कि एलआईसी, पीपीएफ, पीएफ, एनपीएस जहां लोग जमा कराते हैं, बुजुर्ग लोग भी और बाकी अन्य लोग भविष्य को देखते हुए 80सी की छूट होती है, 80जी की होती है उन सबमें कटौती कर दी गई। इस प्रकार से मैं समझता हूं उचित नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है वह पहले भी मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक बार सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखा था कि क्या कारण है कि एक तरफ तो भारत सरकार टीम इंडिया की बात करती है, टीम इंडिया के मायने क्या हैं, सभी राज्य सरकारें और केन्द्र मिल कर टीम बनायें, यहां कौनसी टीम इंडिया मजबूत हो रही है, समझ के परे है। राज्यों के साथ किस तरह भेदभाव सरकार कर रही है, उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग ने 32% से 42% कर दिया जो संवैधानिक संस्था है। एक प्रकार से वह उसने राज्यों का हिस्सा बढ़ाया। बहुत खुशी की बात है, पर उलटा रास्ता निकाल करके वो तमाम जो बढ़ाया हुआ था उसको बराबर कर दिया। कैसे कर दिया, एक तरफ तो पहले जो शेयरिंग पैटर्न था राज्यों के साथ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में हण्ड्रेड परसेंट केन्द्र का और जीरो राज्यों का, अब 40:60 कर दिया। राज्य कृषि विकास योजना में 100% था केन्द्र का यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, जीरो था राज्यों का, अब उसको भी कर दिया 40:60. समेकित बाल विकास सेवाओं में 90:10 था, अब

(श्री अशोक गहलोत)

40:60. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 75:25 था राज्यों का, अब 40:60. मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई निर्माण में 90:10 था, अब 40:60. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 75:25 था, अब 50:50. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 75:25 था, अब 60:40. समेकित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम में 100:0 था, अब 40:60. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 100:0 था, अब 40:60.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जगह पर जो बढ़ाया गया था एक तरफ तो यह पैटर्न कर दिया और दूसरी तरफ आप आगे सुनियेगा कि नयी एप्रोच भारत सरकार की हो रही है कि पैसा जो है, संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें जमा कराते थे पहले सीएसएस का फंड, उसकी बजाय नया तरीका निकाला है कि बैंक में जमा करवायेंगे। इनसे पूछो, क्यों करवायेंगे वहां पर? जो लिक्विडिटी होती है राज्यों के पास में तो वो अपने आराम से काम कर सकते हैं, उस लिक्विडिटी को खतम करने के लिए इस प्रकार से कि आइडल पड़ी रहे मनी बैंकों में तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहनी चाहिये। उसका फैसला किया। पीडी खाते में जो सरकार की राशि वो दे रहे थे इसका नुकसान राज्यों को हो रहा है, उसको भी पीडी खाते में नहीं दे रहे हैं।

जल जीवन मिशन में जो केन्द्र का हिस्सा है वो भी हम बैंकों में जमा करवायेंगे, आपको नहीं देंगे। अब आप मुझे बताइये, और तो और, अभी एक नया पायलट प्रोजेक्ट का मैसेज दिया गया है राज्य सरकारों को कि हम चाहते हैं कि आप ही पूरा पैसा खर्च करो, स्टेट का भी और केन्द्र का अंश भी, उसके बाद में हम आपको देंगे। बताइये आप, यह कौनसा तरीका है, किस तरह से यह क्या चाहते हैं?

मैं इस मौके पर सदन में निवेदन करना चाहता हूं और इसका क्या फाल-आउट हुआ है, कितना सीरियस हुआ है, सकल केन्द्र का जो कर है 33 लाख 52 हजार 79 करोड़ का 41% होता है 13 लाख 74 हजार 352 करोड़, यह बंटना चाहिये। राजस्थान का हिस्सा आता है 6.0026%, 82 हजार 818 करोड़ रुपये मिलने चाहिये और 2023-24 के बजट में राज्य का हिस्सा रखा गया है 61,552 करोड़, मतलब 21,266 करोड़ कम मिलेंगे राजस्थान को। किस कारण से मिलेंगे? यह समझ से परे है कि ये अचानक कम क्यों कर रहे हैं वो? क्या कारण है और 21 हजार 266 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती है।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, यह सब बातें मैं इसलिये कह रहा हूं, हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी बैठे हुए हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? आप यहां विपक्ष में हैं, केन्द्र में आप लोग सत्ता में हैं। क्या आप में से कोई लोग या आपके 25 एमपी साहब, केन्द्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, कभी राजस्थान की पैरवी करते हैं वो? नहीं करनी चाहिये क्या उनको? आज मान लीजिये आपकी सत्ता वहां पर है, मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि जब-जब ऐसी स्थिति बनी है राज्यों के अन्दर, पक्ष और विपक्ष मिल कर गये हैं वहां पर कई राज्यों के और प्रधान मंत्री जी को वहां पर अपनी बात बताई है, अपनी शिकायत बताई है, अपने सुझाव दिये हैं, पर मैंने देखा चार साल पूरे हो गये, आपने कभी इस प्रकार का सहयोग नहीं किया। यह मेरा आरोप है आप सब पर, नेता, प्रतिपक्ष पर भी। जीएसटी कमीशन का पैसा गारंटी देकर लोन के रूप में दे दिया। वाह, किस प्रकार से तंग करेंगे, यह नमूने हैं सब आपके सामने।

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, कई बार समझ में नहीं आता कि हम लोग सब जनता के सेवक के रूप में आकर बैठे हुए हैं और जो जनता के इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट होते हैं उनको आप लोग क्यों इस प्रकार का व्यवहार करते हो, यह मेरी समझ के परे है।

पूनियां साहब बड़ी-बड़ी सैद्धांतिक बातें कर रहे थे, सुन रहा था मैं। कोई दम नहीं है उनमें। मैं यह कहना चाहूंगा, अगर दम है, पूनियां साहब, आप अध्यक्ष भी हो, अध्यक्ष का एक अलग रुतबा भी होता है, ओरा भी होता है और सब लोग आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं पूरे राजस्थान की बीजेपी की रैंक-एंड-फाइल बहुत बड़ा पद होता है, मैं इसको मानता हूं, मैं तीन बार रहा हूं यहां पर, मैं जानता हूं पद की क्या गरिमा है। क्या आप जाकर कहेंगे प्रधान मंत्री जी को तो आपकी बात नहीं समझेंगे वो? पर नहीं कहा आप लोगों ने, उसके कारण से प्रधान मंत्री जी ने जो बातें बोली हैं वहां पर इस रूप में गुमराह किया है राजस्थान वासियों को। मध्य प्रदेश, राजस्थान को मिला करके नयी बात छेड़ दी, पार्वती, कालीसिंध, चम्बल लिंक-ईआरसीपी को मर्ज करके नयी योजना बना देनी चाहिये तब हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे, योजना मैंने बनाई है? रिफाइनरी मैंने लगायी थी, उसको तो बन्द कर दिया आप लोगों ने वसुन्धरा जी के वक्त में। पांच साल नहीं चलने दिया उसको, आज 40 हजार का प्रोजेक्ट 70 हजार करोड़ का हो गया, वो। कौन दोषी हैं? आप लोग दोषी हैं। आपकी पार्टी दोषी है।

(श्री अशोक गहलोत)

इसका जवाब दें मुझे, ईआरसीपी वसुन्धरा राजे जी ने कंसीव किया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों स्टेट की मीटिंग हुई 2005 में। समझौता हुआ, उसको आधार बना कर यह योजना बनायी गयी है। अब वह पैरा मैं पढ़ कर सुनाऊं, आपको तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, 'राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीच में अन्तरराज्यीय जल समझौते के सम्बन्ध में राजस्थान, मध्य प्रदेश अन्तरराज्यीय नियंत्रण मण्डल की 13वीं बैठक जो 25 अगस्त, 2005 को हुई थी, जिसमें निर्णय किया गया। राज्य की इसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त सम्पूर्ण पानी एवं दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10% प्रयोग कर योजना बना सकते हैं।' इसी आधार पर योजना बनाई गई। मध्य प्रदेश ने अपना बांध बना लिया और फंडिंग लेनी थी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसीज से। ले ली फंडिंग और राजस्थान की गवर्नमेंट को आपने एनओसी भी दे दी।

जब हमारा हक ईआरसीपी आ रहा है, सरकार बदल गई तो क्या हो गया, यह योजना तो आपके वक्त की है। इस योजना को पूरा करने में अड़चन क्यों पैदा की जा रही है, यह मेरी समझ से परे है। इतनी शानदार योजना को आप लोग क्यों बंद करने जा रहे हो? इसके लिए राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने सुझाव दिया है, उसके अनुसार, अभी की ईआरसीपी बनाई वसुन्धरा जी ने, उसमें 3500 मिलियन क्यूसेक्स मीटर पानी चाहिये जबकि प्रधान मंत्री जी जो नई योजना बता रहे हैं, किसकी सलाह से बता रहे हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि इस काम के लिए उनके सलाहकार कौन हैं? उसमें आधा पानी, 1775 मिलियन क्यूसेक्स मीटर पानी ही 13 जिलों को मिलेगा। आप लोग बताइए कि आप चाहेंगे कि इन 13 जिलों का पानी हमें आधा ही मिले? आप स्वीकार करोगे उसको? स्वीकार करोगे तो बताइए जनता को कि क्यों स्वीकार करेंगे आप लोग? यह तो आंकड़े बताते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कर्नाटक ने ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 21,450 करोड़ है, उसे राज्य परियोजना का दर्जा देने की मांग की थी वहां राज्य में। राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन कम से कम 2022-23 बजट में आपकी सरकार ने 5300 करोड़ रुपये उनको दिये। राजस्थान को जीरो। हम रख रहे हैं 9500 करोड़ रुपये, इस बजट में बढ़ाकर मैंने उसके लिए 13,500 करोड़ कर दिये।

आप और नई बात सुनिए, 2 लाख हैक्टेयर सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। जो प्रधान मंत्री जी ने सुझाव दिया है, उसके अनुसार आधा पानी और

(श्री अशोक गहलोत)

2 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई नहीं हो सकेगी। अब बता दीजिए किसान विरोधी कौन है? एक और बात, नये सुझाव में 13 बांधों में पानी मिलेगा। परियोजना का कितना पैसा भारत सरकार दे रही है, यह नहीं बोलेंगे। वह कहते हैं पहले मध्य प्रदेश से बात करो। हम क्यों बात करें? यह पानी का विषय हमारे स्टेट का है, हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ाते जायेंगे। यहां हमारे बाड़ी से आने वाले विधायक ने ठीक कहा, पानी हमारा, आधी जगहों पर बाढ़ से नुकसान हमारा हो रहा है और आधे जिलों में लोग प्यासे रह रहे हैं और परमिशन हम मध्य प्रदेश से लेवें, जबकि आपके साथ मध्य प्रदेश का एग्रीमेंट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह राज क्या है, बताइए? राज आप बता सकते हो। चूरू से आने वाले विधायक, आप बता सकते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी बता दूं या बाद में बताऊं?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह राज क्या है? राज, राज ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राज को राज रहने दो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह तो आप कहोगे, हम क्यों रहने देंगे? हम तो यह कहेंगे क्योंकि वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री नहीं रहीं, उनकी कंसीव की हुई योजना है। आप जानबूझ कर उस योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी, आपसे यही बुलवाना चाहते थे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ठीक कहा आपने। आप उनकी नेचर जानते हो।

यह तो आप मानेंगे मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में इसी निर्णय के आधार पर नेवज नदी पर मोहनपुरा बांध एवं कालीसिंध नदी पर कुंडल्या बांध का निर्माण किया है एवं परियोजना के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज के लोन के लिए जरूरी होने पर परियोजना पूरी होने के बाद राजस्थान से एनओसी ली है और आपने दी है। गौरतलब है कि काम पूरा होने के बाद यह एनओसी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा ही जारी की गई। आपने उनके साथ बड़ी सदाशयता दिखाई क्योंकि यह भाई-भाई हैं, वहां पर भी आपकी सरकार थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभी आमेर से आने वाले सदस्य ने कोरोना को लेकर भी सरकार की आलोचना कर दी। कम से कम

(श्री अशोक गहलोत)

इसको तो बख़्शते आप, क्योंकि हमने आप सबको साथ लिया है। मैं कहीं इंटरव्यू देता हूं तो अभी तक बोलता हूं, विपक्ष के साथियों की चर्चा करता हूं। तीन दिन पहले ही मैंने टीवी वालों को एक इंटरव्यू दिया है। मैंने कहा कि हमने सबने मिलकर उसका मुकाबला किया। आपने यहां पर भी मीनमेख निकाल दी। आप भूल जाते हो क्या? गंगा नदी के किनारे लाशें पड़ी थीं, भूल जाते हो आप लोग। गंगा में बहती लाशें भूल जाते हो आप लोग। क्या नहीं किया आप लोगों ने। आक्सीजन की वजह से इतने लोग मरे हैं। केन्द्र सरकार को यह देश कभी माफ नहीं कर सकता, इतने लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं। कोई तैयारी ही नहीं रखी, दूसरी लहर आ गई, समझ नहीं पाये कि इतनी बड़ी लहर आ सकती है। अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने फरवरी-मार्च, 2020 में कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है, भारत सरकार संभल कर चले। उन्होंने चेतावनी दी थी। अगर उनकी बात को गंभीरता से लेते तो शायद इतनी मौतें नहीं होतीं। मुझे बताइए इसका कारण क्या है?

अध्यक्ष महोदय, गुजरात में एक उदाहरण पेश हुआ। मरीज कारों में, ट्रकों में, बसों में, एंबुलेंस में बाहर बैठे-बैठे ड्रिप लगवा रहे थे। मेरे अभी निमोनिया हो गया था तो मुझे 12 ड्रिप लगी है। मुझे मालूम है ड्रिप लगाना किसे कहते हैं? देश में बाहर सड़कों पर ड्रिप लग रही है, पूरी दुनिया देख रही है गुजरात को। आपको सरकार बदलनी पड़ी। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार मुख्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों की आपने छुट्टी कर दी और नये लेकर आ गये क्योंकि आपको मालूम है यह नमूना था कोविड की फेल्योर का जो गुजरात में उस समय ज्यादा था। आप क्यों भूल जाते हो? आप कहते हो वैक्सीन, अध्यक्ष महोदय, मैंने वीसी में प्रधान मंत्री जी से बात की। मैंने कहा कि आप गलत काम कर रहे हो, आप वैक्सीन को लोगों से पैसे में मत लगवाइए, इसको आप फ्री कीजिए। मैंने यह भी कहा कि जहां तक मेरे को अनुभव है, बचपन से देखते आये हैं कि सारी वैक्सीन फ्री लगती हैं। यह तो कोविड है, विश्वव्यापी महामारी है। प्रधान मंत्री ने उस वक्त तो कोई कमेंट नहीं किया, बाद में जब और जगहों से दबाव पड़ा होगा तब जाकर उन्होंने घोषणा करी कि हम वैक्सीन फ्री लगायेंगे, यह क्यों भूल जाते हो? उनको करना पड़ा, मजबूर होकर करना पड़ा।

आप गौ भक्त बनते हो, गौ भक्त आप हो या यह हैं, मालूम पड़ गया आपको भी। निदेशालय मैंने बनाया, मैंने पहली बार गौशालाओं के लिए

(श्री अशोक गहलोत)

प्रोविजन किया, यह तो सच्चे आंकड़े हैं। आपने खाली नाम बदल दिया, वसुन्धरा राजे जी के वक्त में आपने निदेशालय से विभाग बना दिया। अब क्या है? अब मेरे पास पूरे आंकड़ें हैं। आपने नंदीशालाओं को 3 महीने से 6 महीने तक दिया था, हमने नंदीशालाओं के लिए 12 महीने कर दिया। आपने चार साल में 143 करोड़ रुपये अनुदान दिये, हमने चार साल में 2313 करोड़ रुपये अनुदान दिये। यह गौ भक्त बैठे हैं, बता देंगे आपको। आगे सुनिए आप, अभी लम्पी रोग आ गया। लम्पी रोग किसी के हाथ में तो नहीं है। हमने भारत सरकार से मांग की कि कृपा करके इसको आप कोविड की तरह ट्रीट करो और इसके लिए आप किसानों को थोड़ा मुआवजा दो। हमारी बात स्वीकार नहीं की गई। आप मना लीजिए उनको। हमने कहा है कि हम मरने वाली गायों के 40 हजार रुपये प्रति गाय पैसा देंगे। आप गौ भक्त हैं, आप लोग गौ भक्त हो? राम भक्त भी आप हो, गौ भक्त भी आप हो, वोट लेने के लिए। आपकी और कोई हमदर्दी नहीं है गायों से। हमने यह भी कहा है आगे भविष्य में हमने बजट में दुधारू पशुओं के लिए बीमा किया है। 40 हजार रुपये प्रति गाय देंगे हम लोग। हिन्दुस्तान में है कहीं पर? हिन्दुस्तान में है क्या कहीं पर? गौ भक्त कौन हुए, बता दीजिए आप मुझे।

अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे ही नहीं आ गये हैं। आज आर्थिक विकास दर में देश में नंबर दो पर आये हैं, ऐसे ही आ गये क्या? पूरा चिट्ठा मेरे पास है। 11.4 आन्ध्र प्रदेश और हम लोग 11.04 पर दूसरे नंबर पर आ गये। कैसे आ गये, ऐसे ही आ गये?

मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जिस रूप में अप्रोच बना रखी है, उसका हमें दुःख है। किस प्रकार से इस अप्रोच से आने वाले वक्त में हम कैसे उम्मीद करें कि हमें वे किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स शानदार हैं। हमने सोशल सिक्योरिटी में किसानों को बिजली में छूट दी है और उपभोक्ताओं को भी दी है। युवाओं के लिए कई स्कीमें बनायी हैं। एक करोड़ के लगभग को हम पेंशन दे रहे हैं। हमने अभी पेंशन की राशि बढ़ायी है। हम 9 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं मेरे साथियों को कहना चाहूंगा कि यह तो संवेदनशीलता की बात है। आप मुझे बताइये कि 9 लाख 60 हजार, और हम लोग 90 लाख लोगों को दे रहे हैं। उन 9 लाख 60 हजार को वे 200-300 रुपये दे रहे हैं। मतलब कि लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं और हम लोग 9 हजार करोड़ रुपये दे रहे

(श्री अशोक गहलोत)

हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हमने मिनिमम एक हजार रुपये कर दिये हैं, जिनके पांच सौ रुपये थे, उनके भी और जिनके साढ़े सात सौ थे, उनके भी। अब हमारे उसके अन्दर 11-12 हजार करोड़ रुपये लगेंगे। उसके दो-ढाई हजार करोड़ बढ़े हैं, तब भी हमने मंजूर किया। केन्द्र सरकार से मुश्किल से चार सौ करोड़ रुपये मिल रहे हैं। उन्नीस-बीस का थोड़ा-बहुत अन्तर चल जाता है। हमने कहा कि पूरे देश के अन्दर इसको आप सपोर्ट करेंगे। जो माननीय राज्यपाल महोदय बनने वाले हैं या शपथ लेने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति भवन में मीटिंग होती है, आप इस मुद्दे को उठायें। मैं नेशनल लेवल पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डा. मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने आजादी के बाद पहली बार अधिकार युग की शुरुआत की। आपने पार्लियामेंट में कानून बना दिये, आरटीआई, नरेगा, आरटीई और सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए। पांचवां कानून Right to Social Security पूरे देशवासियों के लिए बनना चाहिए। बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, नि:शक्तजनों के लिए।

मुझे आश्चर्य होता है। आप धार्मिक, हिन्दू धर्म, हिन्दू-मुस्लिम करके दिल्ली के अन्दर भी शासन में आ गये। यहां पर भी आपको यही उम्मीद है। हमारी शानदार परफोर्मेंस, एंटी-इनकंबेंसी नहीं है। आपको उम्मीद यही है कि हम तो हिन्दू-मुस्लिम के नाम से सत्ता में आ जायेंगे। मुझे बताइये कि आप किस रूप में यह बात सोचते हैं? आप सोचते ही नहीं हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं? मेरे तो समझ के परे है कि आपने किस प्रकार से यह जो हिन्दू धर्म का आवरण ओढ़ रखा है। राहुल गांधी जी की देश की यात्रा का मकसद यही था, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा प्रेम, मोहब्बत, भाई-चारा। क्या यह नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। साथ में, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वह खाई नहीं बढ़नी चाहिए। वे यही तो बात कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? उसके लिए हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिले और वे आगे बढ़ सकें, पर जिस रूप में आपने कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, कर्ज की बात की गयी। मैं माननीय पूनियां साहब को कहना चाहूंगा कि हम जब सरकार से गये थे, तब जीडीपी के अनुपात में 23.58 परसेंट कर्जा था। आपने सत्ता छोड़ी तो यह 34.16 परसेंट हो गया, मतलब आपने 10 परसेंट कर्जा बढ़ाया। जब हम वापस आये और हमने जो बजट पेश किया है और जो बजट एस्टीमेट रखे हैं, उसमें आप देखिये, सिर्फ

(श्री अशोक गहलोत)

ढाई परसेंट बढ़ा है। 34.16 से 36.78 परसेंट हुआ है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि किस के वक्त में कितना कर्जा बढ़ा? यह सब आंकड़ों के रूप में आपके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे फिस्कल पैरामीटर्स शानदार हैं। हमने वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार कर रखा है। उसके कारण ही हम ये स्कीम्स लाने में सक्षम बने हैं। अध्यक्ष महोदय, उसकी मैं झलक बताना चाहूंगा। भारत सरकार 2023-24 का फिस्कल डेफिसिट 5.9 परसेंट रखा है और हमने 3.98 परसेंट रखा है। रेवन्यू डेफिसिट भारत सरकार का 2.91 परसेंट, हमारा 1.58 परसेंट है। 2021-22 में केन्द्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट 6.7 परसेंट और हमारा 3.96 परसेंट रहा है, उनसे कम रहा है। उनका रेवेन्यू डेफिसिट 4.1 परसेंट रहा, हमारा 2.12 परसेंट रहा। आप मुझे बता दीजिये कि ये जो पैरामीटर्स हैं, जो कि भारत सरकार ने तय किये हैं, एफआरबीएम एक्ट के अन्तर्गत 2005 में वाजपेयी जी की सरकार के वक्त में यह एक्ट बना था, उसके अन्दर आप बता दीजिये कि जिस प्रकार की व्यवस्था की गयी, उसके अन्दर हमारे पैरामीटर्स ये हैं।

सबसे बड़ी बात, मैं फिर कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय करों में से राजस्थान को कम ट्रांसफर की गयी राशि। अब आप सुनिये। पता नहीं आपको दु:ख होगा या नहीं होगा, हमें तो बहुत दुख है कि 2019-20 में हमारे 10 हजार 284 करोड़ कम कर दिये, ग्रॉस रेवेन्यू। 2020-21 में 13 हजार 974 करोड़ कम कर दिये। 2021-22 में 12 हजार 756 करोड़ कम कर दिये। 2022-23 के अन्दर 17 हजार 755 करोड़ रुपये कम कर दिये। 2023-24 में जो एस्टीमेट है, वह 21 हजार 266 कम होंगे। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 76 हजार 35 करोड़ रुपये भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के कम किये हैं, जो कि देने थे। आप बताइये। तो आप बता दीजिये कि क्या कारण है? इसका कोई कारण है? डिविजिबल जो पूल होता है एक्साइज का, उसको उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी को तो कम कर दिया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। उन्होंने कम करने के तरीके भी निकाल दिये। वह भी हो गया।

अध्यक्ष महोदय, जब बीजेपी की सरकार थी, तब आप देखियेगा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 10.60 परसेंट थी और हमारे वक्त में यह बढ़कर 11.80 परसेंट हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाती है कि

(श्री अशोक गहलोत)

इंफ्रास्ट्रक्चर तब बनेगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। मैं आपको वे आंकड़े बताना चाहूंगा। यह तो लम्बी फ़ेहरिस्त है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे पांच साल में बीजेपी के शासन में आप लोगों ने 80,629.15 कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, उससे दुगुना हम लोगों ने 120437 करोड़ रुपये का हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है। ये सड़कें हम आप लोगों को ऐसे ही दे रहे हैं? शहरी इलाकों में सड़कें आ रही हैं, गांवों में सड़कें आ रही हैं। शानदार नेशनल हाईवे बना है, इसमें कोई दोराय नहीं है, पर स्टेट हाईवे भी। मेगा हाईवे की आपकी सोच थी, जब वसुन्धरा जी थीं, तब की सोच थी, उसको हमने आगे बढ़ाया। हम आपकी तरह नहीं है कि हम सरकार बदलते ही उलट चलने लग जायें। हम सीधे ही चलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो आज स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, विलेज रोड का जो जाल बिछ रहा है, उसके कारण से आज 1 लाख 20 हजार 437 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडीचर हम लोग राजस्थान में कर रहे हैं, जो कि आपसे दुगुना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक तुलना करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार मैंने हमारा और बीजेपी की सरकार के बजट को कम्पेयर किया था। रात-दिन का फर्क था। उसके अन्दर 30-35 पैरामीटर्स थे और सबने उसमें खूब मेजें थपथपाई थीं। आपको याद है? आपके साहस की भी मैं दाद दूंगा। फिर भी आप में इतनी हिम्मत है कि उसके बाद भी आपने बजट की आलोचना करने में कोई कमी नहीं रखी। यह तो आपको कहना पड़ेगा। आपके अन्दर यह जो साहस की बात है कि जो तुलना ही नहीं की जा सकती थी चार साल के कामों की। उसके बाद भी आप में हिम्मत है कि कई गुना पीछे होने बाद भी आपने ऐसी तुलना की। चलिये पांच, एक तो सोशल सिक्योरिटी, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, खेल और कला। ये जो चार-पांच हैं, इनको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि आपके वक्त में 72,835 करोड़ आपने खर्च किये, सब मिलाकर, पांचों सालों में। हम लोग 1 लाख 29 हजार 695 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। इसमें 63.62 तो शिक्षा में हो गया, 86 परसेंट के लगभग स्वास्थ्य में, 85 परसेंट से ज्यादा जल में, सामाजिक सुरक्षा के अंदर 104 परसेंट, कुल 78.07 परसेंट, यह स्थिति है। बताइए आप, आपसे कोई कम्पेरिजन हो सकता है?

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बहुत सारे कम्पेरिजन हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि उन बातों में नहीं जाकर, काफी कुछ कहना है, ओपीएस की बात भी मैं कहना चाहूंगा। कृपा करके अब भी समय है आपके पास में, समझा दीजिए प्रधान मंत्री जी को और केन्द्र सरकार को, ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण का मामला है, यह कोई अहसान नहीं है। हम मैम्बर आफ पार्लियामेंट व एमएलएज जब चाहें तब अपनी पेंशन बढ़ा देते हैं, तनख्वाह बढ़ा देते हैं और भारत सरकार एनपीएस देकर पैसा जमा करवा रही है शेयर मार्केट के अंदर। देखा नहीं, अडानी जी का शेयर नीचे आ गया। अब तो धीरे-धीरे मालूम पड़ेगा, जो हमारा सबका पैसा जमा है, देश भर का, वह जमा कहां-कहां कराया गया है? देश के अंदर बैंकों में और एलआईसी, पता नहीं किन-किन संस्थाओं में? म्यूचुअल फंड के अंदर, अब मालूम पड़ेगा आपको।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए यह पैसा जमा है, वह बर्बाद हो जाता है, मान लीजिए अडानी साहब की तरह नीचे हो जाता तो क्या होगा? आपने अडानी जी को लेकर भी, अपनी सरकार में आप लोगों ने अडानी साहब को कोल ब्लाक दिया। स्टेट गवर्नमेंट का कोल मिला हुआ, अध्यक्ष महोदय, अलाटमेंट हुआ स्टेट गवर्नमेंट को, आपने अडानी जी के साथ में एमओयू किया, एक्स्केवेशन भी किया। आप हमें दोष दे रहे हैं कि हमने जमीन दी उनको। जमीन आपने भी दी, हमारे वक्त में दी होगी। जमीन और भी देने की मांग हो रही होगी, पूरे देश के अंदर, कई उद्योगपतियों से। हम सोच-समझकर स्कीम बनाते हैं। आपने अडानी जी का नाम लिया, मुझे उस पर ही राज लगता है। आपने नाम लिया कैसे? पूरा देश तो मोदी जी को ब्लेम कर रहा है। या तो आपको ऊपर से इशारा हुआ है कि मोदी जी और अडानी जी की दूरी दिखाओ। इसलिए कुछ बोलो वहां जाकर असेम्बली के अंदर, इसलिए बोले होंगे आप। वरना अडानी जी का बोलने का तुक क्या था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे खुशी है कि आपकी और अडानी जी की नजदीकियां राजस्थान देख रहा है, हिन्दुस्तान भी देख रहा है। नये दोस्त आपको मुबारक हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं तो एक बात जानता हूं कि आपने अडानी जी का बोलने की हिम्मत की, मैं आपको दाद देता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चलिये दाद तो मिली।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मेम्बर आफ पार्लियामेंट की और एमएलएज की तनख्वाह बढ़ सकती है, पेंशन बढ़ सकती है, क्या वह पैसा आपका एनपीएस में जमा होगा, शेयर मार्केट में जमा कराने के लिए तैयार हैं आप लोग, तो क्यों हम कर्मचारियों को उनकी मर्सी पर छोड़ें? उनकी मर्सी पर क्यों छोड़ें? हमें चाहिए कि सिक्योरिटी दें उन लोगों को, ये मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय, यही बात कहता हुआ कुछ तो हमारे साथियों ने और कुछ पिछले बजट में पाइंट रह गये थे तो मैं प्रयास करूंगा, दस-पन्द्रह मिनट आपके और लूंगा, चिन्ता मत कीजिए। ठीक है।

1. अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तुत कर रहा हूं-

शिक्षा एवं युवा विकास:

2. हमारे द्वारा नई पहल करते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी English Medium विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। ये विद्यालय गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर हों, इस दृष्टि से एक Expert Committee का गठन कर Long Term Strategy एवं Action Plan निर्धारित किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश में शिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु-

I. राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों व चयनित शिक्षकों को spoken English, administration एवं leadership development के लिए ट्रेनिंग दी जायेगी।

II. प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लाक मुख्यालयों पर स्कूलों/कालेजों में 20 करोड़ रुपये की लागत से English Language Labs की स्थापना की जायेगी। इससे 50 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

III. महात्मा गांधी English Medium स्कूलों में Pre-School Education उपलब्ध कराने के लिए हमारे निर्णय के साथ-साथ चरणबद्ध रूप से Play Elements भी लगाए जाएंगे। इस पर आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

3. ICT परियोजना के तहत 4 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 256 करोड़ की लागत से Computer Labs स्थापित की जायेंगी।

(श्री अशोक गहलोत)

4. महाराव शेखाजी Armed Forces Training Academy, सीकर तथा Services Preparatory Institute, औरंगाबाद की तर्ज पर संभाग स्तर पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में Defence Services Preparatory Institute की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इन पर 35 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए "अग्निवीर" योजना पर पुनर्विचार कर सेना में युवाओं को regular नियुक्ति ही प्रदान करें।

5. पालीटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में Centre of Excellence for Non-Conventional Energy एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में Centre of Excellence for Electric Vehicles की स्थापना की जायेगी।

6. युवाओं को employable बनाने में Skill Development एवं Capacity Building की महती भूमिका को देखते हुए

I. राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पार्टनर्स के माध्यम से vocational certificate courses शुरू किये जायेंगे। इस पर 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. समस्त आवासीय तथा चयनित विद्यालयों में कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए vocational training के साथ-साथ workshop में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केन्द्र' शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं। आगामी वर्ष इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

7. विद्यार्थियों एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में iStart Innovation School Hub की स्थापना की जायेगी। साथ ही, डूंगर कालेज-बीकानेर में Auditorium बनाया जायेगा।

8. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे-

I. कादेड़ा (केकड़ी), बोराड़ा (किशनगढ़)-अजमेर; मुबारिकपुर (रामगढ़)-अलवर; घोसुंडा-चित्तौड़गढ़; गंगाशहर-बीकानेर; बगड़ी (लालसोट); गीजगढ़ (सिकराय)-दौसा; आसोप (भोपालगढ़); देचू (लोहावट)-जोधपुर; कानोता, जालसू-जयपुर; लूणवा (नावां)-नागौर; सेमारी, नयागांव (खेरवाड़ा)-उदयपुर; वजीरपुर-सवाई माधोपुर एवं देसूरी व देवली (रायपुर)-पाली में राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

II. आभानेरी (बांदीकुई), भांडारेज (सिकराय)-दौसा; भिवाड़ी, खेरलीगंज (कठूमर)-अलवर; नगरफोर्ट (देवली-उनियारा)-टोंक; चूनवाड़ (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर एवं सुकार (बामनवास)-सवाई माधोपुर में कन्या राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।

III. जयपुर के हवामहल क्षेत्र में राजकीय उर्दू बीएड महाविद्यालय खोला जायेगा।

IV. ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, भादरा-हनुमानगढ़; मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया-हनुमानगढ़; ज्ञान ज्योति पीजी महाविद्यालय, श्रीकरणपुर-श्रीगंगानगर; शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर-श्रीगंगानगर को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

9. साहडोली (रामगढ़). उमरैण-अलवर; नाहरगढ़-बारां; विजयपुर-चित्तौड़गढ़ एवं लाखनपुर (लालसोट)-दौसा में आईटीआई खोली जायेंगी।

10. विद्यार्थियों की शिक्षण सुविधा के विस्तार हेतु-

I. गिरवरपुरा (केकड़ी)-अजमेर व भेडोली (बौंली)-सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, वैर-भरतपुर व जैसलमेर में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय एवं पहाड़ी (कामां)-भरतपुर में अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे।

II. अग्गड़ (लसाड़िया)-उदयपुर; मारवाड़ जंक्शन-पाली में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास तथा कुचामन-नागौर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास खोले जायेंगे।

11. छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जायेगा। प्रथम चरण में श्रीगंगानगर के छात्रावास सहित 20 छात्रावास खोले जाने के साथ ही पूर्व में संचालित छात्रावासों का जीर्णोद्धार भी किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

12. प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका, एकलव्य, देवनारायण तथा अन्य सभी आवासीय विद्यालयों के साथ-साथ SC/ST/OBC/MBC सहित सभी छात्रावासों में आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

13. विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु-

I. राजकीय महाविद्यालय परिसरों में open gyms स्थापित किये जायेंगे। इन पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. संस्कृत विद्यालयों में खेल सामग्री की उपलब्धता, खेल मैदानों का विकास व अन्य निर्माण के साथ-साथ open gym centres स्थापित किये जायेंगे। इन पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. संस्कृत महाविद्यालयों में योग एवं ध्यान की नियमित कक्षायें संचालित करवायी जायेंगी।

14. चयनित युवाओं को राजकीय विभागों के साथ काम करने के अवसर प्रदान करने, उनके अभिनव एवं प्रगतिशील विचारों के आधार पर योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने हेतु 'यंग इंटर्न प्रोग्राम (YIP)' के तहत 250 युवाओं को अतिरिक्त इंटर्नशिप करवायी जायेगी।

15. साथ ही, आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से गठित राजीव गांधी युवा कोर (RYC) के अन्तर्गत कार्यरत 2 हजार 500 'राजीव गांधी युवा मित्रों' की संख्या बढ़ाते हुए 5 हजार की जानी प्रस्तावित है।

16. दिनांक 10 फरवरी को वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने वर्तमान में प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने सम्बन्धी घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं आगामी वर्ष एक लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूं।

17. प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम व खेल अकादमी स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न खेल सुविधायें विकसित की जायेंगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

18. वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत Empanelled Hospitals में ही विभिन्न Transplants यथा-lung, bone marrow, kidney, liver, heart की सुविधा उपलब्ध है। अब, मैं प्रदेश के बाहर सहित किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा तक समस्त Transplants पर राशि का पुनर्भरण प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

19. Organ Transplant के लिए राज्य के समस्त मेडिकल कालेजों को चरणबद्ध रूप से Organ Retrieval Centres के रूप में विकसित किया जायेगा।

20. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) तथा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत बढ़ते रोगीभार को देखते हुए मरीजों को सुगमता से समस्त चिकित्सा सुविधाएं देने तथा रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री ट्रेक करने के लिए चरणबद्ध रूप से IT आधारित Integrated Health Management System (IHMS) को सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रभावी किया जायेगा। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) तक क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

21. राज्य के चिकित्सा संस्थानों में ICU, Neonatal ICU, Paediatric ICU बेड्स की संख्या में हुई वृद्धि एवं इनमें काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ की विशेष प्रकार की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पृथक कैडर बनाया जायेगा।

22. प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, ट्रोमा सेन्टर खोले व क्रमोन्नत किये जाने के साथ-साथ अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

औद्योगिक विकास:

23. प्रदेश में MSMEs में Energy Efficiency के प्रति जागरूकता कम है। अतः उनकी Energy Productivity को बढ़ावा देने के लिए चयनित MSME Units में निःशुल्क Energy Auditing की सुविधा एवं Energy Efficient Equipments लगाने पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

24. राज्य में उद्योग इकाइयों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मेरे द्वारा CISF की तर्ज पर RISF (Rajasthan Industrial Security Force) के गठन की घोषणा की गयी थी। इसके अंतर्गत 2 बटालियनों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगामी वर्ष RISF की एक अतिरिक्त बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

25. उद्यमियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में भूखण्ड आबंटी द्वारा भूमि की एकमुश्त देय समस्त बकाया प्रीमियम राशि 30 सितम्बर, 2023 तक जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 60 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

26. उद्यमियों एवं निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए जालोर एवं मण्डोर-जोधपुर में RIICO के इकाई कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा:

27. हमारी सरकार विशेष योग्यजनों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। राज्य कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत अविवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री ही पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र है। अब मैं विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र घोषित किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

28. कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को राजस्थान रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन्हें वर्तमान में दी जा रही एक हजार 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये किया जायेगा।

29. जैसा कि विदित है कि उड़ान योजना के अंतर्गत लगभग एक करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को सेनीटेरी नैपकिन निःशुल्क वितरण का कार्य हाथ में लिया गया है। इस क्रम में प्रयुक्त सेनीटेरी नैपकिन्स के recycle, biodegradation एवं eco-friendly disposal के लिए नीति बनाकर आवश्यक व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

आधारभूत सुविधायें

30. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण व उन्नयन एवं अन्य आधारभूत कार्य एक हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाना प्रस्तावित हैं, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

31. कम लागत में उच्च गुणवत्ता के सड़क एवं भवन निर्माण सम्बन्धी अनुसंधान के लिए जयपुर में 'Centre of Excellence for Road and Building Construction' की 40 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी।

32. चिड़ावा-झुंझुनूं में अधिशाषी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) का कार्यालय खोला जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

33. प्रदेश के 50 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में Drainage एवं Grey Water Treatment हेतु 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। साथ ही, विभिन्न निकायों हेतु सीवर सफाई कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किये जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से थ्री-इन-वन (Rodding/Suction, Grabbing and Jetting Robot) मशीनें उपलब्ध करवायी जायेंगी।

34. हाल ही में लम्पी बीमारी के कारण काफी संख्या में गायों की मृत्यु हुई है। बीमारी या अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर उनके अवशिष्ट के निस्तारण की प्रमुख समस्या रहती है। इसके समाधान व त्वरित निस्तारण के लिए प्रथम चरण में जिला स्तर के नगर निकायों में Carcass Plants स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 75 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

35. नगर निकाय क्षेत्रों को कचरे की समस्या से निजात दिलाने एवं प्रभावी निस्तारण हेतु-

I. 118 नगरीय निकायों में डम्पिंग ग्राउण्ड पर पड़े पुराने कचरे के निस्तारण हेतु 54 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

II. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (Construction and Demolition Waste) के recycling व processing हेतु जिला मुख्यालय स्थित निकायों पर plants लगाये जायेंगे। प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपये की लागत से कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर एवं अलवर में प्लांट्स लगाये जायेंगे।

36. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि, आगजनी आदि घटनाओं की रोकथाम एवं quick response हेतु नगरीय निकायों में 200 फायर वाटर टेण्डर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को आगजनी की घटनाओं से बचाव हेतु केशवाना (नीमराणा), खैरथल-अलवर, खारा-बीकानेर, कलढवास-उदयपुर एवं रतनगढ़-चूरू में अग्निशमन केन्द्र (Fire Stations) स्थापित किये जायेंगे।

पेयजल एवं भूजल:

37. 15 हजार से अधिक गांवों में पेयजल व्यवस्था की अत्याधुनिक तकनीक से सेंसर आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु IT आधारित Real Time Monitoring System के साथ ही सेंट्रल कमाण्ड सेंटर की स्थापना की जायेगी। इस पर लगभग एक हजार 500 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

38. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के रोजदा (जालसू)-जयपुर में कनिष्ठ अभियंता; किशनगढ़ रेनवाल-जयपुर में सहायक अभियंता तथा भादरा-हनुमानगढ़ व कोटपूतली जयपुर में अधिशाषी अभियंता के कार्यालय खोले जायेंगे।

ऊर्जा:

39. प्रदेश में ऊर्जा तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 220 के.वी., 132 के.वी., 33/11 के.वी. GSS व कार्यालय खोले जाने के साथ-साथ अन्य कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-06 देखें)

वन एवं पर्यावरण:

40. नगरों में Green Lungs की अति आवश्यकता है। इस क्रम में मूंगस्का, भूगोर तथा करधनी-अलवर, घूघरा घाटी एवं स्मृति वन विस्तार पुष्कर-अजमेर; रतननगर बीड़, राजगढ़-चूरू; मंगलवाड-चित्तौड़गढ़; गणेश टेकड़ी एवं नाथद्वारा-राजसमंद एवं रिसाला उदयपुर में 2-2 करोड़ रुपये तथा खैरखेड़ी-बारां; श्यामपुरा-बांसवाड़ा; किला ब्लाक-चित्तौड़गढ़; नीलकण्ठ महादेव-दौसा, संजय वन-शाहपुरा, मायला बाग व कानोता बांध-जयपुर; चौथ का बरवाड़ा-सवाईमाधोपुर; बांदरिया मगरा-राजसमंद एवं कच्चा बांध टोंक शहरों के आस-पास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु 1-1 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

41. जयपुर में कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर नींदड बैनाड़ वन क्षेत्र में 135 हैक्टेयर भूमि पर तथा कालवाड़ रोड पर गोविन्दपुरा की 10 हैक्टेयर भूमि पर 18 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से जैव विविधता वन (Bio Diversity Forests) विकसित किये जायेंगे।

42. जिला मुख्यालय स्थित नगरीय निकायों में सुविधायुक्त सिटी पार्क बनाये जाने के साथ-साथ मौजूदा शहरी वन क्षेत्रों में सुधार व विकास हेतु विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 40 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर में सिटी पार्क बनाया जायेगा।

43. वन क्षेत्रों के कुशल प्रबन्धन, संचालन एवं आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु-

I. पेट्रोलिंग ट्रैक, फायर लाइन व नवीन वन चौकियों के निर्माण तथा वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये, तथा

(श्री अशोक गहलोत)

II. आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने यथा-ड्रोन के माध्यम से सीडिंग, वायरलेस सिस्टम में सुधार तथा ट्रैप कैमरों हेतु 15 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

44. आकल वुड फासिल्स पार्क-जैसलमेर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए DPR बनवायी जायेगी।

45. राज्य के रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व्स तथा जवाई बांध-पाली और झालाना नेचर पार्क-जयपुर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स में वर्तमान Wildlife Survillence and Anti-Poaching System (WS & APS) को मजबूत करने के साथ-साथ रामगढ़ विषधारी-बूंदी; जमवारामगढ़ अभयारण्य-जयपुर; कुम्भलगढ़ अभयारण्य-राजसमंद-उदयपुर पाली. टाडगढ़ रावली-अजमेर राजसमंद पाली आदि वन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जायेगा। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:

46. प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 5 हजार पर्यटक मित्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, पर्यटक सहायता बल (TAF) हेतु 75 वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

47. बड़ी खाटू-नागौर स्थित दरगाह हजरत समन दीवान रहमतुल्लाह अलेह तथा घाटेश्वर महादेव मंदिर एवं हरमलदास जी महाराज मंदिर विजय नगर (नावां)-नागौर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही, बूटाटी-नागौर में नाड़ी, पार्क व तालाब के सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

48. कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश के दो प्रमुख मंदिरों ऋषभदेव व गोगामेड़ी में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गयी थी। इसकी सफलता को देखते हुए राज्य के अन्य 5 प्रमुख मंदिरों-कुशल बिहारी जी मंदिर, बरसाना व कैलादेवी (झील का बाड़ा)-भरतपुर; माताजी मावलियां-जयपुर; आढदेवी माता मंदिर-कोटा एवं गणेशजी मंदिर (रातानाड़ा)-जोधपुर में भी ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।

49. बानसूर अलवर के किले में स्थित माता के मंदिर व तालवृक्ष में स्थित गंगा मां के मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्य के साथ ही जन सुविधायें विकसित की जायेंगी।

(श्री अशोक गहलोत)

50. राज्य में नृत्य, नाटक एवं संगीत कला के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए स्थापित रवीन्द्र मंच परिसर, जयपुर का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करते हुए इसे Multi Cultural Centre के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, जयपुर कत्थक नृत्य केन्द्र का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

51. सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारां में सहरिया संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।

52. श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिलों के कपास उगाने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं।

53. ऐतिहासिक पाण्डुलिपियों व प्रशासनिक दस्तावेजों की सुरक्षा, संरक्षण एवं Digitization हेतु-

I. अभिलेख संग्रहालय-बीकानेर में आगामी वर्ष 350 स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो व फोटोग्राफी दीर्घा तथा 200 सीटों के वातानुकूलित सभागार का निर्माण करवाया जायेगा।

II. अल्बर्ट हाल पुस्तकालय, जयपुर का नवीनीकरण व दुर्लभ दस्तावेजों का Digitization किया जायेगा।

III. राजस्थान प्राच्य विद्या (Oriental Research) प्रतिष्ठान, जोधपुर का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

गृह:

54. प्रदेश में संगठित रूप से कार्यरत विभिन्न माफियाओं यथा-Land माफिया, बजरी माफिया एवं Loan माफिया इत्यादि पर कड़ी एवं त्वरित कार्रवाई करने के लिए SOG के अन्तर्गत Special Task Force का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

55. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय खोले जायेंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं-

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-07 देखें)

56. घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता व परामर्शी सेवाओं हेतु

(श्री अशोक गहलोत)

संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को देय अनुदान राशि 3 लाख 15 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जायेगी। साथ ही, समस्त पुलिस सर्किलों पर ये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। Women Help Desk पर कार्यरत Counsellors के मानदेय में आगामी वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

57. आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न न्यायालय खोले जायेंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-08 देखें)

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र:

58. कृषकों को अक्सर शिकायत रहती है कि सतर्कता जांच अधिकारी द्वारा आये दिन उनकी भार वृद्धि की वीसीआर भर दी जाती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 30 अप्रैल तक स्वयं declare करने पर पेनल्टी नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि 30 रुपये प्रति HP मासिक दर से दो माह के लिए जमा करवाने पर अतिरिक्त विद्युत भार को नियमित किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

59. कृषि जलवायु आधारित उद्यानिकी फसलों के अनुसंधान के लिए शेष 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से उद्यानिकी Adaptive Trial Centre (ATC) स्थापित किये जायेंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं भरतपुर में ये केन्द्र खोले जायेंगे।

60. बहरावण्डा (सिकराय)-दौसा में पपीते का Centre of Excellence स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

61. थावला (डेगाना)-नागौर एवं बसेड़ी (झोटवाड़ा)-जयपुर में कृषि उपज मण्डी खोली जायेंगी।

62. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा केन्द्र खोले/क्रमोन्नत किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

I. मेरे द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में नवगठित एक हजार 200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में अब मैं पुरानी एक हजार 439 ग्राम पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

II. घोडास (मांडल)-भीलवाड़ा; खारडा (रोहट)-पाली व खुईयाला (सम)-जैसलमेर के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, नसवारी-अलवर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

III. तिजारा-अलवर; बहरावण्डा दौसा; लाडनूं नागौर एवं राजाखेड़ा धौलपुर के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. जोजावर-पाली में नवीन पशु विज्ञान केन्द्र खोला जायेगा।

V. सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।

63. नाथद्वारा-राजसमंद एवं उदयपुर में कैटल फीड प्लांट्स की स्थापना की जायेगी।

64. प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु-

I. नोहर क्षेत्र के 35 गांवों की लगभग एक लाख 20 हजार हैक्टेयर भूमि की समुचित सिंचाई व्यवस्था करने की दृष्टि से नोहर फीडर की री-लाइनिंग के लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

II. भादरा-हनुमानगढ़ में अमरसिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर व नोहर फीडर प्रणाली में पुराने टूटे हुए खालों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। साथ ही, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर क्षेत्र की खालों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया जायेगा।

III. गुड़गांवा कैनाल से शेष रही कच्ची वितरिकाओं को पक्का करने सम्बन्धी कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

IV. बेहरानिया (खेरवाड़ा), कडैयापानी (सलूम्बर)-उदयपुर; आडीवाट के पाल कडैड़या डोहारिया (सीमलवाड़ा)-डूंगरपुर; भूखा-सवाई माधोपुर; चरलिया आक्या (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़ सहित 100 एनीकटों के निर्माण/जीर्णोद्धार व 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

V. बेगूं (चित्तौड़गढ़) के कुण्डाल क्षेत्र की आठ पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई द्वारा चम्बल का पानी उपलब्ध कराने हेतु DPR तैयार करवायी जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

65. कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर (सीकर) में पीजी कक्षायें संचालित की जायेंगी।

66. हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र तथा सीकर में खाद, बीज, दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

सुशासन:

67. योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत GIS प्लेटफार्म 'Raj Dhara' का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न विभागों हेतु सेटेलाइट इमेजरी की आवश्यकताओं के अनुरूप राजधारा प्लेटफार्म पर Time Series High Resolution Satellite Imagery Repository की स्थापना की जायेगी एवं इसके विश्लेषण हेतु High-end Lab की भी स्थापना की जायेगी, जिससे राज्य के विकास एवं आवश्यकताओं की प्रभावी समीक्षा की जा सकेगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

68. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कार्यालय खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं:-

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-09 देखें)

69. नायब तहसीलदार, नर्सिंग अधीक्षक इत्यादि पदों को राजपत्रित घोषित किया जायेगा।

70. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किये गये नवाचारों एवं तद्नुसार अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, (Chief Minister's Awards for Excellence in Public Services-CM-EXCELS) दिये जाने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो उन्होंने अपनी बातें उठायी हैं और मेरी स्पीच में नहीं आ पायी हैं, उनको मैं कैसे हल करना सुनिश्चित करूं, इसमें पूरा प्रयास करूंगा। यही बात कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन समाप्ति के बाद आप सब फोटोग्राफ के लिए वहां पर आमंत्रित हैं।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.08 बजे शुक्रवार, 17 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रियांबड़ी उपखण्ड मुख्यालय (मेड़ता) में बस सेवा का संचालन

164. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रदेश की ग्राम पंचायतों को राजकीय बस-सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई थी? सरकार की उक्त घोषणा के पश्चात् अब तक विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की कितनी ग्राम पंचायतों को राजकीय बस सेवा से जोड़ा गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें उक्त सेवा से वंचित हैं? क्या सरकार वंचित ग्राम पंचायतों को राजकीय बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय रियांबड़ी में भी राजकीय बसों का संचालन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय बस सेवा का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रदेश की ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवहन सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उक्त बजट घोषणा के पश्चात् अब तक विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नई बस सेवाओं का संचालन नहीं किया गया है।

ग्रामीण परिवहन सेवा के संचालन हेतु की गई घोषणा के क्रियान्वयन संबंधी वस्तुस्थिति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण वंचित ग्राम पंचायतों को निगम की बस सेवाओं से जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। निगम के सीमित संसाधनों के कारण उपखण्ड मुख्यालय रियांबड़ी पर निगम की बस सेवाओं से जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

परबतसर में निगम की बसों का संचालन

176. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर के किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों के नाम व संचालित बसों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों तथा शेष गांवों को निगम की बस सेवा से कब तक जोड़ दिया जावेगा?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस मार्ग पर निजी बसों के चलाने का परमिट दिया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस सेवा से जुड़ी हुई ग्राम पंचायतों के नाम एवं उनमें संचालित बसों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्तमान में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित नहीं है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र की शेष वंचित ग्राम पंचायतों व गांवों को निगम बस सेवा से जोड़ा जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र में निजी बसों के परमिटों से संबंधित सूचना परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राजसमंद में कृषि हेतु विद्युत की आपूर्ति

178. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने के पृथक विद्युत प्रदायकों (फीडर) की स्थापना की वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा की अनुपालना में क्या कार्ययोजना बनाई गई व उक्त हेतु वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितना बजट आबंटित किया गया?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति के लिए कितने सब स्टेशनों पर कितने नए ट्रांसफार्मर लगाये गये एवं उक्त पर कितना व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला राजसमंद की प्रत्येक पंचायत समिति में कृषि हेतु दिन में विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्या है? वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उक्त प्रयोजन हेतु कितना व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में किसानों को बिना व्यवधान अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने के लिए आगामी चार वर्षों में कृषि कनेक्शनों के लिए पृथक् फीडरों की स्थापना हेतु की गई घोषणा की क्रियान्विति के लिए की गई कार्यवाही एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) किसानों को कृषि उपयोजनार्थ दिन के 2 ब्लाक में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण निगमों द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 33/11 केवी के कुल 156 सब-स्टेशनों पर कुल 156 ट्रांसफार्मर लगाये गये, जिस पर 68.52 करोड रु. का व्यय किया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अन्तर्गत किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति के लिए वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कुल 48 ग्रिड सब-स्टेशनों पर 52 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं। इन पर 258.69 करोड रु. का व्यय हुआ है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(3) वर्तमान में जिला राजसमन्द में कृषि हेतु दिन के दो ब्लाक में 6-6 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 2020-21 में रु. 37.06 लाख का व्यय किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

179. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति आमेर एवं जालसू में कोई राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आमजन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) प्रदेश में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कितने राजकीय महाविद्यालय खोले गये तथा कितने नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाना प्रस्तावित है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति आमेर एवं जालसू में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में नवीन राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं उन पर की गई कार्यवाही के पत्रों की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में जनवरी, 2020 से दिसम्बर 2022 तक 200 (171-सामान्य शिक्षा एवं 29-कृषि शिक्षा) राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी में न्यायिक अधिकारियों हेतु राजकीय आवास

122. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में न्यायिक एवं राजकीय अधिकारियों हेतु राजकीय आवासों की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय आवास निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में जिले के विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में राजस्व विभाग (उपखण्डाधिकारी एवं तहसीलदार) व सार्वजनिक निर्माण विभाग को छोड़कर अन्य राजकीय अधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों के लिए राजकीय आवासों की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में ग्राम खानपुर मीना में न्यायिक भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आबंटित है जिसमें (04 क्वार्टर द्वितीय श्रेणी व 01 क्वार्टर प्रथम श्रेणी) की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिनका कार्य प्रगतिरत है। स्वीकृत राजकीय आवासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर कार्यरत ई-मित्र संचालकों को मानदेय

123. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कार्यरत ई-मित्र संचालक बिना मानदेय व पारिश्रमिक के कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को मानदेय व पारिश्रमिक देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर कार्यरत उक्त संचालकों को कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा एंट्री आपरेटर अथवा सूचना सहायक के पद पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ई-मित्र कियोस्क संचालकों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत दरों पर उनके द्वारा आमजन को दी गई सेवाओं के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है।

(2) जी नहीं। ई-मित्र कियोस्क संचालक एक स्वतंत्र निजी Enterprenour है। ई-मित्र परियोजना निविदा की शर्तों के अनुसार संचालित होती है, जिसके तहत RISL द्वारा स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) नियुक्त किये जाते हैं। ई-मित्र कियोस्क स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) के अधीन कार्य करता है तथा RISL द्वारा स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) एवं ई-मित्र कियोस्कों को निविदा की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिकृत दरों पर उनके द्वारा आमजन को दी गई सेवाओं के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है।

बोरापाल (उदयपुर ग्रामीण) ग्राम पंचायत में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना

124. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत बोरापाल नेशनल हाईवे पर होने व थाने की दूरी को देखते हुए उक्त ग्राम पंचायत में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत बोरापाल में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

लाडपुरा के विद्यालयों में स्टेडियम की स्थापना

125. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति रूचि जागृत करने हेतु ऐसे विद्यालय जिनके पास पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध

(श्रीमती कल्पना देवी)

हैं, वहां खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कितने राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान हैं? क्या सरकार उक्त विद्यालयों के खेल मैदानों को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत उपखण्ड/तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में 47 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास खेल मैदान उपलब्ध है तथा 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास खेल मैदान नहीं है, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

युवा मामले एवं खेल विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं में इंग्लिश मीडियम विद्यालय

126. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2021-22 में इंग्लिश मीडियम के बारह सौ राजकीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो माह दिसम्बर, 2022 तक जिला झुंझुनूं में कुल कितने विद्यालय खोले गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बजट घोषणानुसार खोले जाने वाले उक्त विद्यालयों में कितने विषय विशेषज्ञ अध्यापकों के पद सृजित किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुभाष पूनिया)

(3) जिला झुंझुनूं में खोले गये उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस विषय के रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। झुंझुनूं जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 73 व शहरी क्षेत्र में 05 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दिसम्बर 2022 तक कुल 78 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गये हैं। सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार पद सृजित किये गयेः-

क्र.सं.	पद का नाम	पूर्व में सृजित	नवीन सृजित	कुल पद
1.	प्रधानाचार्य (लेवल-16)	45	21	66
2.	वरिष्ठ अध्यापक	257	14	271
3.	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	54	09	63
4.	अध्यापक	254	173	427
5.	प्रयोगशाला सहायक	15	8	23
6.	पुस्तकालय अध्यक्ष	16	00	16

(3) झुंझुनूं जिले की कुल 78 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्यापक लेवल-1 के 186 पद, अध्यापक लेवल-2 (अंग्रेजी) के 9 पद, अध्यापक लेवल-2 (गणित/विज्ञान) के 9 पद, अध्यापक ग्रेड-2 (सामाजिक विज्ञान) के 3 पद व अध्यापक ग्रेड-2 (संस्कृत) का 01 पद रिक्त है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में किराडू को वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में मान्यता

127. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जिला बाड़मेर में स्थित संरक्षित स्मारक किराडू को वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में मान्यता दिलाने के लिए रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किराडू के उक्त प्रस्ताव की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में स्थित संरक्षित स्मारक किराड़ू को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जोधपुर वृत्त एवं अधीक्षण पुरातत्वविद्, जोधपुर मंडल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर शहर में इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण

128. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विगत दो वर्षों में अजमेर शहर में ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को किस-किस संस्था के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष आवेदकों को अब कब तक ऋण उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विगत दो वर्षों में अजमेर शहर में ऋण हेतु 9339 आवेदन प्राप्त हुए।

(2) प्राप्त आवेदनों में से कुल 1492 व्यक्तियों को राशि रुपये 397.57 लाख ऋण वितरित किया गया है, जिनका बैंकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	ऋण आबंटित व्यक्तियों की संख्या
1.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	350
2.	बैंक आफ बड़ौदा	476
3.	पंजाब नेशनल बैंक	330
4.	बैंक आफ इण्डिया	24

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र.सं.	बैंक का नाम	ऋण आबंटित व्यक्तियों की संख्या
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	23
6.	बीआरकेजीबी बैंक	8
7.	केनरा बैंक	28
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	14
9.	एचडीएफसी बैंक	11
10.	आईसीआईसीआई बैंक	6
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	53
12.	जम्मू कश्मीर बैंक	3
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	12
14.	यूको बैंक	18
15.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	54
16.	अनुजा निगम	75
17.	ए.यू. स्माल बैंक	7
कुल योग		**1492**

(3) उक्त योजना में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। नगर निगम अजमेर के माध्यम से लम्बित आवेदनों के निस्तारण करने हेतु निरन्तर बैंकों से समन्वय कर ऋण वितरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण की कार्ययोजना

129. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में वायु गुणवत्ता का औसत स्तर क्या है तथा प्रदेश में प्रदूषण व वायु गुणवत्ता के आधार पर जयपुर शहर कौन से स्थान पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा जयपुर शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में स्थापित तीन सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्रों के वर्ष 2022 के आंकड़ों के आधार पर जयपुर शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक का औसत स्तर 141 है जो निर्धारित मानकों के अनुसार मध्यम श्रेणी में है।

प्रदेश के 08 शहरों में स्थापित 10 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र (CAAQMS) के वर्ष 2022 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) के आधार पर, जयपुर शहर तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आकड़े परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जयपुर शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 2021-22 से प्रतिवर्ष माइक्रो एक्शन प्लान तैयार कर विभिन्न स्टेक होल्डर विभागों/अथोरिटी के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों जैसे कि सड़कों का रखरखाव, मरम्मत, सड़क पर उड़ने वाली धूल का प्रबन्धन, यातायात से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, वृक्षारोपण, खुले में कचरा नहीं जलाना, निर्माण एवं विनिर्माण प्रबन्धन एवं औद्योगिक स्तर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि की कार्यवाही की जाती है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा NCAP के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर शहर के क्षेत्राधिकार में स्थित 56 उद्योगों एवं 12 डी.जी. सैट्स की वर्ष में न्यूनतम एक बार मोनिटरिंग की गई है।

(3) प्रदेश के शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की कार्ययोजना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य व मुकन्दरा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना

130. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य व मुकन्दरा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए कब से आरम्भ कर दिया जायेगा? उक्त में हुए विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(2) सरकार शेरगढ़ अभयारण्य के विकास एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु क्या-क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में गराडिया महादेव में प्रवेश व जवाहर सागर के अपस्ट्रीम में बोटिंग का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। पर्यटन हेतु मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा के बफर जोन में 4 रूट स्वीकृत किये गये हैं जिसमें पर्यटन हेतु वाहनों का पंजीकरण कार्य प्रगति पर है।

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण हेतु शिकार बुर्ज, भीमलत व टाइगर हिल रूटों पर स्वीकृति जारी हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त जैतसागर झील में नौकायन हेतु भी स्वीकृति जारी हो चुकी है। बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को आरम्भ करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है। पर्यटन आरम्भ में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं है।

(2) शेरगढ़ अभयारण्य के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 01 सहायक वन संरक्षक, 01 क्षेत्रीय वन अधिकारी, 03 सहायक वनपाल, 04 वन रक्षक, 02 वृक्षपालक एवं 07 बोर्डर होमगार्ड का पदस्थापन कर सुरक्षा एवं नियंत्रण कार्य हेतु 01 बोलेरो कैम्पर व 02 मोटरसाईकिल उपलब्ध करवाई गई हैं तथा विकास कार्यों में अभयारण्य की सीमा पर सुरक्षा हेतु 6 फीट ऊंचाई की पक्की दीवार का निर्माण, जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु पानी के लिए एन्किट, मिनी परकोलेशन टैंक, हेबिटाट इम्प्रूवमेंट, वाच टावर के कार्य करवाये जा रहे हैं।

फलौदी में वृक्षारोपण

131. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2018 से 2022 तक सरकार द्वारा कितने वृक्ष लगाये गये व वृक्षारोपण एवं रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2018 से 2022 तक उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत वृक्षारोपण कार्य में कुल 3,17,995 पौधे लगाये गये और वृक्षारोपण एवं रखरखाव पर कुल 5,15,57,796 रुपये का व्यय हुआ है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसपुर में सोनार एनिकट बनाने की कार्ययोजना

132. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसपुर के ग्राम पंचायत निढाउवा पाल में जाखम नदी पर सोनार एनिकट बनाने हेतु सरकार को कई बार ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त एनिकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आसपुर के ग्राम पंचायत निढाउवा पाल में जाखम नदी पर सोनार एनिकट बनाने हेतु 4 ज्ञापन दिनांक 09.03.2017, 06.06.2017, 24.02.2022 एवं 14.03.2022 को प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जाखम नदी पर ग्राम पाल निढाउवा तहसील साबला में एनिकट का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रतनगढ़ में फसल खराबे का मुआवजा

133. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा फसल खराबे के मुआवजे हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? उक्त मानदण्डों के तहत वर्ष 2019-20 से 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कुल कितने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया गया तथा कितने वंचित रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के फसल खराबे के मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्रामों में वर्ष 2019-20 से 2021-22 (संवत 2076 से 2078) तक किसी भी ग्राम में फसलों में 33

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नही होने के कारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों की फसलों में नुकसान नहीं होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

आहोर में आगजनी से प्रभावित परिवारों को मुआवजा

134. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में विगत चार वर्षों में आगजनी की कितनी घटनाएं घटित हुई? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आये दिन होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोकने व सुरक्षा व्यवस्था हेतु अग्निशमन केन्द्र आहोर को यंत्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में विगत चार वर्षों (2019 से 2022 तक) में कुल 20 आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं।

वर्तमान में अग्निशमन केन्द्र आहोर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आगजनी की घटना घटित होने पर नजदीक के फायर स्टेशन से अग्निशमन वाहन भिजवाया जाता है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आहोर में विगत चार वर्षों (2019 से 2022 तक) में कुल 20 आगजनी की घटनाओं में से भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता देने योग्य 12 प्रकरण ही हैं, जिनमें से 05 प्रकरणों में प्रभावित पीड़ितों को राशि 43,600 रुपये का भुगतान किया गया है। 07 प्रकरण जांच/दस्तावेज हेतु प्रक्रियाधीन है।

देवली-उनियारा में नवीन रोडवेज बसों का संचालन

135. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कितने ग्राम-ढाणियों को वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक रोडवेज बस सेवा से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन रोडवेज बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्ष 2019 से दिसम्बर 2022 की अवधि में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस सेवा का संचालन दिनांक 01.04.2022 से प्रारम्भ किया जाकर विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के निम्नलिखित ग्राम पंचायत/गांवों को उक्त सेवा से जोड़ा गया है:-

मार्ग	**समय**	**निगम सेवा से जोड़े गये ग्राम पंचायत/गांव**
टोंक-टोडा-देवली	13:15	हिसामपुर, नासिरदा, थांवला, मालेडा, रामथला, चान्दथली, नेगडिया, कासीर
देवली-टोडा-जयपुर	06:30	

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित निगम सेवाओं के अतिरिक्त नवीन सेवाओं का संचालन किया जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है, किन्तु राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु निम्न घोषणा की गई है:-

"हमने वर्ष 2012-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं नये वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जायेगा।"

उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में वस्तुस्थिति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहर थाना में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

136. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द प्रसाद)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण बस सेवा संचालित की जा रही है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कितनी ग्रामीण बस सेवा संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में वर्ष 2018 में संचालित बसों की अपेक्षा वर्तमान में बसों का कम संचालन हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां से कहां तक ग्रामीण बसों का संचालन हो रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की ग्रामीण परिवहन सेवा के संचालन संबंधी घोषणा के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम द्वारा वर्तमान में वर्ष 2018 में संचालित बसों की अपेक्षा कम बसों का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित नहीं है।

महाराव भीमसिंह स्टेडियम (सांगोद) का निर्माण कार्य

137. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांगोद में पीपीपी मोड पर महाराव भीमसिंह स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई व कुल कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्टेडियम का कार्य कब तक पूर्ण होगा व उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु सांगोद कस्बे में मेजर ध्यानचंद योजना के तहत महाराव भीमसिंह स्टेडियम में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि. द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को प्राप्त राशि रुपये 90.00 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा अंशदान राशि रुपये 90.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.01.2022 को जारी की गई है।

इस परियोजना पर राशि रुपये 55.37 लाख का व्यय किया जा चुका है एवं लगभग 80 प्रतिशत भौतिक रूप से कार्य करवाया जा चुका है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में मेजर ध्यानचन्द योजना अन्तर्गत चल रहे स्टेडियम निर्माण कार्य को माह मार्च, 2023 के अन्त तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

सूरतगढ़ में खेल मैदान की स्वीकृति

138. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कौन-कौन से गांवों में खेल मैदान स्वीकृत नहीं है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में खेल मैदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सूरतगढ़ शहर के खेल स्टेडियम के अलावा युवा मामले एवं खेल विभाग/राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के नाम से खेल मैदान हेतु कोई भूमि आबंटित नहीं है और न ही कोई अन्य खेल मैदान स्वीकृत है।

(2) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

खेल नीति से लाभान्वित खिलाड़ी

139. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खेल नीति बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खेल नीति के तहत प्रदेश के खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिले के कितने खिलाड़ी लाभान्वित हुए व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी जन घोषणा पत्र जिसे सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकत किया गया है, में खेलों के विकास हेतु नई खेल नीति का निर्धारण किये जाने की घोषणा की गई थी।

प्रदेश में व्यवस्थित योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से खेलों के विकास हेतु आधारभूत संरचनाएं विकसित करना, खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना आदि उद्देश्य से घोषणा की है।

(2) राज्य की नवीन खेल नीति बनाये जाने हेतु प्रारूप तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जावेगा।

बरसनी (आसींद) ग्राम पंचायत में घरेलू विद्युत कनेक्शन

140. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसींद की ग्राम पंचायत बरसनी में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश के सभी क्षेत्रों की भांति विधान सभा क्षेत्र आसींद की ग्राम पंचायत बरसनी में भी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करने पर "विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021 (टीसीओएस-2021)" के उपबन्धों 4 व 6 के अनुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

वर्तमान में घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की कोई अन्य अनुदानित योजना संचालित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र आसींद की ग्राम पंचायत बरसनी में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु सहायक अभियन्ता कार्यालय बदनौर में लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण में नये बी.एड. कालेज खोलने की योजना

141. श्री अविनाश (जैतारण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अविनाश)

(1) प्रदेश में कितने निजी व सरकारी बी.एड., बी.एस.टी.सी. कालेज हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक कितने नये बी.एड., बी.एस.टी.सी. कालेज खोलने की घोषणा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितने निजी व सरकारी बी.एड., बी.एस.टी.सी. कालेज संचालित हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन उक्त कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 942 निजी बी.एड. कालेज एवं 2 सरकारी बी.एड कालेज सत्र 2022-23 में संचालित हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 34 राजकीय एवं 341 निजी डी.एल.एड. (बीएसटीसी) कुल 375 कालेज संचालित हैं।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक बी.एड., बी.एस.टी.सी कालेज खोलने की घोषणा नहीं की गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 02 निजी बी.एड. कालेज संचालित हैं व कोई भी निजी व सरकारी डी.एल.एड. (बी.एस.टी.सी.) कालेज संचालित नहीं है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कोई भी नवीन बी.एड. व डी.एल.एड. (बी.एस.टी.सी.) कालेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

142. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिए जिलेवार कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन जिलों में किस-किस स्थान पर उक्त कन्या महाविद्यालय संचालित हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा में कन्या महाविद्यालय कहां संचालित होगा तथा उक्त के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है? उक्त कालेज के कार्य की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 24 जिलों में 61 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये राजकीय कन्या महाविद्यालयों का जिले व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में 04 राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा।
2. राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा।
3. राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा।
4. राजकीय कन्या महाविद्यालय, रामपुरा संचालित।

जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा, स्वयं के भवन में संचालित है तथा 03 महाविद्यालयों हेतु आबंटित बजट तथा भवन निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रेवदर के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने की योजना

143. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालय, रेवदर में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान, एनसीसी व पुस्तकालय खोले जाने तथा आबूरोड महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान व एनसीसी खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालय, रेवदर में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान तथा राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान विषय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं महाविद्यालय में पुस्तकालय संचालित है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

राजकीय महाविद्यालय, रेवदर एवं राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड द्वारा एनसीसी खोलने हेतु आवेदन करने पर ग्रुप मुख्यालय/इकाई कार्यालयों में एनसीसी की रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर एनसीसी आबंटित की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी, 2023

राजस्थान उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

50. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 01 जनवरी, 2023 को पोक्सो एक्ट, एस.सी. व एस.टी. एक्ट, पी.सी. एक्ट, रेंट कन्ट्रोल एक्ट, डी.वी. एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, एन.आई. एक्ट, हत्या एवं बलात्कार के लम्बित प्रकरणों का वर्गवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उच्च न्यायालय एवं उसके अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों में 01 जनवरी, 2022 से 01 जनवरी, 2023 तक की अवधि में पोक्सो एक्ट, एस.सी. व एस.टी. एक्ट के कितने प्रकरण कब दर्ज हुए तथा उक्त प्रकरणों में कितनों में फैसले दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 01 जनवरी, 2023 को पोक्सो एक्ट, एस.सी. एण्ड एस.टी. एक्ट, पी.सी. एक्ट, रेंट कन्ट्रोल एक्ट, डी.वी. एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, एन.आई. एक्ट, हत्या एवं बलात्कार के लम्बित प्रकरणों का वर्गवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 1 जनवरी, 2022 से 01 जनवरी, 2023 तक की अवधि में पोक्सो एक्ट, एस.सी. व एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज किये प्रकरणों एवं दिये गये फैसलों का संख्यात्मक विवरण प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर)

गैर सरकारी बीएड कालेजों (सीटीई संस्थाओं) में कार्यरत कार्मिकों का शिक्षा विभाग में समायोजन

मान्यवर जी, निवेदन है वर्ष 1986 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ राजीव गांधी शैक्षिक उन्नयन योजना के अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सी.टी.ई. 1986 से राजस्थान में गैर सरकारी बी.एड. कालेजों (पूर्व अनुदानित शिक्षण संस्थान) में शुरू की गई एवं राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत इस संस्थानों में कार्मिकों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गईं एवं समयानुसार स्थायीकरण भी किया गया। साथ ही नियमित सेवा अवधि के आधार पर चयनित वेतनमान एवं सातवें वेतन आयोग के परिलाभों के भुगतान भी स्वीकृत किये गये।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत राज्य की आठ सी.टी.ई. संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्यरत कार्मिकों के समायोजन हेतु सक्षम स्तर की कमेटी बनाकर समायोजन हेतु अनुशंसा की गई एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शिक्षा विभाग ने पत्र दिनांक 26.03.2021 जारी कर सीटीई संस्थाओं की सेवाएं वर्ष 2020-21 से निरन्तर नहीं रखने के निर्देश दिये गये, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्मिकों के समायोजन हेतु किसी प्रकार का दिशा-निर्देश, निर्णय नहीं दिया गया।

शिक्षा ग्रुप-1 के उपशासन सचिव द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के निदेशक से सीटीई के कार्मिकों को डाइट, आईएएसई एवं आरएससीईआरटी में समायोजन करने हेतु प्रस्ताव मांगे गये। स्कूल शिक्षा परिषद् ने निदेशक, स्कूल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को समायोजन का प्रस्ताव बनाकर भेजने हेतु दिनांक 26.07.2022 को व निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर को पत्र प्रेषित किया गया, जिसका प्रत्युत्तर प्रस्ताव शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप-1 जयपुर को प्राप्त हो चुके हैं।

अतः सीटीई संस्थाओं के कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाया जावे।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर)

फतेहपुर में ट्रोमा सेंटर में नवीन पद सृजित कर पदस्थापन

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ट्रोमा सेन्टर में पद सृजित करने की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) में ट्रोमा सेन्टर है, इसमें डाक्टर का एक पद सृजित है तथा नर्सिंग स्टाफ के पांच पद सृजित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिन पर वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं में घायलों को ट्रोमा सेन्टर फतेहपुर लाया जाता हैं। वहां चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के कारण समय पर भुगतान नहीं मिल पाता जिससे जल्दी उपचार नहीं मिलने के कारण घायलों की मृत्यु हो जाती है। घायलों को सीकर रेफर करना पड़ता है, जिससे उपचार में देरी होती है।

अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ट्रोमा सेन्टर में आवश्यक एवं अतिरिक्त पदों का सृजन कर स्टाफ लगाने की कृपा करें ताकि दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को आवश्यक उपचार मिल सके।

श्री जे. पी. चन्देलिया (पिलानी)

पिलानी की उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिलानी में उप तहसील, पिलानी संचालित है। जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा जब इस संबंध में राज्य सरकार को अभिशंसा प्रेषित की गई थी, उस समय जिला कलेक्टर की अभिशंसा में इस क्षेत्र के लिए उप तहसील तथा तहसील दोनों के लिए अभिशंसा की थी क्योंकि इस क्षेत्र में दो नगरपालिका-नगरपालिका पिलानी तथा नगरपालिका विद्या विहार एवं 53 गांव शामिल हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इस उप तहसील पिलानी से छोटी अनेक स्वतंत्र तहसीलें राजस्थान में हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जो भू-भाग और क्षेत्र इस उप तहसील पिलानी में शामिल किया गया है, वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें कई राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं यथा केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी तथा रक्षा महत्व की ब्रह्मोस राष्ट्रीय परियोजना तथा बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंस, पिलानी (बिट्स) आदि स्थित हैं। यह क्षेत्र राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर अवस्थित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उप तहसील, पिलानी के क्षेत्र की दो

नगरपालिकाओं तथा 53 गांवों और 24 ग्राम पंचायतों के लोगों को अपने राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए पिलानी विधान सभा क्षेत्र के बाहर दूसरी विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ जाना पड़ता है क्योंकि उप तहसील के रूप में यह प्रशासनिक दृष्टि से तहसीलदार, सूरजगढ़ के अधीन आती है। इसे तहसील बनाने पर यहां के लोगों का राजस्व संबंधी तथा प्रशासनिक कार्य यहीं तहसील पिलानी से ही हो जायेगा और उन्हें दूसरी विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है।

अतः सारे बिन्दुओं और ऐतिहासिक महत्वों को देखते हुए तथा राजस्थान की सीमा का क्षेत्र होने के कारण इसे प्रशासनिक दृष्टि से उप तहसील पिलानी की बजाय तहसील पिलानी के रूप में क्रमोन्नत किया जाना न्यायसंगत ओर आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उप तहसील पिलानी को तुरंत तहसील के रूप में क्रमोन्नत कर अनुग्रहित करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

पाली नगर परिषद् के कथित ठेकेदार द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

महोदय, नगर परिषद्, पाली के ठेकेदार हनुमान सिंह राजपुरोहित ने परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग होकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसका करीब दो करोड़ का पेमेन्ट इसलिये लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है कि चैक काटने के एवज में परिषद् सभापति, सभापति के पार्षद पति एवं अन्यों द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है। इतना कमीशन देने में असमर्थता बताने पर उसे पेमेन्ट नहीं दिया गया, जिसके कारण उसे मांगने वालों को जवाब देना मुश्किल हो गया। ठेकेदार की मौत पर आक्रोशित लोगों को प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने पर नामजदों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी एवं मृतक का बकाया पेमेन्ट भी सात दिनों के भीतर दिलवा दिया जायेगा। सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आ गई एवं लिखावट मृतक की बताई फिर भी पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध नहीं कार्यवाही की गई। पुलिस इतने गंभीर प्रकरण की जांच भी धीमी गति से कर रही है। मृतक की बकाया राशि भी कुछ दी गई, काफी देनी शेष है। अभी भी सभापति पेमेन्ट देने में अनावश्यक टिप्पणियां कर बिल रोकने में लगी हैं।

सरकार द्वारा इसी प्रकरण में आयुक्त एवं कैशियर के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही कर दी गई जबकि भारी कमीशन नहीं देने के कारण पेमेन्ट नहीं

करने वाले सभापति एवं उनके पति जो आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मुख्य आरोपी हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। परिषद् में सभापति के निर्देश पर ही पेमेन्ट किया जाता है।

दोषियों की गिरफ्तारी एवं निलम्बन हेतु सरकार से निवेदन है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

सिवाना के गांवों में पेयजल व्यवस्था

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना बाड़मेर पेयजल योजना के पोखरण, फलसूंड का कार्य 2018-19 में पूरा होना था, सिवाना विधान सभा के सभी गांव इसी योजना में हैं, परन्तु अभी तक कार्य अपूर्ण पड़ा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जनता परेशान है। इस योजना में स्टाफ नगण्य है। इन सर्दियों में भी पानी नहीं मिल रहा है तो गर्मियों में क्या हालात होंगे। इसमें निम्न गांव आते हैं:- सिणधरी, नाकोड़ा, डंडाली, भूखा, भगतसिंह, कमठाई, धने की ढाणी, लोहड़ी खारामेचान, चाडो की ढाणी, गालानाडी, अरणियाली, मेहचान भाटा, खेड़ा, मिठा और धनवा, हिमे की ढाणी, गोलिया, दाखा, महादेव नगर व सिवाना में सिवाना मूठली, इन्द्रराना, कुसीप, मेली, थापन, पादरडी खुड़द, पादरडी कला, मवड़ी, देवन्दी, अरजियाना, दंताला, बिजलिया, लूधराडा, माहीलावास, मोकलसर, गोलिया, पिपलून, गूंगरोट, रमणियां, काठाडी, धर्बेला, भागवा, तेलवाड़ा, धीरा, जीणपुर, मांगी, सेला, कुंडल, मुबारी, वेरानाडी, रेला की ढाणी, कांकी, पऊ, ईटवाया, पादरू, चिडियाद नगर, मिठौंडा, धारणा, सिरेण, गुड़ा व गुड़ा नाल, थान माता हिंगलाज, बार-बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जनता का धैर्य टूट रहा है और पीने का पानी जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीने का पानी शीघ्र उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़)

विद्युत विभाग में कार्यरत ठेका श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान में विद्युत विभाग में कई ठेका श्रमिक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे कोई एफआरटी तो कोई जीएसएस/132 और क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय में कार्यरत हैं। वर्तमान में उक्त ठेका कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसके कारण कार्य करने वाले ठेका कर्मचारियों को अपना घर परिवार चलाना

बहुत मुश्किल हो गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जो न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया गया है वह बहुत ही कम है। उसमें भी ठेकेदार गबन कर लेते हैं जिस कारण यह न्यूनतम पारिश्रमिक भी ठेका कर्मचारी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। ठेकेदारों द्वारा उक्त श्रमिकों को विद्युत कार्य करते समय उचित सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, ऐसे में ठेका श्रमिक अपने जिंदगी अथवा अंग भी गंवा देते हैं फिर अपाहिज हो जाते हैं। आये दिन इस तरह के मामले संज्ञान में आते रहे हैं, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा या विभाग के ठेकेदार के द्वारा पीड़ित को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं की जाती है, केवल मात्र आश्वासन देकर इतिश्री कर दी जाती है। मृतक के परिजन अथवा पीड़ित स्वयं विद्युत विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा-लगाकर केवल मात्र समय का अपव्यय कर रहे हैं, लेकिन सरकार अथवा विद्युत विभाग के अधिकारी इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आये दिन ठेका कर्मचारी के परिजनों की समस्या को अनदेखा करते आये हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के ठेकेदार श्रमिकों का कई तरह से शोषण करते हैं, जिसमें कोई ठेका कर्मचारी अपने उचित वेतन की मांग भी कर ले तो उसे कार्य से तुरंत निकाल दिया जाता है। श्रम विभाग में शिकायत करने पर भी श्रमिकों के साथ में मारपीट कर शिकायत को खारिज करवा दिया जाता है। इस प्रकार की कई समस्याओं से विद्युत श्रमिक परेशान हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विद्युत विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में नीतिगत निर्णय लेते हुए उनका न्यूनतम वेतन रु. 21,000 प्रतिमाह सीधे उनके खाते में जमा कराया जाए, साथ ही उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा तथा संरक्षण की सुनियोजित व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए और सबसे महत्वपूर्ण, समयानुसार सभी ठेका कर्मचारियों को विभाग मे स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाकर राहत प्रदान करें। सादर।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर)

जोधपुर के राजकीय स्वामित्व के हेरिटेज भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार

मान्यवर, उपर्युक्त विषयान्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध स्थापत्ययुक्त रियासतकालीन सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर की स्थापत्य कला विश्व प्रसिद्ध है। यहां का मेहरानगढ़ किला,

कुएं-तालाब-बावड़ियों, संकड़ी गलियां और विशाल ह्रदय वाले लोगों को देखने विश्वभर के नागरिक आते हैं। यहां का हेरिटेज स्थापत्य बहुत ही मनमोहक है परन्तु संरक्षण के अभाव में अपना स्वरूप खो रहा है। इन हेरिटेज भवनों में बहुत सारे सरकारी कार्यालय और विद्यालय संचालित हो रहे हैं। राजमहल विद्यालय का भवन, न्यू गवर्नमेन्ट विद्यालय का भवन, ह्यूसन मण्डी विद्यालय का भवन, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय खाण्डा फलसा का भवन, जिला कलेक्ट्रेट का भवन, कोतवाली विद्यालय का भवन, विद्याशाला विद्यालय का भवन, प्राचीन कुएं, बावड़ियां आदि बहुत सुन्दर स्थापत्य संजोये हुए हैं, परन्तु यह संरक्षण के अभाव में अपना स्वरूप खोने की स्थिति में हैं। अब भी जितना हेरिटेज स्थापत्य बचा है उन्हें देखकर पर्यटक मुग्ध हो जाते हैं, परन्तु बहुत ही खेद का विषय है कि इन हेरिटेज भवनों के प्रति सरकार और प्रशासन का रवैया अत्यधिक उपेक्षापूर्ण है। इस कारण ये अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं और कई तो दुर्घटना संभाव्य बन गये हैं। यदि इन हेरिटेज स्थापत्ययुक्त भवनों की सही सार-संभाल हो और इनका पुरा वैभव उभारा जाये, तो ये जोधपुर के स्थापत्य की अमिट निशानी सिद्ध होंगे और इससे विश्व पर्यटन मानचित्र में जोधपुर की पहचान मिलेगी और पर्यटन ठहराव बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

अतः मेरी मांग है कि उक्त समस्त सरकारी स्वामित्व के हेरिटेज भवनों और कुओं-तालाब-बावड़ियों के संरक्षण हेतु विशेष कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जावे। सादर।

श्री बिहारीलाल (नोखा)

प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा के लिए सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना

महोदय, हमारे राजस्थान प्रदेश के व्यापारी भाई बड़ी सख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में अपना करोबार करते हैं। ये ऐसे लोग है जो अपने पुरुषार्थ व व्यवसाय कौशल से राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों में हमारे इन परिवारों को मारवाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष होता है कि हमारे यहीं मारवाड़ी भाई हमारे राज्य के आर्थिक तंत्र को भी बेजोड़ मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें सदन को यह बताते हुए भी बहुत दुख होता है कि इन प्रवासी मारवाड़ियों के साथ वहां के गुण्डा संगठनों द्वारा भारी अन्याय व अत्याचार किया जाता है, स्थानीय बदमाशों द्वारा हमारे इन मारवाड़ी परिवारों से जबरन हफ्ता-वसूली, मारपीट तथा कई बार इन्हें जान से भी मार दिया जाता है। विगत में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, किन्तु आज तक किसी आपराधिक संगठन या व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है।

ऐसे में व्यापारियों, मजदूरों, नौकरीपेशा राजस्थानियों को देश के पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में भारी अत्याचार सहना पड़ रहा है। उन लोगों को स्थानीय गुण्डों के रहमोकरम पर मोटी रकम चुका-चुकाकर व अनचाहे समझौतों के साथ चौबीसों घंटे भारी डर और खौफ के साये में जीना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के केन्द्र आसाम में तो अब गुलाबजी भाई साहब संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल बनकर जा रहे हैं परंतु पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना आदि में कौन चिंता करेगा?

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि हमारी सरकार हमारे प्रदेश के व्यापारियों को उचित सुरक्षा देने के लिए संबंधित राज्यों की सरकारों से वार्ता करे व कम से कम प्रत्येक राज्य की राजधानी स्तर पर प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों, मजदूरों तथा नौकरीपेशा मारवाड़ी भाइयों की जानमाल व व्यापार की सुरक्षा हेतु चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष की स्थापना करे, ताकि किसी भी अनहोनी घटना पर पीड़ित परिवार को तत्काल आपात मदद मुहैया कराई जा सके जिससे कि हमारे मारवाड़ी भाई देश के किसी भी कोने में निर्भय होकर अपना सुरक्षित कारोबार कर सकें।

कोरोना काल की विभीषिका में हमने इसकी कमी को बहुत महसूस किया था जब देश के अलग-अलग प्रदेशों में फंसे मजदूर व व्यापारी भाइयों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तब हमने प्रारम्भ में 2-4 प्रशासनिक अधिकारियों को संबंधित प्रदेश की सरकारों, प्रशासन से कोर्डिनेशन के लिए लगाया था जो अपर्याप्त था फिर हमने राजस्थान कैडर के संबंधित प्रदेशों के आईएएस, आईपीएस अफसरों को इस काम में लगाया था, परंतु उस कठिन दौर में यह भी अपर्याप्त ही था इसलिए प्रत्येक राज्य में इस हेतु राजस्थान सरकार का एक कार्यालय या तंत्र विकसित होना चाहिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना)

मनोहर थाना में औद्योगिक इकाइयों का संचालन कर क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में गरीब एवं मजदूर वर्ग के पलायन के संबंध में निवेदन है कि मेरी विधान सभा के लोग ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं जिसके कारण लोगों को खेती करने एवं मजदूरी करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं पठारी क्षेत्र होने के कारण सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इस समस्या के कारण क्षेत्र में भील, तंवर, लोधा, गुर्जर एवं अन्य पिछड़ी जातियां वर्ष में दो बार पलायन करती हैं, घर परिवार को छोड़कर सब लोग मजदूरी के

लिए दूर-दराज क्षेत्र में बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनके जीवन एवं उनके छोटे-छोटे बालक एवं बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है।

पूर्व मुख्य मंत्री महोदया ने औद्योगिक फैक्टरी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया था लेकिन सरकार बदलने के बाद निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है एवं राज्य सरकार ने बजट घोषणा में लाडपुरा बलराम मनोहर थाना में औद्योगिक स्थान प्रस्तावित किया है, जिसके लिए शीघ्र बजट जारी कर कार्य प्रारम्भ किया जावे, जिससे होने वाले पलायन को रोका जा सके एवं उक्त पिछड़ी जातियों का आर्थिक सर्वे करवाकर उनको विशेष पैकेज दिया जावे जिससे उनके जीवन-यापन में सुधार हो सके और उनकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके और रोजगार पाकर बेरोजगारी से छुटकारा पा सकें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

किशनगढ़-अरांई-मालपुरा हाईवे सड़क का किशनगढ़-अरांई से अजमेर सीमा तक ही पुनर्निर्माण कार्य

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सड़कों के समग्र विकास हेतु राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत संचालित महत्वाकांक्षी योजना में किशनगढ़-अरांई-मालपुरा सड़क (एस.एच.-07ई एवं एस.एच.-101) का सुदृढ़ीकरण एवं लम्बाईकरण कार्य पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर बालाजी कम्पनी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी प्रस्तावित लम्बाई 66.950 किमी है। उक्त सड़क की कुल लम्बाई में से 40.00 किमी भाग अजमेर जिले व 26.950 किमी भाग टोंक जिले में पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, उक्त सड़क किशनगढ़-अरांई से अजमेर जिले की सीमा तक सिंगल लेन (3.500 मीटर) की चौड़ाई में स्थित है व पूरी तरह से जर्जर व क्षतिग्रस्त है जबकि टोंक जिले की सीमा से मालपुरा तक के रोड का निर्माण वर्ष 2017-18 में ही करवाया गया है, जो डबल लेन (7.00 मीटर) की चौड़ाई में है व वर्तमान में अच्छी व मजबूत स्थिति में है, जिस पर कहीं भी गड्ढे या पेचवर्क नहीं है। टोंक जिले की सीमा से मालपुरा सड़क के निर्माण कार्य के दौरान सभी पुलियाओं व आवश्यकतानुसार सीसी रोड का कार्य नालियों सहित पूर्ण करवा दिया गया है। इसलिए कार्यकारी कम्पनी द्वारा केवल किशनगढ़-अरांई से अजमेर सीमा तक की सड़क का ही निर्माण कार्य करवाया जाकर टोल प्लाजा स्थापित करना चाहिए। टोंक जिले की सीमा से मालपुरा सड़क का निर्माण कार्य करवाने से क्षेत्र की जनता पर टोल का अनावश्यक

आर्थिक भार बढ़ेगा और उक्त निर्माण कार्य में सरकारी पैसों का दुरुपयोग होगा। इससे क्षेत्र की जनता में असंतोष और भारी आक्रोश है।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक जिले की सीमा से मालपुरा तक की सड़क का निर्माण कार्य रूकवाये जाने की कृपा करें।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा)

गोगुन्दा की ग्राम पंचायत देवला का पंचायत समिति में क्रमोन्नयन

महोदय, निवेदन है कि पिछले 3 वर्ष में पंचायती राज का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया था, जिससे कई नई ग्रा.पं. व पं.स. का गठन हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र के देवला को पं.स. बनाने के प्रस्ताव बनाकर भेजे गये तथा जो पुनर्गठन के प्रस्ताव भेजे गये थे वो प्रस्ताव सभी पुनर्गठन के नियमों को पूर्ण करते हुए भेजे गये थे। नियम के अनुसार जो टी एस पी क्षेत्र की पं.स. बनाने के लिए 21 ग्रा.पं. होना जरूरी था, इस नियम को पूर्ण करते हुए प्रस्ताव भेजे गये थे लेकिन देवला में पंचायत समिति नहीं बनाई गई थी। क्षेत्र के लोगों को पं.स. कोटड़ा जाना पड़ता है तथा कोटड़ा की दूरी लगभग 70-80 किमी. दूर पड़ती है। आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः आम जनता की जन भावना को ध्यान में रखते हुए देवला में पं.स. बनाई जाने की उचित कार्यवाही की जावे।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर)

सादुलपुर में फसल बीमा कम्पनियों द्वारा अतिवृष्टि से हुए नुकसान का भुगतान

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला-चूरू व आस-पास के क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कई बार तापमान जीरो डिग्री से नीचे माइनस में चला जाता है। खराबे की जानकारी के लिए जिला कलेक्टर, चूरू ने गिरदावरी के आदेश दिये है परन्तु गिरदावरी में खराबा आने के बाद भी किसानों को बीमा कम्पनियां क्लेम नहीं देंगी क्योंकि फसलों की बीमा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर भिन्न-भिन्न ब्लाक के लिए भिन्न-भिन्न फसलों एवं किस्मों को नोटिफाई कर दिया जाता है। बीमा कम्पनियां उस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पैदावार होने वाली फसल का चुनाव कर किसान को फसल बीमा कर देती हैं, चाहे किसान ने अपने खेत में अन्य फसल ही क्यों न बोई गई हो।

अध्यक्ष महोदय, कई बार किसान द्वारा अपने खेत में सरसों एवं चने की फसल बोई जाती है। ऐसे में यदि उस किसान के खेत में सरसों की फसल खराब हो जाती है तो बीमा कम्पनी आसानी से क्लेम आवेदन को अस्वीकार कर देती हैं तथा किसान व सरकार द्वारा भरी गई बीमा प्रीमियम राशि डकार जाती है। साथ ही राज्य सरकार के आदेश के बावजूद क्षेत्र से किसानों द्वारा निरन्तर शिकायतें की जा रही हैं कि खराब फसलों के मुआवजे हेतु पटवारी/गिरदावर नहीं आ रहे हैं जिस कारण उन्हें क्लेम मिलने में दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियम बनाकर फसल बीमा के संबंध में बीमित होने वाली एवं बोई जाने वाली फसल का चुनाव करने का अधिकार किसान साथियों को दिया जावे ताकि किसानों को उचित लाभ/राहत मिल सके।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर)

लूणकरणसर ग्राम पंचायत की भूमि का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु किये गये आबंटन को निरस्त करना

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन ग्राम पंचायत लूणकरणसर में रीको औद्योगिक क्षेत्र व मण्डी विकास समिति के समीप खसरा नं. 1047 (पुराना 730/975) है जिसमें अराजीराज रकबा 812 बीघा है, उसका 209 बीघा व 81 बीघा (लगभग 290 बीघा) का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के तहत आबंटन किया गया है, जोकि नियम विरुद्ध राजनैतिक रसूखदारों, प्रशासनिक अधिकारियों, पटवारियों द्वारा मिलीभगत से स्वयं के व अपने रिश्तेदारों के नाम आबंटन कराया गया है।

इस भूमि का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है। आबादी भूमि व औद्योगिक क्षेत्र के समीप इसका उपयोग लूणकरणसर क्षेत्र में मेहनतकश किसान, युवाओं व व्यापारियों की बदौलत लूणकरणसर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके लिए इस भूमि का उपयोग आवासीय योजना लाकर व रीको विस्तार में किया जाना चाहिए।

इस विषय को जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया पर अधिकारियों व पटवारियों की लूट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरा निवेदन है कि जांच करवाकर जो नियम विरुद्ध आबंटन किया गया है उसको निरस्त किया जाए व जिन अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया गया है उन पर कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)

पंचायत समिति सदस्यों की मांगों पर विचार कर उन्हें अधिकार प्रदान करना

महोदय, मैंने इस प्रस्ताव के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराने व अधिकार प्रदत्त किये जाने की आवश्यकता बतायी है। इस संबंध में पंचायत समिति सदस्यों की प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं:-

1. सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार (विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन/प्रमाणीकरण करने का अधिकार) देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जावे।
2. अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि (SFC, TFC व अन्य योजनाओं) में से पंचायत समिति सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचित क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध कराई जावे।
3. अपने वार्ड में पंचायत समिति मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रपत्र 5 दिये जाने की अनिवार्यता को हटाया जाए। इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।
4. स्वायत्तशाषी संस्थाओं (शहरी निकाय) के पार्षदों व पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान, जिला प्रमुख व सरपंच की भांति पं.स. सदस्यों को भी मासिक मानदेय न्यूनतम 10,000/- रुपये स्वीकृत किये जायें।
5. सदस्य के वार्ड में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यों के पूर्णता, उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC, CC) पर पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य किये जावें।
6. पं.स. सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत की कोरम बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों (पट्टा पत्रावलियों, अतिक्रमण आदि मुद्दों) में

कोरम के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु परिपत्र जारी करावें।

7. वार्ड में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यों की शिलालेख पट्टिकाओं पर पंचायत समिति सदस्यों का नाम एवं पंचायत समिति से स्वीकृत विकास कार्यों हेतु पंचायत समिति सदस्यों की अनुशंसा अनिवार्य की जावे।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के पंचायत समिति सदस्यों की सभी वाजिब मांगों पर विचार कर अधिकार प्रदान करने का कष्ट करावें। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

खानपुर के बकानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

महोदय, विधान सभा क्षेत्र खानपुर का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा बकानी है। यहां पर तहसील कार्यालय के अलावा पंचायत समिति कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विधुत सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित है। शिक्षा की दृष्टि से यहां पर आई.टी.आई. कालेज, स्वामी विवेकानन्द माडर्न स्कूल, बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थापित है। वर्तमान में बकानी तहसील के अन्दर 40 सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में लगभग 6000 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 45 किलोमीटर दूर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय पी.जी. कालेज में जाना पड़ता है। बकानी क्षेत्र से लगभग 500 विद्यार्थी पी.जी. कालेज झालावाड़ में पढ़ने आते हैं। वर्तमान में पी.जी. कालेज, झालावाड़ में सबसे ज्यादा छात्र-छात्राएं बकानी क्षेत्र के हैं। बकानी क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवार निवास करते हैं। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह अपने बच्चों-बच्चियों को पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं भेज पाते जिसके कारण कक्षा 12वीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बालिकाओं को आती है। अतः माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बकानी में कालेज खुलवाया जाये जिससे यहां के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े। धन्यवाद।

परिशिष्ट-02

लिखित वक्तव्य

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद पर माननीय सदस्यगण के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका व माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनजाति छात्रावास खोलने व बीलखेड़ा डांग व मेहदरा में 33 के वी जी एस एस खोलने के लिए एवं शाहबाद एवं नाहरगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए जो राशि दी उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूं एवं साथ ही चिरंजीवी योजना की राशि को 10 लाख से 25 लाख करने व उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर सस्ता करने व बिजली के बिलों पर 100 यूनिट की छूट करने और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक घोषणा, कोचिंग एवं विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क फार्म भरने की घोषणा करने का मैं तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। साथ ही मेरी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सहरिया आवास योजना को पुनः चालू करवाने, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र परानियां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। यह पिछले 20 वर्षों से क्रमोन्नत नहीं हुआ है। शाहबाद में ट्रोमा सेन्टर खोलने, केलवाड़ा को उपजिला चिकित्सालय घोषित करने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाहरगढ़ की बैड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाए। मेरी अगली मांग एनिकटों की है, एनिकटों की मरम्मत के लिए बजट दिया जाए। समरानियां, धनसूरी, पंचमहादेव, मिसाइल एवं पीपल्दा इनकी मरम्मत के लिए बजट दिया जाए। सोडाना रैबारपुरा, पीपल्दा, छीनोद, रामपुरिया, बालाखेडा को बढ़ाव बचाओ हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण, सड़क सुरक्षा चन्द्रगढ़ बम्बौरी रोड पर बड़ौदिया के सामने पुल निर्माण करवाया जाए। केलवाडा को नगरपालिका घोषित करने, नाहरगढ़ को उपतहसील से तहसील में क्रमोन्नत करने एवं मुख्यालय शाहबाद में अनुसूचित जाति छात्रावास एवं शाहबाद क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने एवं कस्बा नाहरगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग करती हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में राड़ी बांध निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करें। मुख्यालय शाहबाद से पुराने बस स्टैण्ड से रियासतकालीन रास्ते का निर्माण एवं शाहबाद में कुण्डा खोह में नीचे सीढ़ी का निर्माण करवाया जाए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई घोषणाओं के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि उन्होनें अपने बजट में राजस्थान के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा है।

मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा का धनी दूसरा कोई नहीं देखा कि जो हर समय गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, महिला और एस सी, एस टी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान व कल्याण की सोचता हो। कोविड-19 की महामारी के समय जो शानदार प्रबंधन मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किया उसकी प्रशंसा न केवल देश में बल्कि संसार के कई देशों में हुई। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बजट से राजस्थान के समग्र विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार होगा जो हमारी आगामी पीढ़ी के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

बजट की सबसे बड़ी घोषणाएं-

1. किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक व घरेलू कनेक्शन पर 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध।
2. रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा। रोडवेज किराये में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा व 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाडी केन्द्र खोलने की घोषणा से महिलाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
3. सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। (जो पहले लागू नहीं थी, पहली बार)
4. संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, कान्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। दो लाख संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक लाभ की घोषणा।
5. कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा।
6. लक्खी मेले के लिए कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर,

खाटूश्याम, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, पांडूपोल अलवर, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम के लक्खी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50 प्रतिशत किराये में छूट मिलेगी।

7. किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान व सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा।

8. जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, वीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने की घोषणा।

9. लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा, 40 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा।

10. खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 01 करोड परिवारों को निःशुल्क राशन साथ फूड पैकेट (एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, तेल व मसाले) एवं पीएम उज्ज्वला व बीपीएल योजना के अन्तर्गत आने वाले 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर मिलेगा।

11. सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के तहत बुजुर्गों को न्यूनतम पेंशन 1000 रु. (जो पहले 500, 750 रु.) की गई तथा इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत इंक्रीमेंट दिया जायेगा जिससे परिवार के बुजुर्गों को सम्बल मिलेगा।

12. बीमार श्रमिकों को 7 दिन तक रोज 200 रु. की आर्थिक सहायता।

13. इस बजट में युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सभी ब्लाक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई वाचनालय व डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की गई, जिससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व अध्ययन की सुविधा मिलेगी।

14. युवाओं के लिए 500 करोड़ रु. से युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन तथा जिला मुख्यालयों पर 100-100 आवासीय क्षमता के विवेकानन्द यूथ होस्टल बनाये जायेंगे एवं 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग।

15. सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के बाद कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे सभी वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा व पेपर लीक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन एसटीएफ का गठन किया गया है।

16. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 01 लाख 42 हजार अधिक नियुक्तियां दी जा चुकीं तथा 01 लाख 81 हजार से अधिक प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही आगामी वर्ष में रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां भी की जायेंगी।
17. स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती कि जायेगी।
18. शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व बजट में प्रदेश के सभी सैकण्डरी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया व 2000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गये हैं।
19. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जायेंगे। आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की घोषणा से गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पायेगी।
20. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए स्वीकृत होने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख व मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 रुपये लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किये जायेंगे जो आमजन के लिए बहुत बड़ी योजना है।
21. ईआरसीपी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 9,600 हजार करोड़ व वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 हजार करोड़ के कार्यों से ईआरसीपी को आगे बढ़ाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस वित्तीय वर्ष के बजट से सम्पूर्ण राजस्थान के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा। खासतौर से सभी वर्गों के लिए जो बजट में वित्तीय प्रावधान बढ़ाये गये हैं उससे इस वर्ग के सभी लोगों को फायदा मिलेगा।

मै इन बजट प्रस्तावों का स्वागत एवं समर्थन करता हूं तथा इस वित्तीय वर्ष के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पीएचईडी का XEN कार्यालय, नायला को पशु चिकित्सालय से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत, नीमला श्रीनगर में 33 केवी जीएसएस, जमवारामगढ़ में उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम, 48 हैक्टेयर में इन्टीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क व नकची घाटी से नायला तक 23 करोड़ की लागत से सड़क स्वीकृत करने का जो फैसला लिया, उसका सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए निम्न मांग करता हूं और

मैं आशा करता हूं कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे तथा मुझे व मेरे क्षेत्र को आशीर्वाद प्रदान करेंगे:-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग का नवीन XEN कार्यालय खोलना।
2. मानोता भावपुरा सड़क से धुला रोड वाया सन्नाटा घाटी, चावण्डिया, रामपुरा, दौलतपुरा, धर्मपुरा का निर्माण,

   रायसर रोड (गोपालगढ) से एन.एच.-148 सड़क का निर्माण कार्य, बिलोद से ताला सड़क निर्माण कार्य,

   गुढा (एस एच-52) से जयपुर (एन एच-8) वाया किशोरी, सिघला, तिबारा, झिरी, आंधी रामगढ़ किमी 53/0 से 54/0 एवं 55/0 से 66/700
3. भानपुर कलां में कृषि महाविद्यालय व रायसर में कन्या महाविद्यालय खोलना।
4. ईआरसीपी के तहत जल्द से जल्द जमवारामगढ़ बांध को जोड़ते हुए यदि इसमें पानी आता है तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर तक किसानों व आमजन को पानी उपलब्ध हो सकेगा।
5. उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना।
6. रायसर व चावण्डिया में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत।
7. बूज, डांगरवाडा, नेवर, बहलोड को पीएचसी में क्रमोन्नत करना।
8. जमवारामगढ़ में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध।
9. रायसर में उप तहसील खोलना।
10. ताला में 132 केवी जी एस एस खोलना।
11. जमवारामगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज मण्डी) खोलना।
12. नीमला में पुलिस चौकी खोलना।
13. महाविद्यालय जमवारामगढ़ को पीजी में क्रमोन्नत करना।
14. तहसील आंधी में एसडीएम कार्यालय खोलना।
15. शेष सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षक व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलना।

- बजट सार्वजनिक संबंध को दर्शाने का एक माध्यम है। यदि बजट की तरफ सिर्फ इस नजर से देखा जाए कि इसमें किस सेक्टर को कितना वित्तीय आबंटन किया गया तो यह एक बहुत तकनीकी और बोरिंग

(Boring) दस्तावेज मात्र बनकर रह जाएगा। परन्तु सही मायने में बजट न केवल, जिन लोगों ने सरकार को चुना है उन लोगों के प्रति सरकार के इरादों को जाहिर करता है बल्कि सरकार के स्वयं के विजन को भी प्रदर्शित करता है। हर वर्ष लोगों की बजट के प्रति उत्सुकता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह बजट के माध्यम से यह देखना चाहते हैं कि सरकार देश राज्य के प्रति तथा उसमें रहने वाले लोगों के प्रति कितनी चिंतित है।

राजकोषीय मानकों को साधते हुए आधारभूत ढांचे में किया गया निवेश सरकार के देश राज्य के विकास के लिए दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार लोगों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट में सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर कितना ध्यान दिया गया है, इसमें मोटे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कार्मिक कल्याण से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाता है। अगर इस कसौटी पर रखकर राजस्थान सरकार द्वारा 01 फरवरी 2023 को पेश किये गये केन्द्रीय बजट को देखा जाए तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार ने न केवल लोक कल्याणकारी राज्य का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है बल्कि उसे आत्मसात करने की दिशा में भी सतत प्रयास किया है।

- राज्य बजट का सबसे प्रबल एवं अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक पक्ष है सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान। एक लोक कल्याणकारी राज्य में एक व्यक्ति की जीवन पर्यंत न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होता है। राज्य सरकार ने गत वर्ष (2022-23) के बजट में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जब बहाली की थी, तब अधिकांश विपक्षियों द्वारा इसे सरकार की स्थायी नीति का हिस्सा नहीं मानकर चुनाव की राजनीति के रूप में पेश किया गया था लेकिन इस वर्ष सरकार द्वारा ओ पी एस के दायरे का विस्तार कर इसमें निगम, बोर्ड एवं सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल कर केन्द्र सरकार एवं अन्य सभी राज्यों के सामने एक मिसाल पेश की है। इस संबंध में बेहद दु:खद है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की इस पहल के लिए एनपीएस (NPS) के तहत की गई कटौतियों को राज्य को न लौटा कर नियमों का हवाला दिया जा रहा है। यहां मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस तरह

से कोविड की विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) में ढील दी गई थी, क्योंकि सरकार के लिए राजकोषीय अनुशासन की जगह जनता का कल्याण ऊपर था। ठीक उसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा एनपीएस के तहत की गई कटौतियों का पैसा वापस राज्य सरकार को भेज राजस्थान सरकार की जनहित में की गई इस पहल को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचान देनी चाहिए।

बेहद दु:खद है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2023 को पेश किये गये यूनियन बजट में पहली बार जीडीपी के प्रतिशत हिस्से के रूप में मनरेगा (MGNREGA) को सबसे कम बजट आबंटित किया गया है जो कि मात्र 0.2% है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत जैसे देश जिसमें आज भी लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है वहां मनरेगा का आय के एक औपचारिक स्रोत के रूप में कितना महत्व है, इसी को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार ने "महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना" लागू कर न केवल मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 25 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किये हैं बल्कि समाज के उपेक्षित वर्ग (marginalised section) को न्यूनतम रु. 1000 महीने की पेंशन भी लागू की है।

भारत देश जिसमें 90% श्रम शक्ति रोजगार के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है और उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में आवश्यकता ओ पी एस की व्यवहारिकता पर प्रश्न चिह्न लगाने की नहीं है बल्कि पेंशन के दायरे को बढ़ाने की है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर रु. 1000 प्रतिमाह किया है तथा इसमें प्रतिवर्ष 15% वृद्धि की भी घोषणा की है। कोविड की परिस्थितियों में "gig workers" (गिग श्रमिकों) की सेवाओं का महत्व हम सभी ने समझा है पर उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि राजस्थान सरकार ने "gig workers welfare act" के माध्यम से उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर सम्पूर्ण देश के समक्ष एक अनूठी मिसाल कायम की है।

औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि नियोक्ता एवं कार्मिक के संबंध स्वस्थ हों और वह तभी संभव है जब कार्मिक को उसकी पूर्ण मजदूरी प्राप्त हो। इस कड़ी में सरकार द्वारा RLSDC के

गठन की घोषणा कर ठेका कर्मियों को सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति देने से कार्मिकों में मुख्य नियोक्ता के प्रति विश्वास बनेगा तथा साथ ही नियोक्ता की भी श्रम संबंधी प्रबंध की समस्याओं का अंत होगा।

- कोई भी देश तब तक प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक की उसकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग निरक्षर, अस्वस्थ एवं कुपोषण से ग्रसित हो। मानव संसाधन के इसी महत्व को ध्यान में रखकर सभी विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय किया जाता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि "जनांकिकीय लाभांश" लेने की स्थिति में होते हुए भी भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जो कि इन पर जीडीपी के बहुत कम प्रतिशत हिस्से के रूप में किये गये व्यय में परिलक्षित होता है। वह हिस्सा नीचा ही नहीं बल्कि स्थिर (stagnant) किस्म का भी है।

प्रशंसा करनी चाहिए राज्य सरकार की जिसने "मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना" के माध्यम से "नि:शुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर" उपलब्ध करवाकर मानवीय संसाधन को उन्नत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की राशि को रु. 10 लाख से बढ़ाकर रु. 25 लाख प्रति वर्ष किया जाना इस योजना एवं राज्य की जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है कि स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थानिक विस्तार एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए अब राज्य के सभी 33 जिलों में मेडिकल कालेज की व्यवस्था होगी।

- ऊपर दिये गये विवरण के क्रम में यह ध्यान में लाने योग्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर किया गया व्यय 2.8% था जो 7 वर्ष की अवधि में वर्ष 2022-23 में 2.9% पर ही अटका हुआ है। कुशल श्रमिक पैदा करने की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे अग्रणी देशों में से एक है पर शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भविष्य में हो सकने वाले संभावित लाभों से अपने देश को वंचित करना है।

शिक्षा के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने बजट में आधारभूत शिक्षा के साथ-साथ शोध को बढ़ावा देने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बहुत से नवीन प्रावधान अन्य

सरकारों के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। जैसे बुनियादी शिक्षा का विस्तार करते हुए सरकार ने "राइट टू एजुकेशन" (RTE) में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा को भी शामिल कर दिया है जिसका लाभ विशेष रूप से वंचित वर्ग को नि:शुल्क स्कूली शिक्षा के रूप में मिल पाएगा।

कोविड की असाधारण परिस्थितियों ने हमें सिखाया कि शिक्षा प्राप्ति में लोकेशन की बाध्यता को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सरकार द्वारा ब्लाक लेवल पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक सहभागी बनाएगी।

शिक्षा का महत्व सिर्फ रोजगार प्राप्त करना ही नहीं बल्कि प्राप्त ज्ञान को समाज के हित में रूपांतरित करना भी है। शोध ही वह कड़ी है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान को समाज के हित में व्यवहारिकता में तब्दील करते हैं। यह भी राज्य बजट में शायद पहली बार देखा गया है जब सरकार द्वारा बजट में शोध के लिए अलग से प्रावधान किये गये हैं यूजीसी की तर्ज पर अब राज्य में भी नेट/स्लेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 3 वर्षों तक शोध कार्य करने हेतु रु. 20 हजार प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। साथ ही उन्हें विभिन्न कान्फ्रेंस सेमिनार और कार्यशाला में भाग लेने हेतु 25 हजार की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। उम्मीद की जाती है कि जैसे सरकार ने शोधार्थियों को प्रोत्साहन दिया है, उसी प्रकार शोधार्थी भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर शोध कर प्रभावी नीति निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों को भी शोध के लिए प्रोत्साहन हेतु "टीचर्स इंटरफेस फोर एक्सीलेंस" कार्यक्रम को भी सरकार ने प्रस्तावित किया है।

प्रशासकीय बाधाओं एवं संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" की दी गई सुविधा भी शिक्षा एवं विद्यार्थियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को जाहिर करती है।

- राज्य बजट की एक बहुत बड़ी खूबसूरती "महंगाई राहत पैकेज" के प्रावधान के रूप में देखी जा सकती है। मैंने यहां खूबसूरती शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि केन्द्र सरकार की तरह राज्य सरकार के पास मौद्रिक नीति के रूप में मांग को दबाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कोई हथियार नहीं होता पर फिर भी उस मुद्रास्फीति का सामना करने की ताकत जनता को देने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। 19 हजार करोड़ रु. का मुद्रास्फीति

राहत पैकेज एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें फूड पैकेट्स, सस्ती गैस एवं 100 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा शामिल है।

बजट के संबंध में सबसे रोचक बात यह है कि जनहित में किये गये प्रावधानों का क्रियान्वयन मात्र 3.98% राजकोषीय घाटे के साथ अनुमानित है जबकि दूसरी ओर पर्याप्त संसाधनों पर आधिपत्य होने के बावजूद केन्द्र सरकार का वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.90% अनुमानित है। यहां यह भी ध्यान में लाने योग्य है की लगातार पांचवीं साल राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

यह साबित करता है कि जनहित के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं पर उससे कहीं अधिक आवश्यक है जनहित की भावना और वर्तमान बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने उस भावना को दर्शाया है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में:-

1. बीसलपुर बांध के ओवर-फ्लो पानी को विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी बांधों में डालना।
2. टोडारायसिंह से देवली आवागमन हेतु बीसलपुर डैम के पास बनास नदी पर पुलिया निर्माण करवाना।
3. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा में ट्रोमा हास्पिटल खोलना।
4. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा व टोडारायसिंह में ब्लड बैंक की स्थापना।
5. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह व मालपुरा में जनाना हास्पिटल खोलना।
6. कृषि अनुसंधान केन्द्र डिग्गी (नुक्कड़) (डिग्गी नुक्कड़ में कृषि फार्म) में कृषि महाविद्यालय खोलना।
7. उपखण्ड टोडारायसिंह व मालपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय का संचालन करना।
8. भील समाज के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड टोडारायसिंह व मालपुरा में छात्रावास खुलवाकर एवं कोचिंग सेन्टर का संचालन करना।
9. मालपुरा में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना।

10. मालपुरा व टोडारायसिंह दोनों उपखण्डों में मिनी स्टेडियम निर्माण करवाना।
11. उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में उपजिला परिवहन कार्यालय खोलना।
12. टोडारायसिंह में स्थित पुरामहत्व के ऐतिहासिक स्थानों का संवर्धन एवं संरक्षण कर टोडारायसिंह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
13. टोडारायसिंह में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलना।
14. टोडारायसिंह के न्यायालय को ADJ कोर्ट में क्रमोन्नत करना।
15. मालपुरा में आरएसी व पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
16. ग्राम पंचायत लावा में पुलिस चौकी खोलना।
17. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह व मालपुरा में बैड वृद्धि करना।
18. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह के विलोपित पदों का पुनः सृजन करना।
19. ग्राम पंचायत पारली, उनियारा खुर्द व मोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
20. ग्राम पंचायत लाम्बाहरिसिंह, पचेवर, पंवालिया व लावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
21. लाम्बाहरिसिंह में उपतहसील खोलना।
22. लाम्बाहरिसिंह, लावा व पचेवर में स्वतंत्र कृषि मण्डी खोलना।
23. डिग्गी व लाम्बाहरिसिंह में पंचायत समिति खोलना।
24. जयपुर से कोटा वाया मालपुरा-टोडारायसिंह-देवली व टोंक से अजमेर वाया छाण-टोडारायसिंह-केकड़ी रात्रिकालीन बसों का संचालन।
25. स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालपुरा में सभी संकायों का संचालन करना।
26. विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदानों का आबंटन कर चारदीवारी निर्माण करवाना।
27. विधान सभा क्षेत्र के परिवहन बस सुविधाओं से वंचित सभी ग्रामों को ग्रामीण परिवहन बस सेवा से जोड़ना।
28. विधान सभा क्षेत्र के सम्पर्क सड़कों से वंचित गांव-ढाणियों को डामरीकरण सड़कों से जोड़ना।
29. ग्राम पंचायत बृजलालनगर को नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ना।

परिशिष्ट-03

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 17 में उल्लिखित विवरण के अंश

I. शाहबाद-बारां में खेल स्टेडियम तथा छात्र व छात्राओं हेतु खेल छात्रावास प्रारम्भ किये जायेंगे। इस पर 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. कंवर का बास (झोटवाड़ा)-जयपुर; चांदोली (उमरैण)-अलवर; चौहटन-बाड़मेर; सुजानगढ़, सालासर-चूरू; भुसावर-भरतपुर; सागवाड़ा-डूंगरपुर; मनियां-धौलपुर; बिसाऊ (मंडावा), अलसीसर, चिड़ावा-झुंझुनूं; सरदारपुरा (नाथद्वारा)-राजसमंद; बौंली, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर; शिवगंज-सिरोही; श्रीकरणपुर, सादुलशहर-श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ में खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।

III. सरदारपुरा (नाथद्वारा)-राजसमंद में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें विकसित करने के साथ-साथ कुश्ती अकादमी एवं स्टेडियम निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

IV. जनजातीय खेल प्रतिभाओं को बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व उदयपुर में 40 दिवसीय उच्चस्तरीय आवासीय खेल प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परिशिष्ट-04

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्‍बोधन के पैरा संख्या 22 में उल्लिखित विवरण के अंश

I. राजौरगढ़ (राजगढ़)-अलवर; डुंगराना (भादरा)-हनुमानगढ़; सिरस (वैर), इकरन (सेवर)-भरतपुर; नाथडियास (रायपुर)-भीलवाड़ा; जोगलसर (सुजानगढ़)-चूरू; गोठडा तगेलान (धोद); घिरणिया बड़ा, बीदसर एवं डूडवा (लक्ष्मणगढ़), सकराय सीकर; खेड़ला खुर्द (लालसोट) डूंगरपुर (रामगढ़ पचवारा)-दौसा; मदारिया (देवगढ़), गवारड़ा, उथारड़ा, उपली ओडन, गुंजोल (नाथद्‍वारा), सेखावास (भीम)- राजसमंद, पनोरिया (चौहटन)-बाड़मेर; भाडली (फतेहगढ़)-जैसलमेर; डांगियावास (बिलाड़ा)-जोधपुर; सिरासना (डेगाना), सूंथली (मकराना)-नागौर; चक 13 एफएफ (श्रीकरणपुर)-श्रीगंगानगर; माण्डावास (रोहट), रूपावास-पाली; पंड्यावाड़ा (ऋषभदेव), नवाणिया (वल्लभनगर)-उदयपुर सहित 200 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

II. कालेड़ा कंवरजी (केकड़ी)-अजमेर; मालपुर (गोविन्दगढ़), रसनाली (बानसूर)-अलवर; छीतर का पार (बायतू), बांटा (गुड़ामलानी); गोल स्टेशन (पचपदरा)-बाड़मेर; बसई (रूपवास)-भरतपुर; उमरी (करेड़ा)-भीलवाड़ा; छपरौली-धौलपुर; चिरपटिया (मारवाड़ जंक्शन), शिवपुरा (सोजत)-पाली; सारसोप (चौथ का बरवाड़ा)-सवाई माधोपुर; खरेश (डीडवाना)-नागौर; घाटी मौहल्ला-डूंगरपुर; नलवा (धरियावद)-प्रतापगढ़; काछीपुरा-करौली; गहनौली (महुवा)-दौसा; उण (आहौर)-जालौर, नेवा तलाई (जयसमंद)-उदयपुर; आवंलहेडा (बेगूं)-चित्तौड़गढ़; सुरेरा (दांतारामगढ़)-सीकर एवं अरटिया खुर्द (भोपालगढ़)-जोधपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। साथ ही, बाड़मेर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।

III. गाड़ौदा (लक्ष्मणगढ़), जेजूसर (नवलगढ़)-सीकर; संखवास (खींवसर) नागौर; बामणोर (चौहटन) बाड़मेर; चंदनपुरा (नदबई), बहज (डीग), सेवर-भरतपुर; दियातरा (कोलायत)-बीकानेर; चौरू (फागी) जयपुर; प्रतापपुरा (बांदीकुई)-दौसा; परानियां (किशनगंज)-बारां, सायरा (गोगुन्दा)-उदयपुर; पुनाली, मझौला-डूंगरपुर; बालेर (खंडार) सवाई माधोपुर; तरनऊ (जायल)-नागौर; कैमला (नादोती)-करौली; खुहड़ी (सम)-जैसलमेर; बागरा (आहोर), बागोड़ा, भीनमाल-जालौर एवं नेड़च बनेडिया, कोठारिया (नाथद्‍वारा) राजसमंद सहित 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. खेरली-अलवर; लोहावट जोधपुर; मंडरायल-करौली; बस्सी-चित्तौड़गढ़ एवं खंडेला, खाटूश्यामजी-सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. बाड़ी-धौलपुर व कुचामनसिटी-नागौर के उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VI. मेडिकल कालेज-भरतपुर में Critical Care Unit खोली जायेगी।

VII. श्रीगंगानगर में आयुष चिकित्सालय एवं बाड़मेर में आयुर्वेद चिकित्सालय खोला जायेगा।

VIII. आयुर्वेद औषधालय हिण्डौन सिटी-करौली को क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, 100 आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

IX. तिजारा-अलवर, सरदारशहर-चूरू, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर व रींगस-सीकर में ट्रोमा सेन्टर खोले जायेंगे।

X. उप जिला चिकित्सालय, नोहर-हनुमानगढ़ में ब्लड बैंक खोला जायेगा।

XI. जिला चिकित्सालय, नाथद्वारा (राजसमंद) में 67 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण करवाया जायेगा।

XII. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौली-बूंदी एवं कोटकासिम-अलवर में बैड की संख्या को 30 से बढ़ाकर 50 किया जायेगा। साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेडवा-बाड़मेर में बैड क्षमता 75 की जायेगी।

परिशिष्ट-05

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 30 में उल्लिखित सूची के अंश

I. सड़क निर्माण व सुदृढ़ीकरण कार्य

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
1.	घणोली वल्लभनगर सड़क (6 किमी.) (वल्लभनगर, उदयपुर)	3 करोड़ 50 लाख रुपये
2.	महेशनगर से अन्तर्मना सर्किल होते हुए आर के. कम्युनिटी तक सड़क (3.75 किमी.) (किशनगढ़, अजमेर)	8 करोड़ 02 लाख रुपये
3.	राजगढ़-थाना-धमरेड-अनावड़ा-नयागांव प्रतापपुरा-बालेटा रोड (13 किमी.) (अलवर)	10 करोड़ 40 लाख रुपये
4.	महंगी सीमा से लोठावास-संज्यानाथ महाराज होते हुए पलासाना-मुख्य दौसा रोड-चांदपुरा-मान्डयाला की ढाणी-जादूपुरा-पतालिया की ढाणी से हरियाणा ब्राह्मण की ढाणी-गली का गुवाडा होते हुए गुर्जरों की ढाणी-पाटरोलो का बास से अजबगढ़ रोड तक (26.5 किमी.) (थानागाजी, अलवर)	25 करोड़ रुपये
5.	धौलपुर के बाड़ी में मिसिंग व सम्पर्क सड़कों का कार्य (32.55 किमी.) (बाड़ी, धौलपुर)	15 करोड़ रुपये
6.	बसई नबाव में बाईपास रोड का निर्माण (5 किमी.) (बाड़ी, धौलपुर)	15 करोड़ 10 लाख रुपये
7.	झाड़ेवा-भूदा का बास से बगड़ियों का बास-लालासी चौराहा, खेड़ी राडान-कसवाली-खीचड़ो की ढाणी, बलारा-सांखु, डुडवा-मीलों की ढाणी सड़क निर्माण कार्य (42 किमी.) (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	13 करोड़ 26 लाख रुपये
8.	झाझड़ (एसएच-07) से एसएच-20 (नेछवा रोड) तक बाईपास सड़क (5.5 किमी.) (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	7 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
9.	मण्डावरी-दौसा में बाईपास निर्माण (लालसोट, दौसा)	35 करोड़ रुपये
10.	हवामहल के वार्ड नं. 14 दिल्ली बाईपास मानबाग चौराहे से 02 नं. बस स्टैण्ड तक एवं 02 नं. बस स्टैण्ड से लिंक रोड जाटों की ढाणी तक जाने वाली सड़क के फोरलेन चौड़ाईकरण का कार्य (जयपुर)	8 करोड़ रुपये
11.	अनास नदी पर भुआदरा में हाई लेवल पुल (गांगडतलाई, बांसवाड़ा)	43 करोड़ रुपये
12.	एन. एच. 68 से लुखु सुनारों की ढाणी रोहिला शोभाला-जेतमाल मेहलू मालपुरा से नौखड़ा सड़क (39 किमी.) (गुड़ामालानी, बाड़मेर)	27 करोड़ रुपये
13.	टेचरी का फांटा से कपिल सरोवर सड़क (8 किमी.) (श्रीकोलायत, बीकानेर)	12 करोड़ रुपये
14.	हुड़ला से समलेटी (वाया गोपालगढ़, सिन्दुकी, भोपर, ठेकड़ा, पीपलखेड़ा) सड़क (74 किमी.) (महुवा, दौसा)	35 करोड़ रुपये
15.	डुंगराना-भाड़ी मोड़ रोड (27.5 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	20 करोड़ रुपये
16.	डेवा की ढाणी-चारण की ढाणी-मोहनबाड़ी-कैमरों की ढाणी-बेरी-राजेश की ढाणी-जाखड़ी की ढाणी नाडा-परसरामपुरा-टोडपुरा-नागल-कोससिया-माण्डासी-डूण्डलोद सड़क (60 किमी.) (नवलगढ़, झुंझुनूं)	20 करोड़ रुपये
17.	कृषि मण्डी माताजी की ढाणी-कैराली जोहड़ी, बुगाला, कुमावास, खिरोड़, चिराणा-राणासर-डूमरा-जेजूसर-सुनारी जोहड़ी सड़क (48 किमी.) (नवलगढ़, झुंझुनूं)	16 करोड़ रुपये
18.	कल्याणपुरा से कोटड़ी-आमली रोड के चौराहे तक सड़क निर्माण मय वान्टेड कॉजवे निर्माण (सवाई माधोपुर)	2 करोड़ रुपये
19	भाड़ोती-मखौली रोड (सवाई माधोपुर)	30 करोड़ रुपये
20.	सवाई माधोपुर में लटिया नाले पर वैकल्पिक रोड निर्माण	133 करोड़ रुपये
21.	जैसलमेर में यूनियन चौराहे से एयरपोर्ट चौराहे तक सड़क चौड़ाईकरण	16 करोड़ 45 लाख रुपये
22.	हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क (एसएच-94) पर रेलवे फाटक संख्या 179 के स्थान पर डबल बाक्स आरयूबी मय अप्रोजेज व सर्विस सड़क निर्माण	20 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
23.	पाली शहर में सुमेरपुर रोड पर बांडी नदी पर 2 लेन पुल को फोरलेन (पाली)	35 करोड़ रुपये
24.	एनएच-48 जंक्शन गोपालपुरा-चिमनपुरा फोरलेन रोड (8.5 किमी.) (जयपुर)	16 करोड़ रुपये
25.	अहिंसा सर्किल से बस स्टैण्ड/ तिराहा सड़क मार्ग का नवीनीकरण व इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाला निर्माण (2.10 किमी.) (तिजारा, अलवर)	10 करोड़ रुपये
26.	टपूकड़ा से चौपानकी वाया झिवाना (7 किमी.) (तिजारा, अलवर)	14 करोड़ रुपये
27.	भिवाड़ी टोल से टपूकड़ा तक 6 लेन सड़क मय नाला निर्माण (10 किमी.) (भिवाड़ी, अलवर)	50 करोड़ रुपये
28.	ढाढरिया खुर्द-गाजू-पालड़ी जोधा-जनाणा-झुझण्डा-आमण्डा-बींठवाल-बलाया-पालड़ी व्यासा-भाकरोद-शीलगांव-लालाप-माणकपुर-मेड़ास-कालियास-भदोरा-कंकड़ाय-सैनणी असावरी-दियावड़ी (95 किमी.) (खींवसर, नागौर)	75 करोड़ रुपये
29.	वारिसपुरा से बीबासर सड़क (11 किमी.) (झुंझुनू)	14 करोड़ रुपये
30.	बगड़ से इस्लामपुर सड़क (5 किमी.) (झुंझुनू)	6 करोड़ रुपये
31	भडौन्दा कलां में बाईपास का निर्माण (4 किमी) (झुंझुनूं)	6 करोड़ रुपये
32.	भुकाना में बाईपास का निर्माण (3 किमी) (झुंझुनू)	5 करोड़ रुपये
33.	बयाना-करौली जिले की सीमा पर नवलापुरा, डांडा गांव, ज्ञानी का बेड़ा, गाजीपुर, कोल्हूपुरा, ताली, छुनैनी सड़क (12 किमी.) (बयाना, भरतपुर)	12 करोड़ रुपये
34.	जगदीश भवन से एसएच-39 वाया खुमानपुरा-चिताम्बा-गोवर्धनपुरा-आसींद-बालापुरा-सलारमाला सड़क का चौड़ाईकरण (मांडल, भीलवाड़ा)	60 करोड़ रुपये
35.	बिल्यारा नदी पर ग्राम हाथौड़ में पुलिया मय सड़क निर्माण डूंगरपुर)	6 करोड़ 10 लाख रुपये
36.	दोलपुरा नदी पर पुल निर्माण (खेरवाड़ा, उदयपुर)	6 करोड़ रुपये
37.	नोहर रावतसर बाईपास (4 किमी.) (हनुमानगढ़)	20 करोड़ रुपये
38.	नांगल भरड़ा अमरपुरा रोड से ईटावा भोपजी सड़क तक वाया वाडीपुरा, घोसल्यों की ढाणी, बुनकरों का मौहल्ला, विशनपुरा-चारणवास (3.5 किमी.) (शाहपुरा, जयपुर)	3 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
39.	फोर्ट रोड वाया झरनेश्वर महादेव मंदिर (5.45 किमी.) (जालौर)	27 करोड़ रुपये
40.	नला से बरोनी-सिवाड़ सड़क वाया सिरस, मेहताबपुरा (11 किमी.) (टोंक)	11 करोड़ रुपये
41.	सलेदीपुरा से खटून्दारा वाया गिजरोइयों की ढाणी, बहु जी की ढाणी (9 किमी.) (खंडेला, सीकर)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
42.	सिमारला रोड से छोटा गुढ़ा तक सड़क वाया सिंगोद सीमा, बगड़ियों की ढाणी (10 किमी.) (खंडेला, सीकर)	4 करोड़ रुपये
43.	राजोला, सोजत सिटी, सोजत रोड, कंटालिया, बभाण जिला सीमा तक (17 किमी.) (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	19 करोड़ रुपये
44.	दूदू-फागी रोड चौरू नाड़ा से निमेड़ा पारली रोड वाया छापरी, नारेड़ा तक सड़क (17 किमी.) (दूदू, जयपुर)	19 करोड़ रुपये
45.	हरिपुरा से भाकरा होते हुए चक 5 एचआरपी तरमाला पुल तक सड़क (2.5 किमी.) (हनुमानगढ़)	1 करोड़ रुपये
46.	लांगरा कैलादेवी सड़क वाया भादरपुर-चौबे की गुआड़ी-अतेवा (22 किमी.) (करौली)	22 करोड़ रुपये
47.	भरतुन-डाबरा-सिन्धुपरा सड़क (7 किमी.) (करौली)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
48.	पुरानी वाडेली से मामावली (7 किमी.) (सिरोही)	3 करोड़ 50 लाख रुपये
49.	थोई पीतमपुरी रोड से अहीरों की ढाणी गांधी स्कूल तक सड़क (2 किमी.) (नीम का थाना, सीकर)	90 लाख रुपये
50.	नटनी का बारा से देवनारायण मंदिर तक सड़क मय पुलिया (अलवर)	8 करोड़ रुपये
51.	बूटाटी से डेगाना रोड का 2 लेन का कार्य (50 किमी.) (डेगाना, नागौर)	50 करोड़ रुपये
52.	कावड जौला आदलवाड़ा कलां भगवतगढ़ झौंपड़ा (30 किमी.) (खण्डार, सवाई माधोपुर)	22 करोड़ रुपये
53.	घासेली स्टैण्ड से तिजारा वाया मुसाखेड़ा तीतरका (19 किमी.) (किशनगढ़बास, अलवर)	22 करोड़ रुपये
54.	507 हैड, 1केएम से महादेववाली तक सड़क (10 किमी.) (बीकानेर)	4 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
55.	आलमसर से लालाणीयों का तला तक सड़क (चौहटन, बाड़मेर)	25 लाख रुपये
56.	किरवाड़ा महस्वा कूंजेला मिलकसराय, सोंप सड़क (26 किमी.) (करौली)	30 करोड़ रुपये
57.	खानकी चौकी से चंदेलीपुरा सड़क (16 किमी.) (करौली)	8 करोड़ रुपये
58.	सांगड से सम वाया खुहड़ी तक सड़क (55 किमी.) (जैसलमेर)	58 करोड़ रुपये
59.	इंटरचेंज फ्लाई ओवर से सीकरी तक सड़क (15 किमी.) (नगर, भरतपुर)	15 करोड़ रुपये
60.	कुणी, असावता, खेरोट, छोटा मायंगा, छायण, रतनपुरिया, बड़ी लाक, शाहजी का पठार, पांच ईमली, बमोतर, अमलावद, साकरिया, बसाड, कीटखेड़ी, राजौरा, सेमली, अरनिया, देवद, बसेरा तक सड़क (75 किमी.) (प्रतापगढ़)	40 करोड़ रुपये
61.	दांता से खाटूश्यामजी सड़क (16 किमी.) (रींगस, सीकर)	16 करोड़ रुपये
62.	चन्द्रगढ़ बमोरी रोड पर बडोदिया के सामने पुल निर्माण (किशनगंज, बारां)	60 लाख रुपये
63.	कांकराला-मोरडा सड़क (5 किमी.) (पचपदरा, बाड़मेर)	2 करोड़ रुपये
64.	बालोतरा में लूणी नदी किनारे छत्रियों का मोर्चा से मेगा हाईवे तक सड़क (5 किमी.) (बाड़मेर)	2 करोड़ रुपये
65.	थुम्बली से बलाऊ (7 किमी.) (बाड़मेर)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
66.	स्वरूपगंज से दर्री सड़क मय पुल निर्माण (मांडल, भीलवाड़ा)	15 करोड़ रुपये
67.	अंधियारी गढ़ी जाफर मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (राजाखेड़ा, धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
68.	हथवारी खेरिया मार्ग पर पुल निर्माण (राजाखेड़ा, धौलपुर)	4 करोड़ रुपये
69.	धामली से भीमालिया मार्ग पर पुल निर्माण कार्य (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	4 करोड़ रुपये
70.	हिंगोला-पुल निर्माण (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	5 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
71.	गोगामेड़ी से ददरेवा वाया हुणतपुरा सड़क (20 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	10 करोड़ रुपये
72.	लाम्बा से तिलवासनी (12 किमी.) (बिलाड़ा-जोधपुर)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
73.	भीम क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का निर्माण (58 किमी.) (भीम, राजसमंद)	26 करोड़ रुपये
74.	सरगांव से जिला सीमा तक सड़क (6 किमी.) (सहाड़ा, भीलवाड़ा)	6 करोड़ रुपये
75.	आहोर मुख्यालय से खारा जोगवा, संखवाली, चुंडा, नीमला सड़क मार्ग (25 किमी.) (आहोर, जालौर)	15 करोड़ रुपये
76.	डोडियाना-जेसासरी (एमडीआर 242) सड़क (62 किमी.) (खींवसर, नागौर)	60 करोड़ रुपये
77.	त्रिवेणी जहाजपुर देवली सड़क पर पीपलून्द ग्राम में बाईपास निर्माण कार्य (स्टेट हाईवे-134) (3 किमी.) (जहाजपुर, भीलवाड़ा)	16 करोड़ रुपये
78.	दिल्ली बाईपास मानबाग चौराहे से होते हुए 2 नम्बर बस स्टैण्ड होते हुए जाटों की ढाणी तक सड़क (जयपुर)	20 करोड़ रुपये
79.	रेलवे अंडरपास आजाद नगर व देवनगर के बीच (श्रीगंगानगर)	5 करोड़ रुपये
80.	दहलोद से करेड़ा वाया गोरधनपुरा, भरथला वाया बीड की ढाणी से धतूरी तक, खाजपुरा रोड से भरथला, लुहारा से श्रीसुरतपुरा बैरवों की ढाणी त्यागीजी आश्रम, पटेल टीबी से पंचायत मुख्यालय ललवाड़ी तक मय पुलिया, ग्राम दहलोद से हीरामल बाबा स्थान डोईयो की ढाणी तक (22 किमी.) (टोंक)	8 करोड़ 50 लाख रुपये
81.	बगड़ी से डूसरी, बगड़वा से गूढ़ारामदास, प्यावड़ी से कंवरपुरा बैरवा ढाणी, डिग्गी रोड से मोहम्मद नगर बैरवा की ढाणी (25 किमी.) (टोंक)	6 करोड़ रुपये
82.	खाजूवाला से 7केएनडी 365 हैड जिला सीमा तक (23.70 किमी.) (बीकानेर)	15 करोड़ रुपये
83.	खाजूवाला से एमडीआर-296 वाया 3 पावली, 40 केवाईडी, अलदीन, भागु फांटा (32 किमी.) (खाजूवाला, बीकानेर)	18 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
84.	पूंजपुर कोठडी खेरमाल सड़क (डूंगरपुर)	10 करोड़ रुपये
85.	10 बीजीएस भागसर की सम्पर्क सड़क (2.50 किमी.) (सादुलशहर, श्रीगंगानगर)	1 करोड़ रुपये

II. आधारभूत सुविधाओं व अन्य संरचना कार्य-

क्र.सं.	आधारभूत सुविधाओं के कार्य	लागत
1.	हवामहल से गुजरने वाले नालों को ढंकवाने का कार्य (जयपुर)	105 करोड़ रुपये
2.	जयपुर के गलता पीठ मंदिर, सामुदायिक केन्द्र व दिल्ली रोड स्थित नाग तलाई नाले के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य	35 करोड़ रुपये
3.	नोहर-हनुमानगढ़ में सीवरेज कार्य	20 करोड़ रुपये
4.	जौहरी सागर-चूरू में सीवरेज व ड्रेनेज कार्य	23 करोड़ रुपये
5.	त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथम्भौर-सवाई माधोपुर में गणेशधाम से मन्दिर तक रोपवे का निर्माण (सवाई माधोपुर)	20 करोड़ रुपये
6.	पुष्कर घाट-अजमेर का पुनरुद्धार व विकास कार्य	80 करोड़ रुपये
7.	अजमेर में जल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन एवं अन्य कार्य	31 करोड़ रुपये
8.	जवाई बांध से सिरोही तहसील के गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु डीपीआर (सिरोही)	2 करोड़ रुपये
9.	जैसलमेर के महाराणा प्रताप मैदान में अंडरग्राउण्ड पार्किंग	10 करोड़ 41 लाख रुपये
10.	मझोला तालाब का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (डूंगरपुर)	5 करोड़ रुपये
11.	भृर्तृहरि धाम पर अमर गंगा नाले का जीर्णोद्धार व अन्य विकास कार्य (अलवर)	5 करोड़ रुपये
12.	नमाना में घोड़ा पछाड़ नदी पर लाडेश्वर महादेव के सामने बैंक प्रोटेक्शन कार्य (बूंदी)	7 करोड़ रुपये
13.	गंगापुर सिटी व 109 गांवों के लिए अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति (सवाई माधोपुर)	15 करोड़ रुपये

क्र.सं.	आधारभूत सुविधाओं के कार्य	लागत
14.	चम्बल-पांचना-जग्गर लिफ्ट परियोजना का कार्य (करौली, सवाई माधोपुर)	20 करोड़ रुपये
15.	नसियां जी की पहाड़ियों का सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य (सागवाड़ा, डूंगरपुर)	6 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-06

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 39 में उल्लिखित विवरण के अंश

I. सवा-बाड़मेर में 220 केवी जीएसएस स्थापित किया जायेगा।

II. मुबारिकपुर (रामगढ़)-अलवर; हरसानी फांटा, पनोरिया (चौहटन)-बाड़मेर; पूगल-बीकानेर; उच्चैन (नदबई)-भरतपुर; दल्लुसर, घड़सीसर (सरदारशहर)-चूरू; लोठियाना (रावतभाटा)-चित्तौड़गढ़ एवं जीरोता (लवाण)- दौसा में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. बीघोता (राजगढ़)-अलवर; पथराली-भरतपुर; शिवनगर-बाड़मेर; पातलीसर (सरदारशहर)-चूरू; माधोपुर-चित्तौड़गढ़; कोड (डेगाना), शेरानीआबाद (डीडवाना) नागौर एवं धनियासर (नोहर)-हनुमानगढ़ में 33/11 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

IV. नगर-भरतपुर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) कार्यालय तथा डूडवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर; झोथरी-डूंगरपुर; मासलपुर (करौली) एवं कल्याणपुर, मेहलू (धौरीमन्ना)-बाड़मेर में सहायक अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे।

V. जयपुर में मानसरोवर से स्वेज फार्म होते हुए एसएमएस स्टेडियम तक 132 केवी हाईटेंशन लाइन को अंडरग्राउण्ड किया जायेगा।

परिशिष्ट-07

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 55 में उल्लिखित सूची के अंश

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु-

I. लालसोट-दौसा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जायेगा।

II. सिवाना-बाड़मेर व आहोर-जालौर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

III. तनोट-जैसलमेर; कैलाशनगर-सिरोही; श्रीनाथ जी (नाथद्वारा)-राजसमंद; जाजोद (खंडेला), गोकुलपुरा-सीकर एवं गोठड़ा (नवलगढ़)-झुंझुनूं में पुलिस थाने खोले जायेंगे। साथ ही, बयाना-भरतपुर में सदर पुलिस थाना खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त, नावां-नागौर व कोटपूतली जयपुर में महिला पुलिस थाने खोले जायेंगे।

IV. टांटोटी (केकड़ी) अजमेर; मुख्य बाजार (बानसूर) अलवर; बड़ा महुआ (सुवाणा); चिताम्बा नानकपुरा (मांडल)-भीलवाड़ा; वैर-भरतपुर; बांसखोह (बस्सी)-जयपुर; भगवतगढ़ (खंडार)-सवाई माधोपुर; तुलसी वन रोड (बाड़ी)- धौलपुर एवं जगत (कुराबड़)-उदयपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेंगी।

परिशिष्ट-08

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 57 में उल्लिखित सूची के अंश

I. खाजूवाला-बीकानेर; नदबई-भरतपुर व भीण्डर-उदयपुर में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय खोला जायेगा। साथ ही रामगढ़-अलवर में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट खोला जायेगा।

II. मारवाड़ जंक्शन-पाली में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जायेगा।

III. मावली-उदयपुर; किशनगढ़-अजमेर एवं नाथद्वारा-राजसमंद में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जायेंगे।

IV. बज्जू-बीकानेर; चिखली-डूंगरपुर एवं मंडरायल-करौली में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय खोला जायेगा।

V. तिजारा-अलवर में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) खोला जायेगा।

परिशिष्ट-09

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 68 में उल्लिखित सूची के अंश

प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु-

I. सीकर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जायेगा।

II. केकड़ी-अजमेर एवं लालसोट-दौसा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोले जायेंगे।

III. सुहागपुरा-प्रतापगढ़ एवं आऊ (लोहावट)-जोधपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे।

IV. छोटी खाटू (डीडवाना)-नागौर; सायरा-उदयपुर एवं जनूथर (नगर)-भरतपुर में तहसील कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, रामपुरा डाबड़ी-जयपुर; गजसिंहपुर मण्डी (श्रीकरणपुर)-श्रीगंगानगर को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. बाम्बोली (रामगढ़), डहरा अलवर; हीरा की ढाणी (गिड़ा), चवा. फागलिया-बाड़मेर; साडास (बेगूं)-चित्तौड़गढ़; देलाड़ी (बांदीकुई), बालाहेडी (महुवा) दौसा; झील का बाड़ा-भरतपुर; चांधण-जैसलमेर; पाडवा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर; बूड़सू (मकराना), जोधियासी (जायल)-नागौर; सिरस (निवाई)-टोंक एवं मलारना चौड़-सवाई माधोपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

VI. सावर (केकड़ी) अजमेर; नौगांवा (रामगढ़) अलवर; देई-बूंदी; लवाण-दौसा; खेरनी-सवाई माधोपुर; फागी (दूदू), वाटिका-जयपुर; दूनी (देवली-उनियारा)-टोंक एवं वल्लभनगर-उदयपुर को नगरपालिका बनाया जायेगा। साथ ही, नगरपालिका खैरथल-अलवर व नीम का थाना-सीकर को क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. नोहर-हनुमानगढ़ में रोडवेज बस डिपो खोला जायेगा। साथ ही, निवाई-टोंक बस स्टैण्ड का आधुनिकीकरण किया जायेगा।